# LOK SABHA DEBATES

(Sixth Series)

Vol. XVIII

[August 12 to 31, 1976/Sravana 21 to Bhadra 9, 1900 (Saka)]



Pifth Seesion, 1978/1900 (Saka)

(Vol. XVIII contains Nos. 21-32)

LOR SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

### CONTENTS

No. 30, Tuesday, Augus	t 29,	1978/	Bhadi	u 7,	1900	(Saka)	)
Oral Answers to Questions:							Column
*Starred Questions Nos. 488 t	:0 <b>49</b> 0	and	492				1-24
Written Answers to Questions:							-
Starred Questions Nos. 491 an	ıd 49.	to :	509			•	2.1—43
Unstaffed Questions Nos. 4730	9 to .	1938					<u> 13-208</u>
Reshort Notice Question on Repo	rted •	Murc	ier of	Two	Chile	dren	209-10
Questions of Privilege against (i) Edi (ii) Shri Somjibhai Damor, M.	tor, T P.	he N	ationa •	i Her	ald a	nd	211-12
Message from Rajya Sabha .							212
Calling Attention to Matter of Urger	nt Pul	blic II	mport	ance-			
Reported violent clashes involv Hindustan Shipyard and Bu	ing na	aval p orkers	erson	nel, v	worker	s of	212-20
Shri Vijay Kumar Malhot	ra					. 21	2, 214-15
Shri Dhanik Lal Mandal							212-13
Shri Janardhana Poojary			٠				216-17
Shri Ugrasen						,	218-19.
Shri Jagjivan Ram		•				•	219, 220
Shri Vasant Sathe	•						219-20
Estimates Committee-							
Twenty-second Report and Mi	nutes	•		•	•	•	221
Public Accounts Committee— Eighty-third, Eighty-sixth and	Nine	etieth	Repo	rts			<b>22</b> I
Matters under Rule 377-							٠.
(i) Reported Research into the	rmo-a	uclea	r fusio	on—			
Shri D. D. Desai							221-22

<sup>\*</sup>The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

//// AT 1.0 0 1				_	•		-1	Columns
(ii)) Need for four-lan Road—	ing of r	oad	betwee	en Pan	ivel :	and D	enu	
Shri S. R. Damar							•	<b>222-2</b> 3
(ili) Reported Selection	of Airc	raft	tor ir	idian .	Air I	rorce-	-	
Shri Raj Narain		•	•	•	•	•	•	22325
(iv) Public School Sys	tem							
Shri Raj Krishna	Dawn	•	•	•	•	•	٠	225-26
(v) Reported Deaths Himachal Pradesh	and He	eavy	Loss	es due	to	Rains	in	
Shri Druga Chanc	i	•	٠	•	•	•	•	226
Press Council Bill-								
Motion to consider— Shri R. Venkataran	man							22729
Shri Nirmal Chan	dra Jain							2?9—3 I
Shri C. K. Chand	rappan							231-33
Shri O. P. Tyagi								233-35
Shri Dhirendranat	h Basu					•		235-36
Dr. Ramji Singh								23739
Shri Ram Kishan								239—42
Shrimati Chandray	ati .							242-44
Chowdhry Balbir	Singh						•	241-45
Shri Amrut Kasar			•					245-47
Shri Laxmi Narair	n Nayak		•	•			,	247-48
Prof. P. G. Maval	ankar			•				248—50
Shri Druga Chand	١.		•			•		250-52
Shri Chitta Basu	•	٠	•	•				252-54
Shri Purnanarayan	Sinha		•					254-55
Shri B. C. Kambl	е .		•					<b>255</b> —57
Shri Ajitsinh Dabl	hi .	•		٠				257-58
Shri A. K. Roy.	•							25860
Shri L. K. Advan	i .			. ,				260-74
Caluses 2 to 5	•				•			274—83

	•							Columns
Motion	Re. Increasing Play of Mo	on <b>cy</b>	Powe	r in :	Blectic	ons—		
	Shri K. P. Unnikrishnan				•		•	283—93
	Shri Gauri Shankar Rai							<b>294-9</b> 9
	Shri Vasant Sathe .			•				299—302
	Shri Samar Mukherjee		•					302-307
	Shri P. K. Deo		•				•	307 <b>—3</b> 10
	Shri Krishan Kant .		•		•			311-16
	Shri A. Bala Pajanor .		•				•	316-20
	Shri Hari Vishnu Kamath	١.	•	•		•	•	320—26
	Shri C. K. Chandrappan		•	•	•	•		326—31
	Shri Kanwar Lal Gunta							331-36

### LOK SABHA

Tuesday, August 28, 1982/Bhadra 7, 1988 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Mn. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bharat Singh Chowhan.

SHRI VASANT SATHE: It is such a shocking. .....

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Sathe what is shocking? The Question Hour is not a shocking affair. I am very sorry. Mr. Sathe, you can not just get up and raise any matter you like.

### (Interruptions)

SHRI VASANT SATHE: Two children were killed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no please Mr. Sathe. There is a way of raising things. You cannot do that here; and you cannot obstruct the Question Hour like this. We have never done this before and I am very sorry I will not allow you. Mr. Bharat Singh Chowhan.

#### (Interruptions) \*\*

SHRI SAUGATA ROY: Let the whole thing be expunged.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The whole thing is expunged.

SHRI SAUGATA ROY: Thank you very much.

SHRI VAYALAR RAVI: Thank you very much.

#### (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister. Please take your scats.

(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER Mr. Ugrasen, please take your seat. Mr. Chowhan, you have put the question

Yes, Mr. Minister.

### निर्वारित समय के बाद चलने वाली रेलक्स्वियां 📱

\*488- भी भारत सिंह चौहान दूँनवा रेस अंदी ] नंदी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि बहुत ती रेलगाविका अपने निर्धारित सनव के बाद चलती हैं ;
- (ब) यदि हां, तो क्या रुरकार ने वह सुर्विश्वत करने के लिए कि रेजगाड़ियां देर से व वर्ज, कर्न-चारियों को प्रोत्साहन देने की कोई बोजना हैगार की है:
- (ग) यदि हां, तो तस्संबंधी स्थीरा क्या है ; स्थीर
  - (थ) बदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल नंतीं,(ब्रो॰ सबु बंडब्से): (क) भीवण गर्मी के दौरान मई 78 महीने में गाड़ियों का समय-पालन सन्तोवजनक नहीं था। लेकिन, जुलाई में समय-पालन 90 6 प्रतिन्नत तक हो गया है।

(ब) से (घ). गाड़ियों को तमय से बजाना रेलकमंबारियों की सामान्य स्मूटी है। फिर भी, गाड़ियों के समय-पालन में सुधार जाने के लिए कर्य-बारियों द्वारा किये गये विज्ञाव प्रयाक्षों के लिए नगद पुरस्कारों, प्रजासित पत्नों भावि के रूप में उन्हें कुछ प्रोस्ताहन विये जाते हैं।

श्री भारत सिंह चौहान : मैं रेल मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो गाहियां लेट चलती हैं उनसे संबंधित क्षिरकारियों को दिण्डत किया जाता है या नहीं?

प्रो० सधु बंदबते : माननीय, जब गाड़ियां लेट ध्राती हैं तो उसके कई कारण होते हैं। जैसे मैंने पहले श्री बताया था कि घलांज चैन पुलिए, धोखें से जंजीर खोंचने के केंसिज जनवरी से मई महीने में सब से ज्यादा बे। उसके बाद जून महीने में कम हुए हैं। जब किसी श्री कर्मवारी की पक्चपुलिटी कम होती हैं। जब किसी धीक मंचारी की पक्चपुलिटी कम होती हैं। जब किसी धीक पिए जिम्मेदार होता है तो उसके बारे में जकर एक्बन लिए जिम्मेदार होता है तो उसके बारे में जकर एक्बन लिया जाता है। यह पहले भी मैंने बताया था, उसको फिर दोहराना चाहता हूं।

श्री बारत सिंह बोहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह को कच्छीगुडा-अजनेर लाइन है, यह अनकर केट व्यक्ती है बीर इसका कारण यह है कि पिछले 5.0 सालों से

<sup>\*\*</sup>Expunged as ordered by the Chair.

इस साइन पर कोई तेज रफ्तार नाबी नहीं चलाबी मबी । इस बाड़ी में स्टीम इंजन इंटिज़िंडि कीटिश्चेंट हैं 🥂 🚧 🖹 ही किए मुँह बैट बर्ग होती है? फिर बब देन सिवनस इंक्टों में कोई परिवर्तन नहीं किया नवा जबकि और साइनों पर किया गया है।

### क्ष्याच्यका व्यक्तीयम : भाष प्रश्न पुष्टिए ।

Oral Answers

भी भारत सिंह भीहान : मेरा स्वेश्यन यह है कि क्या उस साइन पर डीजन इंजन काबू किया जाएगा जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिले क्योंकि यह कच्छी-वदा-सम्बन्ध साहन बहत वही लाइन है ?

जो • सब बंदकते : श्रीमन यह बात सही है कि हम शीवों के पास स्टीम इंजनों की तुलना में डीजल इंजन कम है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हं कि इबारे पास 8263 स्टीम इंजन, 1903 डीजल इंजन बीर 844 इलैन्ट्रिक लोकोमोटिक्ज हैं। 1971 के बाद से स्टीम सोकोमोटिन्ज मैन्युफेक्चर करने का काम हम लोगों ने बन्द किया है। बागे चल कर डीजल भीर इनैन्द्रिक लोकोमोटिक्य ही रहेंगे। लेकिन जब तक पूराने ईजन हैं, वे जरूर तकलीफ देते हैं। उन पर मेंटीनैंस भी काफी करना पड़ना है। माननीय सदस्य की यह शिकायत सही है कि जिन रूटन पर पूराने स्टीम इंजन हैं, वहां काफी तकलीफ रहती है. वहां लास ब्राफ पंके बुएलिटी भी होता है। लेकिन ब्राहिस्ता बाहिस्ता जैसे जैसे स्टीम इंजन कम होते जायेंगे, उसकी जगह पर बीजल इंजन लगाये जाते रहेंगे।

भी राम कंबर बेरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता है कि पिछले दिनों में रेलों के ड्राइवर्स को प्रमीमन दी गयी थी, उनको क्लास ए में कर के स्पैशल ग्रेड में कर दिया था, इसके संबंध में जब हमारी निचले स्तर के रेलवे कर्म-चारियों से बातचीन हुई तो उन्होंने बताया कि जो धक्छा काम करने वाले हैं, उन्हें इनाम नही दिया जाता है, धीर मंत्री महोदय यह कह रहे हैं हम उनको पुरस्कृत करते हैं तो इनमें कीन सी बात मही है ? क्या रें लों के कर्मचारियों में इस बारे में बसन्तीय नहीं है ? क्या इसकी शिकायतें भाग के पास भागी हैं ? क्या इसकी जिकायत भी भापके पाम भायी है कि जो शहमदाबाद मेल जाती है वह बादीकुई में जाकर के सेट हो जाती है भीर उस समय लेट हो जाती है जबकि सामने से कोई देन नहीं था रही होती है ?

त्रो॰ **मध् पंडवते** : श्रीमन्, मैने पहले ही बताया है कि जब कोई भी गाडी सेट होती है तो उसके बाद टाइम को मेकब्रप किया जाता है और बन्तिम स्टेशन पर वह गाडी ठीक समय पर पहुंचती है। ऐसे ड्राइवरों को हम नकद भीर विभेष प्रकार के पुरस्कार देते हैं। इस प्रकार की जर्नी पूरी होने के बाद 15 रुपए से 25 रुपए तक हम उन्हें नकदे पुरस्कार देते है और यह तब देते हैं जब वे टाइम मेक अप करते है।

भी प्रारिका नाम तिवारी : क्या यह बग्त सही है कि जैनें बीच में स्टेशनों पर खींची जाती हैं और तभी गाड़ी लेट हो सकती है ? क्या यह बात भी सही नहीं है कि जहां से साड़ी चलती है, या जहां से गाड़ी खोली वारी है, समर उस स्टेसन पर इसकी बार बने समना पर रिसीय की बाती है तो उसे वहां वर बाबा-बाबा वंटा रोकर क्यों केट किया जाता है ? क्यों नहीं पहचे से इस बात का ज्यान रखा बाता कि उस बक्ते लाईन पर गाडी आने वाली है और इन की क्लीबर रखा जाए क्या इन कारणों से भी अप्रक्रियां लेट नहीं होती हैं ?

मी॰ वय पंचवते : मायनीय सदस्य ने प्रका है कि गाडियां देरी से क्यों छुटती हैं ? उसके बारे में मताना जरूरी है। कई मतेबा जिस सेक्सन पर नाडी चलने बासी है उस पर...लाइन कलीयरेंस नहीं है, सैच्रेटेड कैपेसिटी घौर लाइन कैपेसिटी श्रीक्यूप्रेड्ड है। तो जिस स्टेशन से गाड़ी शुरू करनी है वहाँ विक्कत न होते हुए भी आगे सैक्सन में जो दिक्कतें हैं उसकी बजह से कई मतंबा काफी दिक्कतें पैदा होती है। इसको दूर करने की को किस कर रहे हैं।

भी हारिका बाब तिबारी : जब गाड़ी लेट होती है तो सिगनस पर खड़ी करके और सेट कर दी बाती है. इसका क्या अवाब है ?

शो॰ नधु यंद्रवर्ते : हर स्टेशन की कोई टॉमनल कैपेमिटी होती है। मैंने पहले भी कहा कि कई मतैबा गाड़ी ठीक समय पर खाती है लेकिन हर स्टेमन की जो टॉमनल कैपेसिटी है वह कभी कभी पूरी भीक्यू-पाइड होती है इसलिए स्टेशन से कन्द यार्ड पहले गाड़ी मिगनल के पास रोकी जाती है, भीर जब स्टेशन प्लेट-फार्म से गाड़ी क्लीयर हो जाती है तब गाड़ी स्टेशन पर माती है।

भी शंकर देव : इमरजेंसी के समय में एक ही दिन में एक ही बाईर के बनसार देश के बन्दर सारी गाहियां समय पर चलने लगी थीं, क्या माननीय मंत्री ममझते हैं कि यह इमरजेंसी का एक ध्रवीवमेंट था ? माज भी सारी गाडियों को पंक्षप्रली बलाने के लिए भाप ऐसा चार्डर दे सकते है या नहीं?

प्रो॰ सब दंश्वते : इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया था कि इमरजेंसी के दिनों में गाडियों की जो पंग्युएलिटी बी उसके मुकाबले में बाहिस्ता बाहिस्ता पंत्रकुए लिटी बढ़ती रहे। उसके बाद मई महीने में गर्मी में कम हुई थी। जहांतक बीड गेज का सवास है लगातार हर महीने में हमारी कोशिय होने के बाद मई महीने में 1978 के पंक्ष्युएलिटी श्रीड गेज पर 82.4 परसेंट थी, जन 1978 में 85' 1 परसेंट हो गई, जुलाई में 90, 6 परसेंट हो गई भीर उसके बाद भगस्त महीने में 90.4 परसेंट हो गई। और भी बोडा सा उसमें मुधार हवा है भीर कई ऐसे जोंस है जहां, 95, 96 परसेंट भी पक्षुएलिटी हुई है। तो इमरजेंसी न होते हए भी हमारी कोशिय होगी कि पंक्युएलिटी जारी रहे नहीं हो धाप मांग करेंगे कि इमरजैंसी लाइए।

भी मीठा साल पटेल : मैं मंत्री जी से जानना वाहता है कि कई एक पैसेंजर ट्रेनों में जैसे मबुरा-बडीवा पर एक ही कोच है तो एक कोच एक दका लैट होने पर दो, बार विन तक वह लगातार लेट होती चनी जाती है क्वोंकि कोच एक ही है। बीर कुछ सहिकों को बैचे धावरा-कोटा पैसेंकर को सन्द कर रखा है कोचले की कवी के कारण दो बाप मेंट पर हो ब्यान बीचे, सैकिन वो वाहियां बन्च कर रखी हैं या विवक्त पास केवल एक ही कोच है कन कोचों को यहाने के बादे में क्वा सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

त्री॰ लखु वंद्यको : वैने एक सनय सवन में ब्रेयाया या उन माहियों के लिये को स्टीन इंदन से व्याप्ती हैं और इंडस्ट्रीय के लिए स्टीम कोन की व्यस्पत हैं। सैक्तिन कोन के निवस्पत हैं। सैक्तिन कोन के निवस्पत हैं। सैक्तिन कोन के निवस्पत कोन देना है तौर रेल वाहियों के बार हैं। प्रौर रेल वाहियों के बार में विचार करने के सन्द हमने तब किना अपर पायर स्टेबन्स बन्द हो चाते हैं वो सब इन्यस्ट्रीय को सक्कीफ होती हैं। इस्तियें कव स्त्रीन कोन कन हो प्रधा 150 पेयतें आफ ट्रेंस को हमको बन्द करना पड़ा । सेकिन वेस के सक्कीफ होती हैं। इस्तियें का स्त्रीन कोन कर हो प्रधा 150 पेयतें आफ ट्रेंस को हमको बन्द करना पड़ा । सेकिन वेस वेसे कोवना विनता जायेगा हम बुझ और बांच वाइन्स की वाहियां किर बुक करेंसे, प्रीर को बाइन्स की नावियां कर सुक करेंसे, प्रीर को सहस्त्र का सामनीय सदस्य ने रखी है उसकी सरफ करर स्थान देंगे।

श्री चतुर्जुल : मंत्री जी ने रेलों की रक्तार बढ़ाने शौर समय पर चलने के लिये बताया जिसके लिये बहु सन्यवाद के पात हैं। लेकिन क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 30 मई तक कितनी गाड़ियां समय पर वलीं उनका परसेंटेज क्या है, और कितनी गाड़ियां समय पर नहीं चतीं, उनका परसेंटेंज क्या है ?

त्रो० वधु वंडवते : मैने तो बताया, सभी सापके सामने जो आंकड़े बौब गेज के बताए उसमें बताया कि वर्ष 1978 में पंक्कुएनिटी 82. 4 परसेंट रही है भीर मीटर गेज पर 86.1 परसेंट रही, और हिन्कुस्तान में तो 11,000 पाड़ियां चल रही है उसमें 6,000 पैसेंजर ट्रेंस हो इसमिये 6,000 पैसेंजर ट्रेंस का हिसाब लगा कर सापके सामने यह परसेंटेज रखा है बाप कैलकुलेशन कर लीजिए।

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Sir, we are informed that the Janata Party train was waiting outside the outer signal. Because of the mediation efforts in which the Railway Minister was also involved. I would like to know whether he will assure the House that the said train will reach the destination in time.

PROF. MADHU DANDAVATE: I welcome the question. It might be true that the Janata Party train might actually be waiting at the outer signal, but in the Emergency the Congress train and democracy were completely derailed. They actually allowed the derailment.

### Railway Station at Sheloo

- \*489. SHRI D.B. PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) whether there is a constant demand for the last 20 years for a railway station at

Sheloo (between Neral and Wangani) on Bombay Poona line;

- (b) whether it is a fact that near about 2500 passengers from that area travel by railway;
- (c) whether it is also a fact that a station is provided for, if there are more than five hundred passengers travelling daily from a particular spot; and
- (d) if so, what are the reasons for not sanctioning and constructing a station at Sheloo?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):
(a) Yes, Sir. A statement is laid on the table of the House.

- (b) About 2200 passengers travel daily from Neral and Vangani stations which are at a distance of 4.87 Kms, and 3.26 Kms. respectively from the proposed site.
  - (c) There is no such rule.
- (d) The proposal was examined in the past but was not found operationally feasible and there was no financial justification also. However, this proposal is being examined afresh inview of the persistent demand from the people in this area.

### Statement

Railway Station at Sheloo

The following representations have been received from the public for opening a station at Sheloo since 1958:—

S. Name of the party from whom Year No. the representation was

	1 CCC 1 CC	
1	2	3
I	Shri M.J. Dave, Village Sheloo, Taluka Karjat Distt. Kolaba	1958
2	Shri Tukaram Laxman, Sona- vale & others village Shelu, through the Commissioner, Bombay Division	1959
3	The Collector of Kolaba .	1961
4	A joint representation from the residents of Village Bhadwal & Damat, Talu- ka-Karjat (Kolaba)	1961
5	Shri B.N. Dighe, the then M.P., Lok Sabha	1964

Gram Panchayat, Sheloo . 1972 o Shri S.V. Dhamankar, the

Oral Answers

then M.P. (Lok Sabha) 1972 10 Shri Yashvant Gopal Patil,

Village, Sheloo 1973 11 Shri K.B. Tare from Sheloo

1977 12 Shri Vasudev Pitkar, President , Janata Party, Neral. 1978

SHRI D.B. PATIL: It has been admitted that there is a constant demand for the last 20 years and as many as 2,200 passengers travel daily from this particular place. Among those passengers are students and workers going to Bombay, Poona and other industrial areas, and vegetable growers taking the vegetables to Bombay and other industrial areas. In view of the fact that it is necessary and also in view of the fact that you are going to examine this demand. I would like to know from the hon. Minister whether in the near future it is likely to be taken up.

PROF. MADHU DANDAVATE: In 1964 the problem was examined in depth and at that time it was found out that the capital investment that would be required for the introduction of the station would be about Rs. 2 lakhs. To be exact, it would be Rs. 2,36,335. And it was also found out that the recurring losses per year would be of the order of Rs. 69,000. That would ThirdbeactuallyRs.69,405 per annum. ly, it is found out that since the distance between the existing two stations, Neral and Wangani is 7 kilometres, and within such a short distance, if we try to introduce an additional station, since Bombay to Poona is a highly density traffic route, and the capacity of the section is completely saturated today, running of trains is likely to be disturbed. But in spite of that we have received the latest communication on 23-5-1977 from a prominent person, Mr. K.B. Tare, from that area and I have already decided on 7-7-1977 that that particular problem should be gone through by the Central Railway and only when the problem is thoroughly examined, I will be able to give further information.

SHRI R.K. MHALGI: When would this full examination of the problem be completed?

PROF. MADHU DANDAVATE: I can assere you that within a few months we will be able to see what exactly can be done in the matter. Whether the reply is positive or negative, I will be able to give the information to the Hon'ble Mem-ber,

थी कालची जाई । मंत्री महोदय ने आणी यह बताबा कि सर्वे करने के दौरान बीर इस नाइन के पान् करने में इतना **अर्थ** होना । **उन्हों**ने **अर्थ** के कांकरे बताये । जेकिन चांजू हो चांने ने बाब कितने समय के बाद क्या-क्या मुनाका होता है, यह महीं बताबा। यह भी चन्हें बताबा चाहिए ?

औ॰ जब दंडवते । मैंने तर्वे का खर्चा नहीं बतावा है, मैंने" कैपिटल एक्सपेंडियर बताया है। सगर यह नया स्टेशन बनाना होगा, तौ उसके लिए कितनी पूंजी सगानी होगी, वह ब्रांकड़ा मैंने 2,36,335 भगए बताया है। मैने यह भी बताया है कि स्टेशन बनने के बाद भी हर सांस रेकरिंग सांस 69,405 क्पए होया ।

भी कामकी कार्ड : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि भाग कितनी होती । उन्होंने बर्चा बताया है ।

प्रो॰ मध् बंडवरी : प्रगर वह स्टेशन वन बाता, है. तो इस की कैपिटल कास्ट : 2,36,335 क्पए मनिका: 7,446 स्पए, एक्सपेंडिकर: 76,851 रुपए भीर इस लिए मास : 49,405 रुपए होगा ।

### Robberies in Running Trains

•490. SHRI K. LAKKAPPA: SHRI DURGA CHAND :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to lay a statement showing :

- (a) whether Government's attention has been drawn to the serious situation arising out of the activities of robbers in the running trains throughout the country;
- (b) if so, the number of train robberies during the last one year, monthwise, to-gether with date and the number of persons arrested ;
- (c) estimated loss to the passengers in each case and how Government propose to compensate them; and
- (d) whether any steps have been taken by Government to minimise the robbery cases in the Railway and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS ( PROF. MADHU DANDAVATE ); (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

### Statement

(a) Yes.

- (b) and (c). Number of robberies and decoities, monthwise together with the date and the number of persons arrested as well as the value of property lost by the passengers, is indicated in statements 'A', and 'B' laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2730/78] As par the existing rules no compensation is admissible to the victims of such crimes.
- (d) The responsibility of ensuring the personal safety of the passengers and the secuity of their belongings rests with the Railway Government Police which functions under the administrative and disciplinary control of the State Governments. Crime prevention and detection in respect of passenger safety and secu-rity of their belongings fall under the category of 'law and order' which is a State subject under the Constitution. However, the Railways render necessary assistance whenever required and close liaison is maintained at all levels with the State Police Agencies. The Railway Protection Force constituted under the RPF Act has preventive and detective nowers only in respect of unlawful possession of railway property. The R.P.F. is concerned with the protection of goods entrusted to the Railways for carriage and Railway materials.

Bsing concerned with the spate of heinous crimes in Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh, the Minister of Railways had written to the Chief Ministers of these States requesting them to take such measures to curb crimes in running trains. On 5-8-78, there was a high level meeting between the Minister of Railways and the Guief Minister of Uttar Pradesh at Lucknow in which the problem of crimes on railways was highlighted. The Railway Minister discussed this problem personally with the Chief Minister of Maharashtra at Bombay on August 10, 1978 and by relephone with the Chief Minister of Mathay Pradesh on August 13, 1978.

The response from the State Governments has been encouraging. Earlier on 16-6-1978 a high level meeting between the officers of the Ministries of Railways and Home Affairs was held. The following firm decisions were taken which have yielded encouraging results:

- (1) As the dacoits/robbers were silencing the passengers by show of fire arms and escaping after commission of crime generally by pulling alarm chain under cover of darkness a prompt channel of communication to the armed police guard whenever alarm chain was pulled at night was considered necessary. It was decided that the alarm chain whistle should be sounded repeatedly by the driver. On hearing of this alarm the armed police escort should split themselves in two parts and detrain to apprehend escaping criminals.
- (2) The police escort should be accommodated together as far as possible in the centre of the train and they should be equipped with powerful torches.
- (3) The police escort party may progressively be equipped with very light pistols which would be useful in lighting up the area on both sides of the train at night.
- (4) The Guards and Brakesmen should be provided with powerful torch lights in vulnerable trains over affected sections,
- (5) There should be a liaison with the States principally affected for stepping up police protection. Chief Security Officers of Eastern, Northern and Central Railways were specifically nominated to maintain close liaison with the State Police authorities of West Bengal, Bihar, U.P., Madhya Pradesh and Maharashtra. The CSOs of other Railways were directed to maintain liaison with above 4 Chief Security Officers. They were directed to indicate to the State Governments the strength of police guard which should be required on vulnerable trains and request the State Police authorities to provide the necessary protection. The requirement of State Governments has been projected to Ministry of Home Affairs.

The Zonal Railways have launched a drive to ensure strict adherence to the following preventive measures in coaches:

- (i) Vestibuled doors are kept locked between 22.00 hrs and 06.00 hrs. by the Travelling Ticket Examiners/Coach Attendants.
- (ii) Travelling Ticket Examiners and Goach Attendants remain vigilant during night time and prevent entry of intruders, hawkers and unauthorised persons into the coaches.

13

(iii) In case of non-vestibuled trains, the vestibuled doors are permanently closed or dummied.

The above measures formulated are in continuation of the various preventive steps taken by the Govt. Railway Police under the State Governments. The G.R.P. being alive to the problem adopted several regular preventive measures which are given below:

- (1) Escorting of important trains at night by armed guards of Govt, Railway Police of the concerned State Government.
- (2) Beat patrolling at stations, platforms/waiting halls.
- (3) Surveillance over criminals and known bad characters,
- (4) Checking of night trains by Supervisory Officers.
- (5) Armed pickets at vulnerable stations.
- (6) Special Squads of the C.I.D. of the State Governments take up investigation of important cases to apprehend the ganga responsible for these crimes,

The measures have been intensified by the Government Railway Police.

As a further measures to deal with occurrences of train robberies and dacoities, the Minister of Railways ordered deployment of armed RPF to escort the affected trains running in vulnerable sections. Primarily, they will protect railway property and will also help to instil confidence amongst the travelling public and deter criminals from operating on trains. Over 1400 armed RPF men were put on escort duty on different Railways from the first week of July, 1978. This I number has been increased to 2,000 since 16th August, 1978.

SHRI K. LAKKAPPA: The question was held over on that day because the Minister was not furnishing the full facts to this House. I have got great respect for Mr. Dandavate personally. But I do not know why he has failed as a Railway Minister. This question is regarding the spate of robberies in running trains. The answer that has been given is not only unsatisfactory but also not convincing. I do not know what are his powers and controls. He has stated in his reply that as per the existing rules, no compensation is admissible to the victims of such crimes. He has also stated that the responsibility of ensuring personal safety of the passenger is mainly the function of the State Governments and the disciplinary control of the State Governments and that it comes under

the category of law and order which is a State subject under the Constitution. So, he has no control over such things.

In our country about six thousand passenger trains and five thousand goods trains are running every day and twenty thousand CRP men have been engaged. But still the loss to the exchequer is about Rs. 4 crores. They have not even cared to protect the passengers and the robberies and dacotites are on the increase, and they have not been properly identified because he has no control over the States and the States are not furnishing the correct figures. He has laid a wrong statement on the Table of this House and thus bluffing this House. I do not agree with this. I would like to say that in five months from January to May, there has been an increase in the number of robberies and dacotics. But the statement shows that there is no increase as compared to the position that existed in 1977.

What I would like to arrive at is this. Whether this House has allowed him to make such a wrong statement on the Floor of the House under the Rules of Procedure. Will you kindly tell me about it? That is why I would like to bring to your kind notice......

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are asking a question from me... I am asking you to put a question.

SHRI K. LAKKAPPA: With your kind permission, I would like to bring to your kind notice that people are losing faith in travelling trains. On that day, you knew probably, there were about 20 commotions specially in the south bound trains. As far as the area of Madhya Pradesh is concerned, I do not know how Madhya Pradesh is famous for dacoities. Whether you have taken any action against this. The hon. Minister has no control over the law and order situation.

#### (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you put your question?
(Interruptions)

SHRI K. LAKKAPA: He has no control over the law and order situation

SHRI SURATH BAHADUR SHAH : Can I seek one clarification?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH: Mr. Lakkappa is using this form for asking useless questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Actually, he has over-steepped the mark; he has not put the question by now.

(Interruptions)

SHRI K. LAKKAPPA: Robbery and dacoity are increasing. He has no control over the States because the Constitution will come in the way. There are no rules, at present, to give compensation to the victims.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot make a speech during the Question Hour.

SHRI K. LAKKAPPA: On the basis of the statement, I am putting a supplementary. Then he himself has admitted that there are no laws to give compensation to the victims. Property worth about Rs. 1 lakh has been looted during the last 4-5 months especially in the trains.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are repeating the same thing.

SHRI K. LAKKAPPA: Therefore, in the absence of relevant rules and regulations, how the hon. Minister is going to check effectively this kind of a dacoity and robbery in the running trains? How would he control the railway police? In view of these things, will be consider to plug the loopholes and also try to bring legislation to this effect in order to have more control over these railway accidents and save these running trains from being attacked by robbery, murder, dacoity and what not?

(Interruptions)

I did not interfere when you were asking questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You took so many minutes in asking your questions. He has not even started the answer.

PROF. MADHU DANDAVATE: I did not interfere with the question when my hon. friend was asking the question. So, let him have the same patience. He has raised a question as towhat exactly is the authority of the railway in dealing with

such crimes. On more than two occasions I said and I will amplify that answer. is true that general law and order problem on the railways is under the jurisdiction of GRP which is under the jurisdiction of the GRP which is under the jurisdiction of the State Government, but we have also certain machinery like Railway Protection Force whose basic work, no doubt, is for the protection of installations, protections of various types of equipments on the trains and elsewhere. But we have evolved a machinery in cooperation with the State Governments, no matter whatever political complexion of the State administration, and I am happy to say that almost all the States have agreed to give us full cooperation. We have set up a coordination between the State machinery, RPF machinery and the railway machinery also-I mean TT and others—and the machinery that we have set up is like this especially those areas which are vulnerable areas for robbery and dacoities. In that area, wherever there are vestibule trains, we have opened out vestibule doors between two coaches; and for every two coaches, we have kept two RPF men.

We are putting one T.T. and two as med RPF. I am happy to inform the House that with the help of this arrangement we are able to control the situation though it took some time. Let me come to the dates, Initially there was trouble. There were dacoities.—after 11th August when we made this machinery tight not a single case of robbery and dacoity has taken place in Madhya Pradesh. Though efforts were made........

#### (Interruptions)

Let me complete the answer. (interruptions) That is before that.

After 11th August, no robberies and dacoities have taken place in Madhya Pradesh. But that does not mean that efforts were not made. Efforts were made by G.R.P. one RPF was able to detect them and we have been able to arrest them. I have given you in the table the number of persons that have been arrested. I, therefore, do not want to repeat it.

SHRI K. LAKKAPPA: I understand, I cannot get a relevant reply. I would like to give the reason why the Railway Ministry is not functioning properly. There is a conspiracy in the Government itself, Mr. Dandavate. The Home Ministry wanted to bring and also throw a muzzling on the Railway Ministry. The Hindi knowing officers are playing tricks and letting this loose in the areas where Jayanti Janta operates, G.T. operates and K.K. express operates. That comes into Madhya

16

Pradesh daily, All shore south bound trains are being attacked. Same type of people are operating. I will read out.

MR. DEPUTY SPEAKER: I do not want any help from you to deal with the member. I will deal with him myself.

Mr. Lakkappa, please put the question.

SHRI K. LAKKAPPA: Nearly 400 people in the form of a gang again and again are operating in the same place. (Interruptions).

MR DEPUTY SPEAKER: The more members get up the more time he will be taking.

Mr. Lakkappa, please come to the question.

SHRI K. LAKKAPPA: Such gangs are operating in collusion with these officers who are knowing Hindi and they are purposefully attacking and bringing a had name to the Railway Ministry. Therefore, I would like to know—because there is an impression already carried in the impression country specially in the Southern States that the passengers travelling in there trains have no safety-whether such a conspiracy is there? The same gangs gangs What operating several times. machinery has been engineered to atop all this.

MR. DEPUTY SPEAKER: You keep on repeating.

SHRI K. LAKKAPPA: I have not repeated. You can take action, if even a word has been repeated.

MR. DEPUTY SPEAKER: I willshow you. You will yourself know this tomorrow when you go through all this.

PROF. MADHU DANDAVATE: Let me first totally refute the charge that either in the past or at present there is any civil war between the Home Department and the Railway Department. I completely refute that. Then again there is no conspiracy on the basis of language at all.
Robbers and dacoits have a language of their own, and that is the language of dacoity and language of robbery...... (Interruptions) I do not want to inject the language issue into the question of dacoity and robbery at all. I had already given a statement of robberies and dacoities statewise that have taken place and you cannot expect any one particular language group to be responsible for dacoities throughout country, and therefore, I refute that charge altogether. I do not want either the Southern States or the Northern States to be alleged that they are responsible for any type of coaspiracy.

But there are certain vulnerable areas where the law and order situation is bad. He made reference to one particular portion of Madhya Pradesh. There we have enforced our machinery and I tell the House very firmly that after the enforcement of that machinery, after 11th of August particularly, in that particular area of Madhya Pradesh, not a single dacoity and robbery has been successful.

भी दुर्गाचन्यः जो स्टेटमेंट टैबल पर रखी है उससे यह मालूम होता है कि 1-1-77 है 30-6-78 तक यानी डेंड साल की भवधि में सारे देश में 184 रावरीज भीर 76 डकैतियां पड़ी हैं भीर राबरीज में 3,59,000 **घीर वर्क**तियों में 5,88,000 के करीब की लूट हुई है। विहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बैस्ट बंगाल में राबरीज और डकैतियां बहुत पड़ीं हैं । स्टेटमेंट से मालून होता है कि सर्दर्ग रेलने हारा जो कदम उठाए गए हैं ने तसल्लीनका हैं भीर काइम्ज को रोकने में मदद मिली है भापने यह कहा है:

"The Railway Protection Force constituted under the RPF Act has preventive and detective powers only in respect of lawful possession of railway property. The RPF is concerned with the protection of goods entrusted to the Railways for carriage and Railway materials".

इतनी ही इयुटी है कि वह रेलवे प्रापर्टी को प्रोटैक्ट करे ग्रीर इक्वियमेंट को प्रोटैक्ट करे। पैसेंजर्ज की प्रापर्टी और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझवा हूं कि रेल मंत्रालय को इस घोर भी ध्यान देना चाहिए जिस की जिम्मेदारी पैसैंजर्च की लाइक बीर प्रापटीं की रक्षा करना हो और राज्य सरकारों से भी श्रक्तिक तालमेल की अवरत है। मैं आनना बाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा करने जा रही है?

मो॰ मध् बंडवते : पहले भी दी बार मैं बता चुका हूं कि मार पी एक की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है । शेकिन हम लोगों का प्रनूपन यह रहा है कि हमेशा धार पी एफ के नोगों को जब हमे नीचिज में रखते हैं और जी बार पी की पावर्ज हैं उसकी तरफ आप न जाएं। लेकित

The very existence of RPF acts as a

बकैतियां भीर रावरीज पर मंकुक लगाने में नदद मिलती हैं। लेकिन मैं बताना बाहता हं कि रेलबेज के भन्दर चेंज भसारम होती हैं, दूसरी इक्विपमेंट होती है उनकी रक्षा करने के लिए भी वे कीचित्र के सन्दर रह सकते है उनकी भीर जी भार पी का कौभीविनेशन घण्छा चल रहा है। पूरे डिटैस्ज में नहीं देता हूं। लेकिन जितनी इस साल भीर पिछले साल चौरियां हुई, उन मैं प्रापर्टी का किलना भाग रिकरव हुआ वह मैं भापको बता देना चाहता हूं। इस साक्ष जितनी प्रापर्टी बोरी हुए उसका बीस परसेंट रिकवर हुआ है जबकि पिछले साल दस परसेंट हुआ बा। लेकिन हमें संतोष नहीं है । हम और भी तरककी करना चाहतें हैं। शेकिन वस परसेंट से तरकी बीस परसेंट तक हुई है।

SHRI T. A. PAI: Sir, for the last 30 years we never had a situation like this that law and order is given a go-bye and the railway passengers have become victims of robbery and dacoity. It has always been the explanation of the Railway Minister that this is a problem for which the State Governments are responsible. Now, is it the fault of the passenger who travels long distance that the train has to go through so many States and in every State he has to look to the State Govern-ment to look after him, or is it the primary responsibility of the Railways who have undertaken to give him this lowney, to protect his interests? The journey, to protect his interests? The Railway Minister has said that the State Governments have agreed to cooperate and prevent such occurrence. But we do not know how far that would be effective. Even if he is able to get all the assistance from the State Governments, will he give an undertaking to the country that the Railway Ministry itself will be responsible if there are losses, and the lives and the property is the responsibility of the Railways? And this is a question which cannot be avoided. Otherwise, I think this explanation will not satisfy anybody and travelling by railways is going to be more and more hazardous.

PROF. MADHU DANDAVATE: The hon. Member himself was fortunately a Railway Minister. I have got with me all the statistics. He has raised very refevant questions. Ido not want to attribute any motive to him. He has raised the question: Will the Railways shrik the responsibility and let the entire matter of safety of passengers be left only to the State machinery? I want to assure him that though there are certain jurisdictional problems, sitting together we have already been able to tackle them and without raising this technical issue the recent coordination that we have brought about is albe to ensure better safety.

In addition to what I stated earlier, I want to state that in addition to joint patrolling by RPF and GRP men especially in the vulnerable sections where more robberies are taking place, we have taken some additional care. Sometimes when the dacoits commit an act of dacoity and try to run away, the passengers do not know and probably other staff members do not know whether the train has stopped because there is no signal or there is some mischief. When therefore, there is a pulling of the chain, we have set up a certain code whistle by he engine driver. As soon as that is given, all the policemen, GRP men and RPF men on the train divide themselves into two batches, one will go to the left of the train and the other will go to the right of the train and if it is evening or night, we have made special arrangements and put powerful lights on both sides of the train. Wherever vestibule trains are there, at ro O'Clock in the might the vestibule doors will be kept closed. Only between two coaches the vestibule door will be open because it has to be protected by RPF and GRP men. For two coaches we have set up this machinery and I can assure he hon. Member that especially after the tightening of this machinery incidence of crime, robbery and dacoity has gone down and therefore, as demanded by the hon. Member, I can assure this House that we shall not shirk the responsibility, but we will undertake the responsibility that has devolved on us.

K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I charge the Minister for deliberately misleading the House. On 16th August at 2 O'Clock in the night between Nagpur and Bhopal there was a robbery in the Andhra Express. I was also present there at that time. There is a report in Bhopal. Whatever he said This happened is absolutely wrong. in the air-conditioned chair car. Two brief cases were snatched away and the train was stopped and the robbers went away. The people went to the constable who was sitting in the compartment throughout the night. In spite of the complaint the constable did not taken any action. In the morning at 07.30 hrs. all the passengers forced the train to ston at Bhopal for nearly two hours and have a complaint to the police. Unfortunately all your arrangements are not effective. You must think of some more stringent methods which will infuse confidence into the people who travel by train. I request the Minister not to miselead the House, but to take more effective steps and see that nothing happens.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is never my intention to mislead the House. I have concretised the various steps that are taken and they are working well. If you have listened to my reply very carefully, I did not say that after 11th August, not asingle effort was made by the decoits and robbers. All that I have said is that they made efforts after 11th of August, but they did not succeed.

(Interruptions)

SHRI A. BALA PAJANOR: I am forced to believe from what the hon. Minister said that nothing has happened for the last 15 days. He wanted that to be on record. But he should not say that. He must admit it.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have never tried to mislead this House. I want to make it clear that I used the words......(Interruptions) Please listen to me. There are three types of things that are happening in the trains, there are sometimes thefts, there are robberies and there are dacoities. Please check up

the records. Sir, you may also check up the records. I did not say that thefu have not taken place in trains. You can check up the records. The hon. Members may laugh. But in my written statement, I had drawn a distinction between minor thefts, robberies and dacoities, where people openly come and indulge in such activities. The particular instance, to which the hon. Member has made a reference, is a theft. You can yourself check the records. In my tabulation also, I have divided the crimes into thefts, robberies and dacoities and I have given separate charts for them. Therefore, minor thefts are taking place and I have never said that there are no thefts. But there are no armed robberies and dacoities in which gangs are coming and successfully doing such things. That is what I have said and I stand by that. As far as this particular theft is concerned, I will try to enquire into the matter and give the details.

### Salaries and perquisites of Chairmen and Managing Directors of Union Carbide and other Companies

•492. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government have by now taken a decision to alash appropriately the fantastic salaries, allowances, perquisites drawn by the Chairmen/Managing Directors, Executive Directors and other top executives in public limited Companies like Union Carbide and others:
- (b) if so, what and if not, the reasons therefor; and
- (c) the difficulties which lie in the way of Government in taking necessary action to cut down the very high salaries etc. which have a direct bearing on the prices of consumer articles manufactured by such Companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) to (c). The question of the revision of the existing guidelines relating to the remuneration payable to Managing Directors/Whole-time Directors/Managers of Public Limited Companies and Private Companies which are subsidiaries of Public Limited Companies is still under consideration of the Government. It is not possible to give further details.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: In our country, the salary of the first citizen of this country, the President of India is

Rs. 10,000 a month, the salary of the Chief Justice of India is Rs. 5,000 a mouth and the salary of the Prime Minister, if I am right, is about Rs. 3,000 a month.

Now, this is the information that I have in hand. In Batas, the Managing Directors' Annual remuneration is Rs. 2,70,650, for the Products Research & Development Manager Rs. 2,04,162. These are the figures per annum. It comes to roughly Rs. 20,000 a month. In Colgate Palmolive (India) Private Limited, the Managing Director gets Rs. 2,12,424, the Director (manufacturing)—Rs. 2,16,900 and in Cadbury (India) Limited the Managing Director gets Rs. 2,10,460; in Glaxo Laboratories, the Managing Director gets Rs. 2,12,0,460; in Glaxo Laboratories, the Managing Director gets Rs. 2,18,521. I have got one or two more examples.

I gather that there is a ceiling of Rs. 7,500 on the basic salary. How is it that in the case of Cadbury (India) Limited, Mr. D.W.McPhie has been given a salary of Rs. 7,700, which exceeds Rs. 7,500 and how is it that in the case of Colgate Palmolives, Mr. H. Rai, an Indian national is given a salary of Rs. 10,000 a month and a total remuneration which exceeds Rs. 2,12,000? In this context, I would like to ask the hon. Minister to give us the break-up of these high salaries that have been paid to the Executives of the different multinational companies and big business houses of India. What is the maximum percentage on profit that you allow as commission to executives of companies?

SHRI SATISH AGRAWAL: So far as the break-up of the remuneration that is permissible under the Company Law is concerned, I may inform the hon. House that for salaries, the maximum limit is Rs. 7,500 per month, which comes to 90,000 per annum.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: How is it that Mr. McPhie is getting more?

SHRI SATISH AGRAWAL: I will come to that later. I am just submitting what is provided under the law. Under the law, there are four items. One is Salaries, the maximum limit of which is Rs. 7,500 per month, which comes to Rs. 90,000 per annum. Then comes, the Commission on profits at the rate of one per cent subject to a maximum of 50 per cent of the salary, i.e., Rs. 45,000 per annum; then, perquisities limited to one-third of salary i.e., house rent, car telephone and club subscription, the maximum ceiling being Rs. 30,000 per annum and that makes a total of Rs. 1,65,000. The fourth category is approximate value of benefits not included

in the third category above, viz., perquisites, i.e., Provident Fund contribution upto ten per cent of the salary, Rs. 9,000 per annum; contribution to pension/ superannuation fund upto 15 per cent of the salary, Rs. 13,500 per annum leave travel concession approximately equivalent to one month's salary Rs. 7,500 per annum medical facility Rs. 5,000 per annum; Gratuity at the rate of halfmonth's salary Rs. 3,750 per annum plus reimbursement of actual entertainment expenditure Rs. 6,000 per annum, that makes a total Rs. 44,750 per annum under this head. The total of these four heads come "to Rs. 2,09,750 per annum. These are the outside maximum celling limits prescribed under the law.

So far as the specific instances are concerned, for the expatriates there is a different limit.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mr. Rai is an Indian national,

SHRI SATISH AGRAWAL: I do not know about Mr. Rai. You know more than I do about persons. You have been in Parliament for twenty years and I have not been here. So, I do not know about individuals. But I will look into the matter. But these are the maximum limits that have been prescribed under the law. So far as some large houses, about which you were enquiring, are concerned, I may give the details of the position that exists in some of the large houses. For example, in Godrej Soaps Limited, Dr. B.P. Godrej gets a salary of Rs. 7,500 per month plus a commission of Rs. 45,000 per annum. Similarly, in Guest Keen Williams Limited, Shri Sukhenduaray gets Rs. 7,500 plus Rs. 45,000 commission; in J.K. Chemicals Limited, Mr. V. Singhania gets Rs. 6,000 per month as salary, in Tata Iron & Steel Company Limited, Mr. R. H. Mody gets Rs. 7,500 as a salary plus Rs. 45,0000 as commission; in Greaves Cotton & Co. Mr. Mathrani gets Rs. 7,500 per month as a salary and Rs. 45,000 as commission, in Hoechst Pharmaceuticals Limited, Shri R. Bink gets Rs. 10,000 per month as salary, in this case he may be a repatriate in Dunlop India Limited, Mr. M.W.L. Logan, Whole time Director gets Rs. 7,500 per month as salary and half percent of the profit as commission sub-ject to a maximum of Rs. 30,000 per annum. Of course, in the case of repatriates, the limits are somewhat different. They are decided on the basis of technical knowhow, their requirements, and the administrative ministry makes a recommendation to the Company Law Board and then they give their approval. It may be a different thing. (Interruptions)

MPs are not appointed by the Company Law Board, but they are elected by the people at large. Mr. Patwari cannot be appointed as a whole time director of a company buy the Company Law Board, but he can be elected as a Member of Parliament by the people.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Mr. Agrawal has not replied to my question as to how Mr. H. Rai why is not an expatriate—who is very much an Indian national—of Colgate Palmolives get a salary and remuneration of Rs. 2,12,424 (Interruptions) which exceeds Rs. 2,10,000; How is it being allowed? Mr. Baldik of Batas, who is only a Commerce graduate and who is not a technograt gets Rs. 2,70,650. Last year, he has got Rs. 3,10,000. I would like to know how these were allowed and how these are being allowed now. My second question is, he has stated in his reply—this shows the lack of political will on the part of the Government, as it was the case with the previous Government.—

"The question of the revision of the existing guidelines relating to the remuneration payable to Managing Directors/Whole-time directors/Managers of Public Limited Companies and Private Companies which are subsidiaries of Public Limited Companies is still under consideration of the Government. It is not possible to give further details."

I would like to ask a specific question here. Since what date this is lying with the Cabinet and why is it that it has been delayed to this extent?

SHRI SATISH AGRAWAL: The decision with regard to the fixation of ceiling for managerial remuneration is pending with the Cabinet. In the month of October'77, Government appointed a study group under the chairmanship of Shri Bhoothalingam and this committee submitted its report somewhere in May, 78. This is being studied. The report of the Sachar Commission is also to be received by the Government. In the light of these two reports the Government is to take a final decision. When the final decision is taken, these things will be considered.

श्री राज विजास वासवान : उपाध्यक्ष सहीवव, एक तरफ इस देश में जोगों की सलाना धामवती 250 द० भी नहीं है। जोग धानवर की तरह जीवन व्यवित्त करते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट कम्मियों के प्रविकारियों की ढाई जाब द० खालाना दिया जाता है। क्या सरकार जिब्बा में इस बात पर विचार करेगी कि इस देश में किसी भी कर्मचारी का, चाहे वह सरकारी कमंबारी हो गैर-सरकारी कर्मचारी हो गैर-सरकारी कमंबारी हो, किसी का बेतन 500 द० से कम नहीं होगा और 2,000 द० ...

247

श्री एष० एस० पटवारी: किसी का वैसन एम० पी० से ज्यादा न ही।

भी राम विकास पासवाल : मैं पूछना वाहता हूं कि किसी की सरकारी वा नैर-सरकारी कर्मवारी की जो तमाम तरह की मुजिधार्य और नेतन हैं उन सब को सिला कर 500 दं से कम नहीं होना वाहिए और 2,000 दं से काधिक न हो क्या इस पर सरकार विवार करेगी?

भी सलीस अध्याल : जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि 500 कि से कम किसी का बेतन, अला और अस्य सुविधायें नहीं होनी चाहिएं और 2,000 कि से धीक किसी को नहीं प्रिकाश चाहिए, स्पूनतम और अधिक किसी को नहीं प्रिकाश चाहिए, स्पूनतम और अधिक किसी को स्थापक करने के सम्बन्ध में जो उन्होंने प्रश्न किया है, स्थापकार कर से सम्बन्ध में जो उन्होंने प्रश्न किया है, स्थापकार कर से सम्बन्ध में अपनी तक सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है। इस सम्बन्ध में सरकार के सामने साथ प्रश्न विचारकीय के सामने साथ प्रश्न किया किया को प्रशास को स्थाप कार की सम्बन्ध में स्थापन की सम्बन्ध में स्थापन की सम्बन्ध में स्थापन की स्थापन की सम्बन्ध में स्थापन की स

SHRI SAUGATA ROY: I do not agree with the Minister when he refers to the Bhoothalingam Committee report which has been totally rejected. (interruptions). In a large number of Indian companies also, salaries beyond Rs. 10,000 per month are being given. The Minister has not replied to Part (c) of the question of Shri Jyotimmoy Boau as to what are the difficulties being faced by the Government in the question of reducing the salaries, whether the difficulties are that in principle, the Government is opposed to the reduction of the large salaries in private sector undertakings or whether there are other positive legal hurdles in the way of reducing the salaries in the top private sector undertakings.

SHRI SATISH AGRAWAL: There are no legal hurdles in the way of the Government so far as the reduction in the remuneration is concerned. So far as the question of principle is concerned, the Government is not opposed to the idea of limiting or putting a ceiling on the remuneration of the whole-time Directors, Managing Directors and business executives. As I said earlier, the Sachar Committee report is to be received by the Government and one of the terms of reference is this. After studying the report, Government will take a decision very soon in the matter.

बोबरी बनबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोबय, यह रिपोर्ट की स्टबी करने का क्या सवाल है ? सीबा सा सवाल है कि बाप ऊंची से ऊंची कोई लिमिट मूकरैर करने की तैयार हैं कि कितनी धामवनी ज्यादा से ज्यादा किसी आदमी को सालाना मिल सके ? यह रिपोर्टस तो जनती जायेंगी, मूचाँकनम क्लेटी के प्रलाश कोई घौर कमेडी बैठ खाएकी यह कांग्रेस का साथा घाए पर कितनी देर रहेका? बाप कितनी देर लगायेंगे, जल्य से क्ल्ब इसके खिए वस्त मुकरेर करें। घाप यह घी मुकरेर करें कि ज्यादा से क्यादा तनक्वाह यह होगी, इससे कवद नहीं होगी?

भी सतीस सप्तवास : कम्पनियों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में निर्णय करते का बहुत बीध सरकार का विचार है, इसमें किसी प्रकार का विकास करने का सरकार का विचार नहीं है धीर जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में निर्णय निया बाएगा ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिजेविक (एव्टीबायोटिक) श्रीवश्चियों की कमी

\* 49 1. डा॰ महाबीचक तिह सावच : क्या वेड्री-लियम रसावन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या बाजार में प्रतिजैविक ग्रीवधियों की बहुत कमी है; ग्रीट
- (क) यदि हो दो सरकार द्वारा क्या उपचारा-त्मक कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलिसम तथा रसायन और उर्वरक नंती (की हेनसर्ती नम्बन बहुनुका): (क) घीर (ब). चिन एन्टीवायोटिस्स फार्मुलेसनों से बारे में येश के विधिक्त सामों के कारी भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वे स्ट्रेटोबाइस्टीक् इनजेस्त्रन और स्ट्रेटो पेंतिसिन इन्येस्त्रन हैं। बरूक पेंतिसिन का पर्याप्त उत्पादन होता है लेकिन अन्तर्रास्ट्रीय बाजार में प्रपर्याप्त उपलब्धता के कारण प्राथानित स्ट्रेटोबाइसीन सरकेट के वेर के पहुंचने के परिलाम स्वयप उपरोक्त कार्मुलेसनों भी कुछ करी हो गई थी।

स्टेट कैमिकस्स एण्ड फार्मास्यूटिकस्य कारपोरेखन धाफ इंडिया लि॰ ने इन फार्मुलेखनों के उत्पादन के लिए विनिन्न बायलरों को मन बच्छ स्ट्रैप्टोनाइसीन सल्केट की पर्याप्ट नाला की सप्लाई कर दी है। ग्रम्म-भून, 1978 के दीरान हिन्दुस्ता एडीवावी-टिन्स लि॰ मीर इंडियन इन्ड एण्ड फार्मास्यूटिकस्य लि॰ में स्ट्रैप्टोनाइसीन का उत्पादन गत दो बचों की मुलना में घालिक रुप से मिक्क रहा है।

### Earnings from passengers and goods Transportation

\*494. SHRI DHARMAVIR VASISHT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether earnings in the first quarter of the current year from passengers and goods on Railways suffered as compared to the same period last year;
- (b) if so, the details of the same monthwise with reasons;

- (c) whether werking expenses in the same period increased; if so, to what extent: and
- (d) whether Government still hope for a sizeable surplus this year, and the reasons therefor?

## THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) and (b). As compared to the period ending June 1977, there has been an increase of Rs. 12-51 crores under passenger earnings and a shortfall of Rs. 14-57 crores under goods earnings during the quarter ending June 1978. Month-wise details of the earnings under passenger and goods traffic is as under:

(Figures in crores)

Month		er nings	Goods Earnings		
***************************************	1977- 78	19 <b>78-</b> 79	1977- <b>7</b> 8	1978- 79	
April .	53.00	56.11	118.85	111.97	
May .	62.07	64 - 77	116.05	112.89	
June .	54 40	61 - 10	109 - 42	104 -86	
Total upto June	169 47	181 -98	344 · 29	329 72	

The Railways' gross carnings during April to June, 1978 amounted to Rs. 544.96 crores, which was Rs. 9 lakls more than the earnings of the corresponding quarter of the last year (Rs. 544.87 crores).

Shortfall under goods earnings has been as a result of a drop in tonnage lifted to the extent of 5.28 million tonnes compared to the budget target for the quarter ending June 1978 and 3.11 million tonnes as compared to the corresponding period of last year.

The various sectors affected include collieries, washeries, steel plants, ore mines and ports. The drop in loading in these sectors was largely due to shortfall in production and other factors.

- (c) During the period ending June, '78 there has been an increase of Rs. 29.68 crores under working expenses as compared to the period ending June, 1977.
- (d) It is too early to make a forecast as to whether a sizeable surplus will be achieved by the end of the year. Efforts

are continuing to overcome the operational difficulties in respect of goods traffic and if the lost ground in respect of goods traffic can be regained during the remaining months of the year, our expectations regarding achieving a surplus during the year will be fulfilled.

## Cases of lecting of passengers in fouth bound trains

\*495. SHRIN. SREEKANTAN NAIR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) how many cases of looting of railway passengers have been reported this calender year in the Sotuth bound trains leaving New Delhi/Nizamuddin/Delhi Stations.
- (b) what steps have been taken to prevent the mounting looting of railway passengers;
- (c) whether the victims of looting had been given compensation by the Railways, if not, whether the Railway will seriously consider such a proposal while intensifying security measures at least in longdistance trains; and
- (d) whether the newly introduced alarm system is a success?

## THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

- (a) During this calendar year, so far, there have been four cases of looting of railway passengers in the South bound trains leeving Now Delhi/Nizamuddin/Delhi Stations.
- (b) The responsibility of ensuring the personal safety of the passengers and the security of their belongings rests with the Government Railway Police which functions under the administrative and disciplinary control of the State Governments. Crime prevention and detection in respect of passenger safety and security of their belongings fall under the category of 'law and order' which is a State subject under the Constitution. However, the Railways render necessary assistance whenever required and close liaison is maintained at all levels with the State Police Agencies. The Railway Protection Force constituted under the RPF Act has preventive and detective powers only in respect of unlawful possession of railway property. The R.P.F. is concerned with the protection of goods entrusted to the Railways for carriage and Railway materials.

On 16-6-1978 a high level meeting between the officers of the Ministries of Railways and Home Affairs was

held. The following firm decisions were taken which have yielded very enheld. couraging results:

- (1) As the dacoits/robbers were silencing the passengers by show of fire arms and escaping after commission of crime generally by pulling alarm chain under cover of darkness a prompt channel of communication to the armed police guard whenever alarm chain was pulled at night was considered necessary. It was decided that the alarm chain whistle should be sounded repeatedly by the driver. On hearing of this alarm the armed police escort should split themselves in two parts and de-train to apprehend escaping criminals.
- (2) The Police escort should be accommodated together as far as possible in the centre of the train and they should be equipped with powerful torches.
- (3) The police escort party may progressively be equipped with very light pistols which would be useful in lighting up the area on both sides of the train at night.
- (4) The Guard and Brakesmen should be provided with powerful torch lights in vulnerable trains over affected sections.
- (5) There should be liaison with the States principally affected for stepping up police protection. Chief Security Officers of Eastern, South Chief Eastern, Northern and Central Railways were specifically nominated to maintain close liaison with the State Police authorities of West Bengal, Bihar, U.P., Madhya Pradesh and Maharashtra. The CSOs of other Railways were directed to maintain liaison with above 4 Chief Security Officers. They were directed to indicate to the State Governments the strength of police guard which should be required on vulnerable trains and request the State Police authorities to provide the necessary protection. The requirements of State Governments have been projected to Ministry of Home Affairs.

The Zonal Railways have launched a drive to ensure strict adherence to the following preventive measures in coaches.

- (i) Vestibuled doors are kept locked between 22.00 hrs. and 06.00 hrs. by the Travelling Ticket Examiners/ Coach Attendants.
- (ii) Travelling Ticket Examiners and Coach Attendants remain vigilant

during night time and prevent entry of intruders, hawkers and unauthorised persons into the coaches,

(iii) In case of non-vestibuled trains, the vestibuled doors are permanently closed or dummied.

The above measures formulated are in continuation of the various preventive continuation of the various preventives steps taken by the Government Railway Police under the State Governments. The G.R.P. being alive to the problem adopt several regular preventive measures which are given below:

- (1) Escorting of important trains at night by armed aguards of Government Railway Police of the concerned State Government.
- (2) Beat patrolling at stations; platforms/ waiting halls.
- (3) Surveillance over criminals and known bad characters.
- (4) Checking of night trains by Supervisory Officers.
- (5) Armed pickets at vulnerable stations.
- (6) Special Squads of the C.I.D. of the State Govts, take up investigation of important cases to apprehend the gangs responsible for crimes.

These measures have been intensified b/ the Government Railway Police.

As a further measure to deal with occurrences of train robberies and da-coities, the Minister of Railways ordered deployment of armed RPF to escort the affected trains running in vulnerable sections. Primarily, they will protect railway property and will also help to instil confidence amongst the travelling public and deter criminals from operating on trains. Over 1400 armed RPF men were put on escort duty on different Railways from the first week of July, 1978. Since 16th August over 2000 R.P.F. personnel have been deployed in escorting trains. Being concerned with the spate of heinous crimes in Madhya Pradesh area, Minister of Railways had written to the Chief Minister of Madhya Pradesh requesting him to take special measures to curb crimes in running trains. He had also spoken to him on phone on August 13, 1978. In the affected Divi-sions viz. Jhansi and Nagpur, 220 RFP personnel are escorting 20 trains of which 16 are long distance trains and 4 short distance trains. 30 GRP personnel are escorting 9 long distance trains. The

- 29
  - South-bound trains excerted are (1) G.T. Express, (2) Dalahin Express, (3) Jayanti Janata Express, (4) Jammu Tawi Express, (5) Tamil Nadu Express, (6) Andhra Pradesh and (7) K.K. Express.
  - (c) Crimes like robberies, including those committed on trains, is a law and order problem which is a State subject. Under extant rules, no compensation is admissible to the victims of such crimes.
  - (d) Yes, Sir. On 15-8-1978 while RPF was escorting 131 Down Jayanti Janata Express, its alarm chain was pulled near outer signal of Bhopal. The RPF escort on hearing the code whistle got down and apprehended one person who pulled the chain. He was handed over to G.R.P., Bhopal, for prosecution.

### , Concession in Railway Freight Charges

- \*496. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state:
  - (a) whether it is a fact that in order to promote country's export trade Government have agreed in principle to help by way of giving concession in railway freight charges;
  - (b) if so, whether Government will introduce this scheme in respect of all exportable commodities; and
  - (c) if not, the names of the commodities in respect of which this concession will be given?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):
(a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

#### Dacolty in Aligarh-Chaudausi Local Train

\*497. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether on 1st July, 1978 Aligarh and Chandausi local train was stopped and more than a dozen armed dacoits entered the train and looted it;
- (b) have the criminals been traced and arrested; and
- (c) steps to prevent such high rise of crimes on Railways?

THE MINISTER OF RAILWAY (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) There was no dacoity on 1-7-78 in Aligarh-Chandausi local tr4in. But there

- was a dacoity in 355 UP Passenger train (Aligarh-Barcally) on sy-6-78/s6-6-78 (night). When the train started from Bhojot station 5 to 6 persons who were already atting in the compartment threatened Sh. Ajay Bahadur Johri and his friends with country pistol and looted property worth Rs. 700 (Approx.), Government Railway Police, Chandausi registered crime No. 81 dated 4-7-78 under section 395 IPG (Dacoity). The case is pending investigation.
- (b) So far, there has been no recovery of property nor has any arrest been made.
- (c) The responsibility of ensuring the personal safety of the peasengers and the security of their belongings rests with the Government Railway Police which functions under the administrative and disciplinary control of the State Governments. Crime prevention and detection in respect of passenger safety and security of their belongings fall under the category of 'law and order' which is a State subject under the Constitution. However, the Railways reader necessary assistance whenever required and close liaison is maintained at all levels with the State Police Agencies. The Railway Protection Force constituted under the RPF Act has preventive and detective powers only in respect of unlawful possession of railway property. The RPF is concerned with the protection of goods entrusted to the railways for carriage and railway property, materials and stores.

Being concerned over crimes on Railways, Minister of Railways had drawn attention of Chief Minister of Uttar Pradesh through Demi Official letters. On 5-8-78 there was a high level meeting between Minister of Railways and Chief Minister of U.P. in which problems of crime were highlighted.

On 16-6-1978 a high level meeting between the officers of the Ministries of Railways and Home Affairs was held. The following firm decisions were taken which have yielded very encouraging results:

(1) As the dacoits/robbers were silencing the passengers by show of fire arms and escaping after commission of crime generally by pulling alarm chain under cover of darkness a prompt channel of communication to the armed police guard whenever alarm chain was pulled at night was considered necessary. It was decided that the alarm chain whistle should be sounded repeatedly by the driver. On hearing of this alarm the armed police escort should split themselves

in two parts and de-train to appre-

- (a) The police escort should be accommodated together as far as possible in the centre of the train and they should be equipped with powerful torches.
- (3) The police escort party may progressively be equipped with very light pistols which would be useful in lighting up the area on both sides of the train at night.
- (4) The Guards and Brakesmen should be provided with powerful torch lights in vulnerable trains over affected acctions.
- (5) There should be liaison with the States principally affected for stepping up police protection. Chief Security Officers of Eastern, South Eastern, Northern and Central Railways were specifically nominated to maintain close liaison with the State Police authorities of West Bengal, Bihar, U.P., Madhya Pradesh and Maharashtra. The CSOs of other Railways were directed to maintain liaison with above 4 Chief Security Officers. They were directed to indicate to the State Governments the strength of police guard which should be required on vulnerable trains and request the State Police authorities to provide the necessary protection.

The Zonal Railways have launched a drive to ensure strict adherence to the following preventive measures in coaches:—

- Vestibuled doors are kept locked between 22.00 hrs. and 06.00 hrs. by the Travelling Ticket Examiners/ Coach Attendants.
- (ii) Travelling Ticket Examiners and Coach Attendents remain vigilant during night time and prevent entry of intruders, hawkers and unauthorised persons into the coaches.
- (iii) In case of non-vestibuled trains, the vestibuled doors are permanently closed or dummicd.

The above measures formulated are in continuation of the various preventive steps taken by the Government Railway Police under the State Governments. The G.R.P. being alive to the problem adopt several regular preventive measures which are given below:

 Escorting of important trains at night by armed guards of Government Railway Police of the concerned State Government.

- (e) Beat patrolling at stations; platforms/
- (3) Surveillance over criminals and known bad characters,
- (4) Checking of night trains by Supervisory Officers.
- (5) Armed pickets at vulnerable stations.
- (6) Special Squads of the C.I.D. of the State Governments take up investigation of important cases to apprehend the ganga responsible for these crimes.

These measures have been intensified by the Government Railway Police.

As a further measure to deal with occuprences of train robberies and dacoities, the Minister of Railways ordered deployment of armed RPF to escort the affected trains running in vulnerable section. Primarily, they will protect railway property and will also help to instil confidence amongst the travelling public and deter criminals from operating on trains. Over 1400 armed RPF men were put on escort duty on different Railways from the first week of July, 1978. Since 16th August 1978 over 2000 RPF personnel have been deployed in escorting trains.

The following trains are escorted in Aligarh-Chandausi section jointly by Railway Protection Force/Govt. Railway Police:—

#### Ъ. Escort RPF G 3 AB Passenger Barcilly 1-3 Ar n:cd train Bareilly to Aligarh Aligarh both ways. 2 ACM Ali-Aligarh- 1-3 Armed 2 garh-Chandausi Moradabad Moradabad-Passenger. both ways. 356 Dn. Bareilly-Aligarh. Both ways 1-3 Armed 2 355 UP Aligarh-Bareilly

In all 87 passenger trains are being escorted by Railway Protection Force, 206 by GRP, of which 60 trains are jointly escorted by RPF and GRP in U.P.

In these duties 630 RPF and 328 GRP men have been deployed in Uttar Pradesh.

### Union Office Bearers Transferred from Delhi to Jedhpur Division

- \*498. SHRI CHANDRADEO PRA-SAD VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that some office bearers of recognised Railway Union of Delhi Division were transferred from Delhi Division to Jodhpur Division in April, 1978
- (b) whether some departmental enquiry proceedings were instituted against them during emergency for some previous claim cases;
- (c) whether all other employees, against whom same or similar proceedings have been instituted, have also been transferred; if not, the reasons thereof;
- (d) whether there are policy orders to the effect that office bearers of recognised union cannot be transferred without the consent of the unions, unless it is a case of promotion or a vigilance case is substantiated against such office bearers; if so, whether the trade union officials so transferred to Jodhpur Division come under the above category; and
- (c) whether it is also a fact that thirteen Members of Parliament had made the representation in MayJune, 1978 against the above mentioned transfers; if so, whether the transfers are being cancelled or pended as a result thereof?
- THE MINISTER OF (RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) A Chief Parcel Clerk at New Delhi Station, who is also the Vice President of the Uttar Railway Mazdoor Union, New Delhi Branch, was relieved on transfer to Jodhpur Division on ,30-4-1978.
- (b) Proceedings under the Railway Servants Discipline & Appeal Rules 1969 for imposition of a major penalty were initiated against him in September 1976.
- (c) No, Sir. Orders transferring the Chief Parcel Clerk were issued for administrative reasons.
- (d) The extent policy orders to provide that the office bearers of recognised unions should not be transferred without the concurrence of the unions. However, the General Managers of the Zonal Railways have special powers to order transfers even without such concurrence, after giving them an opportunity to have their say.
- (c) Yes, Sir. Representations have been received from Members of Parliament against the transfer. The case is under consideration.

### Delay in Laying Pipelines system from Salaya to Viramgam and Koyali Refinery

- \*499. Shri D. N. TIWARY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) whether there has been considerable delay in laying the pipeline system from Salaya to Viramgam and from Viramgam to Koyali refinery;
- (b) when the tender was called for and when it was finalised;
- (c) the reasons for the delay in the execution of this project; and
- (d) losses incurred due to non-laying of this pipeline?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (d). Separate tenders, one for the construction of the Viramgam. Koyali pipeline, and another for the Salaya-Viramgam pipeline were called by Indian Oil Corporation in December, 1975 and March, 1976 and July, 1976 respectively. The Viramgam-Koyali section was to be completed by June, 1977 and the Salaya-Viramgam section by October, 1977. The works were, however, actually completed in May, 1978 and June, 1978 and there was thus a delay of 11 months and 8 months respectively beyond the contract dates.

- 2. The pipeline project is designed to feed crude to the Koyali Refinery in the context of its capacity expansion from 4.3 million tonnes per annum to 7.3 million tonnes per annum.
- 3. The delay in the completion of the contracts for laying the pipelines as compared to the completion dates mentioned in the contracts is mainly due to (a) delay in arrival of specialised construction equipments from abroad, (b) non-availability of blasting material, (c) failures occurring in the pipes during hydro-static testing of the Virangam-Koyali pipeline, etc. Particular mention may be made of the numerous failures in the 18" line pipes used in the Virangam-Koyali pipeline which has contributed mainly to the delay in completion. In fact the pressure rating of the pipeline had to be reduced from 93 kg/cm² as originally specified to 80 kg/cm² in order to successfully complete testing of the pipeline. However, the desired throughput of 5 million tonnes per year willstill be achieved.

36

4. The contracts provide for grant of extension of time for completion as well as for levy of liquidated damages for delays caused beyond the extended time of completion

### Disparity in Wage Structures and Allowace of Various Drug and Chemical Underthings.

\*500. SHRI R.K. MHALGI: Will the Minister of PETROLIUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is a great disparity in the wage structure and allowances of the various drug and chemical undertakings controlled by Government:
- (b) whether Government have any proposals to bring them in line with other firms in private sector and maintain a uniformity in the wage structure and allowances at least among the chemical and drug firms contrilled by Government; and
- (c) what are the reasons for this delay in implementing the I.L.O. convention of equal pay for equal work?

THE MINISTER OF PETROLEUM
& CHEMICALS AND FERTILIZERS
(SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) Wage structures and allowances
vary in the units under the control of
Government.

(b) There is no proposal to bring about uniformity with the private sector. As a matter of fact, it cannot be said that there is any degree of uniformity in this regard within the private sector itself.

While approving wage agreements in public sector undertakings, Government take into account among other things, the wage structure prevailing in respect of comparable posts in other similar public sector undertakings, keeping in mind also other relevant factors like regional wage conditions.

(c) The relevant I.L.O. Convention prohibits discrimination in the payment of wages on the ground of sex. It does not provide for the payment of equal wages for the same or similar type of work in different establishment.

### महादेवपुर---विहपुर रेलवे स्टीमर सेवा

\*501. डा0 रामजी लिंह : क्या रैल मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) बरारो-महावेवपुर-विह्नपुर रेलवे स्टीमर सेवा कितने वर्षों तक बलती रही है और यत तीन वर्षों में इतकी बीच बीच में बन्द कर विए जाने के क्या कारण हैं;

- (क) क्या रेल मंत्री के धारवासन के बावजूद इस वर्ष वह रेलवे स्टीजर देवा बन्द कर की वर्षे है:
- (ग) क्या कुछ रेलवे प्रधिकारी तीन वर्तों के प्रयास के प्रकार इस सेवा को जानवृत्रकर मानवृत्र में बन्द करने में सकल हो गए हैं ताकि प्राइवेट धापरेटरों की लाभ हो सकें : बीर
- (थ) उपर्युक्त रेलवे स्टीमर सेवा पुनः कव चालू होगी और क्या इसके प्रगले वर्ष भी बन्द रहने की सम्भावना है?

रेल संकालय में राज्य मंत्री (थी तिव नारावण):

(क) और (ब). याना बिहपुर-महादेवपुर घाट रेलगाड़ी सेवा और महादेवपुरघाट तथा बारीधाट के बीच स्टीमर सेवाएं 19वीं सताब्दी के मतिम दशक से चल स्टीमर सेवाएं 19वीं सताब्दी में मारी बाढ़ के कारण मानसून की प्रविध में सेवाओं में गढ़वड़ों हो गई है। इस वर्ष भी बाद के कारण 20-7-78 से सेवा रष्ट कर देनी पढ़ी थी।

### (ग) जी, नहीं।

(व) जैसे ही नदीय परिस्थितियां धनुकूल होंगी, ये नेवाएं फिर चालू कर दी जायेंगी। अगले वर्षे इन नेवाओं को चालू रखना अथवा इन्हें रह करना इस बात पर निजरे करेगा कि उस समय परिस्थि-नियां कैसी रहती हैं।

### Rail Finances in a Jam

\*502. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state.

- (a) whether attention of the Government has been drawn to the news report appearing in the National Herald dated 23rd July, 1978 under the caption "Rail financesin a jam";
- (b) if so, what is the reaction of the Government to the various observations made therein;
  - (c) the facts of the matter; and
- (d) details regarding the action taken/ proposed to be taken?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):
(a) Yes, Sir.

(b) The news report refers to the drop in the Railways' goods loading and traffic earnings and to certain factors that have added to the working expenses. The report contains some inaccuracies and has drawn exaggerated conclusions.

### (c) The facts are as under:--

### (i) Gross Earnings :---

The Railways' gross carnings during April to June, 1978 amounted to Rs. 551 96 crores, which was Rs. 9 lakks 54: 98 crores, which was as, y same more than the earnings of the corresponding quarter of last year (Rs. 544-87 crores) but were short of the budget proportion for the current year (Rs. 568-46 crores) by Rs. 23-50 crores. While the earnings are more than the budget anticipations in respect of Passenger, Parcels and Miscellaneous, there is a drop in total earnings due entirely to a set-back in Goods traffic.

### (ii) Originating Goods Loading:-

The Revenue goods loading during April to June, 1978, was 49 62 million tonnes as compared to 52.73 million tonnes during the corresponding quarter of last year and the budget proportion of 54'90 million tonnes. The current year's bading, therefore, shows a drop of 3.11 million tonnes as compared to last year and is short of the target by 5.28 million tonnes. The various sectors affected include collieries, washeries, steel plants, ore a mines and ports. The drop in goods loadings in these sectors largely due to shortfall in production and other factors.

### (iii) Warking Expenses :-

The Woring Expenses during the first quarter of the current year amount to Rs. 389:18 crores as against Rs. 359:50 crores in the corresponding period of last year. The expenditure during April to Jung, 1978 is within the budget for the current year.

The allegation that some of the additional expenses to be incurred during the current financial year were deliberately not taken into account at the time of the presentation of the Railway Budget, is not correct. The decisions regarding revision of running allowance, payment to staff as a result of the adjustment of the strike period in May, 1974 with leave due, payment of additional dearness allowance and increase in steel prices, were all post-Railway budget developments, which could not be taken into account while finalising the Railway Budget presented to Par-liament on 21-2-1978. The recommenda-tions of the Railway Workers' Classification Tribunal are also under finalization which will involve additional expenditure.

### (iv) Upgradation|creation of additional posts at the higher level :--

As per the decision of the Government of India on Third Pay Commission's Recommendation, a review of the Class I Cadres/Services has to be made once in three years. The first review of the Railway cadres was made n 1973-74. The second cadre review has now been taken in hand. It is premature to furnish the details of the proposals at this stage.

### (v) Staff Relations :- ?

While it is true that there have been a few agitations in some parts of the railway system, it is an exaggeration to describe "widespread discontent among the staff" as the sole factor responsible for the deterioration in operation. On the other hand, very special attention is being paid to the redressal of staff grievances and to the settlement of various economic demands of the labour. Apart from the announcement regarding the reinstatement and vacation of punishments of all those who have been pena-lised after the 1974 strike, several measures have been taken to improve the service conditions of Railway employees. Industrial relations on the Railway are very satisfactory now and conducive to efficient working of the system. Minor 'pin-pricks' here and there in a organisation like the Railways are inevitable and are not a matter of great concern.

(d) The Railways have been given directions to step up traffic earnings, particularly the performance under Goods, and also to pursue vigorously the measures to control working expenses. As a result of strick monitoring of various operations particularly connected with goods loading and regular coordination between Ministries of Railways, Energy, Industry, Steel & Mines, Labour and Finance, overall performance in July 1978 has improved considerably. The originating loading in June 1978 was 23193 (B.G.) and 5191 (M.G.) wagons per day. In July 1978 it increased to 23803 (B.G.) and 5228 (M.G.) wagons per day.

### रेलचे स्टेशनों पर कैटीन भीर बुक स्टाल

- , 503. वी चतुर्गुंज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) रेलवे स्टेशनों पर कितने कैटीनों भीर बुक स्टार्कों के ठेके 31 मार्च, 1977 की समाप्त हो गए हैं:
- (ब) उनमें से कितने ठेके भागामी वर्षों के जिए पिछले ठेकेदारों के नाम दिए गए हैं :

(ग) क्या सरकार ऐसे ठेने देने के मामले में हरिजनों भीर पिछने नगीं के सोगों को विशेष सुविधार्वे भीर प्राथमिकता देगी ; भीर

Written Answers

(भ) यदि हो, तो ऐसी विशेष सुविधाओं का पूरा बंबीरा क्या है ?

रेस मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण) । (布) 亩 (甲)。

### रेलचे स्टनमां पर कैम्टीमां घोर बुक स्टाल

बान-पान और बेडिंग ठेकों के घावंटन के लिए अनुसूचित जातियों भीर अनुसूचित जनजातियों 🕏 व्यक्तियों की तरजीह दी जाती है। मेकिन युक स्टानों के ठेकों के बावंटन में इस प्रकार की काई तरजीह नहीं दी बाती।

गाड़ी के निकट कोमचे लगाने और छोटे-छोटे स्टाल सगाने जैसे छोटे ठेके घव केवल धनुसूचित जातियों भौर धनुसुचित जनजातियों के उम्मीदेवारी को ही भावंटित किये जा रहे हैं। बड़े ठेकों के मामलों में भी धन्य बातें समान होने पर धनुसूचित जाति/प्रमुखित जनजाति के व्यक्तियों को धव प्राथमिक रूप से तरजीह दी जाती है।

31-3-77 को ठेके समाप्त हो जाने वाली केंटीनों भीर बुक स्टालों की संख्या भीर पिछले ठेके-दारों के नाम में दिए गए ठेकों की संख्या से संबंधित सूचना इक्ट्टीकी जारही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## Global Tenders to Import Wheel

- \*504. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that the Railway Board have recently invited global tenders to import wheelsets:
- (b) whether it is also a fact that Durgapur Steel Plant offered to supply such wheelsets; and
- (c) if so, why the global tenders have been invited?

THE MINISTER OF RAILWAYS DANDAVATE) (PROF. MADHU DANDAVATE):
(a) Yes, Sir. The following five Global Tendershave recently been invited:

- (i) GP-79 for 1280 Nos. Wheelsets for the manufacture of Broad Gauge ICF Type Goaches.
- (ii) GP-80 for 3000 Nos. 20-Ton Wheelsets for the manufacture of BOX/ RH/CRT Wagons (BG).

- (iii) GP-84 f or 3200 Nos. 20-Ton Wheelsets for manufacture of BOX/ BRH/CRT Wagons (BG).
- (iv) GP-82 for 264 Nos. Wheelsets for the manufacture of DC EMU Coaches.
- (v) GP-83 for 3340 Nos. 16-Ton Wheelsets for the manufacture of BG Tank Wagons.
- (b) The supplies offered by Durgapur Steel Plant are being accepted by the Railways in full; and
- (c) Global Tenders are invited only in those cases where the supplies made by Durgapur Steel Plant or Tata Iron & Steel Company fall short of the requirements of the Railways for meeting the mainte-nance needs or Coach and Wagon-building Programmes or where the manufacture of certain types of Wheelsets has not been developed by Durgapur Steel Plant and Tata Iron & Steel Company.

### Drilling work near Suthri Village, Kutch

- •505. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) whether drilling platform for oil is ready near Suthri village in Kutch District;
- (b) whether the drilling work is going to start this year;
- (c) whether the work has now been entrusted to ONGC; and
- (d) if so, what is the progress in this regard and when this work will be completed?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) to (d). A location near Suthri was released by the ONGC in September 1973 for exploration of Mesozoic and Tertiary prospects. A foundation on this location for the deployment of rig was also constructed. However, in view of the further geological information obtained by the ONGC in the area, the onland drilling at Suthri has been deferred.

#### in Freight Earnings Decline

- 506. SHRI C. K. JAFFER SHARIFF : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) whether there has been any decline in freight earnings during last six months; and

(b) if so, whether Government have taken steps to meet all outstanding orders for wagoas even for movement of low priority items?

41

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE)
(a) Yes, Sir.

(b) Steps have been taken to meet all cubitanding demands for wagons, including low priority traffic. As a result, the number of outstanding indents has been brought down by 20% on the B. G. and 30% on the M.G. as on 16th August, 1978 as compared to the demands at the end of June, 1978.

#### Longth of Railway Lines in Bihar Adivasi Areas

\*507. SHRI AGHAN SINGH THA-KUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 95 on 21-2-1978 regarding length of railway lines in Bihar Adivasi areas and state:

- (a) whether any decision has since been taken regarding construction of the lines mentioned as surveyed; and if so, the details thereof, and
- (b) if not, the reasons therefor and the time by which a decision will be taken?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). No decision has so far been taken regarding construction of lines mentioned in the reply given to unstarred question No. 95 on 21-2-199B. The limited funds which are made available are not sufficient even to meet the requirement of projects which are already in hand. The decision regarding construction of these lines would, therefore, depend upon the allocation of funds in the coming years.

### रेसबे वर्फशायों से चौरी गई बस्तुवें

\*508. भी जालको जाई : क्या रेल मंत्री यह क्याने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में विभिन्न रेलवे वर्कशायों से सम्बन्धित कर्मवारियों की लापरवाही के कारण प्रति वर्ष लाखों रुपए के माल की चौरी होती है जिससे सरकार को भारो हानि होती है; और
- (ब) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?
- रेल मंद्रासय में राज्य मंत्री (की शिव नारायण) । (क) बापराधिक गतिविधियों के कारण प्रति

वर्ष भीसतन सगभग 2 लाख रुपए मूल्य का रेलीं का सामान रेलवे कारखानों से चोरी चला जाता है।

- (ख) रेलवे कारवानों से रेलों के सामान की बोरी/उठाईपीरी की रोक-बाम के लिए निम्नलिकित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :—
  - (1) अनाधिकृत प्रवेश अववा बिना नेट पास के सामान को बाहर ले जाने को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा कारखानों के द्वार पर नियमित पहरा देना :
  - (2) कारवानों को परिसोना दीवार के बारों भोर रेनवे मुरना दन द्वारा गरन जनाना ;
  - (3) खाली माल डिब्बों तथा सभी वाहनों के साथ-साथ कारखानों से बाहर ग्रामे वाले सभी श्रमिकों की जांच करना ;
  - (4) रेलचे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा सादी पोजाक में अपराध-आमूचना एकत करना तथा सन्देहारुप्रद व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखना:
  - (5) सिविल पुलिस विभाग के साथ निकट सम्पर्क बनाथे रखना ;
  - (6) कारबानों में तैनात रेलवे सुरक्षा वल के कर्मचारी प्रपनी ह्यूटी पर सतक रहते हैं और मली प्रकार प्रपनी ह्यूटी निभाते हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के प्रवेचेकक कर्मचारियों हारा कारबानों में घवानक गम्त लगाया जाता है:
  - (7) कारकानों में मूल्यवान सामग्री तासें में बच्च भीर सील लगाकर रखी जाती है :
  - (8) कारकानों में राजि के समय गक्त लगामें में कुता दल का उपयोग भी किया जाता है;
  - (9) कारकानों में भाषश्यक बुनियादी सुरक्षा प्रबन्ध भी किए जाते हैं।

## Accommodation and other Facilities for Judicial Administration

- \*509. PROF P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether Government are aware that the judicial administration in the whole country has been suffering for want of proper office and court accommodation, basic facilities and amenities for the judicial officers etc. at many places in various States of the Union;
- (b) if so, what concrete and effective steps are being taken by Government to correct and improve the said situation and for how long and at what expenses during the years 1976, 1977, 1978; and

(c) broad outline of the improvements, if any, effected in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## Additional duty to the Managing Directors of Orissa F. C. L.

4739. SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) is it a fact that the Managing Director of Orissa F.C.I. (Talcher) is given additional duty work other than his own duty;
- (b) if so, what is the additional work attached to him and how many days he was absent from Headquarters since last two years upto date; and
- (c) for this additional work what is the additional remuneration/T.A. drawn by him since last two years?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZER (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) There is only one Chairman-cum-Managing Director for the entire Fertilizer Corporation of India, of which Talcher is one of its Divisions. The Talcher Division is headed by a Genral Manager and apart from his regular duties, he wa not assinged any additional work during the last two cars;

(b) and (c) Do not arise.

Issue of New Licences to synthetics and Chemicals Limited, Barellly

4740. SHRI SURENDRA BJKRAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether new licences which have been issued to Synthetics and Chemicals Limited, Bareilly, are still process or implementation; and
- (b) which new projects have been constructed by Synthetics and Chemicals L'imited at what cost and from what sources the finances were arrenged.

THE MINISTER OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). The position as reported by the company is as follows:

Industrial Licence and capacity	Cost and sources of finances for the project	Position of the project	
(i) Nitrile rubber—2000 tonnes per annum.	Project cost Rs. 140-2 lakhs Sources of Finances :	Project has been implemented.	
	(a) ICICI		
	(b) LIC		
	(c) Internal resources of the company.		
(ii) Butadiene Catalyst—	Project cost Rs. 39 41 lakhs.	Project has been implemented.	
60 tonnes per annum.	Entierly financed from internal resources of the company.	imponence.	
(iii) A.B.S.—2000 tonnes per annum	••	Project is under implementation. Industrial licence is valid upto 8-12-1979.	

leave of a Letter of Intent to Colente-Palmelive India Limited

### 4741. SHRI P. K. KODIYAN: SHRI YADVENDRA DUTT:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government have issued a letter of intent to Colgate-Palmolive India Limited to manufacture menthol;
- (b) whether it is a fact that the small units engaged in the industry are capable of meeting the entire domestic demand of mentiol; and
- (c) if so, what are the details and reaons for granting permisson to a multi-national to enter into this field?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA: (a) Yes, Sir.

- (b) The exact demand estimate of menthol has not been made. The present demand of menthol is, however, met by the existing units, both in the organised sector and small-scale sector.
- (c) The project which envisages production of menthol from natural Mentha grass was sanctioned on the strong recommendations of the State Government of J&K as this will promote the agricultural economy of the backward area in the State. An export obligation of 60% of the production of menthol has been imposed to protect the interests of small scale units.

### नकरी लेक्सों से इन्वेक्सनों का बनावा करना

- 4742: भी पुरेला शा तुलल : वया पेट्रोलियल, रतायल भीर फर्बरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कितनी बोगस फर्ये नकली नेवली तथा बोडों में इन्वेबलन तथा प्रपत्तिश्वत प्रोषधियां सप्ताई कर रही थी और उनके विषद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और
- (ख) क्या झौबधियों में अपिममण को रोकने हेलु झोबध निर्माता कर्नों की अवानक बांच करने के लिए कोई योजना शुद करने का सरकार का क्रियार है?

बेद्रोलियम तथा रतायन और उर्वरक मंत्री (थी हैमबती मन्द्रम बहुगुजा): (क) और (ख)-सूचना एक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी आएगी।

- Representations forwarded by Local M.L.As. and Members of Parliament to the Management of F. C. I., Sindri
- 4743. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) what is the number of letters of representations forwarded by the local MI As and M. Ps. received by the Management of the Sindri Unit of the F.C.I. and their dates of receipt;
- (b) whether it is a fact that despite clear Government instruction to acknowledge such letters immediately and to give a final reply within 21 days most of them have remained unattended and unanswered;
- (c) whether it is a fact that the F.C.I. management also adopts discriminatory policy to the C.I.T.U. affiliated F.C. Kamgar Union led by the local MLAs. and the M. Ps.; and
  - (d) if so, reason thereof?]

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) to (d). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

#### Inadequate facilities at Ottappalam Station

4744. SHRI K. KUNHAMBU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether Government are even that facilities at Ottappalam (Kerala) Railway station are inadequate; and
- (b) if so, what are the steps taken to improve the facilities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) The facilities provided at Ottappalam Railway station are considered adequate for the present level of traffic offering at this station.

### Movement of Coal and Wheat

4745. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the task of gearing the railways to perform adequately and efficiently in the revival and growth of the economy did not receive

(b) if so, what steps are being sought to be taken to improve the situation?

FITHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) Does not arise.

47

# k Resolution from All India Railway Accounts Employees' Association

4746. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- ¶(a) whether Government have received a resolution passed by the All India Railway Accounts Employees' Association and also by the Danapur Branch, Eastern Railway; and
- (b) if so, the demands of the Accounts Staff and steps taken by Government to finalise each demand?

METHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) (a) and (b) In the absence of details it has not been possible to identify the resolution referred to. Necessary information is being collected and will be laid on the table of the House.

### Action against M/s. Alkali and Chemicals for Illegal Activities

4747. SHRI S. S. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether in spite of the fact that it has been brought to the notice of the Government that the activities of Alkali and Chemicals are illegal, no action has been taken in the matter; and
- (b) why protection is being granted for illegal activities and why the price approvals have not been cancelld?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FRETILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) and (b). No, Sir. Government have already instructed State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Ltd. and M/s. Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited to stop release of canalised raw materials to M/s. Alkali and

Chemical Corporation of Initia. The company were also asked on agth May, 1978, to stop the manufacture of such formulations as are presently manufactured by them under loan licence arrangements but are not covered by any Industrial Licence. The compnay have represented against this decision of the Government. On the prices side, the West Bengal State Drug Controller has been instructed to ensure that the company complies with the revised lower prices for propranolo Hcl. fixed by Government. Thus needed action has been taken in the matter.

### Proposal to bring Medical Store Depets under the Ministry

4748. SHRI A. MURUGESAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware that Government Medical Store Depots under Ministry of Health and I.D.P.L. under Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers are performing almost the same work;
- (b) if so, whether Government have examined the above and the details thereof; and
- (c) the action proposed to be taken to bring the Medical Store Depots under the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHBMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). The primary functions of the Medical Stores Organisation, a Government body under the Ministry of Health and Family Welfare, is to supply on payment, the requirements of hospitals and dispensaries in different States. In particular they handle the supply of bulk of the material required for various National Programme, like Malaria Eradicacation Programme, T. B. Control Programme, Cholera Control Programme and Family Welfare Programme. Emergency supplies are also arranged by them as relief measures in the case of floods, cyclone and other natural calamities. They function on a no-profit-no-loss basis.

The Medical Stores Depots at Bombay and Madras have factories attached to them which produce about 100 common Pharmaceutical preparators comprising mainly tinctures, syrups, ointments, tablets and surgical dressings.

I.D.P.L. a public sector undertaking under the Department of Chemicals and Fertilizers are engaged in the manufacture of bulk drugs and formulations consisting of Penicillin, Streptomycin, Tetracycline, exytetracycline, Griscofulvin, Vitamins, Sulphas, Analgesics, Antipyretics, Tranquilizers, Anti-amoebic, Diructics, Antireheumatics, Anti-tuberculars, Anti-filarials Anthelmintics, typnotics, Auti Confulsants, Contraceptive pills and Anti-micro-They also manufacture some ls. They manufacture various bials etc. fine chemicals. types of Surgical Instruments also. have marketing organisation to market their products on a commercial basis both to Gothroughout the country vernment institutions as well as the trade. R and D activities are also undertaken by them to stabilise and up-date available technologies, improve process know-how and develop new products.

Hence there is no comparison or duplication between the roles of Medical Stores Depots and I.D.P.I..

(c) There is no proposal under consideration at the moment to bring the medical Store Depots under the control of the Ministry.

## Use of 'Selson' as Shampoo by M/s. Abbot

4749. SHRI GOVINDA MUNDA -Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that M/s. Abbot used 'Selson' as a shampoo to the tune of Rs. 38 lacs in violation of Excise Duty rules;
- (b) whether fungus is added to Selson; if so, how it could be a shampoo; and
- (c) when did the company remove Selson from their list of shampoos and under what provisions of I (D & F) Act they were allowed to do so?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) :

(a) 'Selson' labelled earlier as 'Dandruff Treatment Shampoo' manufactured by M/s. Abbot, Bombay, is a subject matter of dispute between the Central Excise Department and the manufacturer since 15th of June, 1976. The Government of India have issued a show cause notice dated 18-5-1978 to manufacturer under

Section 35A of the Central Excise and Salt Act, 1944 to review the decision passed by the Collector of Central Excise, Bombay, to continue classifying the product under Tariff Item 14E and the matter is pending decision. If Govt. decides to classify the product on the basis of the above findings under Tariff Item 14E of Central Excise Tariff then the differential central excise duty on clearances of 'Selsun' effected from July '75 till May 78 upto sbout Rs. 3782 lakhs. From June '78 onwards, no clearances have been effected for Selsun for home consumption.

- (b) Commissioner, Food and Drug Administration, Maharashtra, has confirmed that the preparation of Selsun does not contain any fungus.
  - (c) The matter is under examination.

#### Proposal to fix selling price of Bulk Drugs

4750. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of PETRIOLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether interms of new Policy common selling price for bulk drugs based on the cost of production of major efficient producers are proposed to be fixed; if so, the basis on which such prices shall be fixed;
- (b) bow Government will protect new and small scale units who have generally high cost of production; and
- (c) whether any representations were received in this regard and if so, Government's reaction to such representation?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The Pricing Policy which forms a part of the Statement laid on the Table of the Lok Sabha on the 29th March, 1978 containing Government decisions on the report of the Committee on Drugs & Pharmaceuticals Industry (Hathi Committee) envisages that where the indigenous bulk drug is produced by more than one manufacturer, a common selling price for sale to all formotors will be fixed initially on the basis of the average cost of production of relatively more efficient firms which account for a large percentage of the output.

(b) and (c). Representations from the Associations of Drug Manufacturers on the question of providing protection to the new and small scale units in the matter of price fixation were received. It has been clarified to them that Government may fix a weighted average price with separate retention prices for individual firms in appropriate cases, where there are substantial differences in the cost of production of any bulk drug among the different manufacturers.

### Release of canalised bulk Drugs for various Drugs and non-drug Units

4751. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PET-ROLEUM, CHEMICALS AND FERTI-LIZERS be pleased to state:

- (a) details regarding name, quantity and date of recommending release of canalised bulk drugs for various drug and non-drug units by his Ministry to the CPC/IDPL during the last 2 years;
- (b) provisions of policy under which each of these letters were issued; and
- (c) whether through this mechanism certain foreign and Indian companies have been helped and if so, details of unintended benefit in the form of more raw materials obtained by them?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Min. of P. C. & F. (Department of C & F.) laid down parameters for distribution of canalised bulk drugs within the frame-work of Import Trade Control Policy to Small Scale and DGTD units. Clarifications arising out of the application of the distribution policy were also given as and when sought.

During 1975-76 and 1976-77 action was taken to regulate releases of Methyl Dopa

and the position in this regard has already been indicated in reply to part (b) of Lok Sabha Starred Question No. 502 answered on 20-12-77. Details of instructions issued for release of Methyl Dopa during 1976-77 are given in the attached statement.

In 1977-78, the Deptt. issued allocation orders in respect of L-base to individual units in accordance with the Ministry of Commerce notification No. 42-ITC(PN)/77 dated 2-7-77. Details of these allocations are also indicated in the attached statement.

As regards the circumstances in which CPC were asked to release 1.5 kgs. of Prednisolone in favour of M/s Warner Hindustan Ltd. during 1977-78, the relevant details have already been furnished in reply to Lok Sabha Unstarred Question No, 8802 answered on 2-5-78.

Certain releases of Vit, B 1, Vit. B 2 and Folic Acid were also cleared by the Deptt. in 1977-78 in favour of a few non-drug units. The details of such releases and the circumstances under which these were cleared have already been furnished in reply to Lok Sabha Starred Question No. 341 answered on 8-8-78.

On 29-12-77, CPC were asked to release 16 kgs. of Vit. 'A' in favour of M/s Mysore Snackfoods Ltd., Bangalore who required it for being utilised in the manufacture of extruded ready-to-eat food for use in the mid-day meal programme of the Education Deptt. of Government of Karnataka. It is, however, not known whether the material was actually supplied by the CPC.

(c) As the action taken by the Deptt. was based on well-defined policy and principles, the question of certain foreign and Indian companies deriving unintended benefits does not arise.

### Statement

Name of canalised bulk drug/raw-material	Date of recommendation	Name of Company	Quantity (kg.)
1	2	3	4
			1976-77
Methyl Dopa!	3-8-76	IDPL	. 5000
		Merch Sharp & Dohme	. 2000
		Dey's Medical Stores .	. 2000
		Themis	. 2000
		Sunceta Labs	. 2000

•	1				4
	<u> </u>				7
			Gujarat Pharmaceuticals		200
			Jagson Pal & Co		200
			Unique Chemicals	•	200
			Cadila Lab		200
		14-9-76	Dolphin Laboratories Pvt	. Ltd	200
		26-11-76	C. I. Laboratories	•	600
		28-2-77	Cadila Labs	•	50
					For 1976-77 & 1977-78
L-Base		• 19-7-77	Day-Sc-Chem		45000 (1977-78 only)
		19-8-77	Microbe Labs.	•	2374 (1977-78 only)
		19-7-77	Trichem Labs	•	2968
		19-8-77	Nectrine Pharmacy	•	5805 (1977-78 only)
		19-7 <b>-</b> 77	Vitco Labs	•	269 t
		Do	Imperial Pharmaceuticals	•	2242
		Do.	Usan Labs	•	7514
		Do.	Metro Chemicals	•	575
		Do.	Fine Organic	•	575
		Do. }	British Pharmaceuticals	•	2942
		Do.M	Unique Pharmaceuticals	•	575
		19-8-77	jagson Pal & Co. , .	•	3951 (1977-78 only)
		28-7-77	Pharmachem . •	•	6138 (1977-78 only)
		19-8-77	Pharma Indiana	•	3348 (1977-78 only)
		Do.	Piya Pharma	. •	1365 (1977-78 on )
		19-7-77	Syntholab	•	575
		19-8-77	Pure Drug (India)	•	2340 (1977-78 only)
		Do.	Jatin Pharma	•	1 <b>267</b> (1977-78 only)
		21-9-77	Nirlac Pharmed	•	1040 (1977-78 only)

1		2	3	4
L. Base		19-7-77	Allied Chemicals & Pharma- ceuticals	- 575
		Do.	Basic Pharma	• 575
		Do.	Bombay Drug House Pvt. Ltd.	. 575
		Do.	Gratus Pharma	• 575
		Do.	Sundeep Drugs Pvt. Ltd.	• 575
		Do.	Poly Drug Chem	. 575
		Do.	Theo Pharma	• 575
		Do.	Champharma Chemicals & Pharmaceuticals Products	. 575
		Do.	Intrachem	• 575
		Do.	Reverie Pharmachem.	• 575
	•	Do.	Gufic Pvt. Ltd	• 575
		Do.	Suchem Lab	• 575
		Do.	Vichem Labs	• 575
		Do.	Barichem India Ltd.	• 575
	,	Do.	Biomex Remedies	• 575
		Do.	Orion Chemicals	• 575
		Do.	Avron Pharmaceuticals	• 575
		19-8-77	J. K. Pharmaceuticals	. 250 (1977-78 only)
	•	27-8-77	Premier Pharmachem.	. 250 (1977-78 omly)
		5-9-78	Pharmaryuth Chemicals	. 1047
		8-9-77	Polydrug Laboratories	• 575
		Do.	Imphachem Industries	• 575
		Do.	Santosh Pharmaceuticals	• 575
		28-9-77	Sunchem Laboratories	· 250 (19 <b>7</b> 7-7 <b>8</b> only)
		20-1-78	Canberra Chemicals	. Do.

# Pilferage or Theft of Fertilizers from Fertilizer Factory

4752. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSB ALLURI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the amount of loss suffered by way of pilferage or theft of fertilizers from fertilizer factories during the last three years; and

(b) what steps are being taken to prevent such recurring losses due to pilferages?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

48

VIJAY KUMAR 4753. SHRI MALHOTRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

- (a) what is the approximate number of people who travel daily to New Delhi from neighbouring States;
- (b) is it true that the trains by which they travel are frequently behind schedule and the commuter can never be sure of reaching the office or place in time ;
- (c) is it also true that such commuters swarm into the reserved compartments and cause great inconvenience to the other passengers; and
- (d) if so, what steps are being taken to set the above things right?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) About 25,000.

- (b) No. Punctuality performance of local trains in Delhi area is satisfactory.
- (c) Cases of commuters entering re-served coaches around Delhi and other important stations, have come to the notice of the Railway Administration.
- (d) Staff manning reserved coaches have instructions to ensure that unauthorised passengers do not enter the reserved coaches. At times, however, it becomes difficult to control such passengers. Surprise checks are conducted and unauthorised passengers travelling in those coaches are dealt with as per rules. Cases of deliberate negligence on the part of the staff manning reserved coaches are viewed seriously and appropriate action taken against them.

### Discussions with Chairman Indian Oil Corporation by representatives of Refinery Works of Refinery Union

4754. SHRI AHMED M. PATEL 1 Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- representatives of (a) whether Barauni Oil Refinery Works Union met the Chairman of the Indian Oil Corporation recently to resolve the dispute arising out of the 'go slow' tactics launched by the Technical Staff of the refinery;
- (b) if so, the nature of the talks held;

(c) the reaction of the Government in this regard ?

THE MINISTER OF PETROLEUM. AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes,

- (b) The major demand made by the various unions and different groups of workers during the talks was a removal of stagnation among the employees. An offer was made to the representatives of the various unions providing stagnation relief to employees of single cadre posts by giving them one scale higher as personal to them without change in their job and designation. This is on the basis of a similar offer made to the recognised union of Gauhati Refinery and accepted by them. However, the Unions at Barauni have made demands for reducing the limit of 12 years to as low as 5 years and have demanded that the scheme should cover categories of employees in posts other than single cadre also.
  - (c) The matter is under examination.

### Vacancies Filed by Promotions and Direct Recruitment

4755. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) the number of vacancies filled by promotions and direct recruitment in each class/category and grade over Allahabad Bikaner, Delbi, Firozpur, Jodhpur, Lucknow, Moradabad and railway electrification of Northern Railway and how many among them were from SC/ST and how many of them were belonging to Non-SC/ST in the year 1977;
- (b) the number of vacancies in each class, category and grade which had come to the share of SC/ST as reserved quota including carry forward vacancies;
- (c) whether the entire vacancies in reserved quota were fully subscribed (give details); and
- (d) if not, whether any steps are being taken to a secure adequate representations of SC/ST and wipe out the back-log?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS
SHEO NARAIN): (a) to (d) . Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

### प्याज के परिवहन के लिए रेलगाड़ियां

4756 भी धर्मसिंह माई पटेल : न्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सोराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट जिले में भाषाबार, घोराजी, भीर उपलेटा स्टेशनों,

- (ख) क्या प्याच के लदान हेतु वहां वैशक्तों की कमी बी सीर यदि हां, तों इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या प्याज नष्ट होने वासी वस्तु है सीर वर्ष हो, तो क्या प्याव के लिए वैननों की सप्लाई हेतु इस वर्ष कोई समय-सूची तैयार की गई है सौर क्या सनले वर्ष के लिए भी इस प्रयोजन हेतु कोई समय सूची तैयार करने का प्रस्ताव है?
- रेन नंतानय में राज्य मंत्री (भी शिव मारायण): (क) संगम विवरण में व्योश दिया हुआ है।
- (बा) इस बाताबात की निकासी न्यूना-धिक रूप से साथ-साथ होती रही है। लेकिन,

जब क्षी बड़ी हुई मांगें की पूर्ति के बिए बाल बिल्मों की बच्चाई सहाई वह तर को वैदाने पर मांग पत रह कर दिये कई है

(ग) प्याज यातायात एक कड़ी समय अध्युष्टी के अनुसारे नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्याज के लिए मार्जिक्यों की सांचें बहुत से स्वेचकों के लिए होती है और ने मार्ग क्नाविक कड़-कड़ा कर की आती है जितका तबूत यह है कि यालडिक्ये सप्वाई कर देने पर उनके लिए मांत्रपक्ष (खेंट) बड़ी तावाद में रह कर दिये जाते हैं। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कवब उठाये जा रहे हैं कि यालपि प्याज कोई सर्वाक्षक्ष मध्य माल नहीं है, तो जी जहां तक सम्भव होता है, प्याब यातायात को माल डिक्या आवंटत के लिए अपेकाइन उक्य प्राविक्ताता से कर स्वक्त स्विक्त मान्य यातायात मानुसूची के अस्तर्गत 'ज' प्राविक्तिता रिकार मान्य यातायात मानुसूची के अस्तर्गत 'ज' प्राविक्तिता रिकार कड़ी नजर स्वकर तथा मार्गविद्यों पिद्यां विकार मांच प्राविक्त को इर करने के लिए उनकी मानीटरिंग करके जल्दी से अस्तरी भेज दिया जाये।

#### विवरण

		व्याः	म से लादे गये मा	ल-डिब्बों की संख्या	31-7-78	मांग-पत्नों का	
स्टेशन	स्टेशन		-	15-6-78 31-7-78	जनवरी <b>से</b> जुलाई, 78	को बकाया पंजीकरण	रह करवादेना
		1		2	3	4	5
भायबादर				214	953	16	1187
धोराजी		•		87	356	28	581
उपलेटा 🕴		•	•	65	250	5	301
<b>जाम</b> जोधपुर	₹			18	92		259
लानपुर				4	7	1	3
वेरावल				230	823	2	1375
केमोद				7	42	6	154
महुधा				8	586	147	600
भावनगर					683		359

### Survey of lines during 1978-79.

4757. SHRI GIRIDHAR GO—MANGO: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state:

- (a) the names of the lines included for survey for the year 1978-79 and in the Sixth Plan in the State of Ocissa to convert into B.G. lines;
- (b) the reasons for non-inclusion of Naupada-Gunupur N.G. line for survey; and
- (c) progress of the work and programmes for the new lines to be included?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). A reconnaissance engineering-cum-traffic survey for the conversion of Rupus-Talband narrow gauge line into broad gauge and its extension up to Gorumahisani / Chakulia has been taken up during the current financail year.

Surveys have also been taken up on the request of the Government of Orissa for construction of two new railway lines from Talcher to Sambalpur and from Koraput to Salur/Parvatipuram. Construction of the first phase of the Jakhapura

Banspani line from Jakhapura to Daitari is in progress. It is not proposed to consider conversion of Naupada-Gunupur narrow gauge line into broad gauge at present due to constraint of resources.

The list of new lines and conversion projects to be included in the Sixth Plan has not yet been finalised.

#### Demand for halt of Nava Jeevan Express at Raichur

- RAISHEKHAR SHRI 4758. SHRI RAJSHEKHAR KOLUR: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state :
- (a) whether it is a fact that there has been a demand from a wide section of the puple to provide a halt of Nava Jeevan Express at Ruchur Railway Station in Karnataka:
- (b) if so, whether a decision has been taken to provide a halt; and
  - (c) if not, the reasons for such decision?

THE MINISTER OF STATE IN THE (SHRI MINISTRY OF RAILWAYS SHEO NARAIN) : (a) Yes, several representations have been received.

(b) and (c) 145/146 Ahmedabad-Madras Nava Jeevan Express provides fast service between these two cities. vision of additional stoppages will slow down the train to the inconvenience of through passengers who have been representing for reduction in journey time.

### Pilferage on Railways

- SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state :
- (a) whether it is a fact that during the financial year 1977-78, the pilferage on Indian Railways was more than what it was in the previous years;
- (b) if so, comparative figures for the last three years;
- (c) whether as a result the railways had to pay a huge sum in the form of compensation; and
- (d) if so, total amount paid during the last three years separately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). The cases of pilferage during 1977-78 were 86,985 as compared to 86,985 during 1976-77, i.e. a decrease of 4,059.

The statistics of the number of cases and the amount of compensation paid in these cases of pilferage during the last three years are:

Year			Amount of compensa- tion paid
	 		(in crores of rupees)
1975-76.		1,56,181	7 · 22
1976-77.		86,985	<b>₹5</b> -46
1977-78.		82,926	5 · 47

# Procurement of Oxytetracycline by M/s. Pfizer from I.D.P.L

4760. SHRI BALWANT RAMOOWALIA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1275 regarding manufacture of Oxytetracycline by M/s. Pfizer dated 25yth July, 1978 and state:

- (a) was the entitlement and actual release of Oxytetracycline effected in favour of M/s. Pfizer on the basis of policy parameters as indicated in reply to the said question ;
- (b) how M/s. Pfizer were entitled for release of Oxytetracycline from IDPL when they themselves are licenced to produce this drug; and
- (c) whether M/s. Pfizer are still pro-curing Oxytetracycline from IDPL and if so, quantity supplied by IDPL during current year to M/s. Pfizer and whether IDPL have met the demand of other users of Oxytetracycline in full before supplying to Pfizer, under what provisions of policy these supplies have been effected?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTI-LIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Upto the year 1976-77, the relesses of Oxytetracycline were made by IDPL as per demand received from various units because this drug was banned for import upto that year.

Oxytetracycline was canalised for the first time in 1977-78. M/s. Pfizer were entitled to a release of more than 20 tonnes during 1977-78, both in terms of the ald policy regarding supply of canalised raw

materials and the revised policy announced in October, 1977, but they were actually supplied a quantity of 5.00 tonnes by IDPL.

- (b) There are no guidelines or instructions that drug manufacturing units licensed for production of a particular bulk drug are debarred from obtaining supplies thereof from other manufacturers/ suppliers' of the same drug.
- (c) Yes, Sir. Oxytetracycline has been decanalised and put on the banned list for the year 1978-79. For 1978-79, M/s. Pfizer registered a total quantity of 27 tonnes with IDPL with delivery schedule of 9 tonnes in each of the remaining three quarters. While IDPL have so far released a quantity of 15 tonnes of Oxytetracycline to M/s. Pfizer against the delivery schedule for the first two quarters, they have met the demand from other units also in full.

# पूर्वोत्तर रेलवे से मान्यता प्राप्त संब

- 4761. भी हुक्स चन्च कछचाय: क्या रेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (च) इस समय पूर्वोत्तर रेलवे में मान्यता भ्राप्त संघ का नाम क्या है;
- (ख) क्या किसी संघ ने मान्यता के लिए घपने दावे को प्राथमिकता दी है; ग्रीर
- (ग) यदि हां, तो उसका नाम क्या है और इसे तदनुसार मान्यता न देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय कें राज्य मंत्री (की शिव नारायण): (क) इस समय पूर्वोत्तर रेलवे पर निन्नलिखित दो यूनियनों को मान्यता मिली हुई है :—

- (i) एन० ६० रेलवे मजदूर यूनियन— यह भाल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के साथ सम्बद्ध है।
- (ii) एन० ई० रेलवे एम्पलाइज यूनियन (पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ)— यह नेमनल फेडरेशन भ्राफ इण्डियन रेलवे मेन के साथ सम्बद्ध है।
- (बा) धौर (ग) पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, जोकि एक मान्यता रहित यूनियन है, ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रवाधक को एक पत्न लिखा है जिसमें मान्यता प्रदान किये जाने का धनुरोध किया गया है।

मई 1977 में हुए लिपक्षीय मजदूर सम्मेलन के बाद श्रम मंद्रालय ने एक लिपक्षीय समिति स्थापित की थी जो भ्रन्य बातों के साथ-साथ यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के मानदण्डों के बारे में सिफारियों करेगी। सरकार नये भीषोगिक सम्बन्धों के बिल के बारे में उनकी रिपोर्ट पर विचार कर रही है। जब तक इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली सामान्य नीति पर निर्णय नहीं लिया वाला तब तक रेल प्रवासनों द्वारा किसी नई बूलियन को मान्यता प्रवास नहीं की जा रही।

# Progress of complete take over of Swadeshi Cotton Mills

- 4762. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to reply given to Starred Question No. 761 on 18th April, 1978 regarding Swadeshi Cotton Mills and state:
- (a) the progress so far made by the National Textile Corporation in taking over complete management of Swadeshi Cotton Mills Company Ltd., Kanpur and its 5 units alongwith assets investments share, land, subsidiary company owning two sugar units etc; and
- (b) why not other civil and criminal action/proceedings are taken against erring crstwhile management?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Possession of six textile undertakings of Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, was taken by the National Textile Corporation Limited immediately after the issue of the Notification dated 13-4-1978 in terms of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. The question of take-over of other industries of the Company did not arise since such take-over would not have merited action under the said Act. Meanwhile, in terms of the arrangements approved by the Delhi High Court, National Textile Corporation is also in possession of certain portions of the premises of the Company.

(b) The Ministry of Industry which is concerned in the matter has informed that there is no move for any such action. As for as this Department is concerned, action under section 408 of the Companies Act, 1956 had already been taken but the matter is subjudice.

# Representation from Sangli Municipal Council

- 4763. SHRI ANNASAHEB GOT KHINDE: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state:
- (a) whether at the time of his visit on the 15th June, 1978, to Sangli, Maharashtra State, 'the President of the Sangli Municipal Council had made some representation to him regarding the amount of more than Rs. 13 lakis paid by the said

council to the Railways as the price of the Railway land sold to the Council;

- (b) if so, taking into consideration the fact that such blocking of funds has resulted in seriously affecting the developmental activities of the said council, whether Government will take a decision at an early date in the matter;
- (c) if so, the probable date when the decision is likely to be taken;
- (d) whether till then the Government will stay the demand of the remaining amount of about Rs. 5 1/2 lakh raised against the said council; and
  - (e) if not, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

- (b) and (c). The land in question was handed over to the Municipal Council and other parties last year, but in view of the subsequent proposal for restoring Miraj-Sangli branch line, the Municipal Council and other parties to whom the railway land between Sangli and Miraj was handed over have been requested not to make any construction thereon. In case, it is ultimately decided to restore the branch line, the land will be taken back, otherwise it will be permitted to be used by the Municipal Council. It will however, take some time more before a decision is taken.
  - (d) Yes.
- (e) In view of (d) above the question does not arise.

# **Promotion to Loyal Workers**

4764. SHRI R. L. KUREEL: SHRI SUBHASH AHUJΛ:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 6514 on 11th April 1978 regarding promotion of coaching clerks as Commercial Apprentices at New Delhi Station and State further:

- (a) whether such like promotions have been given to other loyal workers in Indian Railwayss;
- (b) if not, reasons for giving preferential treatment to these employees;
- (c) whether these employees were deputed by the Administration to work against the Railway Strike in 1974;
- (d) if so, reasons for making them absent from their duty from 8th May, 1974 to

- 13th May, 1974 and declaring them loyal;
- (e) if so, number of other employees given this type of preferential benefits to promotions in Northern Railway; and
  - (f) if so, the further redressal actions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No. There were no other such cases.

- (b) As indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 9638 answered on 9-5-78, there was only one solitary case. It was a case of fresh appointment as Commercial Apprentice against 20% quota for wards of Railway employees on the basis of service rendered by his father. There was no question of giving any preferential treatment in this particular case.
- (c) to (f). Do not arise as there were no other employees similarly treated.

#### Change of name from Dumex to Pfizer

4765. SHRI MOHAN SINGH TUR: Will the Minister of PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) when it became known for the first time to his Ministry that Pfizer have purchased Dumex in India.
- (b) when was the request for change of name from Dumex to Pfizer received by Government and what were the details furnished by Pfizer for seeking transfer of independent licence/approvals possessed by M/s. Dumex in their name; and
- (c) when was the approval of Government granted for such change in name and on what basis and under what provisions was this change in name allowed by Governe at ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c) & M/s. East Asiatic Company, a Denmark based international Corporation were marketing, since 1946, Pharmaceutical products bearing the name of "Dumex" manufactured by a combine of six drug manufacturing firms known as Danish United Medical Export. On 21st November, 1950 this was organised as a Private Lmitted Company in the name of Dumex Limited, as a subidiary of the Danish firm—East Asiatic Company.

In May, 1958, M/s. Dumex submitted an application for the issue of capital of Rs. 30 lakhs as preference capital of M/s. East Asiatic & Co. India Limited and Rs. 30 lakhs as equity capital to M/s. Pfizer, Panama. They stated, as justification therefore, the fact that M/s. Pfizer proposed to invest and would also furnish technical know how etc. for the manufacture of antibiotics in India from the basic stage. This application was considered by the Govt. in 1958 and was agreed to with the approval of the then Minister of Industry.

On 10th June, 1960 Govt, agreed to the issue of shares worth Rs. 25 to lakhs to M/s. Ptizer Corporation, Panama by M/s. Dumex Limited, Bombay for the establishment of a plant in Chandigarh for the manufacture of Oxytetracycline and Tetracycline.

In July, 1960 the East Asiatic Company (1) Pvt. Ltd., intimated that 15,000 preference shares out of e 30,000 preference shares held by them in M/s. Dumex Limited were redeemed out of the accumulated profits, on the 3rd June, 1960. Hence, the East Asiatic Company (1) Pvt. Ltd. were left with only 15,000 preference shares with a value of Rs. 15 lakhs only. The M/s. Pfizer acquired controlling interest in M/s. Dumex Limited.

Later in 1960, a proposal was made by East Asiatic Co. (1) Pvt. Ltd., and East Asiatic Co. Ltd. Danmark wanting to sell all their shares in Dumex Limited amounting to Rs. 9:9 lakhs of the face value of Rs. 100 per. share to M/s. Pfizer at Rs. 200 per share

This proposal was agreed to in consulta-tion with the then Ministry of Commerce and Industry and Department of Company Law Administration. The Department of Company Law Administration considered the price of Rs. 200 as fair and reasonable. The procedure at that time regarding consulting the concerned Administrative Ministry about association of foreign equity and the Department of Company Law Administration to check up the reasonableness of the price at which the shares would be transferred was duly observed in this case. Hence by the end of 1960 M/s. Pfizer acquired the entire share-holding of M/s. Dumex. As a result, M/s. Dumex Pvt. Ltd. ceased to exist as a separate Company in India, on its reincorporation as M/s. Pfizer. The name of M/s. Dumex Pvt. Ltd. was subsequently changed to M/s. Pfizer and Industrial Licences and Registration Certificate held in the name of Dumex were also endorsed in the name of M/s. Pfizer in July, 1961.

# Time taken by train from Udaipur to Jodhpur

4766. SHRI R. D. GATTANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a time of more than 15 hours is taken by the train for reaching Udaipur from Jodhpur which is a distance of 301 Kms.; and

(b) if so, whether efforts would be made to bring down this time to a reasonable limit?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) 221 UP Jodhpur Udaipur Passenger takes 12 hours 50 minutes from Jodhpur to Udaipur.

(b) Speeding up of this train is not operationally feasible under the present conditions of track and traction and the need to maintain connections enroute.

# Strength of Assistant Officers

4767. SHRI KISHORE LAL 1 Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

- (a) What was the strength of Assistant Officers, Senior Scale Officers, Junior Administrative Officers and Principal Officers, department wise, in each zone in the Indian Railways in April, 1974 and in April, 1978; and
- (b) What percentage of upgradation has been done in the case of officers gradewise and Class III and IV employees since 1974?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2731/78].

(b) Number of gazetted posts upgraded after 1-4-1974 305

Number of Class III posts upgraded to Class II . 506

Number of Class III posts upgraded . . . 24297

Upgradations are done only on the basis of worth of charge and responsibilities and not on percentage basis.

# Representation regarding Work Done by ONGC in Tripura

4768. SHRI SACHINDRALAI. SINGHA: Willthe Minister of PETRO-LEUM, CHEMICALS & FERTILIZ-ERS be pleased to state:

(a) whether he had received any representation either from any M.P. or from

the workers representatives of ONGC working in Tripura regarding the delay of work in the State:

Written Answers

- (b) if so, the details of the representation/representations; and
- (c) the details of action taken on the basis of representation/representations.

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) to (c) The General Secretary, ONGC Workers' Union, Tripura Project Agartala and General Secretary, ONGC Workmen Association, Calcutta jointly submitted a Memorandum dated 8-4-78 through Shri Samar Mikherjee, M.P. vide, his letter dt. 11-5-77 Para 1 of this Memorandum which refers to the alleged mis-management and unplanned drilling in Tripura Project, besides West Beng il Project reads as under :--

# "Drilling Aspects:

Drilling is being carried out at West Bengal and Tripura since last 12 years but so far practically is nil. Although there are so many reasons behind it still our 12 years practical experience does not permit that a major portion of the reasons cannot be avoided, viz., regular stuck up in the wells die to unplanted drijling operation and mere negligence of the namagement, indecision-freleasing of drilling point, frequent changing of decision in all respects, which spoils the man power, material, money and time etc. Therefore, it is expected that you will probe into the matter to put this vital organisation to a sound footing."

The matter was examined and comments were called for from the ONGC. In regard to West Bengal I had already supplied the reply in answer to Question No. 2192 in the Lok Sabba on 1-8-1976, which may be referred to. In so far as the drilling work in Tripura is concerned the apparent slow pace of exploration by the ONGC in Tripura has been mainly due to the remotness of the area, difficult sub-surface conditions and the high pressures encountered in the drilling of the wells in that State, However, notwithstanding these difficulties, further drilling in Tripura is being continued by the ONGC more vigorously.

#### Geological and Geophysical Survey by ONGC in North Eastern Region and Eastern Region.

4769. SHRI SUDHIR GHOSAL: Willthe MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the name of the area in North Eastern Region and Eastern Region where

- ONGC conducted geological and geophysical survey up-to-date, period-wise;
- (b) the names of the scientists participated in these survey work areawise;
- (c) the details of the Report submitted by each of the survey team?

THE MINISTER OF PETROLEUM, & CHEMICALS AND FERTILIZERS: (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) to (c) The necessary information is being obtained from the ONGC and will be laid on the table of the Sabha.

#### Petrochemicals Complex at Haldia

4770. DR. BIJOY MONDAL: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZEES be pleased to state:

- (a) whether West Bengl Government have given any proposal for a petrochemicals complex at Haldia;
- (b) if so, details of the proposal of the State Government; and
- (c) the action taken up-to-date in this regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM & CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIH.N. BAHUGUNA): (a) to (c) A letter of intent was issued to the West Bengal Industrial Development Gorporation Limited, in November, 1977, for the setting up of a petrochemical complex upto the capacities specified below:

Items of manufactu	ire	Annual capaciles/ tonnes
(1) Ethylene		54,000
(2) Propylene .		30,000
(3) Prolysis Gasolin	ie .	46,000
(4) Butadiene . (5) Benzene	:	8,000 8,000
(6) Ethylene Oxide		3,000
(7) Ethylene Glyco	l .	10,000
(8) Diethylene Gly	col .	1,500
(9) Ethyl Hexanol		21,000
(10) Isobutanol .		8,100
(11) N-Butanol .		3,100
(12) HDPE	•	20,000
(13) P.V.C		45.000

The Corporation have yet to come up with the feasibility reports.

# भंजालय में हरिजनों के लिए विशेष बैल

- 4771. भी मही लाल : क्या पेट्रोलियन रसामन भौर उर्घरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 1958 के नवभारत टाइम्झ' भीर 'जनवृग' में उनके मंत्रालय में हरिजनों के लिए दो विशेष सैल बनाये जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की धोर दिलाया गया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त दो विशेष सैल उपरोक्त समाचार पत्र में उल्लिखिन निगमों, विशेष रूप से भारतीय तेल निगम में मनुसूचिन जातियों भौर मनुसूचिन जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाये गये हैं:
- (ग) यदि हां, तो इन सैलों के सदस्यों का क्यौरा क्या है और क्या अनुसूचित जातियों के अधिकारी/कर्मचारी इन सेलों का अध्यक्ष नियुक्त किये जायेगा क्योंकि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की समस्यार्थे अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उन्हें बेहतर हल कर सकेंगे : और
  - (घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

# पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रीर उर्वरक मंत्री (श्री हेमबती नन्वन बहुगुणी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस मंत्राध्यय के नियंत्रणा-धीन मार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक उद्यमों में प्रम-सुचित जातियों और धनुमुचिन जनजातियों के पैर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चिन करने हेतु प्रशास-निक कदमों की शुरुधात करने के लिए दा प्रकोब्ट स्थापिन करने का निर्णय किया गया है। पेटी-लियम विभाग में खाले गये मेल का संचालन इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा भीर रसायन तथा उर्वरक विभाग में स्थापित सेल (प्रकोष्ट) का संचालन भारतीय उर्वरक निगम द्वारा किया जायेगा । इन प्रकोप्ठों का स्वरूप प्रशासनिक इकाइयों जेसा होगा भीर ये प्रकोष्ट कुल मिला कर इस मंत्रालय की देखरेख में अपने अपने उपक्रमों के भाग के रूप में काम करेंगे। इंडियन भागल कार्पोरेशन नथा भारतीय उर्वरक निगम से प्रनरोध किया गया है कि वे इन प्रकोप्टों का गठन करने के लिए तस्काल कार्रवाई करें। इन प्रकोप्टों को प्रभावी बनाने से सम्बन्धित सुझाणों पर विचार किया जायेगा ।

# टाटा ब्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए डलबां सोहे का परिवहन

- 4772 श्री रामधेव सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सच है कि टाटा नगर इस्पात संग्रंत के लिए दलवां लोहा मध्य प्रदेश, उड़ीसा श्रीद

प्रत्य राज्यों से टाटा नगर (जमशेदपुर) को बैगनों द्वारा भेजा जाता है:

- (ख) क्या टाटा प्रोजेक्ट के स्रोधकारियों की सांठ-गांट से रेल स्राधकारी इन बैंगनों को बापसी बाला के समय खाली दशति हैं जब कि वे वस्तुतः टाटा स्टील के उत्पादों से भरे होते हैं जिसके परिणामस्वकप रेलवे कों भारी नुकसान होता है;
- (ग) क्या इस बारे में गवनेमें स्ट रेलवे पुलिस (जी । भारत पीठ) के पास कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्श कराई गई है भीर इस मामले की जांच चल रही है;
- (प) क्या बिहार के नीठ ग्राई० डीठ अधिकारियां ने इन मामणे को दबाने के लिए जांच रोक दी है: ग्रांर
- (छ) यदि हां, तो इस बारे में सरकाद 🖛 द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण): (क) जी नहीं ।

- (ख) प्रश्न नहीं उठना ।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) प्रश्न नहीं उठता ।
- (छ) प्रक्त नहीं उठता ।

Sanctioned Strength of House Surgeons in Northern Railway.

4773. SHRI NATHU SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) the present sanctioned strength of House Surgeons in Northern Railway Hospital, New Delhi and the existing working strength in that Hospital; and
- (b) if the working strength is not commensurate with the sanctioned strength when the remaining vacancies are likely to be filled up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) The maximum permissible number of House Surgeons that could be appointed in the Central Hospital, New Delhi is 10. At present 7 House Surgeons are working Action is being processed to fill the remaining three posts.

#### Maintenance of Rake

4774. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that according to the instructions existing on the Railways each rake should get primary maintenance after a run of approximately 1000 kms. and secondary maintenance after a run of 500 kms.;
- (b) whether it is also a fact that 63 UP/64¶ Lucknow Agra Express has been extended upto Kota without any secondary maintenance at Kota though the one side run is more than 600 kms.; and
- (c) what remedial measures are proposed by the Government to avoid the violation of rules which endangers safety?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No. Normally Primary maintenance is given at the originating Station and secondary maintenance at the terminating Station depending on the Rake links. No kilometrage targets have been laid down for this purpose.

- (b) Yes, 63 UP/64 Dn. Lucknow-Agra Express has been extended upto Kota. The Primary Maintenance of this train is based at Lucknow, the originating Station, and Safe-to-run examination at Kota, the terminating Station. After the Safe-to-run examination the train is fit to run for its return journey.
- (c) Does not arise, as no Safety rules have been violated.

# अवानक-वम्बई एक्सप्रैस ग्रीर सावरणती एक्सप्रैस रेलगाडियों में ग्रीधक मीड-माड

4775. **भी रायवजी:** स्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जात है कि लखनऊ-बम्बई एक्मप्रेस झीर साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में हमेबा भीड़काड़ रहती है नया इसके परिचाम-स्वकप भारी भीड़ के दिनों में यात्री इन रेलगाड़ियों में नहीं वढ़ पाते हैं:
- (ख) क्या सरकार का विचार इन रेल-गाड़ियों भी बोगियों की संख्या बढ़ाने और इनको डीजल इंजनों से चलाने का है; ग्रीर
- (ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया कायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (ची तिव नारायण): (क) 115/116 बस्बई-लखनऊ एक्सप्रैम घीरे 165/166 साबरमती एक्सप्रैस गाहियों में कुछ बण्डों पर मीट-माड देखी गई है। (ख) और (ग). गुंजाइस न होने के कारण इन गाड़ियों में सतिरिक्त डिब्बे नहीं लगाये जा सकते । लंबी दरी की याती गाड़ियों में डीजली-करण का काम यसनारमक साधार पर किया जा रहा है परन्तु यह बीजल इंजनों की उपलब्धता पर निर्मर करता है जो प्राथमिक रूप से माल यानायात की निकासी के लिए धरेकित हैं। फिर मी, जब माड़ियों के डीजलीकरण के प्रकृत पर सी बिबार किया गाड़ियों के डीजलीकरण के प्रकृत पर भी विवार किया जायेगा।

# मीटर नेज स्टेशन, संबाई माधोपुर के पीछे खाली वड़ी चूनि

4776. भी मीठा लाल पटेल : क्या रेल जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि सवाई माझोपुर अंक्शन (कोटापश्चिम रेलवे) में मीटर गेज स्टेझन और मनटाऊन बाओरिया दुकानों के पीछे रेलवे भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है और यदि हां,तो भूमि का कितना क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है:
- (ख) क्या यह सब है कि इस क्षेत्र में पानी, जमा हो गया है भीर कई वर्षों से रुका हुआ पानी सड़ांध फैला रहा है क्यों कि इस पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर प्रायः बीमारियां फैलती हैं; और
- (ग) यदि हो, तो क्या इस पानी को निकासी और इस स्थान को साफ रखने के लिए सरकार द्वारा कार्य बाही की जा रही है और यदि हो, तो तत्मस्वन्धी स्थीरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और इस स्थान को कब तक साफ कराया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंती (भी शिष नारावण):
(क) से (ग). सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पीछे रेलवे भूमि की सीमा निवादा-स्पद हैं। रेलवे सीमा के साथ-माथ बहुत सी हुकामें/ होटल का पानी रेलवे सीमा के साथ-माथ बहुत होटलों का पानी रेलवे सीन में स्वित कुछ निचचे भागों में जमा हो जाता है। भूमि-सीमा के बारे में विचाद का निपटारा करने और साथ ही उस क्षेत्र से पानी के निकास की समस्या के समाधान के लिए सवाई माधोपुर नोटिकाइड एरिया कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। रेलवे सीमा के साथ-साथ पानी की निकासी के लिए प्रवाई के साय एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। रेलवे सीमा के साथ-साथ पानी की निकासी के लिए प्रवाई पर नोटिकाइड एरिया कमेटी के साब खात-बीत की जा रही है।

### Consumer Price of L.P. Gas

- 4777. SHRI P. VENKATASUBBA-IAH: Willthe Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) whether the consumer price of L.P. (cooking gas) produced and marketed by

the Government owned oil companies is statutorily or otherwise fixed by the Government;

- (b) if so, the formula on which the consumer price is fixed both in the case of direct marketing by Indian Oil and Burmah Shell through their retail agents and in the case of Hindustan Petroleum through their wholesale distributors like M/s. Kosan Gas Go. and East Goas Pvt. Ltd., and Domestic Gas Pvt. Ltd.;
- (c) whether it is a fact that wholesale distributors like M/s. Kosan Gas Co., Bombay and East Coast Gas Co., Visakhapatnam, while showing in their costings to Ministry as if they are allowing Rs. 3.37 p. as retail agents margin are actually paying Rs. 2.75 p. only per cylinder; and
- (d) the reasons for the delay in implementing the decision of the Government for the take over of M/s Kosan Gas Co. as announced on the Floor of the Lok Sablia on 4th September, 1977 by the Hon'ble Minister?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The consumer price of domestic cooking gas for all marketing companies is fixed by Government—but not statutorily.

- (b) and (c). The formula on which the the consumer is fixed price to takes into account the various elements of cost, evlinder filling charges, marketing and distribution charges, margins, dealer's commission, local taxes, etc. It includes a commission of Rs. 3.37/ cylinder. While the formula applies to all the marketing companies, the commission of Rs. 3.37 cylinder is applicable to a full-fledged ag nt with complete facilities/services to customers. Kosan Gas (one of the con-cessionaires of Hindustan Petroleum Petroleum Corporation), has one main agent and some agents and sub-agents. The commissions is shared between the concessionaires and their agents/sub-agents in proportion to the services/facilities provided by them. Agents are given commission ranging from Rs. 2.75 to Rs. 3.37 per cylinder and the sub-agents from Rs. 1.25 to Rs. 1.75 per cylinder depending on the services performed by them. As per arrangement reached by East Coast Cas Co./Domestic Gas Co. Pvt. Ltd., (which are the concessionaires of the Vishakh Marketing Unit of HPCthe erstwhile CORIL) with their agents directly, an amount of Rs. 2.75/ cylinder is given to their agents as against Rs. 3.37/ cylinder pro ided in the price build-up.
- (d) Steps in this regard have already been initiated.

# Consideration of Hathi Committee Report

4778. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

- (a) whether Government have considered the report of Hathi Committee;
- (b) if so, the details of the major recommendations thereof accepted by Government;
- (c) whether Government have also accepted the recommendations made in the Hathi Committee report about multinational Drug Companies; and
  - (d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) to (d). Government have taken comprehensive decisions on the recommendations of the Hathi Committee and a Statement reflecting the New Drug Policy has already been laid on the Table of the House on 29th March. 1978. The said Statement contains inter alia, Government's decisions on the regulation of activities of multi-national drug companies and summarises the recommendation of the Hathi Committee on the role of foreign companies vis-a-vis Government decisions thereon.

# दिल्ली में कृष्किंग गैस के लिए पंजीकरण

4779. श्री राजकेशर सिंह: नया पेट्रोलियम, रसायन ग्रीर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंग्रे कि:

- (क) क्या दिल्ली में सभी ग्रैम एजेंसियों में ग्रैस के कनेक्शनों के लिए पंजीकरण काफी समय से बन्द है ; भीर
- (ख) यदिहां, तो उस के क्या कारण हैं और सरकार का पंजीकरण धारंभ करने के लिए कब धादेश जारी करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्बरक मंत्री (भी हेमबली नत्यन बहुनुषा) : (क) खाना पकाने की तैस को मांग की धपेका इस उत्पाद की लगातार कमी को देखते हुए तेल कंपनियां द्वारा (दिल्ली सहित) कुछ क्षेत्रों में तरल पेट्रोलियम ग्रैस (खाना पकाने की ग्रैस) के कनेकान प्रदान करने के लिए नामों के पंजीकरण को निकम्माहिन किया गया था !

(ख) तेल कंपनियों को वर्ष 1980 से अब खाना पकाने की ग्रैस पर्याप्त माला में उपलब्ध होनी स्राप्तम्भ हो जायेगी, जहां कहीं भी जरूरी होगा एक विज्ञष्ट पैमाने पर नये प्राहकों को स्थान में स्वाते हुए नया पंजीकरण स्नारंभ करने की सलाह दी गयी है ।

### Contractors engaged for construction of Mathura Refinery

4780. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3236 re: contracts for construction of Mathura Refinery on 8-8-1978 and to state:

- (a) the names and addresses of the Indain and Foreign Contractors/Firms engaged for the construction/erection of the Mathura Refinery; and
- (b) what is the nature, magnitude and value of work to be executed under the contract by each contractor?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZ-ERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2732/78].

# मेरठ, देहरादून ग्रौर ग्रागरा में कुर्किंग गैस को एजेंसियों का ग्रावंटन

- 4781. श्री नवाब सिंह चौहान : नया पेट्रोसियम रसायन श्रीर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) मेरठ, देहरादून और भागरा में कुकिंग ग्रैस की कितनी एजेंसियां भावंटित करने का निर्णय किया गया है;
- (ख) उन के ग्राबंटन के मामले में किन सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ;
- (ग) उन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य बग्नौं के लिए क्या कोटा निर्धारित किया गया है : और
- (घ) इस संबंध में कि तने धावेदन पन्न प्राप्त हो चुकेहँतयाउन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वेद्रोलियम तथा रसायन और उर्घरक मंत्री भी हेनवती नत्वन बहुगुषा): (क) इंडियन भागल कार्परिकान ने एक मेरठ में, एक देहरादून में और दो झागरा में कृकिंग गैस की वितरण एजेंसी खोलने का निक्वय किया है।

- (ख) वर्तमान मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, झाबेदन पत्नों को झामंत्रित करने के लिए विकापन प्रकाशित करने पढ़ेंग और वाणिप्यक महत्व को ध्यान में स्वाप्त वित्रण एजेंसी दी जायगी, वास्तविक उपमोक्ता हिकारी सोसाइटियों और कृषि उद्योग निगमों को प्रायमिकता दी जा रही है।
- (ग) सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदेशी रूप-रेंबाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां

- पेट्रोल पम्प, तरल पेट्रोलियम ग्रैस (बाना पकाने की ग्रैस) एस० के० झो० एस० बी० घो० को श्री एजेन्सियां निम्नलिखित घाघार पर देशी :—
  - (i) अनुसूचित जाति।अनुसूचित जनजाति के के लोगों को 25 प्रतिशत ;
  - (ii) शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 2 प्रतिकृत ; भीर
  - (iii) भेष को वाणिज्यिक शाधार पर, जिन में वास्तविक उपभोक्ता सरकारी सोसाइटियों भीर कृषि उद्योग निगमों को प्राथमिकता दी जारही है !

दिनांक 15-5-1978 को लोक सभा में बिये गये विवरण के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों में तेल कम्पनियों हारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति में संबंधित लोगों के लिए 87 में से 24 नयी कृकिंग ग्रैस की वितरण एजेंसियां खोली जायेंगी। इस 24 स्थानों में मेरठ, देहरादून और आगरा को शामिल नहीं किया गया है।

(घ) देहराडून और प्रागरा में वितरण एजेंसी के लिए प्रावेदन पत्नों को मंगाने के लिए प्रेम विज्ञापन प्रभी हाल ही में प्रकाणित किए गए हैं पीर खावेदन पत्नी होण करने की प्रान्तम तारीख प्रभी समाप्त नहीं हुई है । इसलिए कुल कितने प्रावेदन पत्न प्राप्त हुए इस संबंध में इतना शीध बताना कठिन होगा । साधारणतः चयन करने और नियुक्ति के संबंध में पत्न जारी करने में 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं।

# Paying of rent by I.D.P.L.

4782. SHRI KACHARULAL HEM-RAJ JAIN: Willthe Minister of PETRO-LEUM. CHEMICALS AND FERTI-LIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that I.D.P.L. is pay...g rent 20 per cent more to the land-lords in addition to that a penalty of Rs. 45,000 has been imposed by D.D.A.; and
- (b) if so, the reasons therefor and whether it is proposed to inquire into the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited have been paying 20% of the rent per month as composition fee to Delhi Development Authority only with effect from 1-7-1977. They deposited with Delhi Development Authority a sum of Rs. 40,000 as security money which has since been adjusted against the composition fee due.

(b) This arrangement was entered into with the Delhi Development Authority

as shifting to alternative accommodation would have proved more costly, apart from the fact that suitable alternative accommodation was just not available. The Company propose to shift to their own office building, which is under construction.

# मेहराना रेलने रकेकन के होनों कोर माले का होना 4783. भी नोतीकाई बार0 चौघरी : क्या केस मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

- (क) क्या मेहसाना रेलवे स्टेशन से मेहसाना
   कस्वे तक स्टेशन के दोनों झोर रेलवे के नाले हैं;
- (क) क्या ये नाले बहुत छोटे हैं और अपेक्षित कौंकाई क न होने के कारण वहां पर प्रायः दुर्घटनायें होती हैं और क्या हाल ही की एक दुर्घटना में दां व्यक्ति मारे गये ये और क्या इस कारण मेहसाना नगर-पालिका ने इन नालों को बौड़ा करने के बार में मांग प्रस्तुत की है; और
- (ग) यदि हां, तो क्या इस प्रपरिहार्य मांव को पूरा किये जाने का प्रस्ताव है ; यदि हां तो कब भीर यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

रेल बंबालय में राज्य मजी (श्री शिव नारायण): (क) मेहसाना यार्व में दो रेल पुल (नं० 962 और 963) हैं। इनका निर्माण केवल स्थानीय नालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था न कि निचले सडक पुल के रुप में उपयोग के लिए।

- (ख) नालों के बहाब के प्रयोजन के लिए इन पुलों की बौड़ाई पर्याप्त है। इन पुलों के नीचे यातायात के कारण युष्टनाझों की रेलों को आनकारी नहीं है। इन पुलों को चौड़ा करने के लिए सेहमाना नगरपालिका ने रेल विभाग के लाए सेहमाना नगरपालिका ने रेल विभाग के साथ कोई पत-व्यवहार नहीं किया है।
  - (ग) प्रक्न नहीं उठना ।

# Composition of Board of Directors of Khandelwal Ferro Alloys Limited

4784. SHRI M.A. HANNAN ALHAJ: Willthe Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) what is the composition of Board of Directors of the Khandelwal Ferro Alloys Limited, Bombay, and the names of its allied units;
- (b) whether there are reports of mismanagement in this group of companies and its directors are drawing heavy salaries and perquisites; if so, full details thereof; and
- (c) what action Government have taken to check mismanagement in this group of companies and whether any inquiry has been made thereinto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) The composition of Board of Directors of M/s. Khandelwal Ferro Alloys Limited, Bombay as

per the annual return of the company made upto 13-4-1978 is as under: ---

- (i) Shri Madan Mohan R. Ruia, Chairman.
- (ii) Shri K.R.K. Menon
- (iii) Shri Jasvantlal Matubhai
- (iv) Shri K. Sadagopan
- (v) Shri Shreenath R. Khandelwal
- (li) Shri Premnath R. Khandelwal
- (vii) Shri O.K. Shah
- (viii) Shri L.N. Jadhvani (Nominated by IFC of India).

According to the Annual Report for the Year 1977, the company has got two units namely,

- (i) FERRO MANGANESE UNIT
- (ii) TUBE MILL UNIT
- (b) Certain complaints were received from a shareholder of the company making allegations regarding (i) the management set up of the company since the abolition of the Managing Agency system, (ii) drawal of excess perquisites by the Directors and (iii) sale of steel tubes to Khandelwal Private Limited to derive substantial profits for Khandelwal Directors.
- (c) Enquiries were made into these allegations and it was found that there was no substance in these allegations.

# Removal of Chairman and Director of Belapur Sugar and Allied Industries

4785. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of LAW JUS-TICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether his attention has been drawn to the news published in the Financial Express of 27th June, 1978, regarding resolution for the removal of the Chairman and Director of Belapur Sugar and Allied Industries;
- (b) if so, whether there is any pressure direct or indirect on the Government for changing the management; and
- (c) what are the views of Government on the existing management which is nominated by the Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN). (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) S/Shri H. B. Dhondy and R.R. Desai were appointed as Government Directors under section 408 of the Companies, 1956 for a period of two years with effect from 28-3-1973 and their tenure expired on 27-3-1975. There are no Government nominated Directors on the Board of the company after 27-3-1975.

# Memorandum from Employees Union of Eastern Gas Power Company and its Associated Concerns.

4786. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of PETROLEUM CHEM-ICALS AND FERTILIZERS as pleased to

(a) whether Government have received a memorandum from the Eastern Gas "Power Company and its associated concern's employees union expressing apprehension, the sizeable section of the employees may be rendered surplus and retrenched as a result of the Courre's reported decision for restructuring of the present system of distributorship;

(b) if so, whether Government have taken steps to alleviate the fear expressed by the employees' union; and

# (c) the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM ANDICHEMICALS ANDFERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): As already indicated in the Statement made in the Lok Sabha on 15-5-1978, restructuring of the cooking gas distributorships has been decided upon to ensure that such distributorships do not become or continue to be too big and thus deprive others from the opportunity of running such distributorships. While the restructuring may result in certain employees being rendered surplus at certain points, it may at the same time generate better employment opportunities at the new points. Oil companies may also persuade the new distributors to explore the possibility of engaging employees retrenched by big distributors.

# Shifting of Main Office of Bongaigaon Rafinery Petro-Chemicals Ltd

4787. SHRI PURNANARAYAN SINHA: Will the Minister of PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS be Pleased to state:

(a) if it is a fact that Chairman and Managing Director, Bongaigaon Refinery and Petro-Chemicals Limited promised to shift the main office of Project to Bon-

gaigaon while answering to some agitators in Assam;

- (b) is it afact that the office of the undertaking has failed to implement his promise and he still maintains his office in New Delhi and still following the policy of denying employment to local people in employment and allotment of contracts;
- (c) if so, action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c): The Managing Director had promised to shift his office to Bongaigaon by the 1st June, 1978, and his office has been shifted to Bongaigaon with effect from 1st June, 1978.

The company is having at present a liaison office and some other staff in New Delhi. The purpose of having this office is to maintain contact with the company's consultants, whose head offices are located in Delhi, and also the administrative Ministry.

The employment policy of the Company is governed by the Government's guide-lines issued from time to time.

Contracts are awarded by the Company on the hasis of tenders and strictly in accordance with the normal tender procedures.

# न्यायालयों भौर ग्रम्य स्थानों पर नियुक्त एडबोकेट

4788. श्री हुकम वेष नारायण यादव : क्या विक्रि म्वाय और कम्यमी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों, प्रावि-वास्त्रीयों, महिलाकों, मुसलमानों और पिछड़े बता के कितने एडवोकेटों को न्यायालयों , प्रायोगों अथवा प्रन्य विभागों में नियुक्ति की और जनन्यायालयों, प्रायोगों अथवा प्रन्य विभागों के नाम क्या है जिन में उन की नियुक्ति की गई और सरकार ने कृत कितने एडवोकेटों की नियुक्ति की गई और सरकार ने कृत कितने एडवोकेटों की नियुक्ति की ?

विधि, न्याय और कम्यनी कार्य संस्ती (भी शांति भूवण): जानकारी इकट्टी की जा रही है स्त्रीर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

# मई, 1974 की हड़ताल के परचास राजपनित पर्वो का बनाया जाना

4789. भी हरगोविन्य वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा क रेंग्रे कि:

(क) मर्ड, 1974 की रेलवे हड़नाल के पश्चात् कितने राजपित पद बनाये गये और कितने राज-पित प्रधिकारियों को पदोक्षत किया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उच्च बेतन मान वियो गयेथे:

Written Answers

- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार 1974 से पहले की स्थित बहाल करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी;
- (घ) यदि हां, तो कब भीर यदि नहीं, तो इसके क्या कोरण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (घ). बढ़े हुए कार्य भार को सम्भातन ग्रीर निसान्त अल्पकालिक निर्माण कार्य के लिए 1974 की रेल हडताल के बाद भाज नक विभिन्न क्षेत्रीय 1265 राजपत्रित पद सुजित रेलों पर लगभग ऐसे कई पद उस काम के परा होने पर कियेगये। जिस के लिए वे पद स्वीजत किये गये थे, बाद में, अभ्यपित कर दिये गये । इस अवधि के दौरान नियमित श्रंखलाबद्ध प्रबन्धों के परिणामस्वरूप, (लगभग. 1947 भ्राधिकारी उच्चत्तर ग्रेडों में पदोन्नत किये गर्थ भीर वे उपयक्त वेतनमानी में सामान्य नियमों के प्रधीन । चाव ऐसा हडनाल लगा दिये गये नहीं किया गया था, उसलिए हड़नाल को बहाल करने का प्रश्न ही नहीं की स्थिति उरता

# Permission letters issued to Drug Units without Seal of the Ministry

4790. SHRI UGRASEN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state;

- (a) whether it is a fact that Industrial licences, their clarifications and other letters issued under I (D & R) Act possess the seal of the issuing Ministry;
- (b) whether it is a fact that Permission Letters which were granted to drug manufacturing units don't possess any seal and were issued by officers in excess of their powers, violating provisions of I (D & R) Act and rules made thereunder: give details of officers involved in the issue of Permission letters; details of permission letters issued product wise, whether before issuing each and every such Permission Letter, application for industrial licence was received or not; and
- (c) how many applications of Indian firms for such formulations were rejected at the same time: details of such applications and reasons for rejection?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTI-LIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) All Industrial Licences issued under the Industries (Development & Regulation) Act or any amendments made to the Industrial Licence under this Act bear the Seal of the Ministry of Industry.

(b) Consequent on the coming into force of the I (D&R) Act in 1951, firms which were in existence before the Act came into force were entitled to Registration under the Act for their existing range of production as well as such items where the parties had taken effective steps to manufacture

Various Companies approached the Govt. from time to time subsequently, seeking authorisation for the manufacture of articles which could be produced by them without adding to their existing plant and machinery. The Licensing Committee at their meeting held on 23-11-1953 examined this issue in the context of the implications of the term "new article" and held that a broad view of the definition of "new article" was reasonable and should be taken. The Committee felt that, where no new Trade Mark or new Patent was involved and the product was covered within the ambit of the same item in Schedule I of the I 'D & R) Act, 10% for which the concerned company held a Registration/Industrial approvals, then such product would not be a "new article" and there should be no objection to the Company manufacturing it.

Based on this decision, and with a view to enabling Companies already holding valid authorisation to fully utilise the existing machinery, without adding to either royalty burden or plant and machinery or seeking any additional concessions for import of raw materials in relaxation of the general import policy. Permission Letters were issued to such Companies.

Generally, these letters were issued without any seal of the issuing Ministry because they were in the nature of a clarification as to the meaning of 'new article" and elaborated the authorisations for manufacture available to the party, namely, Registration Certificates and Licence, thereby explaining to them that they were authorised to manufacture these additional items without a separate licence, previded the following 4 main conditions were satisfied:

- (i) No additional plant and machinery will be required for the purpose;
  - (ii) No royalty will be payable;
- (iii) The products would be marketed under trade marks already in use and no new patent was involved.
- (iv) No special concession in regard to the import of basic raw materials and ingredients would be made in relaxation of the general Import Policy in force from time to time.

Details of Permission Letters are furnished in Annexure II of Chapter V of the Hathi Committee Report, which has already been laid on the Table of the House.

Written Answers

(c) Since the Permission Letters were issued in the fifties, it is not possible to state if Indian Companies had been refused the manufacture of any such item covered by Permission Letters issued to Foreign Companies.

# Reduction in cost of production of Fertilizers

4791. DR. SAROJINI MAHISHI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) in view of the fact that more than Rs. 50 crores are given by way of subsidies to indigenous phosphatic fertilizers, what concrete steps are being taken by Government to reduce the cost of production of these fertilizers; and
- (b) what is the total quantity of phosphatic fertilizers imported in the past three years?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA); (a) About 60 to 70 per cent of the cost of production of phosphatic fertilizers is accounted for by the cost of basic inputs like imported phosphatic acid, rock-phosphate, bulk of which is imported, and potash and sulphur, both of which are also imported. As the inputs are mainly imported, we have little control over their cost. However, it has been the constant endeavour of Government to reduce the cost of production and make fertilizers available to the farmers at reasonable prices. With this in view, measures such as reduction in import duty on phosphoric acid, reduction in excise duty on super-phosphate and reduction in the price of imported potash were taken in the past in order to reduce the cost of production and thereby, he price to the farmers. Since, however, these measures were not adequate to bring about significant reduction in the prices of phosphatic fertilizers, the scheme of price support was introduced with a view to bringing down the prices.

(b) The quantity of imports of phosphatic fertilizers in terms of nutrient is furnished below:—

Year	.g.ca.Newser.gev	Quantity in lakh tonnes of P 205			onnes of
1975-76 1976-77 1977-78	,				3.37
1976-77					0.23
1977-78			•		1 64

#### Lay off in M/s. Dharanghdra Chemical Works and M/s. Plastics Resins Limited, Sahupuram Arumuganeri and Tirunelyeli

4792. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there was lay off in Messrs Dharonghdra Chemicals Works, Sahupuran and Messrs Plastics Resins Limited, Sahupuram, Arumuganeri Tirenelveli District Tamilnadu State during the current year as
  - (b) if so, what is the reason therefor;
- (c) whether Government are aware that a number of small scale industries depending upon the raw material Resins, will be affected if M/s. Plastics Resins were to stop production; and
- (d) if so, whether the Government would take over the management of this Unit in the interest of the small scale industries or whether the alternative entrust the management with its sister Unit viz., Dharanghdra Chemical Works Ltd.. Sahupuram for its management?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) (a) and (b). There was no lay off in M/s. Dharanghdra Chemicals Works during the current year or during the last year. M/s. Plastic Resins and Chemicals Limited was closed from 11th November to 24th November, '77 and during this period the workers were laid off. The factory again closed down on 15th February, 78 due to uneconomic operations and the lay off of the workers continues since then.

(c) and (d) . The problems of this Company were discussed in an inter-Ministerial Meeting and the matter is under examination.

In the meantime, import of PVC resins is being allowed to meet the gap between the demand and the indigenous availability.

### Sale of Non-Canalised bulk drugs to-IDPL on high-sea basis

4793. SHRI RAMJILAL SUMAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) details of non-canalised bulk drugs sold to IDPL on high-sea basis during the last three years, year-wise;
- (b) under what authority were these high-sea sales were also effected in favour of any other authority; if so, detailsthereof; if not, why; and

(c) whether for allowing high-sea sales and making delivery of non-canalised bulk drugs it was ascertained that IDPL hold necessary in lependent licence for manufacture of formulations covered; if not, under what authority were non-canalised items released to IDPL on high-sea basis?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Details of non-canalised bulk drugs sold by CPC to IDPL on high sea sales basis during the last three years are indicated below:

	1975-76	1976-77	1977-78
Vitamin A		7 · 1 75	MMU
Procaine			
Penicillin		3000 BU (By air)	tono BU

(b) The import of Vit. A which was a banned item for import during 1976-77, was authorised at the instance of Ministry of Health and Family Welfare in favour of IDPL to meet a specific requirement in respect of the Family Planning Programme. This import was necessitated due to shortage of this drug in the indigenous market and it was an ad hoc arrangement.

As regards Procaine Penicillin the material was imported by CPC to meet IDPL's requirements for an export order from Afghanistan and the import was authorised against an advance licence issued in favour of IDPL by the Office of CCI&E.

In the case of canalised raw materials, IDPL share with CPC the responsibility for distribution of such raw materials and in this capacity take delivery of materials on high sea sales basis from the latter. On the same analogy, in the instant cases also, the material was transferred on high sea sales basis by the CPC.

If the reference in the words 'any other authority' is to an 'Actual User', the Ministry has no knowledge whether arry other actual user made a sim lar request to CPC for supply of non-canalised traw materials on high sea sales basis.

(c) No, Sir. The basis on which noncanalised items were released to IDPL on high sea sales basis, has been explained in (b) above.

# Cost price of urea

- 4794. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) what is the present units cost price of urea produced in the country; and
- (b) what is the present unit cost price of urea which is being imported from aborad and the reasons for the difference in costs?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA). (a) and (b). The cost of production of urea in the country varies from plant to plant depending upon such factors as the capital cost, feedstock used, vintage, process adopted, location, cost of utilities etc. The price of imported urea does not depend on its cost of production in the exporting countries but on the international market forces. Data in respect of the cost of production of urea in other countries is not available in a form that makes comparison with the cost of production of indigenous urea possible.

# Money collected by Ms. Bharat (P) Ltd. from Cement Stockists

4795. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of LAW. JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a huge amount have been collected by M/s. Bharat (P) Ltd. from the Germent Stockists in the form of advances security loans, etc. and misappropriated; and
- (b) if so, what action has been taken by Government against the Ex-Exective Directors of the Company?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) (a) and (b). Presumably the question refers to M/s. Bharat Overseas Private Limited This company was acting as sole selling agents of M/s. Jaipur Udyog Limited, and had taken large sums of money from cement dealers. The precise position in this regard is not known, since the company has not filed any balance sheet after March 31, 1974.

Due to complaints received about nonsupply of cement and/or non-refund of the advances, action is being taken to conduct an inspection of the books of accounts etc., of the company under section 209A of the Companies Act. 1956 to get a clear idea of the irregularities committed, if any, and to take such action as may be called for.

# बील बड़े धौद्योगिक गृहों के परिसमापन का समाचार

4796. श्री जगवीश प्रसाद माणुर : क्या विधि, ज्याय ग्रीर कम्यमी कार्य मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का घ्यान 8 जून, के 'दि इण्डियन एक्सप्रैम' में "गवनेमेंट घार डिटरमिण्ड टूलिक्बिडेट 20 बिग हाउसिज" शीर्षक में प्रका-जित समावार की ग्रोर दिलाया गया है; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो इस बारे में ग्रव तक क्या कार्यवाही की गई है ?

# विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति वृक्षण): (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद में रखें गये छोडोगिक नीनि विवरण में मरकार ने बड़े गुहों के सम्बन्ध में प्रपानी पहुंच की म्मण्ट घोषणा की हैं। इस निति को, लाइसेंग नीति की सीमा प्रीर एकाधि-कर एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा प्रधिनियम का बुढ़ता से लागू करने के रूप में कियानिवन किया जा रहा है। सरकार ने कुछों के हाथों में प्राधिक क्षत्ति संकेदण पर विस्तीण एवं क्लिएट प्रमान पर छाते विचार किया है गौर इस प्रकार के संकेप्टम को प्रभावी रूप से समाप्त करने के प्रस्तावों की प्रभी परीक्षा की जा रही है।

### Drug to control Tuberculosis

4797. SHRI AMRSINH V. RATHAWA: SHRI SUKHENDRA SINGH:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar has achieved a break-through in preparing a drug from a seaweed to control tuberculosis;
- (b) if so, the progressive results achieved so far in this direction; and
- (c) the time by which the drug is likely to be put in commercial production?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

# मायुर्वेदिक ग्रीवधि कारखानों की स्थापना

- 4798- भी लक्ष्मीनारायण मायक : क्या पेट्रोलियम, रत्यायन भीर उर्वरक मंत्री यह बनाने की कृपा करेंग्रे कि :
- (क) देश में राज्यवार उन स्थानों का स्थीरा क्या है जहां मरकारी सायुर्वेदिक स्रीविध कारखानें हैं:
- (ख) श्रायुर्वेदिक श्रीयधि के उपयोग को बढ़ाबा बेने की दृष्टि में वर्तमान जनना पार्टी सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद भव तक कितने नये भ्रायुर्वेदिक भ्रीयधि कारखाने स्थापित किये हैं भ्रीर उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे कारखाने स्थापित किये गये हैं; भीर
- (ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में ऐसे कारखान की स्थापना करने की है जहां प्रभर-कष्टक भीर भन्य जंगनी जड़ी बूटियां बहुतायत से उपलब्ध हैं?

वेद्रोलियम तथा रसायन धौर उर्धरक मंत्री (धौ हेमबती नस्वन बहुगुचा). (क) से (ग): स्वास्थ्य धौर परिवार कत्याण मंत्रालय ने बताया है कि धर्पक्षित मूचना उसके द्वारा एकत की जा रही है धौर सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेग्री।

# Request for shifting of Mathura Refinery

4799. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether twelve eminent personalities of the country have written to him requesting him to intervene and shift the site of Mathura Refinery to a less risky site to save Taj Mahal and Agra city from pollution; and
- (b) if so, what action he proposes to take in the matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA); (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

# Appointment of Managing Director of Jeypore Sugar Company Orissa

4800. SHRI M.R. LAKSHMI NAR-AYANAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the answer given to Starred Question No. 1017 on 8th May, 1978 regarding Jeypore Sugar Co. Ltd. and state:

(a) whether the Jeypore Sugar Company Orissa, has now made an application for ·QI

- (b) whether it is true that the Management of Jeypore Sugar Company consisting of one family also is in the management of K.C.P. Ltd., Madras; if so, what are the family members; and
- (c) whether it is a fact that representations were made by shareholders of K.C.P. Limited more than a year ago for appointing Government Directors; it so, what action; has been taken so far on these representations?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI) SHANTI BHUSHAN: (a) Ye, Sir. The proposal of the company for the reappointment of Strimati RAJESHWARI RAMAKRISHNAN as the Managing Director of the company for a period of five years with effect from 3-9-1977 on her existing remuneration has since been received, and is under consideration.

- (b) The following five directors of the Jeypore Sugar Company Limited are also the directors of M/s. K.C.P. Ltd.
  - (i) Shri V.L. Dutt (Managing Director)
  - (ii) Mrs. V.R. Dhurgambal
  - (iii) Shri M.A. Krishnamachari
  - (iv) Shri R. Prabhu
  - (v) Shri P.R. Ramakrishnan
- (c) A representation from Shri K. Rajendra Chowdhary, Advocate has been received on behalf of some shareholders of the company for the appointment of Government Directors on the Board of M/s, K.C.P. Ltd. The same is underconsideration of the Government.

#### Selection of Station Masters

48or, SHRI RAM PRAKASH TRI-PATHI :

SHRI DAYA RAM SHAKYA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that All India Station Masters Association, Delhi Division boycotted selection of Station Masters Grade Rs. 455-700 on 11th June, 1978 and 16th July, 1978;
- (b) whether the boycott was due to serious allegations of anomalies and favouritism in the oral test which have been totally ignored by the administration of Delhi December 1, time;

- (c) whether the same procedure of selection in Grade Rs, 455-700 for S. Ms. and A.SMs is held in All Railways, if not, the reason thereof; and
- (d) what action the Railway administration took for the favouritism given to juniormost persons under the cover of emergency?
- THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes,
  - (b) No.
- $(\epsilon)$  Yes; the post of ASMs/SMs in grade Rs. 455-700 (RS) are selection posts on all Indian Railways.
  - (d) Does not arise.

# शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलके

4802. श्री कैलाश प्रकाश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) शाहदरा--महारनपुर लाउट रेलवे के स्थान पर बड़ी रेल लाइन बनान की योजना कब तक परी ही जायेगी;
- (ख) इसके निर्माण के लिये तथा वाणिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, ग्रीर
- (ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस समय रेल याता की वो मुनिधायें उपलब्ध नहीं हैं जो पहले उपलब्ध थी, निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये कोई योजना बनाई गई; है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):
(क) से (ग). शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन को पूरा करने के काम को पहले ही उच्च प्राथमिकता की गयी है। शाहदरा से बागपत रोड तक का खंड यातायान के लिए खोला भी जा कृता है। बागपत रोड से शामली तक के प्राणे चरण को चालू वर्ष में भीर सम्पूर्ण परियोजना को मार्च, 1980 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश में ग्रीवय तथा रसायन संयंत की स्थापना

4803. भी मुखेन्द्र सिंह: नया पेट्टोलियम, रतायन ग्रीर उर्वरक मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार निकट मविष्य में मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में ग्रौषध तथा रसायन संयंत्र स्थापित करने का है ; ग्रौर
  - (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमबसी नम्बन बहुगुजा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में एक संयुक्त क्षेत्रीय फार्म्लेशन एकक स्थापित कर के लिये इंडियन इन्स एण्ड फार्मास्यिटकरूस लिए एक सरकारी उपक्रम तकनीकी भाषिक संयाब्यता रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

93

निम्नलिखित मदों का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुधा जिले में मेघानगर नामक स्थान पर एक नया एकक स्थापिन करने के लिये मैससे एम पी एयो मोगरजी फॉटलाइजर्स लि० को मार्च, 1978 में एक झाणय पत्न जारी किया गर्यों है।

- (i) सल्फूयरिक एसिड 1,40,000 टन प्रतिवर्ष
- (ii) फास्फोरिक एसिंड 50,000 टन प्रतिवर्ष
- (iii) मोनो एमोनियम फारफेट 73,600 टन प्रनिवर्ष इस प्रायोजना को एम० पीठ एयी इन्डस्ट्रीज इक्तपमेंट कारपोरंगन द्वारा सैमर्स धर्मसी सोरारजी केमीकल्स कम्पनी के सहयोग में संयुक्त क्षेत्र में स्थापिन क्रिया जारहा है।

# निम्न भेणी लिपिकों की वरिष्ठता-सूची

- 4804 श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: नया रेल शंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह मच है कि रेलवे बोर्ड के महायकों भीर उच्च श्रेणी लिपिकों की बरिष्ठता सूचिया तैयार की गई है:
- (ख) रेलवे बोर्ड के निम्न श्रेणी लिपिकों की विरिष्ठना मूची पिछली बार किस वर्ष तैयार की गई बी:
- (ग) यदि नही, तो निम्न श्रेणी लिपिकों की वीरष्ठता-सूची भव तक तैयार न किये जाने के क्या कारण है; भौर
- (घ) यह सूची कब तक तैयार होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण): (क) जी हां।

- (毒) 1978
- (ग) भौर (घ). प्रश्न नहीं उठता

# Inclusion of Representatives of RPF in Staff Council

1805. SHRI DAYA RAM SHAK-YA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1327 on 25th July, 1978 regarding All India RPF Association and state:

(a) whether representatives of the All India R.P.F. Association will also be included in the Staff Council (Karamchari Paridiad) and if so, the number thereof; and (b) the justification for including a representative and C.S.O. of the Zonal Railway Protection Force Association in the Staff Council when the Zonal Railway Protection Force Association is recognised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

- (b) The presence of Chief Security Officer on Staff Council is considered necessary on account of the following:—
- (1) Chief Security Officer is the head of the Force on the Zonal Railway as such is conversant with the various problems of the Force. (2) Zonal Railways' Associations do not represent the entire Force and as such the CSO's presence will take care of the interest of the other staff who are not members of the Association. (3) The attendance of CSO will help ultimately to accelerate the follow-up on decisions taken which is in the ultimate interest of the Railway Properties.

# यमुना-पार श्रेत्र के निवासियों के लिए परिवहन सुविधाओं में सुधार की योजना

4806. श्री फूल चन्द वर्माः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्यायमुनापार क्षेत्र के लाखों निवासियों के लिए परिवटन जन मुख्याओं में मुख्यर की उन के संखालय की कोई योजना हैं। भीर
- (ख) क्यायानायान की भीड़ और कठिनाडयों को देखतहुए सरकार हापड़-णटल गाड़ी को नई दिल्ली की स्रोर मोड़ने का प्रयास करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):
(क) नयी दिल्ली दिल्ली धीर गाजियाबाद के बीच यात्रा करने के लिए बहुत सी गाड़ियां उपलब्ध हैं। मार्ग-वर्ती लाइन क्षमता पर प्रत्यक्षित दबाव होने तथा दिल्ली/नयी दिल्ली में प्रपर्थान्त टीमनल मुविधाओं के कारण कोई मीतरिक्त गाड़ी बलाना परिचालनिक दूरिन्ट से व्यावहारिक नहीं हैं।

(ख) । एत० एच० के० घटल गाड़ी दिल्ली बाहदरा, दिल्ली तथा नयी दिल्ली के रास्ते खुर्जा। हापुड़ धौर हजरत तिजामुद्दांन के बीच पहले से ही चल रही है और इस गाड़ी का मार्ग बदनकर, दिल्ली धादि का परिहार करते हुए, तथे यमुना पुल, तिलक क्रिजा के रास्ते चलाये आने की इस गाड़ी के वर्तमान जययोगकर्ता पसन्द नहीं करेंगे।

# Broad Gauge Line from Guntakal to Hospet

4807. SHRIP. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the broad gauge line from Guntakal to Hespet is in

Guntakal Division and metre gauge track from Guntakal to Hospet is in Hubli Division:

- (b) whether it is a fact that there are administrative difficulties and waste of man-power in regard to inspection of track and other assets; and
- (c) in view of the above facts whether Government are willing to transfer the metre gauge line also to Guntakal Division?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes, The Broad Gauge line from Guntakal to Hospet falls in Guntakal Division and the metre gauge line from Guntakal (excluding) to Hospet in Hubli Division of South Central Railway,

(b) and (c). No specific administrative or operational difficulties and waste of manpower in regard to the inspection of track and other assets have so far come to light, arising out of the existing arrangement. As such the question of transfer of the section from Hubli to Guntakal Division is not under consideration of this Ministry.

# Transfer of Name in respect of L.P.G. Connection of Indian Oil

4808. SHRI R.I.P. VERMA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that L.P.G, conpections of Indian Oil cannot be transfered from the name of a dependent father or his son; and if so, the reasons therefor;
- (b) whether Government have received such requests for transfer and if so, the action taken by Government in this behalf;
- (c) whether Government will ronsider transfer of gas connections from dependent parents over 60 years of age; and
- (d) what is the procedure for transfer of a gas connection to the next of kins in case of death of parents?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) to (d). As per present practice, normally gas connections are non-transferrable. The Indian Oil Corporation has no system of transferring a gas connection from one name to another. However, in exceptional circumstances involving death etc., as and when a connection has to be transferred at the request of a close blood gelation, at the Corporation's instance, IOC's distributor first prepares a Termination

Voucher in the name of orginal su treriver and then issues a new gas connection in lieu of the said Termination Voucher (with a changed name). In such cases, security deposit for the gas cylinder and pressure regulator is collected at the prevailing fates.

During the period from 1-1-78 to 31-7-78 no such request was received in this Ministry.

# नवा में शोकत रेसपाड़ी

4809: **जी ईंग्जर जीकरी : क्या रेज संती** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मंत्रालय को पता है कि शया (बिहार)
   में मोकन रेन गाडी में बहुत चिक्र चीड़ रहती है;
- (ए) क्या सरकार को यहा के सोगो में इस्सा बारे में किकायन मिसी है;
- (ग) स्था सरकार का विचार दिस्ती-हावडा का समय बढुने धीर उसका मार्ग सवा से होकर कसाने का है ; धीर
- (व) स्था मरकार का विकार धामनकोल जाने वाली विल्ला एक्सप्रैम का मार्व मया से होकर करने का है

रैण संसालय में राज्य संसी (भी सिथ साराज्य): (क) पटना-नया सम्य पर मानने वाली समारी नाड़ियों में कुछ भीड़ -भाड़ देखी नवी है ।

(वा) भी हा।

(न) मीर (म). जी, नहीं ।

#### Acromognetic Survey of Mahazondi Basin

4819. SHRI JANARDHANA FOOJARY: Will the Minister of PETROLEUM. CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether the Aeromagnetic Survey of Mahanandi Basin has been completed; and
  - (b) if so, the results thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir.

(b) The results will be known after the data is analyzed by the National Geophysical Research Institute of India at their laboratory and research or true at Hyderabad.

# मालगाड़ियों द्वारा ले जाये गये ढोरों की संख्या

4811. श्री चन्द्रशेखर सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा क रेंगे कि :

- (क) गत एक वर्ष के दौरान माल गाड़ियों द्वारा कितने ढोरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया और उन से कितनी आयहुई
- (ख) क्या उन को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सम्बन्धित अधिकारी इन ढोरों को ले जाने के लिए 50 रुपए प्रति वैगन के हिसाब से ग्रतिरिक्त धन-राशि ले रहे हैं ; ग्रौर
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने नया कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) रेल द्वारा ढोये गये मवेशियों की संख्या के **भां**कड़े नहीं रखे जाते हैं। लेकिन, वर्ष 1977-78 केदौरान भारतीय रेलों की बड़ी लाइन, मीटर लाइन श्रीर छोटी लाइन के स्टेशनों से चौपहियों के हिसाब से 98,848 माल डिब्बों में मवेशी लादे गये थे । यद्यपि लेखों को ग्रंतिम रूप दिया जाना है, ग्रभी शेष है! फिर भी उन से 6.85 करोड रुपये की ग्रामदनी (ग्रनन्तिम) होने का ग्रनमान है।

- ं (ख) जी नहीं।
  - (ग) प्रश्न नहीं उठता

# Bogies and Buses set on fire in Marathawada

4812. SHRI AMAR ROYPRADHANS

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that some rail bogies and buses were set on fire in Marathwada on the 27th July, 1978; and
- (b) if so, what are the details in this regard and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS NARAIN : (a) and (b): The violent agitation launched in the Marathwada region affected the Railways from 28th July, 1978 onwards and as such there was no incident of burning of bogies on the 27th July, 1978. There were 4 instances of arson—all on 28th July, 1978 involving 11 coaches in all. Out of 11 coaches 9 were completely burnt and two slightly burnt, Two cases as Crime No. 36 & 37/78 of GRP/Jalana u/s. 147/148/149/ 426,323-324-336-337-427-431 IPC read with Section 127 and 128 IRA were registered in connection with the incident which took place at Sailu Railway Station where 7 bogies were burnt. In another in sident which took place at Boker Railway

Station, involving 3 coaches, GRP/ Purna registered a case under crime No. B-44/78 u/s. 100-B, IRA, Similarly, in another incident which took place at Chudawa Railway Station involving coach, GRP/Purna registered case under Crime No. B-40/78 u/s. 100-B IRA. 26 agitators were arrested.

The information regarding burning of buses in Marathwada region is not available.

# Statewise Production of Crude Oil, Chemicals and Fertilizers

4813. SHRI AHSAN JAFRI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) what is the State-wise production of crude oil, chemicals and fertilizers in India during the last three years;
- (b) what is the State-wise refining capacity; and
- (c) whether Gujarat is getting its due share in the allocation of funds and other benefits?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZ-ERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) and (b): A statement giving information in respect of production of crude oil and refining capacity is attached. Information regarding chemicals and fertilizers is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(c) Allocation of funds to projects in various States including Gujarat is made according to the Annual Plans.

# Statement

'ooo' Tonnes

			000	Tomics
ion	Oil	1975	1976	1977
		4189	4267	4510
		4094	4164	4237
		Nil	228	1438
I		8283	8659	10185
		ion	4189 4094 Nil	4189 4267 4094 4164 Nil 228

99

Refini	ng Ca	apaci	ty	Mn. T	onnes j um	per Ann-
Andhra	Prad	esh				1.55
Assam			•			1.25
Bihar						3.30
Gujarat					•	4.30
Kerala						3.30
Maharas	h tra					8.75
Tamil N	adu					2.20
West Be	ngal					2.20
	Т	otal				27.45

### Raids on Petrol pumps for adulteration in North India

4814. SHRI RAGHBIR SINGH: Will the Minister of PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government of India conducted any raids on the Petrol Pumps in Northern India during the last three years;
- (b) if so, the names of such Petrol Pumps on which raids were made for adulteration of Petrol and Diesel;
- (c) the names of petrol pumps whose petrol and diesel was found adulterated; and
- (d) whether an y action was taken against them and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):

(a) to (d): No raids have been conducted by the Government of India on petrol pumps in Northern India during the last three years.

State Governments have been requested to ensure periodical sample checks of petrol sold from retail outlets (petrol pumps) and take appropriate action against those indulging in adulteration.

According to the information available with this Ministry, in the case of two retail outlets (petrol pumps) of Hindustan Petroleum Corporation Limited (Viaskh Marketing Unit), raids were carried out during May' 78 by the State Governments'

Civil Supplies Authorities. The details thereof are as under:—

- (i) At M/s. Modern Auto, Lucknow: The raid was based on a complaint of a scooterist. Petrol sample was drawn by the Civil Supplies Department, but, so far, no advice has been received by the oil company from them regarding adulteration of the oil company had carried out the filter-paper test at the site and he did not find evidence of adulteration.
- (ii) At Lakshmi Motors, Jaipur: Petrol sample was drawn by the District Supply Officer, Jaipur, on the basis of a complaint by a scooterist. The oil company has tested a sample of the product which was found to be on specification.

Pending receipt of advice from the concerned State Authorities no action has been taken by the oil company in these two cases. Besides, the above two cases, in one case at Ballabhagarh (Harvana) a retail outlet of Bharat Petroleum Corposition Ltd., (BPC) Petroleum Corpoation owned by M/s. Tara Ghand Saluja & Sons, was inspected by the Police on recript of complaint about the alleged adulteration of petrol and high speed diesel oil. As per BPC's report, the analysis showed that while the high speed diesel samples were found to be on specifications, the petrol samples failed on two counts namely, octane number and the final boiling point. The petrol appeared to be contaminated to the extent of approximately 10% with product like kerosene and mineral turpentine oil. BPC had conveyed the test reports to the Police authorities and simultaneously wrote to the dealer asking for his explanation. The dealer had replied saying that no adulteration had taken place at his site. As further investigations in this regard are being carried out both by the oil company and the Police authorities the question of taking action against the dealer, at this stage, does not arise.

#### Study group on salary structureof executives of Private sector

4815. SHRI SARATKAR: ND the Minister of LAW, JUSTICEd to COMPANY AFFAIRS be pl' state:

- (a) whether Government have price and study Group of ranking and fat look into the salary structes of private perquisites of the top execut sector companies;
- (b) if so, the salient ft tures thereof; and

ğ

102

(c) what is the constitution of the Group and by which date it has been asked to submit its report?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) (a) to (c): No such Study Group has been constituted by the Government recently. However, the Bhoothalingam Study Group on Wages, Incomes and Prices, which was set up in October, 1977, has already submitted its report. The report, besides other things, deals with the remuneration structure of managerial personnel of private sector Companies and is under examination of the Government.

# कोयले पर बाधारित नया उर्वरक संयंत्र

4816. श्री गोबिन्द राम निरी: श्री छविराम धर्गल : श्री सधम सिह ठाफुर : श्री कथक्ताल हेमराज जैन :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बसाने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या कोरवा उर्वरक संयंत्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य में उपलब्ध कीयले के प्रवृत मंडारों पर आधारित कोई अन्य नया उर्वरक संयंत स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और
- (ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर सगाया जायेगा ?

वेट्रोलियम तथा रसायन और उर्थरक मंत्री (औ हैमबसी नव्यन बहुगुजा): (क) प्रीर (ख): जी, नहीं। पश्चिम बाट में बड़े पैमाने में गैस की उपनवधी को ब्यान में रखते हुए फतिरिक्त उर्वरक अमता की स्थापना के लिए गैस के प्रयोग को फीड-स्टाक के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। कोयने के रूप में फीड स्टाक पर प्राथमित प्रति-रिक्त समता की परियोजना तालवर और रामा-गुक्य के कोयले पर प्राथमित उर्वरक संयंत्रों के प्रमुक्तों के पश्चात् ही सारम्य की जायेगी।

# Manufacture of Chloramphenicol by M/s. MAC Laboratories Pvt. Ltd.,

- 4817. SHRI GAURI SHANKAR RAI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) what is the total licenced capacity of M/s. Mac Laboratoris Pvt. Ltd., to manufacture Chloramphenicol from basic stage;
- (b) what is the total quantity of various intermediates they can import during the current Import Trade Control Policy on the basis of past consumption; and
  - (c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The total licensed capacity of M/s. Mac Laboratories Pvt. Ltd., for the basic manufacture of Chloramphenicol is 25. Tonnes per annum.

(b) and (c). The intermediates allowed for imports which are required for the manufacture of Chloramphenicol figure either in Appendix 5 of the 1978-79 Import Policy (Restricted Items) or in the OGL list. As far as the OGL items are concerned, the import will be governed by para 23 of the 1978-79 Import Policy. As far as Appendix 5 items are concerned, the import will be according to policy set out in paras 24 to 36 of the Import Policy.

#### Linking of Shravanabelagola by Railway

4818. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) are Government aware of the fact that in the year 1981 there is going to be a big celebration of 'Mahamastitabhishep' of Gommatteshwar, the world famous 1000 year old statute situated at Sharavanabelagola in the State of Karnataka for which at least 1 crore people are likely to reach there;
- (b) do Government not feel their duty to see that for providing them with suitable transport facilities, it is necessary to link that place by Railway; and
- (c) will Government provide such a facility?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). Government are aware of the need for construction of new railway lines in the areas where transport facilities are lacking, or are inadequate to meet the demands of the area, but have not been able to take up the construct'on of more suchlines on account of constraint of resources.

#### Registrar of the Court of Judicial Commissioner of Goa, Daman & Diu

4819. SHRI AMRUT KASAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the Registrar of the Court of the Judicial Commissioner of Goa, Daman and Diu was not in services of the Judiciary from June 1966 to April, 1968.
- (b) whether he was attending law classes at the R. L. Law College Belgaum

during the above period but regularly drew payments from the Government treasury; and

(c) if so, what action has been taken against the Registrar of the Court of the Judicial Commissioner for cheating the Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) According to the Government of Goa, Daman & Diu, the present Registrar of the Court of Judicial Commissioner of Goa, Daman and Diu was Superintendent in the District and Sessions Court during the period June 1966 to April, 1968.

(b) and (c). According to the information furnished by the Judicial Commissioner the Registrar had attended service regularly and was paid during the above period on the basis of his attendance. The Judicial Commissioner has also intimated that the information regarding his attendance of Iraw classes at the Law College Belgaum is not available, but that there has been no cheating and therefore there is no question of taking action against him.

# Complaints Regarding Air Pollution due to Chemical Plants

4820. SIIRI K. PRADHANI: Will the Minister of PETROLEUM, AND GHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government have received any complaints regarding air pollution from localities where major chemicals plants in the public and private sectors are located; and
- (b) if so, what are the details thereof and the steps Government have taken to redress their grievances?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Government have received complaints of air pollution caused by the operation of the following plants:

- (a) Caustic Soda unit of M/s. Jayshree Chemicals at Ganjam (Orissa).
- (b) Trombay unit of Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited at Trombay (Maharashtra).
- 2. In the case of M/s. Jayshree Chemicals, the Government decided that grant of letter of intent and licence (both resh ones and renewals) and other pending matters relating to this firm should

be deferred till the firm has taken all steps to check pollution of air and water in and around Ganjam town. All administrative Ministries/Departments have been requested to give effect to this decision.

3. The Trombay unit of the Rashtriya Chemicals & Fertilizers is implementing anti-pollution measures costing Rs. 677 lakhs. The air pollution from this plant will be substantially reduced when it starts using low-sulphur gas from Bombay High in place of Naphtha in December, 1978.

### Exchange of Railway Expertise between Australia and India

4321. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) Whether the Australian Parliamentary Delegation which visited India recently mentioned about wide scope for exchange of expertise between the two countries in the field of railways; and
- (b) if so, Government's reaction there-on?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b). The Ministry of Railways have no information in the matter.

# लखनक ग्रौर वाराणती के बीच नई गाहियां चलाने का प्रस्ताव

4822. श्री गंगा भन्त सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या लखनऊ झौर वाराणसी के बोच कुछ नई गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; झौर
  - (ख) यदि हां, तो वे कब तक चलाई जार्येंगी?

रेल संवालय में राज्य संवी (श्री शिव नारायण): (क) भौर (व). जी, नहीं । तथानि, वाराणधी भौर सवनक के रास्ते हावड़ा भौर जन्म् नते के बीच स्पताह में टोबार चलने वाली एक तेव गाड़ी भ्रम्तूबर 1978 के मान पास चलाये जाने का प्रस्ताव है ।

# Shortage of Judges of High Courts in West Bengal

4823. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of West Bengal is facing a great difficulty in High Courts because of the shortage of Judges;

- (b) whether the Government of West Bengal have urged the Central Government to sanction eight posts of Judges recently; and
- (c) if so, what is the reaction of the Central Government.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). The Government of West Bengal have pointed out the heavy arrears that have accumulated in the High Court of Calcutta and have proposed the creation of eight more posts of Additional Judges. They have been requested to obtain and send to the Central Government the views of the Chief Justice of the Calcutta High Court, before a final decision is taken in the matter.

# पिबकोल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ग्रीर सहायक स्टेशन मास्टर का समान ग्रेड

4824 श्री राम नरेश कुशवाहाः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वाराणसी डिबीजन में पिवकोल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर भीर सहायक स्टेशन मास्टर का ग्रेड समान है;
- (ख) यदि हां, तो स्टेशन मास्टर के पद का दर्जान बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ;
  - (ग) क्या इस स्टेशन पर बिजली नहीं है; भौर
- (घ) इस स्टेशन की दशा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेस मंत्रासय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण): (क) जी, हो।

- (ख) विभिन्न ग्रेडों के लिए प्रतिकृत पर भाषारित स्टेकन मास्टरों धौर सहायक स्टेकन मास्टरों के संवर्षों के पुनर्गठन के घाषार पर ग्रेडों को ऊंचा किया गया है।
  - (ग) स्टेशन पर विजली नहीं लगी है।
  - (क) जिसत लागत पर विजली उपलब्ध होने कौर उपलब्ध निधि के भीतर रेल उपयोगकर्ता पुर्विक्ष समिति द्वारा सिफारिक किये जाने के बाद इस स्टेशन पर विजली लगाने का कार्यक्रम बनाया जायेगा

# भारतीय तेल कियम हारा कवित साथ

- 4825. श्री छीतुमाई गामिल: क्या वेद्रोलिक्स रलायन और उर्वरक मंती यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या गत वर्ष भारतीय तेल निगम द्वारा पिछले सभी वर्षों से प्रधिक लाभ प्रणित किया गया या :
- (ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप कितना लाभ अजित किया गया ; और
- (ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मृत्य ढांचे पर पुनर्विचार करने का है?

वेट्रोलियम तथा रलायन श्रीर उर्घरक मंत्री (श्री हेमबती नन्दन बहुगुना) : (क) जी, हां। इंडियन प्रायल कापरिशन का गुढ़ लाभ पिछले वयों की प्रयेक्षा वर्ष 1977-78 के दौरान प्रक्रिक था। वर्ष 1977-78 के दौरान प्रक्रिक था। वर्ष 1977-78 के दौरान प्रक्रिक था। वर्ष 1977-78 के दौरान प्रक्रिक का था जब कि वर्ष 1976-77 में प्रुढ़ लाभ 48.41 करोड़ रूप्य । वर्ष 1977-78 में प्रुढ़ लाभ प्रायकर प्रशिनयम के प्रत्नेत कर का दायिरक कम होने के कारण प्रधिक हुआ था।

- (ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।
- (ग) इस समय पेट्रोलियम उत्पादों काः मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

# Oil Prospecting in Contai and Tamluk, West Bengal

4826. PROF. SAMAR GUHA: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government have any project to undertake prospecting of oil in the Contai and Tamluk sub-divisions of West Bengal;
- (b) whether according to the report of the preliminary survey oil is likely to be found in that area, and along the off-shore area of Contai;
- (c) whether Government will also undertake off-shore drilling project along the coastal area of Contai subdivision of West Bengal; and
- (d) if so, facts about the replies related to the above questions?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA); (a) to (d). The necessary information is being collected from the ONGC and will be laid on the Table of the Sabha

# विश्व वैंक से सहायता

4827. डा॰ सक्वीनारायण पांडेय : नया रेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

- (क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक तथा धन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भारतीय रेसों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता देने के लिए तैवार है; और
- (ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए परि-कोजना प्रका योजनायें बनाई गई हैं प्रथना इस बारे में क्या ब्यौरा है?

रेल मंबालय में राज्य संजी (भी शिव नारायण): (क) भीर (ख). भारतीय रेलें भयने विकास स्थय के विदेशी मुद्रा शंक को पूरा करने के लिए विश्व बैंक/धन्तरोष्ट्रीय विकास संच की सहायता प्राप्त करती रही हैं।

श्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संव जो विश्व देंक से सम्बद्ध है, ने हाल ही में प्रस्तावित रेल प्राश्चीनकी-करण एवं भनुरकाण परियोजना के लिए 1900 लाख धनरीकन बालर का एक धीर ऋण देने के लिए धपनी सहमति प्रदान की है। प्रस्तावित ऋण में जामिल मदों का क्यीरा धीर प्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संव द्वारा उनके लिए महमत सहायता की राक्षि नीचे बताई गई है:—

मद (लाख	डालर में)
(i) कारखाना भाधुनिकीकरण वरियोजना	1250
(ii) पहिया एवं धुरा संयंत	380
(iii) पहियों, टायरों भीर धुरों का भायात	150
(iv) विकास सहायता	120
 ओड़	1900

# मझारा स्टेशन पर रेलवाड़ी के पटरी से अंतर बाने ,से सम्बन्धित बस्तावेकी का गुम होना

4828. भी राम साल राही: क्या रेल संती यह बताने की क्रुपा करेंगे कि 8

- (क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मझारा स्टेशन पर विनांक 10 जून, 1977 को रेलगाड़ी के पटरी से उत्तर जान की जांच से सम्बन्धित दस्तावेज गुम हो गये हैं; ग्रीर
- (ख) यदि हां, तो उसके लिए कौन व्यक्ति दोषी पासे गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेस अंकास्त्य में राज्य संबी (भी शिव नारायण)ः (क) जी नहीं।

# .(ब) प्रश्न नहीं उठता।

#### Persons Coming to Delhi by Suburban Trains

4829. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware of the fact that thousands of central government employees and workers daily come to Delhi/New Delhi by suburban trains and they have to reach their offices before 10 A.M.;
- (b) whether keeping in view the large number of Government servants who come to their offices from faraway places, Government would ensure punctuality of suburban trains especially trains coming from Ghaziabad and Faridabad like Meerut shuttle etc.;
- (c) the number of times when Meerut shuttle reached New Delhi station late during the last six months month-wise;
- (d) whether Government would attach Diesel Engine to Meerut Shuttle for its speedy operation and if so, by what time and if not, the reasons therefor; and
- (e) whether Government propose to introduce at least two more electric trains between New Ghaziabad to New Delhi/Delhi viu Indraprastha rail bridge to avoid congestion in Meerut shuttle; if so, by what time and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

- (b) Yes. Every endeavour is being made to run suburban trains in time.
- (c) During the period from January to June 1978, 2NM Meerut City-New Delhi shuttle arrived New Delhi late on three days each in January and February, six in March, two in April, three in May and one day in June.
- (d) Dieselisation of this train is not feasible for want to spare diesel locomotives.
- (e) Introduction of any new train between Ghaziabad and New Delhi/Delhi is at present not operationally feasible for want of necessary terminal facilities at Delhi/New Delhi.

# Manufacture of Synthetic Menthol

4830. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government have de-cided to allow a large scale unit to Manufacture Synthetic Menthol;
- (b) if so, whether this large scale unit is under Public Sector or Private sector and if it is a Private sector unit the name of the company;
- (c) whether Government are aware that by this decision nearly 200 small scale units engaged in menthol production will be badly affected and more than 35 thousand employees will lose their jobs; and
- (d) in view of the production of men-thol by small scale units is enough to meet the internal requirements will Government reconsider to allow large scale unit in this field of Industry?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTI-LIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and(b). Yes, Sir. Shri Jayant S. Dalai has been granted a Letter of Intent on 28-10-1975 for the manufacture of 200 tonnes of L-Menthol etc. (through Synthetic route). The letter of Intent has been issued, apart from other conditions, subject to an export obligation of 25% of the annual production of Menthol.

An application for the import of Capi-All application los the import of capi-tal Goods by M/s. Camphor & Allied Products Limited, Bombay for the manu-facture of Menthol and Thymol has also been approved on 19-8-1978 subject to an export obligation of 60% of the an-nual production and the party advised to apply to DGTD for registration of

(c) and (d). No precise demand esti-mate for this item has yet been made. The present demand of Menthol, is however, met by the existing units, both in the organised sector as well as in the small scale sector. With a view to protect the interests of small scale sector, a suitable export obligation is imposed by Government in the case of large scale units.

#### सरकारी बकील

4831. भी मती चन्द्रावती: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1977-78 में कितने सरकारी वकील नियुक्त किये गये ;

- (च) उज्यतम न्यायालय में शंतकातिक बचवा पूर्वकालिक कान-कान से सरकारी नकीन नियक्त किये गये भीर उनके नाम भीर पते क्या
- (ग) उनमें से पिछली सरकार के कार्यकाल बौरान धापात स्थित में नियक्त किये गर्ने मरकारी वकीलों के नाम और पते क्या हैं?

बिस, म्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (भी शांति मुबल): (क) 2741

- (क) भारत के उच्चतम न्यायालय में नियक्त सरकारी प्लीडरों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है। क्रिन्वालय में रखा गया। वेंखिए संस्था एल-टी-2733/78]
- (ग) भाषात स्थित के दौरान निम्नलि**खित** प्रधिवन्ताओं को सरकारी प्लीडरों के रूप में निवन्त किया गया वा :

#### भारत का उच्चतम म्यायालय

श्री भार० बी० दातार भौर कुमारी सुषमा महिन्द्र (श्रीमती सुषमा कंवर)

विल्ली उच्च ग्यायालय श्री ए० एन० गोस्वामी

जिला न्याबालय, दिल्ली श्री दौलत राम गप्ता

# मम्बई उच्च ग्यायालय

सर्वश्री सोराब, डी० विमादलाल, के० के० सिषवी, डी० पार० धानक प्रौर बी० पी० टिपणिस

# कलकता उच्च न्यायालय

सर्वेधी एस० एम० हाजरा, ए० पी० राय, बी० एस० चौत्ररी, शिदयास वनर्जी, बी॰ के० नाहा, एग० बी० मुखर्जी, हरिमाहन धर, प्रदोष मलिक, विश्वरंजन घोषाल, एस॰ पाल, मधुसुदन बनर्जी भौर दिलीप कुमार बोस ।

इन ग्रधिवक्ताभों के पते उनके अपने भपने न्यायालयों की मार्फत हैं।

# Restriction on Profit of Essential **Drug Formulations**

4832. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS & FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) is it a fact that margin on essential drug formulations in the category I and II will be restricted to 40 and 55 per cent respectively;
- (b) has there been any representa-tion from the Industry on the ground

that this would made their production uneconomical and will badly hit their profitability; and

- (c) have Government given an assurance to the Industry that formulations in category III and IV will enable them to maintain their profitability while reducing the prices of essential drug;
- (d) how would this help units which are predominantly producing formulations in Category I & II only; and
- (c) will Government allow—such units, as jisted in (d) above, to diversify their formulations activity to category III and IV drugs as long as they are within the ratio of 1:5 or 1:10 as the case may be.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTI-LIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes, Sir. The new Pricing Policy contained in the Statement laid on the Table of the Lok Sabha on the 29th March, 1978 envisages a mark up (including the distribution costs, outward freight, promotional expenses, manufacturers' margin and trade commisson) of 40 per cent and 55 per cent respectively on Category I and II formulations.

- (b) Yes, Sir. Representations were received from the drug industry on this point.
- (c) to (e). It has been clarified to the Industry that in order to make their overall operations economically viable, with lower mark ups in Category I and Category II, Government would consider their II, Government would considerations falling in Category III and Category IV. Such a diversification would be considered keeping in view the provisions of paragraph 14, 17, 20, 22, 25 of the Statement referred to in (a) above.

# Import of Crude Oil

4833. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) what is the total quantity of crude oil being imported and what is the quantity available in our country;
- (b) within how many years we can be self-sufficient; and
- (c) after becoming self-sufficient whether there is any possibility of reducing the prices of petrol, kerosene, diesel etc.?

- THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTI-LIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA); (a) A quantity of 15 million tonnes of crude oil is expected to be imported during 1978-79. Indigenous crude oil availability during this period is expected to aggregate to 12.14 million tonnes.
- (b) While all attempts are being made to intensify our exploration activities, and while plans are being made for the exploitation of our established reserves, keeping in view the need to conserve this non-renewable source of energy, it is difficult to hold out any promise of self-sufficiency in crude oil. Our exploration policy will be pursued vigorously with a view to making an inventory of our hydrocarbon resources.
  - (c) Does not arise in view of (b) above.

# पेट्रोल का उत्पादन बढ़ाया जाना

4834. **चौधरी राम गोपाल सिंह: क्या** पेट्रोलियम, रसायन धीर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:

- (क) गत वर्ष के पेट्रोल के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है भीर भागामी वर्ष में इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है:
- (ख) क्या पेट्रांल के उत्पादन में वृद्धि को देखने हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इसका मुख्य कम करने का विचार है; और
  - (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

बेट्रोलियम तथा रास्तम और उर्धरफ संजी (भी हेमबती नन्दन बहुगुना) : (क) वर्ष 1978 के प्रथम छः महीनों के दौरान पेट्रोल के उत्पादन में (मोटर स्पिरिट) वर्ष 1977 की तद्नुरूपी प्रविध के 691,000 मी० टन उत्पादन की तुसना में 768,000 मी० टन वृद्धि हुई। प्रगले वर्ष मोटर स्पिरिट के उत्पादन में बृद्धि पर निर्भर करेगी जिसका इस समय 5 प्रतिज्ञन प्रनुमान लगाया गया है।

(ख) भीर (ग). भागानित कच्छे तेल के ऊंचे मूल्यों के कारण पैट्रोल के मूल्य की कम करना संभव नहीं होगा।

# कोरोमंडल एक्सप्रैस का गोवाबरी के जिलों तक बढाया जाना

4835. श्री कसुम हुज्जमूर्तिः स्था रेखः मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरोमण्डल एक्सप्रैम की सुविधाओं का, जो क्षेत्र में एकमात्र एक्सप्रैस गाड़ी है, घान्प्र प्रदेश में गोदावरी के जिलों तक विस्तार किया जाः सकता है: भीर

(ब) यदि नहीं, तो तमिलनाड् एक्सप्रैस बौर के के एक्सप्रैस वाकियों की समय पर मिलाने के लिए विजयवाड़ा में गौदावरी के जिलों के लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

ेरेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण): (क) जी नहीं।

(ख) घौर (ग). गोदाबरी जिलों से मदास भीर दिल्ली की तरफे यात्रा करने वाले स्रूयात्रियों की सुविधा के लिए 121/122 तमिल नार्डुएक्सप्रैस भीर 125/126 के० के० एक्सप्रैस गाड़ियां विजय-बाड़ा में 45/46 हबड़ा-गुटूर ईस्ट कोस्ट एक्सप्रैस 4 महास-हवड़ा मल ग्रीर 79 पुरी-तिरुपति एक्सप्रैस के साथ उपयक्त 🐇। से लेती हैं।

# Different rate of Wages in different Drug Units

- 4836. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased
- (a) what are the reasons for having different rates of wages in two different drugs and chemicals units managed by Government:
- (b) whether the discremination is resulting in dissat's fiction among the workers; and
- (c) whether this has affected production of drugs and chemicals?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) Presumably, the Hon'ble Member is referring to M/s, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd. and Bengal Immunity & Company Ltd, whose management has been taken over by Government recently under the Industries (Development & Regulation) Act. Since Government has only taken over the mana-gement of these companies, the wage structures that existed while they were under private management, continue. Any revision of such wage structures is possible only after the future status of these com-

(b) and (c). The different rates of wages, as far as the Government is aware, has not led to any dissatisfaction among the workers, nor has it affected production.

# Railway Line from Khamgaon to Jaina

4837. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to

(a) whether a decision was taken to lay a railway line from Khamgaon to

- Jalna in Buldana district in Maharashtra:
- (b) the expenditure incurred by Government on laying this line in 1935, and 1936 and the reasons for stopping the construction works on this railway line later on; and
- (c) whether Government propose to complete this railway line and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN HE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). A survey for Khamaon-Chickli-Jalna line was carried out in 1900 and the carthwork for the same was also taken up as famine relief measure. The work was subsequently abandoned. Several sur-veys for the line have been carried out since then. The project was sanctioned in July 1931, but the construction of the line was postponed due to lack of funds. The project was again reviewed in the year 1933 and a Traffic Survey was carried out in 1933-34. It was abandoned in 1935 on account of its unicmunerative character. Information regarding the expenditure incurred on the line at different stages is not available. No investigations have been made for the project in the recent past. In view of very limited availability of resources which are not sufficient even for meeting the commitments already made, the project, may have to await better times for consideration.

# Amritear Railway Station

4838. DR. BALDEV PRAKASH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the work to provide entry to Railway Station, Amritsar from the Gol Bag side has started;
- (b) is it a fact that provision has been made in the current year's budget for this work; and
- (c) how long it will take to complete the work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). The work of providing an entry from Gole' Bagh side to Amrittar Railway station has been included in the Railway's Works Programme for the current year. Designs and Drawings are being prepared. It is expected that this work will be completed in about 3 years time. }

115

# Petro-Chemical Complex at Cochin

4839. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased

- (a) whether the Kerala State Government have submitted its projects for a petro-chemical complex at Cochin; and
- (b) if so, what are the details of the

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Proposals have been received from the State Government of Kerala from time to time for setting up a Petrochemical complex at Cochin.

(b) The initial proposals were with regard to a petrochemical complex based on a naphtha cracker, whereas the latest proposals envisage production of aromatics.

A number of studies are under way to work out the details of the new petrochemical projects which need to be set up during the Sixth Five Year Plan. A final decision regarding the projects to be taken up for implementation, including their locations, will be taken on receipt of the reports of the studies. If and when it is decided to set up any new petro-chemical project the proposal of the Kerala Government would also be kept in view.

#### Capital Reduction of under FERA

484). SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether the Indian Chemicals Industry has been asked to reduce its capital under the FERA;
- (b) if so, whether the shares are sold only to the Kirloskars; and
- (c) if so, the steps taken to distribute the shares to Public?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) No company under the name and style of Indian Chemicals Industry has been directed to dilute the the foreign holdings under the provisions of FERA, 1973.

(b) and (c) Does not arise.

# Shortage of Life Sevings Drugs

4841. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS & FERTILIZERS be pleased

- (a) whether Government are aware that recently there has been acute shortage of life savings dr gs, not to speak of other vital medicines;
- (b) whether Government are aware that these drugs can be procured only at exorbitant prices; and
- (c) if so, whether Government will consider chalking out a dynamic strategy to meet social demands of the consumers who are not immediately concerned whether multinationals or Indian industry behave well within the bounds of National Law?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) A close watch is maintained over the availability of essential drugs. The supply position of drugs and pharmaceuticals is by and large satisfactory. Occasionally reports of shortages of patent or proprietary products are received but in these cases equivalent substitutes of other producers are available. Recently reports about the non-availability of both proprietary and non-proprietary substitutes in respect of the following formulations have been received:

- (1) Dapsone Tablets
- (2) Adrenaline in Oil Injection
- (3) Neoepinine Tablets
- (4) Clinestrol Injection & Tablets
- (5) Gas-Gangrene Anti-Toxin
- (6) Insulin Lente
- (7) Ethyl Chloride Sprav
- (8) Mycostatin Tablets.

Suitable action to relieve the shortages has been taken in consultation with the manufacturers concerned.

(b) The prices of drugs and medicines are controlled under the provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1970. Prior approval of the Government is necessary to effect any increase in price.

Any violation of the provisions of the Drug (Price Control) Order 1970 is punishable under the Essential Commodities Act, 1955.

(c) The following data relating to over-all production of drugs and pharmaceu-ticals in respect of the last two years would reveal that the availability of drugs in the country is increasing:

Written Answers

### Rs. Crores

Year	Availability of drugs*	Availability of formu- lations*
1976-77	150	700
1977-78	164	900

\*Indigenous Production+Imports-Exports.

# 379 बाउन पसबस-दिल्ली शहन रेलगाडी का तिलक विक. गई विस्ती में बकना

4842. जी राम संबर बेरवा : क्या रेख मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि 379 डाउन पलवल दिल्ली बटल रेलगाड़ी तिलक बिज के बाहरी सिगनस पर प्रतिदिन 10-15 मिनट रुकती है क्योंकि एम0 एन । बी । मेरठ शटल (जो नए यमुना पुल से गुजरती है), प्रतिदिन विसम्ब से पहुंचती है जिसके कारण पलवल झीर फरीदाबाद से माने वाले हजारों सरकारी कर्मचारियों को दके रहना पड़ता है और वे अपने कार्यालय विलम्ब से पहुंचते हैं ;
- (ख) क्या सरकार उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है जिन्हें तिसक विज स्टेशन पर रेलगाड़ी के विसम्ब से पहुंचने के कारण देरी हो जाती है तथा क्या उनके विरुद्ध धनुकासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है; धीर
- (ग) यदि हां, लो क्या सरकार 379 डाउन रेलगाड़ी को तिलक किज पर इसके निर्धारित समय यचा सुबह नौ बजकर चालीस मिनट पर रोकने के लिए अधिकारियों को निदेश देगी, भीर यदि नहीं, तो इन दोनों रेलगाड़ियों को साथ-साथ तिलक किंज पर रोकने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए हैं ताकि इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय समय पर पहुंच सकें ?

रेस संवालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण): (क) से (ग) जब कि 2 एन एम नेरठ---नई विल्ली शटल भेरठ सिटी से प्रातः प्राने वाली एक माल दैनिक याली गाड़ी है, पलवल की तरफ से धाने वाले दैनिक याती 367 हाउन ग्रथवा 379 हाउन पलवल-दिल्ली मटल गाहियों से 09.50 बजे या 10.20 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं। केवल कुछ मबसरों पर, जब कि 2 एन एम मेरठ शटल विलम्ब से चल रही थी, प्लेटफार्म सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण 379 डाउन को तिलक बिज के बाहरी सिगनल पर रोकमा पडा । 379 डाउन पंत्रवल-दिल्ली श्रद्धल का समय पालन संतोच जनक रहा है।

#### Assistance by Bulgaria for setting up of Chemicale and Pharmaceutical Unit

4843. SHRI TRUN GOGOI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased state:

- (a) whether Bulgaria will help India to set up chemicals and pharmaceutical units and agro-industrial complexes in various parts of the country;
- (b) whether the assistance will also include training programme by the Bulgarian Technocrats and experts in various fields; and
- (c) if so, how soon the aid would be forthcoming and the extent of it?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILI-ZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c) At the Fourth Meeting of the Indo-Bulgarian Joint Session for Eco-nomic, Scientific and Technical Coopera-tion held recently, Bulgaria has offered technical assistance for setting up che-mical and agro-industrial complexes in various parts of India. The assistance offered includes training of Indian personnel.

The offer of assistance by Bulgaria is being studied.

# Availability of Imported Life-Savings Drugs

4844. SHRI S. R. REDDY: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS & FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware that certain imported life-saving drugs for cancer and other fatal diseases are not available in the country; and
- (b) if so, what steps Government pro-pose to take to ensure adequate supply of these drugs?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTI-LIZERS (SHRI H. N. BAHUGINA); (a) and (b) Anti-cancer formulations in respect of which complaints about shorttages have been reported recently are Clinestrol tablets and Injections. Shortages of other life saving drugs for cancer and other fatal diseases have not been reported.

The main reason for the shortage of Clinestrol tablets and Injections is that M/s. Glaxo Laboratories (India) Ltd.,

who were manufacturing these preparations, have stopped production due to very low demand. Other firms are marketing these tablets under the name of Stilboestrol tablets and they are available in the country.

The import policy for the year 1978-79 provides for liberalised import of anticancer drugs and other life-saving and essential medicines; and the consumers can import the same under the Open General Licence.

# रेल माल डिम्बों को कमी

4845. श्री श्रनन्तराम जायसवाल: नय रेल मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह मच है कि रेल माल डिब्बों की कमी के कारण भौद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है:
- (ख) यदि हां, तो 1977 में किमने रेल माल दिब्बों का उत्पादन हुमा तथा 1976 में उत्पादित माल दिब्बों की संख्या से उनकी संख्या कितनी मधिक थी :
- (ग) रेल विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में माल दिख्ये सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं तथा क्या यह कमी उत्पादन में कार्य-कुमलता के कारण खब्बा पर्याप्त संख्या में माल दिख्ये न उत्पादित करने के कारण उत्पक्ष हुई है; भौर
- (थ) रेल माल डिब्बों की कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (ब्री शिव नारायण): (क) से (य) रेलवे के माल ढिब्बों की कमी के कारण घोषोंगिक उत्पादन पर पड़े प्रतिकृत प्रभाव का ब्यौरा इस मंत्रालय को झात नहीं है। किन्तु उर्वरकों और सीमेंट के मधिक झायात के कारण रेलों पर धसारणीवढ यातायात के परिणामस्वरूप रेलों को लस्बी दूरी वाले यातायात की दुलाई करने को कहा गया है जिसके कारण माल ढिब्बों के फेरों पर प्रधिक समय लगने लगा। माल को लावने, उतारने धादि के लिए होने वाले बिलम्ब के कारण भी माल डिब्बों के फेरों पर प्रति-कृत प्रभाव पड़ा है जिसके कारण माल ढिब्बों की सम्लाई में मामुली सी गिरायट झायी और कुछ क्षेत्रों से इस बारे में विकायतें मिलीं।

1976 में बनाये गये माल डिब्सों की संख्या बौपहियों के हिसाब से 11284 भीर 1977 में 12669 थी। इस प्रकार 1977 में उत्पादन में 1385 माल डिब्सों की बृद्धि हो गई। माल डिब्सों की उपलब्धता में कभी के कारण उत्पादन में अकुशलता नहीं कहा जा सकता क्योंकि 1975—76 थीर 1976—77 के बीरान योजना में निर्धारित स्तरों से स्विक उत्पादन हुआ था। सरकार ने निर्धार किया है किया है कि 1978—79 के बजट में चौपहियों

के हिसाब से 10,000 माण बिज्यों का आईर देने का जो स्तर रखागया है उसे बढ़ाकर 12,000 माल डिस्बें कर दिया जाये जिसे और बढ़ा कर 13,000 तक कर देने की सम्झावना हो सकती है।

# Wagon Shortage in Guntskal Division

4846. SHRI K. OBUL REDDY: Will the Minister of RAILWAYS be-pleased to state;

- (a) whether he is aware of the acute shortage of wagons in Guntakal Division after its merger into South Central Railway:
- (b) what action Government are going to take for the supply of nearly 1000 pending demands for wagons in Cuddapah and Kodur stations of Guntakal Division;
- (c) what action Government propose to take to meet the future demands of wagons for export of huge quantifies of Baryts to various countries abroad from Cuddapah and Kodur Stations of Guntakal Division;
- (d) whether Government propose to run a Baryts goods special to Madras Harbour from these stations to meet the heavy Bartysts traffic for export; and
- (c) whether Government are aware that nearly 50,000 tonnes of Baryts Powder has to be moved to North West and North Eastern parts of the country for the drilling requirement of O.N.G.C. in closed wagons and whether the Govt. will take action for supply of closed wagons for O.N.G.C. and for export of Baryts Powder?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) Wagons are being supplied for clearing demands at Cuddapah and Koduru depending upon the availability of suitable stock. At the end of July only 585 demands were outstanding at Cuddapah and Koduru stations of Guntakal Division.

- (c) and (d) One box rake has been formed and put into close circuit between Koduru and Madras Harbour for loading Barytes. In addition, block specials with open wagons are planned to run from Cuddapah and Koduru to Madras Harbour and available covered wagons are secured to load Baryts Powder.
- (e) Yes. Supply of covered wagons for clearing demands of Barytes Powder from Koduru on O.N.G.C. account will be arranged depending on the availability of covered stock.

# Conversion of Sholapur-Gadag Line

4847 SHRI K. B. CHOUDHARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

- (a) whether there is any proposal to convert Sholapur-Gadag Railway line from metre gauge to broad gauge; and
- (b) if so, when the conversion job is going to be undertaken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) and (b) No; in view of the severe constraint on he availability of resources, it will not be possible to undertake the conversion of Sholapur-Gadag line at present.

# Shortage of drugs for T.B. Treatment

4848. SHRI D. AMAT: Will the Minister of PETROLEUM, AND CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drugs for the treatment of T.B. cases in the country; and
- (b) if so, what are the reasons and what steps are being taken to remedy the situation?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N BAHUGUNA): (a) and (b): The only anti-T.B. formulation whose shortages have been reported from different areas of the country, from time to time; is Streptomycin Injection. The main reason for the shortage of this drug is late arrival of imported material due to insulequate availability of bulk drug Streptomycin Sulphate in the international market.

Apart from arranging for the needed imports, the following steps were also taken to deal with the situation:—

(i) The State Drug Controllers/ Associations of Drug Munufacturers were requested to ask the Streptomycin viallers to curtail their production of Streptomycine-Penicillin in order to increase the availability of Streptomycin Injections. Major viallers were also separately requested to do so.

(ii) IDPL and HAL, both public sector enterprises, were requested to augment their production of bulk Streptomycin Sulphate.

> GPC have since released adequate quantities of bulk Streptomycin Sulphate among various viallers who are lifting the material and the supply of Streptomycin vials is improving.

#### Private Railway Companies

4849. SHRI AHMED HUSSAIN & Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) the name and number of private Railway companies operating in N.E. region with State-wise break-up of Kilometers, liabilities and payments made to and received from Government;
- (b) how and by when Government propose to take over them; and
  - (b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) There are Two Light Railway Companies viz., the Chaparmukh-Slighat Light Railway Company and Katakhal-Lala bazar Light Railway Company which are privately owned but worked by the N.F. Railway in the State of Assam. The statement attached gives the details.

(h) and (c): In case of both the railways the Govt, have the right to exercise its option once every ten vears to purchase the Railways. The last option to purchase fell on 41-3-78 for Chaparmukh-Silghat Light Railway Co. And on 31-3-74 or Katakhal-Lalabazar Light Railway Co. It was decided not to purchase these lines, because the purchase was not considered financially viable. The general policy of the Govt. in regard to purchase of privately owned railways has been to conserve resources for acquisition of new assets rather than to purchase old and wornature.

123

#### Statement

#### Chaparmukh-Silghat Katakhal-Lalahayar z. Length 81 Kms. 98 Kms. 2. Liabilities as on 31-3-77 (i) Subscribed capital, 31,00,000 Subscribed capital 8,91,100 (ii) Balance on Reser- 11,63,890 Reserves & Surplus 60,633 ves & Surplus Acc-Accounts OHD IS. (iii) Loan from Govt. 1,13,633 Debentures. 6,50,000 for capital expendi-(iv) Advance to the Co. 1,50,000 2,51,982 Misc. (v) Misc. 1,29,368 3. (i) Payment made R4. 1,42,555 Rs.3,74,293 the Company during 1976-77. (ii) Payment\* received from the company Rs. 94,210/-Rs. 6,505/during 1976-77.

This does not take into account the actual experditure in ented by the N 1. Fig. viry in running the lines,

# Cost of construction of pavilion at Exhibitions arranged by A. I. Congress Party

4850. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state;

- (a) the total cost (for construction) of pavilion or stalls paid to contractors in the exhibitions arranged by All India Congress Party on the eve of Session of All India Congress Committee.
- (b) in case these were constructed departmentally, the cost debited to these works may be given separately for each work;
- (c) the fre, rent or any other charges paid by railways to the organizers of the exhibititons showing details of such payments;
- (d) cost on the maintenance of the aforesaid pavilions or stalls;
- (e) cost of dismantling these pavilions or stalls after the exhibitions were over; and
- (f) under whose order or recommendations these exhibitions were held and the details of the orders or recommendations thereof?

- THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) A sum of Rs. 2,99,900 was paid by the Railways to the contractors for construction of railway pavilions in the various exhibitions arranged by the AICC on the eve of AICC Sessions.
- (b) Rs. 48,720 was incurred for departmental construction of pavilions, out of which Rs. 41,000 was spent on erection of stalls, floorings, etc. and Rs. 7,720/as miscellaneous charges including T.A./D.A. paid to the staff employed at stalls, electrical work, etc.
  - (e) Rs. 1,01.360 as rent.
  - (d) Rs. 17,278/-.
  - (e) Rs: 21,380/-.
- (f) The Rai'ways' participation in these exhibitions was decided upon by the Ministry of Railways (Railway Foard) vide details in the enclosed Statement:

#### Statement

Exhibitions held during A.I.C.C. Session and participated in by the Zonas Railways

#### NORTHERN RAILWAY:

A.I.C.C. Session at Kamagatamaru Nagar, Chandigarh, held in December, '75/Jan:, '76.

# NO RTHEAST FRONTIER RAILWAY:

A.L.C.C. Session at Gauhati held in

November/December, '76.

### BASTERN RAILWAY:

- (1) A.I.C.C. Session, 1965 at Durgapur.
- (2) A.I.C.C. Session, 1972 at Bidhan Nagar, Calcutta.

#### of Books and Agencies Railway Stations

4851. SHRI ARJUN SINGH BHA-DORIA: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 4619 on 28th March, 1978 regarding sale of books and Agencies at Railway stations and state :-

- (a) whether the said information has been collected; and
- (b) if so, what are the details of the same 3

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHLO NARAIN): (a) and (b). The Implementation Report containing the required information has already been laid on the Table of the House by the Department of Parliamentary Affairs, on 27-7-1978.

# Subjects for Diplome Courses Company Secretaryship

4852. SHRI BIRENDRA PRASAD: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 9633 on 9th May, 1978 regarding syllabus of Diploma in Company Secretaryship of Delhi and state :-

- (a) whether the syllabus of the Post-Diploma in Company Secretaryship and the correspondence course of the Institute does not contain the subjects like Project Report/Dessertation and experienced trained employed persons in the field are admitted in the course;
- (b) whether persons who have already passed the full-fledged two years Delhi State Course of Company Secretaryship are required to again appear in the exami-nations conducted by the All India Insti-ture of Company Secretaryship; if so, reasons thereof; and
- (c) whether Government propose to recognise the Post-Diploma in Company Secretaryship under Rule 2(a) of Com-panies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975 or to refer the matter to the Expert

Committee on Company Law, already appointed by the Government?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) As per syllabus of the correspondence course of the Institute of Company Secretaries of Irdia and the Post Diploma in Company Secretaryis as under :--

	Correspondence Course of the Institute	
(i) whether Project Report/Desserta- tion is included in the course.	No	Yes
(ii) whether experienced, trained persons in the field are admitted.	No	Yes

- (b) Yes, Sir. Under rule 2(a) of the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975, a person in order to be eligible to be qualified as Secretary of a company having paid up share capital of Rs. 25 lakhs and above, is required to have the membership of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi.
  - (c) There is no such proposal at present.

#### बिहार में स्टेशनों को नया रूप देना

4853. भी राम सेवक हकारी : वया रेख मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि:

- (क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में स्टेशनों पर सफोई रखरखाव भीरसन्दर बनाने के बारे में किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप उक्त रेलवे का कार्य धव सुचारपूर्ण ढंग से हो रहा है ;
- (का) वया बिहार में हसनपुर रोड, नया नगर, कोसरा, किशनपुर तथा मनतापुर स्टेशनों पर सफाई, रखरखाव भीर सुन्दर बनाने के लिए भी इसी प्रकार के कार्य किये जाने हैं; और
- (ग) यदि हां, तो इस बारे में व्योरा क्या **?** ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण): (क) से (ग). रेल प्रशासन का निरम्तर यह प्रयास रहता है कि स्टेशनों की साफ़-सूचरा रखा जाये और उनका रखरखाव ठीक तरह से किया जाये।

The Control of the Co

127

दिक्षण-मध्य रेलवे पर कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों के बूढां में परिवर्तन/नवीकरण किया गया है। खब ऐसे काम पावस्यक होते हैं तब तक कार्यक्रम के साधार पर उन्हें किया जाता है बशर्त सेवीय रेल खयांगकतों सुविधा सिति उनका प्रनुसोदन कर है और धन उपलब्ध हो।

इस समय पूर्वोसर रेलवे के हसनपुर रोड, नयानगर, क्सेड़ा घाट, किशनपुर और मुक्तापुर रेलवे स्टेशनों के ढॉर्वे में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

# Hindi Medium in Railway Schools, Dahod

- 4854. SHRI SOMJIBHAI DAMOR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) is there any propsal to extend educational facilities from 1st to IV Class in Hindi Medium in Railway Schools, Western Railway, Dahod;
  - (b) if so, please give full details thereof;
  - (c) if not, the reasons therefor; and
- (d) whether C:ntral Government are pressing Gujarat Government to open a primary school of Hindi Medium?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

- (b) Does not arise.
- (c) There already exists one Railway Primary (Hindi Medium) School at Dahod in addition to two Hindi Medium Schools run by railwaymen.
  - (d) No.

# Short Payment of Wages to Labourers performing Parcel Handling Work at Allahabad

4855. SHRI N. K. SHEJWALKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to reply given to Unstarted Question No. 312 on the 18th July, 1978 regarding short payment of ways to labourers performing Parcel handling work at Allahabad and state:

- (a) whether it is the policy of Government to encourage Society by way of giving them extensions beyond the contractual term who were/are systematically and continuously cheating poor and innocent workers by way of making short payments to the time of several lakhs of rupees daring a short period of few years;
- (b) what action has been taken by the Government to recover short payment of Rs. 1,23,525/- provisionally worked out against the Society:

- (c) whether officers of Headquarters Office, Northern Railway are interfering with the Divisional Superintendent, Allahabad, in the matter of recovery of amount from the Society; and
- (d) if so, what remedial action is proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

- (b) Recoveries are being effected from the bill of the Society commencing from the month of April, 1978.
  - (c) No.
  - (d) Does not arise.

# Booking of Low Rated Goods Traffic

4856. SHRI G.M. BANATWALLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the railways have recently completely closed or suspended booking of low rated goods traffic;
- (b) if so, since when and what are the reasons therefor; and
- (c) in view of the inconvenience and losses to small dealers particularly when is the said booking expected to recommence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

# Trains Running between Mysore and Chamarajanagar

4857. SHRI B. RACHAIAH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the trains are running between Mysore and Chamarajanagar;
  - (b) if so, from what date; and
- (c) what are the imminent causes for cancelling the running of these trains started by M.S.R. belonging to former Indian State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) and (c). Out of 8 pairs of passenger trains running on Mysore-Ghamarajanagar s: tion 3 pairs of trains were cancelled on 22nd and 23rd July, '78. One pair of trains was restored on 24-7-78 and another pair on 26-7-78. At present only one pair of trains remains cancelled. This will be restored as and when the steam coal position becomes satisfactory.

#### Regularisation of services of Casual Workers

4858. SHRI T. S. NEGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the services of casual workers with six months service are regularised by Government;
- (b) whether there are employees in the catering department of the Railways who have rendered more than three years service but have not been made regular;
- (c) if so, the reasons therefor; and whether Government proposed to regularise the services of these casual workers;
- (d) whether an interview was held in January, 1978 for the regularisation or services of casual workers working in the canteens in Parliament House and its Annexe:
- (e) if so, how many workers were made regular as a result thereof indicating the length of their service; and
  - (f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS: (SHRI SHEO NARAIN): (a) Casual workers with over 120 days of service are eligible for screening but their regularisation will depend on vacancies being available.

### (b) Yes.

(c) As stated in reply to part (a) of the Question, regularisation of services of casual workers depends on the availability of regualr vacancies. The screened candidates are listed and absorbed in regular vacancies as and when the same occur,

(d) to (f) A sitting of the Screening Committee was held in January 1978 but the screening of all the canual labour could not be finalised as the eligibility of some of them was under examination. The screening will be finalised shortly.

#### Trains Originating from and terminating at Allahabad

4859. SHRI DHIRENDRANATH BASU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) the number of mail, express and passenger trains originating and terminating from and to Allahabad and through mail, express and passenger trains including parcels express with stoppage at Allahabad during the financial years 1960-51, 1961-62, 1975-75, 1976-77 and 1977-78.
- (b) the number of parcels packages handled at Allahabad including packages in sealed vans during the financial years 1960-61, 1961-62, 1975-76, 1976-77 and 1977-78; and
- (c) the assessed number of parcel proters required to exclusively handle parcels traffic at Allahabad upon which monthly lump-sum rate payable to handling contractors was fixed by Railways during the financial years 1960-61, 1961-62, 1975-76, 1976-77 and 1977-78?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The number of trains originating and terminating and passing through Allahabad including Parcel Express and COD shuttle were 46 in 1960-61, 46 in 1961-62, 66 in 1975-76, 74 in 1976-77 and during 1977-78 were 74.

(b) and (c). A statement is attached.

#### Statement

(b) Yearwise comparative figures of packages booked, received and handled at parcel transit at Allahabad are as under:

Year	No, of Packages Booked	No. of Packages received	transit Packages handled	Total No. of packages dealt with
1960-61 \ 1961-62 \	Figures are not	available as records have since	been destroyed.	
1975-76	288791	371125	54966a	1209576
1976-77	327812	420738	567210	1325760
1977-78	345917	410972	569184	1326073

(c) The number of porters required to perform parcels handling work and other miscellaneous items of work was assessed at 110.

Written Answers

#### Train Accidents

4860. SHRI V. M. SUDHEERAN : Will the Minister of RAILAVAYS be pleased to state :

- (a) whether Government are aware of the increasing number of train accidents;
- (b) whether Government received any report on this rail accident at Valachive near Kottayam ;
  - (c) the details of the damages; and
  - (d) the steps taken therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAHLWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) During July, 1978, there were 75 train accidents in the categories of collisions, detailments, level crossing accidents and lires in trains on the Indian Government Railways against 95 and 88 train accidents in May, 1978 and June, 1078 respectively.

- (b) Presumably, the reference is to the detailment of 47 Up Trivandrum-Canno-nore Express between Kuruppantara and Piravam Road stations of Sonthern Railway on 1-8-1978. The report of the Additional Commissioner of Railways Safety, who inquired into this accident, has not yet been received.
- (c) The cost of damage to railway property involved in this accident has been estimated at approximately Rs. 80,000/-.
- (d) Since human failure is the largest single factor responsible for accidents, Safety Organisations on the Railways have been engaged in a relentless campaign to create greater safety consciousness amongst the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or inclulge in shortcut methods that may lead to accidents. In order to reduce dependence on human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track-circuiting, axle counters, automatic warning system, etc. are being introduced progressively. It has been decided to complete track-circuiting on run-through lines on all the stations on trunk routes by 1981. In addition, track-circuiting of 100 vulnerable stations from fouling mark to Advanced Starter will be completed by 30-9-1979.

# तदर्व कर्मचारियों को नियमित करना

4861. बीधार० एम० राकेश: नवा रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार उन तवर्ष कर्मचारियों को नियमित करने का है जो सक्षम अधि-कारियों द्वारा नियमत किये गये थे :
- (ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड के श्रेणी III के उन तदथें कर्मचारियों को नियमित करने के श्रभी तक आदेश जारी न किए जाने के नया कारण हैं जी वर्ष 1975-76 में सक्षम मधिकारियों द्वारा नियक्त किये गये थे:
- (ग) क्या उनके द्वारा 11-6-77 की लोक सभा में घोषित वह नीति वर्ष 1975-76 में सक्षम श्रधिकारियों द्वारा नियनत रेलवे बार्ड कर्मचारियों पर लाग नहीं होती कि सक्षम प्रधि-कारियों द्वारा नियथत नदयं कर्मचारियों को नियमित कर दिया जागेगाः
- (घ) यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा भीर यदि नहीं, तो उन के सम्बन्ध में यह नीति लाग क्यों नहीं की गई है : भीर
- (ङ) वया सरकार का विचार जिनको क्षेत्रीय रेलवे में प्रथवा रेलवे सेवा प्रायोग में खपान का है भीर मदिहां, तो कब तक और मदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य भंती (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) से (घ). 1976 में जो विशेष कर्मचारी तदर्थ सोधार (पर नियुक्त किये गये से वे हिन्दी टाइप जानने वाल वलको की कमी की पूरा करने के लिए थे। उनकी नियुक्ति विभिष्ट हुए इ.प.से थोड़ी भवधि केलिए इस मते के आधार परकी गई थी कि जब भी नियमों में की गई व्यवस्था के अनसार निर्धारित स्रोत से अहंता-प्राप्त कर्मचारी उपलब्ध हो जायेंगे इन्हें हटा दिया जायेगा ।

इन सभी तदर्थ कर्मचारियों। की सेवामी की तब तक नियमित नहीं किया जा सकता जब तक में लोग कर्मचारी चयन द्यायोग द्वारा ली जाने वाली परीका पास नहीं कर लेते और कार्मिक विभाग धारा नामित नहीं किये जाते।

(क) इन कर्मचारियों को क्षेत्रीय रैलीं [मैं समाहित करने के प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक ये लोग रेल सेवा मायोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास नहीं करू नेते भीर उनके द्वारा नामित नहीं किये जाते 🗓

# स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या

4862 भी रवीना प्रताप सिंहः नया रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पश्चिम-पूर्व भीर दक्षिण रेलवे में ट्रेन सुपरिच्टेंग्डेंग्टों की मंजूरणुदा संख्या कितनी है;
- (ख) उनमें से कितने पद रेलवे केटीरंग विभाग में से, रेलवे-वार, भरे गये ;
- (ग) क्या दक्षिण रेलवे के उपरोक्त पद पर केवल धन्य विभागों के कर्मचारी लेने का निर्णय किया गया है;
  - (भ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; ग्रीर
- (इ) क्या सरकार का विचार केवल केटरिंग विभाग के कर्मचारियों में से इस पदको भरने का है जिससे याजियों की देखभाल भली भांति हो सके ?

# रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण):

(क) पश्चिम रेलवे	एक
पूर्व रेलवे	एक
दक्षिण रेलवे	25
(ख) पश्चिम रेलवे	एक
पूर्व रेलवे	एक
दक्षिण रेलवे	11

- (ग) जहां तक पश्चिम भीर पूर्व रेलों का सम्बन्ध है, प्रत्येक रेलवे पर केवल एक-एक पद है थीर उस पर, फिलहाल, खानपान विभाग से सम्बन्धित कमंवारों ही लगा हुआ है। जहां तक दिला रेलवे का सम्बन्ध है, रेल प्रशासन ने, मान्यताप्राप्त श्रीमक सगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, स्थानीय तीर पर यह विनिश्चय किया है कि इन पदों को भरने के लिए खानपान विभाग के कमंबारियों के साथ-साथ बाणिय भीर परिचालन विचागों के उन कमंबारियों पर भी विचार किया जाय जिन्हें वन सम्बन्ध का भन्मव प्राप्त है।
- (घ) याड़ी ध्रधीक्षक का काम केवल खान-पान प्रबन्धों का प्रयेवेक्षण करना ही नहीं है। उससे प्राणा की जाती है कि यह विभिन्न धास्वाओं के कमैचारियों के काम ससन्वय एंच पर्यवेक्षण की,व्यवस्था करे और गाड़ी में जिन विविध सुविधाओं की व्यवस्था की हुई है उनके उचित रूप से काम करने को सनिश्चित करे।
- (क) भाग (ग) और (भ) के उत्तरों को देखते हुए, इसका प्रक्न नहीं उठता।

# Wagons supplied to Hindustan Steel Stockyard at Bhubaneswar

4863. SHRI SIVAJI PATNAIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that wagons supplied to the Hindustan

- Steel Stockyard at Bhubaneswar deliberately returned by the contractor caused a great loss to the revenue of the railways;
- (b) if so, what action Government have taken against this; and
- (c) whether Government are also aware that officials are involved to manipulate demurrage charges for the interest of the contractor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The Railways do not deal with any contractor but only with the Branch Manager of Hindustan Steel Ltd. Stockyard, Blubaneswar, Any request for diversion or removal of wagons is generally made by the Depot Superintendent of the Stockyard.

- (b) Does not arise.
- (c) Since the Railways have no dealings with any contractor, the question of officials involved in manipulating demurrage charges in favour of the contractor does not arise.

#### Loss detected in investigation against DeputyChief Engineer, N.E. Railways in 1961

- 4864. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state #
- (a) whether a loss of Rs. 32,500 oo was detected in an investigation done by the Chief Vigilance Commissioner and his staff against a Deputy Chief Engineer (presently promoted as General Manager) on the N.E. Railway in the year 1961;
- (b) is it a fact that the then Chief Vigilance Commissioner instead of recommending recovery of the loss of public money directed an oral warning to be administered to the officer; and
- (c) how many such cases were investigated by the Commission from 1965 upto 1977 and what was the amount of public money written off?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI STHEO NARAIN): (a) and (b). In 1961, tenders were invited by the North Eastern Railway for the construction of 31 units type I, 10 units type II, 3 units type II and 3 units type IV quarters for medical staff at Gorakhpur and while the tenders received were under scrutiny, a decision was taken to change the side in respect of 31 units type I quarters. The Change of site necessitated extra plinth involving extra earth work and brick work. The contractor, whose tender was

the lowest with respect to quantities of work at originally proposed site, was awarded the contract. His rates for the additional work for the new site were higher than those quoted by other contractors. The C.B.I. investigation showed that the value of the contract became higher by Rs. 32,500 as compared to next higher tender taking into consideration the quantities at the new site. The Central Vigilance Commission to whom he case was referred, as per extant procedure, advised that no malafides had been established against the Officer and that it would be enough if he was administered a warning to be careful in future, which was done.

The case was investigated by the Central Bureau of Investigation and not by the Central Vigilance Commission. (There is no post like Chief Vigilance Commissioner.)

(c) The Central Vigilance Commission has advised that no record is available to show the number of such cases investigated by the Commission. Such statistical record is not maintained by the Commission.

#### Increase in Price of Urea

4865. SHRI CHHITUBHAI GAMIT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether the Gujarat State Fertilizers Company Limited has demanded increase of 40 to 50 per cent in the price of urea fertilizer; and
  - (b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) and (b). Yes, Sir. The Gujarat State Fertilizer Company Limited have made a representation for increase in their retention price of urea from Rs. 1006 to Rs. 1557 per metric tonne. While a part of the increase has been sought on account of increase in cost of packing material, catalysts, consumable stores and repairs and maintenance, bulk of the increase claimed by the company is on the ground that the basic parameters of pricing like consumption norms, level of capacity utilisation and the working of net worth adopted in fixation of retention prices should be relaxed and related to their actual experience.

# Expansion of Capacity by Synthetics and Chemicals Limited

4866. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the rated plant capacity of Synthetics and Chemicals Limited and how much rubber every year this factory has manufactured year-wise for the last three years and what was its value in terms of money year-wise; and

(b) whether the Government have any idea of allowing this industry to expand its capacity even when its production costs are extremely high, huge wastage of money prevails and additional quantitites cannot be given to this industry of alcohol which will be consumed in other precious industries?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) The licensed capacity of SRR and Nitrile rubber plants is 30,000 M.T. and 2,000 M.T. respectively. Production and value of these rubbers during the last three years as reported by the company is as follows:

	1975	1976	1977
Production	22,712	23,264	27,328
	M.T.	M.T.	M.T.
Value	Rs.	Rs.	Rs.
	19: 25	21 · 67	27·09
	crores	crores	crores

(b) No such proposal is under consideration.

# Setting up an Antibiotic unit in Nagpur

4867. SHRI R.K. MHALGI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Central Covernment and the State Government of Maharashtra have proposals under consideration to start antibiotic unit in Nagpur area;
- (b) if so, at what stage the said proposals stand; and when it is likely to be commissioned; and
- (c) what is the total outlay of each of the projects and the break-up of the share of Centre and the State Government?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA):
(a) and (b). Government have approved on 3rd August, 1978 the setting up of a joint venture formulation unit near Nagpur in Maharashtra State, by Hindustan Antibiotics Ltd., and the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra. This project is expected to be completed by August 1980.

(c) The project involves a total capital outlay of about Rs. 2-84 crores with equity of Rs. 114 lakhs. The contribution of Hindustan antibiotics Ltd., and the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra to the equity would be 51% and 49% respectively.

# Railway Platforms in Kerala

# 4868. SHRI K. KUNHAMBU : SHRI VAYALAR RAVI :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

- (a) whether Government are aware that the Railway Platforms in Kerala are not in accordance with climatic conditions;
- (b) whether these uncovered platforms are very inconvenient and troublesome to the passengers during rainy seasons; and
- (c) do Government propose to make provision of covered platforms in major stations in Kerala ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). Covers on Railway Platforms including those in Kerala are being provided according to their relative needs, on a programmed basis, in consultation with Railway Users Amenities Committee and subject to availability of funds.

## Trains between Ferozepur and Chandigarh

4869. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that a train between Ferozepur and Chandigarh via Abhor & Malout has been routed through Suratgarh and Bhatinda;
  - (b) if so, the reasons for the same; and
- (c) whether in the interest of better political and social link of Chandigarh with Ferozepur than Suratgarh the old link will be restored?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). No, 87/88 Kalka-Bhatinda-Chandigarh Express has been extended to Suraigarh with effect from 15-5-78. Two through coaches continue to run on this train between Firozepur and Chandigarh/Kalka.

### Persons arrested for Sabotage on Railways

SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA: Will the Minister of

- RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 3768 on 21-3-78 regarding persons arrested for sabotage on Railways and
- (a) whether the information regarding the number of persons arrested for sabotage on railways has since been collected;
- (b) whether these culprits belonged to certain political party or any cult otherwise; and
  - (c) action taken against them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. Twenty persons were arrested in one case of sabotage on Central Railway between Mana and Murtizapur in Akola District.

- (b) No complicity or collaboration of any political party or cult bas been proved in the course of investigation.
- (c) Charge-sheets have been filed against eleven persons. The case is pending trial,

#### Distribution of Fertilizers imported from U. K.

- 4871. SHRI MOHINDER SINGH SAYIAN WALA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5482 regarding distribution of fertilizers imported from U. K. on the 4th April, 1978 and state.:
- (a) whether details for distribution of fertilizers imported from U. K. have since been finalised;
- (b) if not, the reason for the same; and
- (c) whether some supplies have been received from U. K. ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). The details of the Fertilizer Educational Project to be financed from U. K. Aid Funds are being discussed with the concerned Ministries with a view to obtaining the necessary approval of Government.

No supply of fertilizers has so far been received from U. K. under this scheme. However, an order has been placed by Fertilizer Corporation of India for suply of 25,000 tonnes of Urea from U. K. which is expected to arrive during the current financial year.

# Section Officers in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway

4872. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the Section Officers working in the Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway at Delhi are not transferable and the Section Officers working on Vadodra, Ratlam, Kota, Rajkot and Bhavnagar Divisions are transferable; and
- (b) if so, steps taken by the Government to bring at par all the Section Officers in the matter of transfer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No. The posts of Section Officers (Accounts) are selection posts. Their seniority is maintained on whole railway hasis and they are liable for transfer anywhere on Western Railway.

(b) Does not arise.

#### Demonstrations at gate of Foreign Traffic Accounts Officer

4873. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that series of Demonstrations were held at the gate of the Foreign Traffic Accounts Officer, Western Railway at Delhi from 1st May, 1978 to 31st July, 1978; and
- (b) if so, the demand of the employees and steps taken by Government to finalise each demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) There were 5 demonstrations during the period.

- (b) The demands are :
  - (1) Inter-section transfers.
  - (2) Refund of CDS (Other than annual).
  - (3) House Building Advance and Flood Advance.
  - (4) Shortage of Staff,
  - (5) Delay in disposal of staff representations.
  - (6) Out of turn allotment of Quar-
  - (7) Construction of more Quarters,

(8) Matters pertaining to passes and establishment claims.

In accordance with Government's policy staff demands received from any source are given due consideration and necessary action is taken. The demands of all categories of staff are considered and solved through the various tiers of the Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consultative Machinery.

#### Cash Award to Staff of Asansol Division

4874. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) how much amount has so far been spent towards payment of cash award to staff of Asansol Division with effect from April, 1977 and onwards (month-wise);
- (b) what are the basic principles/conditions of considering grant of cash award to staff;
- (c) how much staff has been granted cash award on more than one occasion from April, 1977 and onwards;
- (d) whether there is any improvement in Railway working in Asansol Division after payment of Cash Award to staff; and
  - (c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SIRI SHEO NARAIN): (a) The details are as under :—

Month/Year		Amount
	 	 Rs.
April '77 .		12,025
July '77 .		1,300
August '77		1,550
October '77		8,750
January '78		1,100
February '78		2,850
March '78		5,97
April '78 .		23,750
May '78 .		400

- (b) Awards are given in recognition of examplary and extraordinary work done by the staff.
  - (c) 33

- (d) and (e). It would not be possible to correlate improvements in Railway working with the grant of individual cash awards as the railway working is pependent on a variety of factors. However, speaking in general, following improvements have been elected in the Asansol Division:—
  - (i) Disposal of Pension and P.F. settlement cases.
  - (ii) Clearance of Deposit P. F. items.
  - (iii) Recoveries effected from assorted staff Bills by intensified Internal Audit.
  - (io) Closure of Audit references.
  - (v) Recoveries of dues from non-Railway parties.
  - (vi) Timely calculation of electric charges bills.
  - (vii) Dealing with direct purchase of store bills.
  - (viii) Weeding out the time expired records, etc.

# Number of staff working in Asansol Division

4875. SHRI ROBIN SEN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the strength of staff working in Asansol Division of Eastern Railway in respect of the following categories:—

- (i) Officers; (ii) Supervisors
- (iii) Artisans; (iv) Semi-skilled;
- (v) Un-skilled and (vi) Ministerial;
- (b) the number out of the above who have been granted cash Award from April, 1977 and onwards; and
- (c) the figures may please be shown category-wise as mentioned above?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c):

No. of

staif

No. of

staff

Category

		granted cash Award
Officers ,	92	1
Supervisors .	1026	81
Artisans .	36 <b>48</b>	41
Semi-skilled	940	10
Un-skilled .	8862	17
Ministerial	1151	158
	15,719	308

#### Award of Contract to Union Carbide

- 4876. DR. RAMJI SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:
- (a) have Government seen the report of Hindustan Times dated the 31st July, 1978 'Modifinational bags big dairy Board deal' if so, what is the reaction of the Government;
- (b) is it a fact that in preference to the Indo-Burma Petroleum Company (I.B.P.) a public sector Co. the contract has been given to Union Carbide;
- (c) is it that the Union Carbide quoted the highest unit price; and
- (d) will Government enquire into this and stay this apparently deal?
- THE MINISTER OF PETRO-LEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHU-GUNA): (a) Yes, Sir ; but the press report is not correct.
  - (b) No. Sir.
- (c) and (d). The bids made by the various parties in response to the globel tender are under processing by the National Dairy Development Board.

# रेल कर्मकारियों का 6 सूत्री मांग पत

4877. डा॰ रामजी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार रेल कर्मवास्यिं द्वारा 1974 में दिए गए 6 मूनी मांग पत्न की बैधता तथा श्रीचित्य को स्वीकार करती है; यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तां उसके क्या कारण हैं;
- (ख) इस समय सभी रेलवे में नैमिलिक श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ग्रीर वे कितनी भविष्ठ से कार्य कर रहे हैं;
- (ग) उन्हें नियमित नीकरी देने के सम्बन्ध में जनता मरकार ने क्या कार्यवाही की है भीद करने का विचार है;
- (घ) क्या सरकार रेल कर्मचारियों को उन्हें भ्रन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से भ्रलग करके बोनस देने का जोखिम ले सकती है; यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) म (क), (ग) धीर (घ). इन मांतों के बारे में स्थिति झेलम- विवरण में दी गई है।

क्प से एक भागवार्ती प्रध्यसन करने के प्रश्न पर विचार करना पढ़ेगा। जहां तक बेतन में समानता साने का प्रश्न है, तीतरे बेतन बायोग का यह मत वा कि प्राइवेट या सार्वजनिक क्षेत्र के साच बेतन की उचित समानता को रेन कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बेतन स्तर को निर्वारित करने के लिए स्रांश

Written Answers

# तत्सम्बन्धी स्थिति

ठीस भाषार के रूप में नहीं माना जा सकता । जो भी हो, यह एक ऐसा मामला है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सम्पूर्ण रूप के प्रभावित होते हैं तथा जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, रेल मंत्रासय द्वारा कोई भी एकतरफ़ा कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह बेतन, आय तया मूल्य नीति से भी जुड़ा हुआ है और इस पर सरकार द्वारा होल ही में नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा उक्त मुद्दों पर गहराई से घष्ययन कर लिये जाने के बाद ही विचार किया जायेगा।

- 3. बर्च 1971-72 क्रीर 1972-73 के लिए एक माह के बेतन की दर पर बोनस ।
- सभी गैमिलिक रेल कर्मचारियों को विगमित करना तथा पूर्व-स्थाप्ति लाभ सहित जनका मधी लाघों के साथ सेवाफ्रों में स्थायीकरण ।
  - विश्वाणीय तौर पर चनायी गयी दुकानों के माध्यम से पर्याप्त एवं रिवायती वरों (पर बाखानों तथा प्रत्य धावस्यक वस्तुकों की सप्लाई।
  - 6. उत्पीडन के सभी मामले वापस लिये जायें।

- 3. यह बेतन, धाय भीर कीमतों की नीति के प्रश्न के साथ वनिष्ठ रूप से जुड़ा है और सरकार द्वारा भूतलिंगम भ्रष्ट्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिये जाने के बाद इस बारे में विचार किया जायगा।
- यद्यपि पूर्ण रूप से नियमित करने की भावनं स्थिति को प्राप्त करना तत्काल सम्भव नहीं है किन्तु नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित मौकरी देने में काफी प्रगति हुई है। नियमित रिक्तियों की कमी के कारण जिन व्यक्तियों को नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में लगे रहना पड़ा है उनकी शिकायतों को दूर करने के उपाय भी किये गये हैं।
- उठाये गये मुद्दे पर रेल मंद्रालय द्वारा धकेले विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सरकार को सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में निर्णय करना है।
- 6. उत्पीड़न के बहुत से कबित मामले हाल ही में सरकार के नोटिस में लाये गये थे और उनकी जांच कराई गयी है और प्रत्येक मामले में गुण-दोष के माधार पर मावस्थक तथा व्यावहारिक कार्रवाई की गयी है।

## Products Manufactured by M/s. Sandoz (India) Ltd.

4878. SHRI S. S. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased

- (a) what are the products manufactured by M/s. Sandos (India) Ltd. under authorisation of May, 1969; detailed composition of each product;
- (b) is the podophyllum project shelved and if so, why the company have not been asked to return the licence; and
- (c) what was the investment made on podophyllum project alone, source of

funds and how this investment have been utilized?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZ-ERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) (a) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

- (b) Apart from active principals of (o) Apart Hull acute paragraphs of Prodophyllum (Glycoside/Aglycone Fractions), Industrial Licence No. L/a2/166/69.
  Cn. III dated 21-8-63 granted to M/s.
  Sandoz also includes the following items, added subsequently in the said licence on 16-5-67:-
  - 1. Active Principals of Senna
  - 2. Active Principals of Belladone

- Synthesis of O-Nitrophenol and Nitrophenol
- 1. Synthesis of O-Aminophenol
- 5. Synthesis of 3-hydroxyquinoline
- 6. Stathais of 8-hydroxyquinaldine
- A. Sandoz are manufacturing certain items out of those added subsequently. The question of asking them to return the licence, therefore, does not arise. However, this aspect would be looked into at the time of issue of a consolidated licence to them.

### Paring Industrial Licences Applications of Foreign Drug Firms

1879. SHRI S. S. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) details regarding date, name of the product, capacity etc. of the pending industrial licence applications of the foreign companies as on date and the reasons for delay in disposing of such applications;
- (b) how many applications of Indian companies for similar product are pending; and
- (c) whether this delay in disposing of applications is helping certain foreign companies?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIAND (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The requisite details in respect of foreign drug companies having direct foreign equity exceeding 40% are indicated in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library Ses No. LT-2734/78.]

The processing of Industrial Licence applications received from foreign companies wa kept in abeyance pending Government's decision on the recommendations of Hathi Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry. The New Drug Policy has been anounced recently and all such pending applications are now being processed in the light of that. Some of these applications have already been processed by this Ministry and cases forwarded to the Licensing Committee/LC-cum-MRTP Committee for their consideration.

(b) and (c). 5 (five) applications from Indian companies for certain similar products, out of which 4 (four) have been received very recently, are under consideration of the Government. It cannot

therefore, be said that there is delay and that it is helping foreign companies.

## Approval of prices for New Products by M/s. Warner Hindustan, Limited

4860. SHRI S. S. DAS: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) names of the new products for which price approvals have been granted to M/s. Warner Hindustan Limited.
- (b) how many new products are indicated in the price list of this company now as compared to the year 1975, and
- (c) if this company have introduced the products without price approval why action has not been taken against them?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) and (b), M/s. Warner Hindustan Limitei, were granted price approval for the following new products between the years 1975 to 1977:

- (1) Agarol M Emulsion
- (2) Tedral C Tablets.

Since price list for the year 1975 is not available, price list effective from 1st January, 1974, has been compared with price list effective from 28th March, 1978. It is noticed that the above two products are the only products appearing in the later price list, compared to the former price list.

(c) As the Company introduced these products with prior price approval of the Government, the question of taking any action against them does not arise.

# Guest houses maintained by synthetics and chemicals limited

4881. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) how many guest houses Synthetics & Chemicals Ltd. has been maintaining at various places in the country for the last three years and how much expenses are being incurred on each guest house very year;
- (b) for what sort of guest such guest touses have been kept at company's expenses; and
- (c) do employees also stay in these guest houses during their official duties?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTIBHUSHAN): (a) to (c): M/s. Synthetics and Chemicals Limited has furnished the following information :-

The company is maintaining one guest house at 63 Golf Links, New Delhi and two guest houses at its plant at Bhitaura, Bareilly. The expenditure incurred at Delhi guest house and Bareilly guest houses during the last 3 years is given below:

	New Delhi	Barcilly
	 Rs.	Rs.
1975	40,299	95,057
1976	36,506	1,31,166
1977	31,996	1,32,478

The guest house at Delhi is rented by the company and those at Barcilly are owned by the company.

The guest house at Delhi is maintained for the use of directors of the company for business purposes or on their way to Bareilly/Lucknow and for discussions and meetings. One of the guest houses at Bhitaura, Bareilly is located within the housing colony near the factory and is maintained for the use of the directors as there is no accommodation available nearby. The other guest house at Bhitaura is maintained within the housing colony for the staff of the company on official visit. This facility is also extended to the representatives of the suppliers, auditors who visit factory for the purpose of business of the company and to the government officials on official visits.

The expenditure is less than one per cent, of the total revenue of the company and hence it has not been shown separately in the published accounts and is grouped under miscellaneous expenses.

# Finances paid by Synthetics and Chemicals Limited to Distillers Trading Corporation

4882. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) How much finances from time to time Synthetics and Chemicals Limited la paid to Distillers Trading Corporas tion Limited for rendering various services,

(b) what is the justification of these payments to Distillers Trading Corporation limit d; and

(c) is Distillers Trading Corporation as sister concern of Synthetics and Chemicals Limited?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b): M/s. Synthetics and Chemicals Limited had appointed M/s. Distillers Trading Corporation Limited as agents for handling storage and transport of alcohol at Kandla at mutually agreed rates. The precise amount of payment made by the Synthetics and Chemicals Limited to M/s. Distillers Trading Corporation Limited is not available with this Department atp resent. An Investigation into the affairs of the company has been ordered and is in progress.

(c) The Distillers Trading Corporation has registered itself as an inter-connected undertaking of M/s. Synthetics and Chemicals Limited under M.R.T.P. Act.

#### Rise in prices of canalised items due to loading of pricing by CPC.

4883. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) why canalised items of drugs have not been kept open for REP import licences ;
- (b) whether it is a fact that consumer prices of canalised items have gone up in Indian Market due to loading of pricing by CPC; if not, how; and
- (c) formulations of canalised items whose consumer prices have not gone up/have gone down during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) It is not a fact that, under the 1978-79 Import Policy, canalised bulk drugs cannot be imported under REP import licences. The Policy provides that wherever the product exported contains a canalised bulk drug, the same can be imported under REP entitlement upto a certain percentage.

(b) During 1977-78, the prices of for-mulation of canalised bulk drugs like the anti-malarial chloroquin phosphate, the anti-TB streptomycin sulphate etc. which are required by the masses have been held at levels lower than those entitled by the landed cost of these bulk drugs, through the instrument of loading the pooled prices of newer antibiotics canalised bulk drugs like ampicillin, chloromphenicol etc. where the demand is more selective. During 1978-79, there have been no increases in prices of formulations based on canalised bulk drugs.

(c) Formulations based on canalised bulk drugs run into large numbers and time and effort involved in compiling information regarding increase/decrease in the price of formulations during the last three years would not be commensurate with the results likely to be achieved.

#### Issue of COB Licences

4884. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state :

- (a) details of COB licences granted during the last three years y sear-wise, with name of the company, products granted, production before the grant of COB and after the grant of COB;
- (b) whether Government have recognised installed capacity as one of the criteria for grant of COB and if so, would it not benefit the foreign companies; and
- (c) full details of amendments made to the COB licences during the said period and whether such amendments confirm to the basis followed in the past, if not reasons for deviation vis-a-vis New policy?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA):

(a) A Statement furnishing the requisite details in regard to the drugs and pharmaceuticals industry to the extent available, is attached.

- (b) The uniform criteria both Indian and foreign companies for fixing annual capacities in the COB Licence are as under:—
- (i) Where production has been established and reported for a period of more than one year or to the specified date, the capacity is fixed at the level corresponding to the highest annual production, subject to a minimum economic capacity to be determined in respect of the concerned industries/products, whichever is higher. However, where it is not practicable to fix a minimum economic capacity, the capacity is fixed provisionally on the basis of peak production in any of the previous years.

- (ii) Where production had commenced within less than one year before the specified date or the Undertaking has no yet gone into production, the capacity is provisionally determined on the basis of the minimum economic capacity. But in cases where it is not practicable to fix the minimum economic capacity, the capacity is provisionally determined on the basis of the capacity claimed or the computation based on plant and equipment installed.
- (iii) Where a minimum economic capacity or a provisional capacity is fixed, this capacity is fixed finally on the basis of the highest annual production, after the unit has been in production for a period of 3 years.
- (c) The details of amendments made to the COB Licences mentioned in the Statement referred to in part (a) above are as under:—
- (i) COB Licences granted to M/s. Roussel Pharmaceuticals Ltd., & (ii) M/s. Tamil Nadu Dadha Pharmaceuticals Ltd.

Their COB Licences were amended to include certain items which were carlier left out in the COB Licence inadvertently.

(iii) COB Licence granted to M/s. Cadila Lab.

Initially, M/s. Cauila Lab were granted a COB Licence for the manufacture of certain drug formulations where the annual capacities for various types of formulations were fixed category-wise on the basis of maximum production achieved by them for each item during the preceding 3 years from the date of submission of COB Licence application by them. After obtaining the said COB Licence, this party represented against the annual capacities fixed the COB Licence on the ground that, since it was by the virtue of installation of additional machinery which made them change over from being a small scale unit to a DGTD unit, theis annual capacities should be fixed on a provisional basis upto the level of additional installed capacities, in addition to the capacities already granted to them in the COB Licence. With the approval of the Licensing Committee, the party's request was acceded to and their COB Licence was amended accordingly on 28-11-77.

The above amendments to the COB Licence are in conformity with the policy indicated at (b) above.

# Statement

SI. No.	Name of the party	No. & date of GOB Licer	nce to the higher pro- last 3 years prec	and annual Capacity equivalent duction achieved during the eding the year of submission of COB licence.
1	2	3		4
r.	M/s. Roussel Pharm. Ltd.,	IL: 551 (75) dt. 27-12-75	<ol> <li>Tablets</li> <li>Ointments</li> <li>Liquid Orals</li> <li>Vials</li> <li>Ampoules</li> <li>Sofratulla</li> </ol>	475·36 lakhs p.a. 25·377 kgs. per annum. 22,680 Ltres p.a. 11·98 lakhs p.a. 7·19 lakhs p.a. 1000 units p.a.
2.	M/s. Uni-UCB Pvt. Limited.	IL : 25/76 dt. 23-2-76	V spicie Fablets	5 2 Million Nos. per annum.
3.	M/s. Tamil Nadu	IL: 53/76	1. Tablets	89 Million Nos. per annum.
	Dadha Pharma. Ltd.	dt. 8-4-76	<ol> <li>2. Ampoules</li> <li>3. Vials</li> <li>4. Capsules</li> <li>5. Ointment</li> <li>6. Liquids</li> </ol>	18355 Ltrs. p.a. 692 ", ", 7 '7 Million nos. per annum. 7000 kgs. 4550 litres
4	M/s Cadila Labs .	IL: 134 (76) dt. 6-10-76	1. Tablets 2. Liquids 3. Capsules 4. Granules & Dry Syrup 5. Ointments 6. Injections	986 lakh Nos. 317-20 litres 135-28 lakh Nos. 17075 kgs. 4960 kgs. 22-25 litres
5. M	I/s. Kerala State Drugs & Pharm, Ltd.,	IL: 15 (77) dt. 24-1-77	1. Tablets 2. Capsules 3. Liquid (Bottles) 4. Parenteral 5. Lakhs Nos (Ampoules)	630 lakhs Nos. 110 lakhs Nos. 70,000 litres.
6.	M/s. East (I) Pharm. Works Ltd.	IL:3 (77) dt. 11-1-77	1. Tetracycline Capsules (250mg). Tablets (500 mg.)	t. Million Nos.
		•	2. Chloramphenicol Capsules (250 mg).	One Million Nos.
			3. Chloramphenicol Streptomycin	One Million Nos.
			Caps. (125 mg. + 12	5 mg.)
7.	M/s. German Remadies Ltd.	IL : 21 (77) dt. 1-2-77	1. Hydroxy Progres- terone Caproate 2. Bisacodyl B.P. 3. Hydroxy Ethyl Theophylline	— 3 kgs. —126 kgs. —3828 kgs.
			4. Tablets & Dragees	—1335 lakh Nos.
			5. Ampoules 6. Liquids 7. Suppostories 8. Ointment	53 lakh Nos. 98,000 litres. 5 lakh Nos. 7360 kgs.

	1	2	3		4
8.	M/s. H Ltd.	oechst Pharm.	IL : 92/77 dt. 27-6-77	1. Catilan Capsules 2. Vitahext 3. Hostacortin 'H' 10 ml.	3 i lakh Litres
9.	M/s. H Pharma	affkine Bio- ceuticals Ltd.	IL: 140 (77) dt. 8-12-77	1. Diphtheria Tetanus Vaccine	6-40 lakhs doses
10.	M/s. A	mrutanjan Ltd.	IL:36 (78) dt. 14-6-78	ı. Annutanjan l'ain Balm (5-25 gms.)	21,65,000 Nos.
				2. Do. (12 gns.)	20.57 Million Nos.
				3. Do. (24 gms.)	2,60,000 Nos.
				4. Dermal Ointment (16 gms.)	1,80,000 Nos.
				5. Cetomix Cough Mixture	20,000 Nos.

(60 ml.)

## Rise in prices of Antibiotics

Written Ansiders

4885. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of PETROLIUM, CHEMICALS & FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that prices of two antibiotics formulations viz. Ampicillin and Chloramphenicol have gone up substantially during last one year;
- (b) if so the reasons for the same and percentage increase in prices; and
- (c) what steps have been taken to ensure their availability at cheap prices?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA):

- (a) During the last one year, there have been some increases in Ampicillin and Chloramphenicol formulation prices.
- (b) The price increases have followed increases in the prices at which Ampicillin and Chloramphenicol, which are capalised bulk drugs, were made available to the formulators. The prices of these new antibiotics were increased so as to enable drugs like the anti-malarial chloroquin phosphate and the anti-TB streptomycin sulphate to be distributed at low prices.

The increase in the prices of Ampicillin formulations allowed after 1-8-1977 varied from 1.70 per cent to 19.90 per cent and in the case of Chloramphenicol formulations, the increases allowed after the same

date varied from 0.60 per cent to 10.70 per cent.

(c) The pooled price of Chloramphenicol powder has since been reduced from! Rs. 586 kg. to Rs. 460/Kg. Consequential reductions in the price of formulations of this drug would be notified in due course.

#### Forums Associated by Government for Fixation of Prices of Bulk Drugs.

4886. SHRI YASHWANT BOROLE: Will the Minister of PLTROLFUM. CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) what forums have been associated by Government for fixation of prices of bulk drugs during the last three years;
- (b) what was the categorisation for placing the cost of production of different bulk drugs for discussion at different forums and who decided for discussion at a particular forum; and
- (c) how it was ensured that no discrimination was exercised in fixing the prices full history of price fixation of Indomethacin, Phenothiazine, Frithe-mycin Streate, Griscofulvin, Pthaly-Sulphathiazole, Tetracycline and Metonidazole may be given ?

# THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA):

(a) The Prices of bulk drugs have been fixed by the Government on the advice

- of Drug Prices Review Committee/High Level Group on Inter-Ministerial Coordination in the field of Drugs and Pharmaceuticaly.
- (b) Broadly, the High Level Group dealt with the price fixation of essential bulk drugs listed in Schedule I of the DPCO, 1970 and bulk drugs cost examined by the Working Group set up in 1974 ander the Chairmanship of Chairman, BICP. The DPRC dealt with the price fixation of other bulk drugs.
- (c) The composition of DPRC and of the High Level Group was broad-based and it included representatives from the concerned Ministries and Departments of Government including the Ministry of Commerce and DGTD; the conclusions of these groups would, therefore be objective. Details regarding the price fixation of Indomethacin, Phenothiazine, Erthromycin Streate, Griscofulvin, Pthalyal Sulphathiazole, Tetracycline and Metronidazole are given in the attached Statement.

W	ritten A	nswers	<b>AUGUST</b>	29, 1978	Written An	swers	160
Remarks	r.	The Company have since intimated that they are no longer producing this drug.	Both bulk drugs are for veterinary use. The preent price of formalutions are based on a price of Rs. 28,200 per tonne for Phenothiazine, Fine dispersible powder.!	The Company have declared a price of Ra. 1642 56/kg. in Sept., 1975. They supplied the drug at a price of Ra. 1112 50/kg. bn the 4th Sept., 1976, the price was fixed at Ra. 1300/kg.	The company is producing from basic stage as compared to Themis who produce from intermediate stage.	. 19-11-77 Rs. 4925/kg. (declared A pooled price covering indigenous pro- by IDPL)  Rs. 1471/kg. on 31-1-1978.	9-5-1978 Rs. 139 ool/g. (Do.) A pooled price based on IDPL's indi- May, 1977 Rs. 173 ool/g. (Do.) genous production and imports was fixed at Rs. 189 40/kg. on 30-9-1977.
Price as prevailing from time to time	+	. 22-1-1977 (Rs. 1268-50/kg. (declared by the Co.)	Ra. 11878-00/vone (declared by the Co. in 1970) Ra. 12480-00/tonnes (Do.)	4-9-1976 Rs. 1300/kg. (fixed on the recommendations of the High Level Group).	Alembic Chemical Works Co., 20-4-1976 Rs. 1706/kg. for Cap- rive use Rs. 1785; 00/kg. for sale to others (Fixed on the recom- mendations of DPRC after cost examination).	. 19-11-77 Rs. 4925/kg. (declared by IDPL)	. 3-5-1978 Rs. 129 co/kg. (Dv., May, 1977 Rs. 173 co/kg.(Do
Name of the Manufacturer	£	. Themis Orgasan Chemicals . : Marmaid Chemicals	Phenothianine Fine veterinary   Alkali and Chemical Corpora- Phenothianine Fine   tion of India Ltd. Dispersible Powder.	. Themis Pharmaceuticals	. Alembic Chemical Works Co., Ltd.	LDPL	. Cadila Chemicals IDPL
Name of the Drug	a	1. Indomethacin	Phenothiazine Fine veterinary Phenothiazine Fine Dispersible Powder.	5. Erythronycin Stearate	Do.1	Griscofulvin . • .	Phthalyl Sulphathiazole
s. No.	-	1 '	ü	**		<b>*</b>	ris

	Written Answe		7, 1900 (SAKA)	Written	Answers	163
en .	The price was notified on the recommenda- tions of the High Level Group.	It was announced on 30-3-77 that dis- tribution facilities of LD.P.L. for this drug could be availed in case the units are interested to sell at a price of Rs. 460/kg.				
		(do.) lared by the co.) I (do.) (do.) (do.) (do.) (do.)				
4	1970 Rs. 1000/kg. (declared) May, 1970 Rs. 850/kg. (Nois- fied in the Official Gazette)  September, 1976 Rs. 650/- (do.)	1970 Rt. 794 33 (declared by the co.) 1977 Rt. 619.00 (do.) 1977 Rt. 460.00 (do.) 1977 Rt. 485.00 (do.)				
ത	. IDPL. Cynamid Pfiner Symbiotics	May & Baker Unichem Unileids I.D.P.L.				
	•		and the second	d e e Ve		
a	6. Tetracycline Hd.	Metronidazole		٠.,		
w	o o	-	·			

# Working of the New Drug Policy

63

4887. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETRO-LEUM, CHEMICALS AND FERTILI-ZERS be pleased to state:

- (a) how the new drug policy ensures that only efficient units are encouraged to produce bulk drugs in the country;
- (b) are any changes in the new drug policy expected in the near future and if so, what main provisions are proposed to be changed are under review; and
- (c) is there any re-thinking on loan licences and scheme of registration with D.G.T.D.?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA):

(a) The new drug policy aims at achieving self-reliance and self-sufficiency in the drugs and pharmaceuticals industry. Different areas of responsibilities have been earmarked for the "Public Sector" "Indian Sector" and "Open for all Sectors". Besides, while considering proposals for licensing the manufacture of bulk drugs. Government keep in view various relevant factors like economy of scale, technology and pricing of products. A cardinal feature of the new drug Pricing Policy is that the prices of bulk drugs will ordinarily be based on the average cost of relatively more efficient manufacturers who account for a large percentage of the production of such bulk drugs.

(b) and (c). Government have received representations from Drug Manufacturers' Associations on various decisions of the Government contained in the New Drug Policy including decisions on loan licensing and abolition of Scheme of Registration with DGTD. These are under consideration of Government. Drug manufacturing units have also been asked to workout their profitability profiles based on the norms contained in the Policy.

### Supply of Bulk Drugs by CPC to IDPL and HAL on high Sea Sale Basis

4888. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETRO-LEUM, CHEMICALS AND FERTILI-ZERS be pleased to state:

- (a) what non-canalised bulk drugs were supplied by the CPC to IDPL and HAL on High Sea Sale basis;
- (b) what was the landed cost of such drugs to IDFL and HAL and what prices for such bulk drugs were allowed in the formulations; and

(c) whether IDPL have enjoyed any unintended benefit on this account and if so, under what authority were such sales allowed without adjusting prices?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) No non-canalised bulk drug was supplied by CPC to HAL on high sea sales basis. The details of non-canalised drugs supplied by CPC to IDPL on high sea sales basis are as under:—

1975-76 1976-77 1977-78

Vit. A .. .. 7' 175 MMU

Procaine Penicil-

lin . . . 3000 1000

(b) and (c): The average landed cost of the supplies of Vit. A and Procaine Pencillin to IDPL referred to in (a) above, works out as under:

1976-77

Vit. A . . . Rs. 2,64,112 MMU

Procaine Pencillin . . Rs. 533 48 Per BU

1977-78

Procaine Penicillin . . Rs. 427 36 Per BU

Vi A was utilised by IDPL for meeting the requirements of Family Planning Programme and Procaine Penicillin for meeting an export order from Afghanistan. The prices of formulations are not fixed with reference to the cost of procurement of individual consignments.

# Distribution of Canelized Raw Materials under New Policy

4889. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETRO-LEUM, CHEMICALS AND FERTILI-ZERS be pleased to state:

- (a) Salient features of the restrictions placed on the organized sector units in regard to the release of canalised raw materials in the new policy;
- (b) what liberalisations have been announced for the small scale and Indian units in the new policy; and
- (c) what is the sancity of the new policy of distribution what are the pen alities for its violation and how of that it has been violated by the CPC after its announcement?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):

(a) and (b): Salient features of old and new policies for release of canalised raw materials in favour of drug manufacturing units in the organised and the small scale sector have already been furnished in reply Lok Sabha Unstarred Question No. 1354 answered on 25-7-78.

In the case of DGTD units, under the new policy the release of canalised raw materials shall be determined with reference to either the releases of same items obtained in 1976-77 or the entitlement as per licensed capacities of individual drug formulations where such capacities are specified and the units concerned choose to claim releases on this basis. This is in line with Government's decision relating to the regularisation of excess production, because the criterion for regularisation of production ... in excess of licensed capacity or capacity based on COB licences, permission letters, registration certificates, no objection certificates etc. with the highest production actually achieved in any year during the three years period ending March 31, 1977. The policy is liberal to the extent that DGTD units can claim raw materials as per licensed capacity entitlement or releases obtained in 1976-77, whereas previously such units were obtaining canalised raw mater-ials to the extent of best of consumption during any of the two previous years or the quantity recommended by the State Drug controllers whichever was less,

In the case of Small Scale Units, it is expected that under the new policy they will get higher allocations of canalised raw materials as compared with their entitlements under the old policy. Moreover, they can exercise their choice in the selection of canalised raw materials within the coverall quantity ceiling applicable to them, which can enable them to adjust their product mix as per requirements of the imarket.

(c) The new policy guidelines for release of canalised raw materials have been prescribed under the authority derived from the provisions of Import Policy, 1978-79, whereby the Ministry of P.C & Fare required to lay down the connected policy in respect of import, price and distribution of raw materials in Appendix

No specific instance where C.P.C. have violated the guidelines has so far come to athe notice of Government.

# Car Shed at Kalwa

4890. SHRI R.K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that because of new car-shed of Central Railway being built at Kalwa near Thana (Maharahtra), at Chinchapada Zopadpatti for about 160 poor families have reached a dangerous situation; and
- (b) what steps Railway Administration propose to take to avert the danger to the said Zopadpatti in this rainy season?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) Does not arise.

## **Bangkok Meeting of ESCAP**

4891. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what decisions were taken at the meeting of the Inter-Government Railway group of the Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) held recently at Bangkok?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): The Inter-Governmental Railway Group of ESCAP, at their meeting held at Bangkok on 12th June, 1978, considered various issued connected with the promotion of economic and technical co-operation among developing countries, sharing of knowledge of railway research and new railway techniques. The Group, being a recommendatory body of ESCAP, by its nature and functioning, made recommendations to ESCAP on various aspects of railway operations and training of personnel.

# Trains running on uneconomic Routes.

4892. SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether any railway trains are being run at present on uneconomic routes, if so, what are the numbers of such trains; and
- (b) whether there is any scheme under Government's consideration to make these trains economically viable; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) About 360 pairs of passenger carrying trains are running on uneconomic lines.

(b) No.

# Availability of Wagons for Movement of Salt from Western Coast

4893. SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is fact that due to non-availability of wagons a heavy set back has been done to the movement of edible salt from Western Coast to the Northern States;
- (b) if so, the quantity of salt accumulated on salt belt: and
- (c) the measures taken by Government to allot adequate number of wagons to clear the accumulated salt?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

(b) and (c): Do not arise.

## Reservation in Service for SC/ST Employees

4894. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether Government have examined the implications of the decision of the Allahabad High Court, interpreting the Railway Board's directive, relating to reservations in service for SC/ST employees and restricting scope of reservation of posts and not of vacancies;
- (b) whether Government have taken a step to nulify its effect of this decision by suitably modifying Railway Board's directive; and
  - (c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c) As the judgement of the Allahabad High Court disputes the policy of the Government in regard to recervation for Sch. Castes/Sch. Tribes in services an application has been filed in the Supreme Court far grant of special leave to appeal to that Court against the judgement of the Allahabad High Court, The application is pending consideration before the Supreme Court.

## Representations regarding Halt and Speed of Somnath Mail

†4895. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that many persons have sent a representation to the General Manager, Western Railway, Bombay and the Ministry on 29-5-1978 regardinghaltage, crossing, and speed of Somnath Mail and Saurashtra Mail at Jetpur city in Rajkot district of Saurashtra region in Gujarat;
- (b) if so, the nature of demands contained therein; and
- (c) the details of action taken so far by Government or Railway Board in regard' to each of these demands or if the action is proposed to be taken, when it will be taken and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No representation appears to have been received.

(b) and (c) Does not arise.

# बम्बई हाई गैस पर बाखारित वो विवसी वरों की

4896. **भी धर्मीत**ह चाई पटेल: न्या पेड्रोलियन, रसायम और उर्थरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की इस नीति का विरोध किया है कि बन्बई हाई तबा ताप्ती हाई तेल क्षेत्रों की गस का विजयी वरों के लिए ईधन के रूप में उपयोग न किया जाये तथा यह मांग की है कि इस गैस पर मार्धारित दी वह विजयी वरों की स्वापना की जाये बीर यदि ही, तो कब;
  - (बा) इन दो मांगों का स्वीरा क्या है ;
- (ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सर-कार की इन दोनों मोगों को स्वीकार कर लिया है भीर यदि हो, दो कब तथा इसका ब्यीरा क्या है भीर यदि नहीं, दो उसके क्या कारण हैं; खीर
- (घ) गुजरात सरकार की इन मांगों की कब तथा किस प्रकार स्वीकार किया आवेगा ?

वेदोलियम तथा रसायन और वर्षरक मंत्री (भी हेलबती नम्बन बहुनुमा) : (क) के (थ). सरकार द्वारा जहां द्वेजन के रूप में बस्मद्व हाई गैस पर आधारित वो विजनी पर स्थापित कंपने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआं है, वहीं पर नुजरात सरकार ने कुछ पक्षों में गुजरात में सुपर विजनी पर की स्थापना करने और सौराष्ट्र में विजली उत्पादन करने के लिए तास्त्री गैंस की उपयोगिता का विश्लेष उल्लेख किया है।

जहां तक बम्बई हाई की ध्रपतटीय गैस का सम्बन्ध हैं, इस का यवासंभव उर्वरक के संभरण गंडार के रूप में उपयोग किया जायेगा। याज वह गैस, जिसका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उर्वरक यूनट इसे लेने की स्वित में न हो, उसे तथा किसी प्रकार की धरित्रका गैस को विज्ञाली उत्पादन के एक धानतरिक उपाय के रूप में जूडगुरु में उपयोग किया जाना जाहिए। ताप्ती गैस को उपयोग करने के प्रमान पर विचार करना धभी समय के धनकुल नहीं है क्योंकि इन संस्वनाधों का समुखत रूप से युद्धांकन करने और उन्हें वाणिज्यक रूप से उपयुक्त बोधिन करने के प्रकार हो ताप्ती गैस के समुयाजन करने के प्रकार हो ताप्ती गैस के समुयाजन की राम परवहन सम्बन्धी निर्णय करना संभव होगा।

गुजरात में धपतटीय गैस की धनुकूलतम उपयोगिता का झध्ययन करने के लिए गठित कार्य-कारी वल की सिफारिकों धन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित विचारधाराओं के झाधार पर थी:—

> "जिस माला में प्राकृतिक गैस के उपलब्ध होने की संभावना प्रतीत होती है वह एक इतनी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री के बराबर है कि इसका उर्वरक का उत्पादन करने जैसे उच्च महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त प्रयोगों में उपयोग करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, जहां पर गैस की भवसर कीमत नेपया की भवसर कीमत से बढ़ जाती है और यह मूल्य र्देशन तेल के श्रवसर मूल्य से कहीं श्रश्चिक बढ़ जाती है, जिसमें भट्टी का तेल, एष० एष० एस०, एल०एस०एष० एस०, भार० एक० भो० भादि तेल सम्मिलित हैं। (गैस के प्रयोग में यह प्राथमिकता बदल सकती है यदि गैस की उपलब्ध माजा में घणवा वर्तमान छ.जी मीति की समीक्षा करने के ब्राधार पर पर्याप्त बढ़ोत्तरी हो जाती है)"

इसको ध्यान में रखते हुए उक्त दल न अतिरिक्त विजली का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक गैंस की भाषी सप्लाई पर कोई विचार नहीं किया।

इस दल में गुजरात सरकार का एक प्रति-निधि भी ज्ञामिल था। मोटे तौर पर इस की सिफारिजें सरकार द्वारा मान ली गई हैं।

गुजरात धौर महाराष्ट्र में धपतटीय गैस की उपयोगिता के लिए कार्यकारी दलों की सिफा-रिकों पर विचार करते समय, इस धावय का भी निर्णय किया गया था कि योजना धायोग को परिचमी प्रदेश में छठी योजना धविष के दौरान विजली की लेखावी मांग के प्रवन का खौर मांग को पूरा करने के विभिन्न प्राविधियों/संसाधनों का भी धाव्ययन करना चाहिए।

# Cases pending in Gujarat High Court

- 4897. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:
- (a) the total number of cues pending in the Gujarat High Court as on the 31st July, 1978; and number of cases of each category among them:
- (b) the reasons why these cases are pending and the time by which they are likely to be disposed of;
- (c) the number of posts indicating the nature thereof which are lying vacant in the Gujarat High Court at present and the reasons therefor; and
- (d) the time by which these are likely to falled:

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Information as on 31st July, 1978 is not available. A statement containing the requisste information as on 30th June, 1978 is given in the attached statement.

- (b) No time limit can be fixed for the disposal of these cases. The main reasons for the pendency indicated by the High Court are:—
- (i) Disposal of some cases is linked with decision of cases filed in Supreme Court or the High Court on similar cr like question of law.
- (ii) Difficulty in serving notices on heirs and legal representatives of parties consequent upon their death and on parties residing in foreign countries.
- (iii) Some vacancies of Judges are unfilled.
- (c) and (d). Two posts of Permanent Judges and four posts of additional judges in the High Court are vacant and steps are being taken to fill them up.

#### Statement

Cases pending in the Gujarat High Court as on 30th June, 1978.

Civil Suits		13
Testamentary Petition	15 .	-3
Liquidation Cases		51
Company Petitions		5. 61
Company Application	18 -	148

Written	Answers	AUGU
---------	---------	------

11 × 4		
Income Tax Reference	:s	778
Income Tax Applicati	ons	19
Sales Tax References		68
Estate Duty Reference	5	37
Estate Duty Applicati	ons	1
Gift Tax Applications		8
Wealth Tax Reference		47
Wealth Tax Application	ens	4
Stamp References .		12
Civil Applications (Or		5
Original Side Appeal		3
Miscellaneous Petition	ns	1
Miscellaneous Applica		22
Criminal Contempt un tempt of Court A	ct	7
Letters Patent Appeals		180
First Appeals		3524
Second Appeals		1142
Miscellaneous First &	Second Ap-	
peals		212
Civil Revision Applica		924
Miscellaneous Civil Ap	-	91
Civil Applications (Ap	pellate) .	811
Givil References .		2
S pecial Civil Application	u	
Service Matters .		523
Land Reforms including ceiling .	ng land	827
Labour Laws		44
Óthers		987
Criminal Appeals		٠.
By person convicted .		370
By Government from ju	dgement of	
acquittal	• •	841
By Complaint u/s. 3780 P.C.	4) of Cr.	67
Criminal Revision App	lications .	242
References		2
Criminal Miscellaneou	s Petitions.	180
Writ Petitions		
(i) Special Criminal A u/Article 226 and 2		28
(ii) Special Criminal A u/Article 227 .	•	gı
Transfer Applications		11
Criminal Cases .		4
		12,520

# Rail | Coordination Directorate at

- 4898. SHRI GIRIDHAR GCMANGO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) whether nis Ministry has received a proposal from the Government of Orissa to set up Rail Coordination Directorate as Bhubaneswar;
  - (b) if so, the details thereof; and
- (c) the steps taken by the Ministry tree far, in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

- (b) The Government of Orissa has proposed to set up Rail Coordination Directorate at Bhubaneswar with a view to bridging the communication gap between the State Government and the Southeastern Railway on the one hand and between the local press, trade and commercial interest and the Railways on the other hand.
- (c) The Government of Orissa has been advised that the Rai Coordination Directorate may be created as a part of State Government establishment for lisison purposes with the Railways at Bhubaneswar. In order to make the Directorate effective, it has also been suggested to the State Government that the Directorate be manned by Senior Railway Officials to be spared by the Railways on deputation basis if the State Government so desires.

## Total Length of Narrow Gauge Lines

4899. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) what is the total route kilometres of narrow-gauge, line-wise in the country;
- (b) what is the total amount required for conversion of narrow gauge into metregauge;
- (c) what is the route kilometres of narrow gauge proposed to be converted into metregauge during the Sixth Five Year Plan;
- (d) whether Pathankot-Joginder Nagar narrow-gauge is proposed to be undertaken during the Sixth Plan;
- (e) if not, what are the reasons therefor, and

(f) what is the expenditure the conversion of this line?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The total length of narrow gauge lines in the country is 4280 Kms.

- (b) Under the present policy existing narrow gauge and metre gauge lines if taken up for conversion, are to be converted to broad gauge in order to have uniform gauge throughout the country in the long run. The total cost of conversion of the narrow gauge lines excluding hill railways into broad gauge would be about Rs. 700 crores, while in the case of hill railways it would be prohibitive.
- (c) and (d). The list of narrow gauge lines to be converted into broad gauge during the Sixth Five Year Plan has not yet been finalised.
- (e) It is not proposed to consider conversion of Pathankot-Joginder Nagar narrow gauge line into broad gauge due to its high cost and constraint of resources.
- (f) No investigations have been made for the conversion of Pathankot-Joginder Nagar line so far. On an approximate basis the cost of the conversion of Pathankot-Jogiader Nagar NG line (164 Kms.) into BG would be about Rs. 80 crores.

# Excursion Tours for Domestic and Foreign Tourists

4900. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether Railway Administration in collaboration with India Tourism Development Corporation is contemplating to start excursion tours for domestic and foreign tourists;
- (b) if so, what are the details thereof; and
- (c) what are the details of the present excursion tours undertaken by the Railways and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) No.

- (b) Does not arise.
- (c) Railways do not as such sponsor or conduct any excursion tours, but only provide passenger coaches and special trains to anybody asking for it on fulfilment of the prescribed conditions and on payment of aormal tariff charges.

# Restructuring of Fertiliner Corpora-

4901. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Government have taken a decision for restructuring of Fertilizers Corporation of India and details thereof;
- (b) at what stage of implementation the decision stands;
- (c) whether Government have received representation/memorandum from the employees Association and other organisations details thereof; and
- (d) what steps have been taken to ensure that the interest of the employees does not get effected, on this account?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) and (b). The Fertilizers Corporation of India and the National Fertilizers Limited have been reorganised into the following. 5 companies w.e.f. 1st April, 1978:

Name of the Company Units/Divisions

 Fertilizer Corporation of India Limited.

Sindri (including Sindri Modernisation and Sindri Rationalisation), Gorakhpur, Talcher, Ramagum dam and Korba.

2. National Pertilizers
Ltd.

Nangal, Bhatinda and Panipat.

3. Hindustan Fertilizer Corporation Limited.

Namrup, Haldia, Barauni and Dugapur.

4. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited.

All units of Trombay and the gas based plants in the South of Bombay.

Fertilizer (Planning and Development) India Ltd.

(Plann- P& D Division of the Develop- FCI.

(c) ani (d). When the reorganisation proposals were under consideration, some representations were received from Employees' Associations etc., stating interactions that the proposed reorganisation had caused apprehensions in the minds of the officers and staff about their future. In order to safeguard the career prospects of

personnel in the new companies, it has been decided that promotion to the posts in the corporate cadre should be made on the basis of an inter-Company Promotion Committee to be set up for this purpose.

# Zone-wise Catering Staff

4902. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) what is the number of casual/temporary catering staff zone-wise engaged on the Railways;
- (b) whether the Government have received representation from the Union of these staff members;
- (c) if so, what are the important contents of the memorandum; and
- (d) the decision taken by the Government recently to improve service/working conditions of these staff members?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a)

•		470
		42
		172
		23
		54
		19
•		12
		12
		54
		174
	· · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(iii) All temporary posts in the departmental catering should be made permanent.

(ii) Betterment of their service conditions like permanent absorption in regular (d) The recent decision is in regard to absorption of Commission bearers as regular Class IV employees in a phased manner based on the length of their service. However, casual labour working in the Caterine, casual labour working in the Caterine, department are already being considered for regular absorption after screening as per extant rules. Temporary staff are confirmed in their turn as and when permanent posts become available.

# Loss to Railways during recent

4903. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) what is the estimated loss caused to the Indian Railways due to recent floods in various parts of the country, zone-wise;
- (b) how does it compare with the loss incurred by Railway during the previous year;
- (c) whether Government propose to take specific measures to avert threat of floods to rail lines on a permanent basis, in selected flood-prone tracts to avoid recurrence of high expenditure on maintaining the rail tracks; and
  - (d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The loss caused to Indian Railways due to recent floods during the period 1-5-78 to 31-7-78 zonewise is as under:—

S.No. Railw	'ay		(F	igure	Approxi- mate estimated loss sin lakhs of Rs.)
z. Central		•			2.17
2. Eastern					nil
3. Northern					0.27
4. North East	ern				1.20
5. Northeast I		ier			0.30
6. Southern					nil
7. South Cent	ral				2.40
8. South East					nil
g. Western	•	•	•	•	10.20
То	tal		• •		17.04

(b) The loss incurred this year during the period 1-5-78 to 31-7-78 is very much less as compared to the loss suffered by the

Railways during the corresponding period of the previous year.

Written Answers

(c) and (d). A statement is attached.

#### Statement

Steps taken to avoid flooding and damaging of Railway lines due to floods.

All Railway lines and bridges are designed and constructed so as to be safe against mormal floods. At the time of construction of new railway lines, careful study is made of the terrain, rainfall, drainage and flood records in the area, in order to ensure that the new line is not affected by the recarefully, the formation level of the track is kept above the flood level in the area and bridges with adequate waterway are pro-vided to let the flood waters of the rivers flow unhampered, so that safety of the railway line is not endangered. Special attention is given to bridges, which are normally designed for a flood frequency of 50 years after a careful consideration of hydrology and past history of floods. Their foundations are designed to withstand neavier floods than those of 50 years frequency.

- 2. The following steps are taken to pre-vent flooding and flood damage on the existing lines:
- 1. All bridges are carefully inspected every year and repairs to substructures, flaring, guide-bunds, pitching etc. carried out as necessary.
- 2. Waterways of all bridges are cleaned before the monsoons so that there is no obstruction to the flow of water.
- 3. Bridge cells review the adequacy of waterway of important and vulnerable bridges. Some bridges may be widened, raised, resttted or additional bridges constructed as a result thereof. Vulnerable bridges are kept under watch.
- 4. Wherever justified and otherwise feasible, the formation may be raised and/ or strengthened, pitched with stones or diverted away from the flood affected area, Training works such as groynes, bunds, pitching of river banks, guide bunds, etc. are provided for rivers where necessary.

Despite all the measures mentioned above, certain amount of flood damage on the vast railway system is unavoiadable.

3. In order to ensure safety of trains, keyman of the permanent way gang examines the track in his beat every day. During monsoons, night patrolling of track is introduced on sections likely to be damaged by breaches/floods. Stationary watchmen are posted at vulnerable spots and bridges. In addition, in the case of severe storms, the mate on his own initiative organises patrolling of track, irrespective of any other patrolling that may be in force. Immediate action is taken to protect the trains in case anything dangerous is observed.

तेल तथा प्राकृतिक वैस बायोग हारा किये गये चु-विज्ञान तका मुन्दीतिकीय सर्वेकण

4904. भी पुरेना शा सुमन : न्या पेट्रोलिक्स, रतावन और उर्चरक मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :

- (क) गत तीन वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक नैस आयोग ने देश के किन स्थानों पर अवैज्ञानिक तवा भूमीतिकीय सर्वेक्षण किये तवा उनके क्या परिजाम निकले: ग्रीर
- इस घवधि में सर्वेक्षण कार्यपर कितनी धनराशि **वर्षकी ग**ई?

वेदोलियम तथा रसायम और उर्वरक (भी हेमचरी मन्त्रम बहुगुणा) : (事) 1975-76 से 1977-78 के पिछले तीन वर्षों की धवधि के दौरान तेल तथा प्राकृतिक धैस भायोग ने जन्म-काश्मीर, राजस्थान, छत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, प्रानुध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, ब्रसम, नागालेण्ड, सिपुरा, ब्रक्णायल, प्रदेश, पश्चिम बंबाल, गुजरात, महाराष्ट्र भीर भण्डमान निकीबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में तेल तथा गैस की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ग्रन्वेची सर्वेक्षण विद्यो ।

प्रपतटीय क्षेत्रों में ये कार्य संचालन बम्बई हाई कोरो मण्डल समुद्रीतट, घरब सागर के सौराष्ट प्रपत्तट, दक्षिण बसीन संरचना, दक्षिण बसीन संरचनी के दक्षिण, वसीन रत्नगिरि, अंगरिका समुद्र तट, रत्न गिरि, मंगलीर, मंगलीर कोचीन, बम्बई रत्नगिरी उत्तर बसीन के उत्तर बम्बई हाई के उत्तर पूर्व, कराय-कल, पाण्डिकेरी, जिबेन्द्रम केपके मरिन, कोसीन के उत्तर पश्चिम, पश्चिम बम्बई के गहरे महाद्वीपीय कम्मतट, अण्डमान निकोकार डीप समृह के मन्मतट, क्षेत्र, और कृष्णा पोदावरी तट बसीन के क्षेत्रों में धायोजित किये गयेथे।

इन क्षेत्रों में विभिन्न किस्म के सर्वेक्षण आयी-जित करने के लिए भनेक फील्ड दलों को लगाया गया था । भू-गर्भीय दशों ने विस्तृत मानविज्ञों द्वारा 1105 वर्ग किलो नीटर, प्रध-म्यीरेवार जानविक्षा क्कारा 10,055 वर्ग किलो मीटर तिर्वक छैदी कारेचन हारा 1798 लाइन किलो नीटर, डोही सर्वेकण के मानचित्र द्वारा 8915 कियो बीटर-धौर भ्-प्राकृतिक विज्ञान धौर नव-वास्तु किल्वी बान-विक्षों हारा 144,900 किसी मीटर के बीक्ष में सर्वेक्षण कर लिया। भूकुम्पीय सर्वेक्षण करले वाले वजों ने सी0वी0पी0 सर्वेक्षण द्वारा 644% साइन कियो मीटर, प्रतिकिम्बत सर्वेकणों हारा 509

... pa .

साइन किसो बीटर, और परम्परागत प्रतिविभिनत सर्वेक्षणी द्वारा 5721 लाइन किसी मीटर क्षेत्र में सर्वेक्षण बायोजित किए । गुरुत-मुम्बकीय क्षेत्र में सर्वेक्षण करने वाले दलों ने 20309 केन्द्रों से इन भांकड़ों का परिमाप किया । अपतटीय केलों में मु-भौतिकीय सर्वेक्षण करने वाले दलों ने पिछले तीन वर्षी में कुल 50,077 लाइन किलो मीटरक्षेत्र का

(ख) पिछले तीन वर्षी में तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा मृत्यहास सहित भू-वर्धीय प्रौर म्-भौतिकीय सर्वेक्षणी परे निम्नलिखित वर्ष किया गेया था :

वर्ष	किया गया खर्च					
	(रुपए लाकों में)					
	क्षपए					
1975-76	832.30					
197 <del>0-</del> 77	704.14					
1977-78	785.67 (ग्रस्वाई)					

# बिहार में कुलिय पैस एचेंसियों का बावंडन

4905. ब्ही ब्हरेश जा सुमन : स्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार राज्य के विभिन्न शहरों में कितने व्यक्तियों को कृषिण गैस की एजेंसियां दी गई है और कितने व्यक्ति सभी इन एजेंसियों में साबंटन की प्रतीका सूची में हैं;
- (क) उन्हें एजेंसियां देने ने लिए न्या नीति निर्धारित की गई है अथका निर्धारित की जा रही है; म्रीर
- (ग) प्रतीक्षा सुची वाले व्यक्तियों को एजेंसियां धाइटित करने के लिए निर्णय कब तक किया जायेगा।

वेट्टोकियम तथा रसायम और वर्षरक मंत्री (बी हेमबती गण्यन बहुगुब्स) : (क) से (ग) . बिहार राज्य में विभिन्न शहरों में इस समय 34 कुकिंग गैस वितरक (एक उप-वितरक को मिलाकर) है।

श्चरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेकाकों के बनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्प-नियों की सभी प्रकार की एजेंसिया धनुसूचित जाति / धनुसूचित जनजाति के कोगों के लिए 25 प्रतिकत बीर बारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिक्षत कारिकत की जाती हैं और शेष 73 प्रतिक्षतः वाजिज्यिक महत्व को ध्यान में रख कर दी बार्चेगी, जिसमें बास्तविक उपधीक्ता सहकारी सोसाइटियों और एग्रो इण्डस्ट्रींक कार्पेरेशन को प्राथमिकता की जाती है। सभी नियुक्तियां

संबंधित क्षेत्र के समाचार पक्ष में प्रकाशित विकापन द्वारा चानेदन पत्र धार्मतिन करके के उसं।

एजेंसियों का धावटन करने के लिए कोई प्रतीका सूची नहीं रखी जाती है। एजेंसी के लिए न्यनितयों द्वारा दिये गवे भाषेदन पत्न पर तभी विचार किया जाता है जब यह धावेदन पक्ष तेल कम्पनियों द्वारा ऐसी एजेंसियों के लिए जारी किये गये विज्ञापन के उत्तर में दिए जाते हैं।

# पूर्वीसर रेसवे में गैनिसिक विनक

4906 भी सुरेन्द्र का सुमन : रेक मंत्री यह बताने की कुपा करेंगे कि:-

- (क) इस समय पूर्वोत्तर रेलवे में, डिबीजन-बार, कुल कितने नैमिलिक समिक हैं और उनमें एक वर्षे से अधिक नमय से काम करने वाले अमिकों की संक्या क्या है:
- (ख) उनमें से धनुषुचिन जातियों भीर धनु-सूचिन जनजातियों के भ्रमिको की प्रतिशतता क्या हैं; भीर
- (ग) क्या इन नैमिस्तिक अमिकों की सेवाझों को नियमित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

# रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (बी शिव नारायण) (事)

मंडल	ओड़	एक वर्ष से श्रक्षिक सेवा	
इञ्जलनगर	1167	574	
लबनक	2683	873	
वाराणसी	1855	1855	
समस्तीपुर	5603	3000	
गोरबपुर	7974	3572	
जोड़	19,282	9,874	

- (अ) सूचना इकट्ठी की जारही है भीर सभा पटल पर रखादी आयेगी।
  - (ग) एक विवरण संलग्न है।

## विवरस

भाकस्मिक श्रमिकों की सेवाएं नियमित करने के लिए निम्नलिखित कदन उठाए गए हैं ---

- (i) 1970 के बाद से चतुर्व भोगी में सामान्य भर्ती बन्द कर दी गई है और लगभग सभी रिनितयो प्राकस्मिक अभिकों की जांच-पड़ताल करके भरी जातीं हैं।
- (ii) इस आक्षय के अनवेश विए गए हैं कि कारवानीं, जोकी बेडों, वाडी-रीवनी

The Paris of the

स्थापनाध्रों, संवारी धीर माल डिस्वा हिपुधों, याडी भीर स्टेशनों जैसी कुछ जगहों में माल चढाने-उतारने तथा सिविल इंजीनियरी, सिगनल और पूल अनुरक्षण के पावधिक कामों को छोड़ कर, कोई धाक-स्मिक श्रमिक नियुक्त नहीं किये जायेंगे। सिविल इंजीनियरी, सिंगनम तथा युल अनुरक्षण के निरीक्षकों की स्थापना सहित इन सभी जगहों में समय-समय पर रेल प्रशासनों को संवर्ग समीका करनी होती है भौर भावश्यकतानसार नियमित पदों का सजन करना होता है।

- (iii) रेल प्रशासनों को यह सुनिश्चिन करने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं कि रेल पथ गैंगों में जहां रेल पथ धनरक्षण की यांत्रिक तथा धन्य धाधुनिक प्रत्रियाएं साग नहीं की गर्वी वहां जितने कमेचारी मंजूर किए गए हों वे सभी नियमित भाषार पर रखे जायें। दूसरे खण्डों में जहां रेल पथ के अनुरक्षण के आधुनिक तरीके लागू किये जाने के कारण गैंग के कर्मचारियों की संख्या प्रत्येक मामले के गण-दोष के भाधार पर निर्धारित की जानी होती है वहां अपेक्षित क्य नियमित भाषार पर भरे जाने चाहिएं।
- (iv) जिन स्थानों पर ब्राकस्मिक श्रमिक नहीं रमाने होते भीर यदि वहां आंच-पड़ताल किये गये या वने गये उम्मीदबारों के सभाव के कारण सथवा किसी सौर कारण से नियमित रूप में रिक्तियां भरना सम्भव न हो तो ऐसी रिक्तियों पर लगाये गये भतिरिक्त व्यक्तियों को बेतन की मासिक दर पर एवजियों के रूप में नियुक्त किया जायेगा न कि वैनिक दरों पर बाकस्मिक अमकों के रूप सें।

# उत्तर विद्वार तथा दिल्ली के बीच चलने वाली वयन्ती जनता भाड़ी

4907. भी सुरेन्द्र जा सुमनः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि जयन्ती जनता वाडी उत्तर विहार और दिल्ली के बीच सीधी चलने वाली एकमाझ गाड़ी है जोकि सप्ताह में दो बार चलती है,
- (ब) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों की क्यी के कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई हो रही है और क्या मैझालय की जयन्ती जनता गाड़ी को प्रतिदिन चलाने के लिए सोगों से धनुरोध प्राप्त हुआ
- (ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिनिया है?

रेल मंत्राचय में राज्य मंत्री (श्री सिंब नारायस ): (क) सप्ताह में दो बार चलने बाली 153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस के शलाबा, उध्य सर्विस डिब्बे प्रतिदिन नई दिल्ली और मुजफ र-पुर के बीच 2 85/86 असम मेल में चल र हैं।

(व) भीर (ग). सप्ताह में दो बार बलने बाली 🛊 153/154 मुजपफरपुर--विल्ली जयन्ती जनना एक्सप्रेस की बारंबारता में वृद्धि करना या इस मार्ग पर एक प्रतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी का चनाया जाना मार्गदत खण्डों में लाइन क्षमता के. प्रभाव और विस्त्री-क्षेत्र में पर्यन्त सुविधाओं की कमी के कारण, स समय परिचालनिक दक्टि से व्यावहारिक नहीं है।

#### Procedure for issue of Priority lettera. for Gas Connections

4908. SHRI MADHAVRAG SCINDIA: Will the Minister of PETRO-MADHAVRAG. LEUM, CHEMICALS AND FERTILIZ-ERS be pleased to state :

- (a) the present procedure being adopted for issue of priority letters to general public for domestic gas connections in urban as well as rural areas throughout the country;
- (b) whether in the absence of properprocedure, the consumers wanting new connections are not able to register their demands with the dealers or with Indian Oil Corporation directly; and
- (c) if so, what steps are being taken to modify the existing procedure so as to enable consumers wanting new connections to register their names with authorities concerned?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) to (c). Applications for cooking gas connections are required to be registered with the cooking gas distributors of the oil com-panies. The gas connections are released by the distributors from amongst those who are registered on a first-come, firstserved' basis, and a waiting list is maintained. Some connections are being released by the distributors on pricerity basis on the advice of the oil companies. Advice is also being given to oil companies by the Ministry for issue of such priority connec-

Generally gas connections are given on . priority to Members of Parliament and State. and the state of t

Legislatures, other VIPs, foreign dignitaries, cases of hardships, commercial contacts, Government Organisations / Institutions etc.

According to oil companies, the registration of names for granting Liquefied Petroleum Gas (cooking gas) connections had been discouraged in certain areas by them in view of the continued shortages of the product compared to its demand.

The oil companies have been advised to start fresh registrations, wherever necessary, keeping in view thepossibilities of enrolment of new customers on a significant scale from about 1980, when substantial quantities of cooking gas will start becoming available.

### Efforts to find Oil off The Kergla Coast

4909. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of PETRO-LEUM, CHEMICALS AND FERTILIZ-ERS be pleased to state:

- (a) whether a proposal to intensify, efforts to find out oil off the Kerala Coast is under consideration of the Government in near future; and
- (b) if so, details therein and steps that have already been taken or proposed to be taken in this regard during the coming year?

THE MINISTER OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZ-ERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) and (b). ONGC had drilled an exploratory well 60 Kms. north-west of Cochin during April-May, 1978. This well was drilled to a depth of 1755 metres. However, as no oil or gas was found, the drilling was suspended.

Further exploration programme in the area will depend upon the interpretation of the data obtained from this well and the seismic data of the area collected earlier.

# Removal of Dr. R.R. Jaipuria from Management of Swadeshi Cotton Mills

4910. SHRI K. MALIANNA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether it is a feet that Mr. R.R. Jaipuria who is responsible for mismanagement of Swadeshi Cotton Mills Company Limited has since been removed from that post;
- (b) if so, what are the details and since when he ceased to be Managing Director;and

(c) what Government propose to do to save Swadeshi Mining and Manufacturing Company Limited (having two sugar Mills) a subsidiary of Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd., from onslaughts of mismanagement of Dr. R.R. Jaipuria!

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRII SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). The company's proposal under section 269 of the Companies Act, 1956 for the re-appointment of Dr. R.R. Jaipuria as Managing Director of the company for the period from 1-7-1977 to 31-8-1980 has been rejected by Department in May, 1978. He ceased to be the Managing Director of the Company with effect from 1-9-1977. A representation has been filled by the company against the said rejection which is pending.

(c) The Government has no material to indicate any acts of mismanagement by Dr. R.R. Jaipuria who is the non-executive Chairman of Swadeshi Mining and Manufacturing Company Limited.

# Complaints regarding Production of Oxytetracycline

- 4911. SHRI MOTIBHAI R. CHAU-DHARY: Will the Minister of PETRO-LEUM, CHEMICALS AND FERTILI-ZERS be pleased to state:
- (a) the nature of complaints received during past three years from various Members of Parliament about Oxytetracycline and its excess profits, addressed to the Minister and the former Prime Minister with details;
- (b) what action was proposed by the former regime and what action has been taken in this regard so far; and
- (c) if no action has yet been taken, reasons therefor?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H.N. BAHUGUNA): (a) to (c). The following points were raised in the main by certain members of Parliament in their letters addressed to the Minister (PC&F) and the former Prime Minister during the last 3 years, about manufacture of Oxytetracycline and excess profits thereof by M/s. Pfizer Ltd.

- (i) Regularisation of their excess production of Oxytetracycline:
- (ii) Non-execution of Export Bond by M/s. Pfizer.
- (iii) Substantial profits on unauthorised production of Oxytetracycline and its formulations since there was no price fixation based on cost examinatian of Oxytetracycline.

- (iv) Suit in USA against M/s. Pfizer of USA charging them with violation of Anti-trust laws in the manufacture of and sale of a group of broad spectrum antibiotics.
- 2. The present position on each of the above points is as under :-
- (i) Regularisation of excess tion of Oxytetracycline beyond the licensed capacity of M/s. Pfizer will be considered in the light of the New Drug Policy.
- (ii) The position in regard to non-execution of Export Bond has already been explained in reply to Lok Sabha Starred question No. 236 answered on 1-8-78.
- (iii) In 1970, when Drug Prices (Control) Order, 1970 came into force, M/s. Pfizer declared the price of Oxytetracycline Hel. at Rs. 960/kg. as they were entitled to, since this item was not included in Schedule I to the said Order. The prices of formulations of Oxytetracycline are allowed based on the above price. BICP conducted cost-cum-technical examination for Oxytetracycline and submitted their report to the Government in the year 1975. Based on the report of the BIGP, Govt, reduced the price of Oxytetracycline from Rs. 960/kg. to Rs. 725/kg. for captive use and Rs. 749/kg. for sale to other non-associated formulators. The prices of formulations based on the reduced price of Oxytetracycline have already given effect to the reduced prices.
- (iv) Government of India filed a suit on 11-10-74 againstsix US Drug Manufactur-ing Companies, including Pfizer for allegedly having entered into a conspiracy for concerted price fixation and over-charging on domestic as well as overseas sales of Broad Spectrum Antibiotics in violation of the US Anti-Trust Laws. The Anti-Trust Laws provide that "any person who shall be injured in his business or property by reason of anything forbidden in the Anti Trust Laws may sue therefor in any District Court of the United States .....and shall recover three-fold the damages by him sustained and the cost of suit, including a reasonable Attorney's icc."

The defendant Companies had contended before the US Supreme Court that a "foreign nation" was not a "person" as defined in the Clayton Act (Anti-Trust Statute) and was, therefore, no eligible to sue them in US Courts.

The US Supreme Court in its judgement delivered on 11-1-1978 has, however, ruled against the defendant companies and held that foreign Governments may sue them in US Courts for "treble damages". The claims are now being processed further.

# News regarding Government Nominees on Board of Directors of private Companies

- 4912. SRHI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state
- (a) whether Governments' attention has been drawn to the news item pub-lished in the 'Economic Times' dated 22nd June, 1978 under the Caption 'Directors on Private Campanies';
- (b) if so, under what special circumstances the Government will place its nominees on the private sector companies;
- (c) in case of defalcations of funds and frauds, how minority shareholders will be able to save their interest and insist on placement of Government nominees on the Boards of Private Companies?

# THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

- (b) In order to prevent the affairs of the company being conducted in a manner oppressive to any members of the company or in a manner which is prejudicial to the interests of the company or to public interest, Government nominees are ap-pointed in public and private limited companies under Section 408 of the Companies Act, 1956. As and when such cases come to the notice of the Central Government, appropriate action as per provisions of the Companies Act, 1956 will be taken.
- (c) In case of defalcation of funds and frauds, the minority shareholders may bring the matter to the notice of Government. If Government is satisfied after inspection or investigation into the affairs of the company that the charges are substantiated, it will take action to-appoint Government directors in the Board of the Company under Section 408. of the Companies Act, 1956.

### Release of canalised bulk drugs to-M/s. Pfizer, Sandox and Hoechst

- 4913. SHRI RAMDEO SINGH: Will the Minister of PETROLEUM, CHE-MICALS AND FERTILIZERS bepleased to state:
- (a) whether it is a fact that M/s Pfizer, Sandoz and Hoechst have been granted canalised bulk drug in 1977-78 substantially in excess of the quantities released to them. in 1974-75 and 1975-76;

- (b) if so, under what provisions of ITG policy and rules laid down by the Ministry these releases were affected; and
- (c) details of bulk drugs released in favour of these companies, each bulk-drug wise along with licensed capacity and what action is proposed to be taken against the officers for flouting statutory conditions?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA).

(a) A statement showing the releases of canalised bulk drugs actually made by IDPL and CPC to M/s Pfizer, Sandoz and Hoechst during during 1975-76, 1976-77 and 1977-78 is attached. These releases were made in accordance with the parameters prescribed for distribution of canalised raw materials from time to stime.

(b) All the three companies mentioned above are DGTD units. Policy regarding distribution of canalised bulk drugs to DGTD units during the last three years has already been indicated in reply to Lok Sabha Starred Question No. 339 answered on 8-8-78. This policy is in line with the provisions in the I.T.C. Policies of last three years whereunder DGTD units were allowed import of raw materials by way of replenishment of such raw materials consumed in any

of the previous two years, whichever is advantageous.

(c) Details of canalised bulk drugs released to the three companies have been indicated in the attached statement. These releases were not linked to requirements as per licensed capacities for individual formulations being produced by them. From the total releases of various items of canalised bulk drugs, DGTD units could manufacture their range of formulations to the extent of market demand. In view of this, it was possible for such units to have produced certain formulations in excess of their approved capacities.

The policy relating to regularisation or otherwise of production in excess of licensed capacity is contained in the Statement laid on the Table of the House on 29-3-78 containing decisions of Govt. on the recommendations made by the (Hathi) Committee on Drug Industry. In terms of the new drug policy it has also been decided in such cases to issue consolidated industrial licences to drug manufacturing units indicating therein, interms of bulk drugs to be consumed. Once this is done, the release of canalised bulk drugs to DGTD units would get linked to their licensed capacities.

#### Statement

	Statement				(Figs. i	n Kgs.)	
Name of the Company	Canalised bulk dru	Canalised bulk drug		QTY released in			
-		_	ı	975-76	1976-77	1977-78	
ı	2			3	4	5	
	CPC items						
M/s. Hoechst Pharmaceu	ti- Chloroquin Phosphate	•		230	••	1 75	
cals Ltd.	Prenylamine Lactate .	•		170	435	435	
	Prednisolone · .				••	19.5	
	Vittamin B6			150	65	170	
	Caffienc				٠.	645	
	Chloramphenicol Powder			N.A.	3137	3015	
	IDPL Items					نتر ، نتر ،	
	Tetracycline Hel.			14710	14180	14180	
	Tetracycline Base			745	1000	1 000	
	Streptomycin Sulphate			5025	5930	5 930	
	Vit. Br oral .			66	66	140	

. . ..

±	, 8	1773		, v∞ ± <b>S</b> ÿ i'ş	may 🛊	6
	Vit.B2			28	30	
	Analgin .	•	•	125000	13117	
M/s Sandoz (I) Ltd.	. CPC Items	•	•		.3/	, 120970
10	Chloroquin Phosphate		_	185	100	100
·	Vit.B6			240	200	20
* + 1	Caffeine					520
	Chloramphenicol			N.A.	900	-
t	Powder					
	Chloramphenicol Palmitate	•	•	250	265	
	Vit. 'C' Plain .	•	•	3465	3720	4725
	Vit. 'C' Coated .  IDPLitems #	•	•	2340	2940	385
	, , ,					
-	Tetracycline Hel Vit. Br-Mono	•	•	3 <sup>2</sup> 35		3050
	Folic Acid	•	•	215	410	480
-	Vit. Ba	•	•	38.7	49.5	48
	Phenobarbitone	•	٠	59		180
	Amidopyrine	٠	٠	1312	1975	-
	Amaopyrme	•	•	890		1050 ipto III arter)
	Tetracycline Base .				900	1250
M/s Pfizer Ltd.	IDPL items					
	Streptomycin Sulphate		•	27695	12000	2000
	Sulphadimidine .			11050	11150	10000
	Piperazine Hexa-Hydrate	•			5000	13185
	Oxytetracycline Hel			•••		5000
	Vitamin B: Hcl.				••	150
	Vitamin B: Amp.			129	100	<b>5</b> 0
	Vitamin B: Mono			5579	6124	8800
	Vitamin Be			2736	2998	3550
	Folic Acid			226	236	250
	Vitamin B2-5-Phos .			93		
	GPC Items					
4.1	Vitamin B6			` 1205	88o	1505
	Chloroquin Phosphate			465	550	775
•	Calcium-D-Pantothenate			3175	3445	3821
	D-Panthenol .			8o	78	75
	Vitamin C			38755	4 <sup>0</sup> 575	45430
	Citric Acid .		•	worth Rs. *40337	worth Rs. *34778	••
	Tartaric Acid		•	worth Rs. *379°5	worth Ra.	worth Rs.
" · .	Prednisolone .	•		••	265	203-5

# सौराष्ट्र में पुष्ठ उद्योगों की वैधन सम्बन्धी शांत

4914. भी वर्ग सिंह माई पटेस : क्या रेस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) 16 मई, 1978 से 15 जुलाई, 1978 तक पोरबन्दर, राणाबाब, घोरजी, उपलेटा, माणाव-दर में उद्योगों की, उद्योगवार, कितने बैगनों की मांग बकाया थी;
- (ख) 16 नई, 1978 से 15 जुलाई, 1978 तक की ध्रवधि के दौरान उद्योगपतियों को कितने बैगन सप्लाई किये गये थे; झौर
- (ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योगपतियों और आपारियों को बैगन मुविधापूर्वक; नियमिन रूप से और पूरी तरह से उपलब्ध हों, कोई योजना प्रथवा कार्यक्रम तैयार किया गया है; यदि हां, तो तत्त्राचन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (की तिश्व नारायण): (क) से (ग). 16 मई, से 15 जुलाई, 1978 तक की मन्नीय के दौरान उस्लिक्ति स्टेमनों पर उद्योग-वार सादे गये माल-डिब्मों की संख्या धौर 15-7-1978 को तथा 31-7-78 को रह किए गये मांग पत्नों सहित बकाया मांग पत्नों की संख्या धनुबन्ध 'क' के रूप में संसम्म विवरण में दी गई। है।

स्पष्टतया कुछ बस्तुओं के लिए मान पत्न बहुत बढ़ा-चड़ा कर पेश किये जाते हैं जैसा कि इस तस्य से प्रकत होता है कि जब मालबिक्यों की सप्लाई बढ़ा दी गई तब भारी माला में मांग पत्न रह कर दिये गये।

मालडिक्यों की सप्लाई मांग पत्नों की वरीयत है और प्राथमिकता के बनुसार की जाती है और प्राथमिकता के बनुसार की जाती है और प्राथमिकता के बनुसार की जाती है कीर प्राथमिक के बाब-तेनों के मामले को छोड़ कर मांगों के संतोच जनक है वे सुरा किया जा रहा है। बाब-तेनों की व्यक्तिका मांगों के गल्लव्य स्टेसन पूर्वोत्तर सीमा रेसके पर स्थित हैं और कृषि इस क्षेत्र पर प्राप्त के स्थलन के जिए भारी मांग रहती है इसलिए उनके संखलन को कोटे द्वारा बिनासित किया जाता है। इस बस्तु के सदान को या सम्भव बनाये रखने के लिए रेस प्रशासन. हारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

### विवरण

उद्योग	16 मई, से 15	वकायाः	167-78 से 31-7-78तंक		
	जुलाई, 1978 तक की संबंधि में सदान	15-7-78 को	31-7-78 新		प्रविध में
सीमेण्ट	4810	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई	नहीं
रसायनिक उद्योग	1385	65	100		15
चाक मिट्टी	482	1761	13		1614
साबुन पत्पर	14	; 22	21		
चूना पत्थर	3650	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई	नहीं
क्षेत्रीय नमक	11	कोई नहीं 🤚	कोई नहीं	कोई	नहीं
गैर-क्षेत्रीय नमक	8	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई	नहीं
तेम	405	1153	1848		42
<b>ब</b> ल	81	222	7		222
वर्ष की नाठें	214	3	कोई नहीं	कोई	महीं
जनता के लिए धनाज	31	3	1	कोई	नहीं
विनीला	11	34	3		3'4
प्याज	279	766	40		673
भीध		15.	43	कीई	नहीं

# सम्पत्ति के प्रधिकार के स्थान पर प्राजीविका का वविकार

193

4915 हा॰ रामजी सिंह: नया विधि. न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा

- (क) क्या जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत में यह बायदा किया गया था कि मल प्रधिकारों की सूची में सम्पत्ति के प्रधिकार के स्थान पर प्राजीविका का प्रधिकार रखा जाएगा :
- (म्ब) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रबातक क्या कार्यवाही की है :
- (ग) क्या सरकार भाजीविका का भश्चिकार देने के पक्ष में नहीं है; भीर यदि हां, तो क्या े यह कायदे से मकरना नहीं है: ग्रीर
  - (घ) यदि भाजीविका का अधिकार नहीं दिया जाता तो रोजगार गारंटी योजना ग्रथवा बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया **2** 3

विधि, न्याय भीर कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण ): (क) जनता पार्शिक निर्वाचन घोषणा-पत्र में यह वचन दिया गया था कि सम्पत्ति को मूल ग्रधिकारों की सुची से निकाल दिया जाएगा ग्रीर उसकी वजाए काम के अधिकार की पुष्टि की जाएगी।

- (ख) मूल अधिकार के रूप में सम्पत्ति के अधिकार को संविधान (पैतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978 द्वारा निकाल देने का प्रस्ताव है।
- (ग) भ्रौर (घ) सरकार का विचार है कि काम के और बेरोजगारी राहत के अधिकार को मत अधिकार के रूप में सम्मिलित करने का उचित प्रथम उस प्रकम पर पहुंचने के बाद होगा जब वेरोजगारी की समस्या को बुनियादी तौर पर हल कर लिया गया हो भौर कुछ थोड़े से ही लोग बेरोजगार रह जाएं जो बेरोजगारी राहत पाने के हकदार होंगे । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सभी व्यक्तियों का लाभप्रद नियोजन देने के लिए उचित परि-स्थितियां भीर नीति तैयार की जा रही है।

## Setting up of a Polyester Filament Yarn Plant at Devas

1916. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether Mafatlal Group have submitted any proposals to Government for setting up a Polyester Filament Yarn Plant at Devas involving an outlay of Rs. 25 crores or so; and
- (b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) Yes, Sir. The proposal is for manufacture of Polyester Filament Yarn as well as Polvester Fibre.

(b) The proposal is under consideration in the Government.

# Memo from All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Association

- 1917. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) whether the Prime Minister had received a Memorandum from All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees' Association on 5th May, 1978 embodying a demand for recognition to the Association;
- (b) whether Government have considered that demand: and
  - (c) if so, the decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) A memorandum submitted to the Prince Minister listing a series of demands including a demand for recognition of the All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees' Association has been received.

(b) and (c). In accordance with the policy of the Government, no Association formed by the employees on the basis of any caste, tribe or religious denomina-tions can be granted formal recognition.

# कोरबा में कोयले पर ग्राधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

4918. भी भारत सिंह चौहान : भी सुखेन्द्र सिंह : भी गोबिन्द राम मिरी :

क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उबंरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

- (क) क्या मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर कोयले पर बाधारित उर्वरक संग्रंत्र की स्थापना की जारही है;
- (ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि कोयला उपलब्ध न होने पर भी संयंक्ष में उर्वरक का उत्पादन होता रहेगा; भौर
- (ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव पर श्रव विचार किया जायेगा तथा इसे कियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी?

है।

(ख) और (ग). कांयने पर आधारित उबंरक प्लांट दूसरे फीड स्टाक पर नव तक नहीं चलाये जा सकते जब तक कि उनमे भारी लागत पर बढ़ें पैमाने पर संगीपन न किया जावे। कोंरवा में कांयन की पर्यान उपलब्धना का विचार में रखते हुए वैकल्पिक फीड स्टाक की व्यवस्था करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

के 1979 के धारम्भ में चाल हो जाने की घाणा

# Location of Vertilizer Plant in Maharashtra

49° a. SHR1 D. B. PATH.: Will the M.nister of PETROLEUM, CHEMI-CALS AND FERTHAZERS be pleased to state:

- (a) whether it is fact that he has laid a precondition for approval of Thal-Vaisher as a site for the proposed Fettilizer Plant to be located in Maharashtra State that the Government of Maharashtra should agree to the proposed stage-five expansion of the Fertilizer Factory at Turkhe (Bombay);
- (b) whether it is a fact that the Bombay Corporation has objected to the expansion on the ground of air-pollution; and
- (c) what is the reaction of the Government of Maharashtra to the above-mentioned condition?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA); (a) No, Sir.

(b) and (c). The issue of a 'No objection certificate' for the Trombay IV & V Expansion schemes is under the consideration of the Bombay Municipal Corporation.

# फर्चचार--मालानी बाढ गेव लाइन का तर्वेक्रण

4920. डा॰ महाबीपक सिंह साक्य: क्या रेल मधी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या रेलवे बोर्ड के निदेश पर पूर्वोत्तर रेलवे में फर्टखाबाद—शाहग्रहांपुर मालानी बाड गैज लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है ; ब्रीर
- (ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं और इस लाइन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हो।

(छ) प्रस्तावित लाइन, जो 154 कि॰ मी॰ लम्बी होगी धीर जिस पर 33 करोड़ रुपए खर्ब धाने का अनुमान हैं, से प्रतिफल घटिवाला होगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है। इस लाइन के निर्माण के बारे में कोई विनिश्चित देश के पिछड़े क्षेत्रों में नई लाइनों के निर्माण के लिए निधियों की उपलब्धना पर निर्भर करेगा।

# कुकिंग गैस के निश्लेष

4921. **दा० महाबीपक सिंह शास्य**: क्य पेट्रोलियम, रसायन श्रीर उर्वरक मुखी यह बताने के कृपा करेंग कि:

- (क) क्या भारत सरकार को कुकिंग गैम के बड़े निक्षेप मिले हैं :
- (ख) यदि हां, तो इसमें कृतिस सैस की कमी को किम हद तक दूर किया जा सकेगा ; धीर
- (ग) तथा उसकी वितरण प्रणानी को संविध-जनक बनाने हेतु सरकार का विचार नई एवंसियां देने का है और यदि हो, तो इसके लिए क्या मानवण्ड अपनाया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्धरक मंत्री (भी हेमबती नवन बहुगुणा): (क) सम्बद्ध गैम और प्राकृतिक गैस से विक्षण्डिन होने के बाद तरल पेट्रॉलियम गैस (खाना पकाने की गैस) उपलब्ध होगी । बम्बई हाई से प्रणोधित तेल के साथ एसी-मिएटिड गैस उपलब्ध है। दक्षिण बसीन से प्राकृतिक सम्पन्न के का प्रस्ताद है। विखण्डन के बाद लगभग 150,000 मी० टन प्रतिवर्ष तरल पेट्री-लियम गैस उपलब्ध होगी।

- (ख) विकाष्ट्रत होने के बाद भीर मधुरा सोधन-साला भीर कोमाली ए सी सी यूनिट के मारम्भ होने के बाद तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता वर्ष 1080-81 के बाद झल्प झबधि में ही 100 प्रतिस्त वह जायेगी।
- (ग) उक्त तरल पेट्रोलियम गैस के विपना के लिए तेल कम्पनियां अतिरिक्त एजेंसियों की स्था है करने के लिए कदम उठायेंगी। वर्तमान सरकार

गीति के अनुसार अनुसूचिन जाति/अनुसूचिन जनजाति के लोगों को 25 प्रतिशत एजेंसियां दी जाती हैं शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत और शेष वाणिज्यिक महत्व को ध्यान में खकरदी जाती हैं, वास्तविक उपभोक्त सहकारी सोसाइटियों और एग्रो-इन्डिस्ट्रियल कार्पोरेशन को प्रथमिकता दी गई है।

# उर्वरकों का ग्रायात

4922 डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या खेलियम तथा रसायन चौर उर्वरक मंत्री यह बताने की कुंग करेंगे कि :

- (क) 1977-78 में विदेशों से कितनी मात्रा में रसायनिक उर्वरकों का ग्रायात किया गया ;
- (ब) राज्यवार कितने एकमात्र एजेंन्टों को किरण के लिए इन उर्वरकों की सप्लाई की गई ; और
- (ग) क्या सरकार का विचार गत वर्ष स्रायात किए गए उर्वरकों की तुलना में इस वर्ष स्रधिक इंदकों का स्रायात करने का तथा इनकी बढ़ती हुई मांग तथा इनके वितरण में कठिनाइयों को ध्यान में खते हुए क्या सरकार का विचार एक मान्न एकंटों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रीर उर्वरक मंत्री भी हेमदती नन्दन बहुगुणा): (क) 1977-78 के रीग (वास्तविक पहुंच के आधार पर) रसायन, कंकों की 2873855 मीं टन मात्रा का सरकार शरा आयात किया गया था।

- (ख) स्वदेशी उत्पादन से उपलब्ध मात्रा तथा कृषि की आवश्यकताग्रों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए आयातित उर्वरक राज्य सरकारों को प्रावंदित कियें जाते हैं। बदलें में राज्य सरकारों मुख्यतः स्कारी एजेंसियों और सहकारिता संगठनों और कृषि उद्योग निगमों आदि जेसे संस्थागत एजेंसियों द्वारा उर्वरकों का किसानों में वितरण करते हैं। परन्तु कृष्ठ मामलों में राज्य सरकार इन वितरण तथा निजी वितरकों को पुनः आवंदन भी करती हैं। आयातित उर्वरकों का राज्यों में वितरण करने के लिए भारत सुरकार ने कोई ऐजन्ट नियुक्त नहीं किये हैं।
  - (ग) यह जानकारी देना जनहित में नहीं है।

# शाखा लाइन का विस्तार किया जाना

4923. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री वह बताने की कुपा करेंगे कि :

(क) कितनी शाखा लाइनों का छठी पंचवर्षीय शेजना में विस्तार करने का प्रस्ताव है, ग्रौर क्या सके बारे में सर्वेक्षण कार्य को ग्रन्तिम रूप दिया जा का है ; ग्रौर (ख) यदि हां, तो उन शाखा लाइनों के नाम क्या हैं, जिन पर कार्य शुरु हो चुका है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण)ः (क) छठी पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में विस्तार कीये जाने वाली शाखा लाइनों की सूची को श्रभी श्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

- (ख) 1978-79 में निम्नलिखित तीन नई रेल लाइनों का निर्माण श्रारम्भ किया गया है।
  - (i) ग्राप्ता से रोहा।
  - - (iii) कल्याणी से कल्याणी टाउन शिप तक ।

# Investigations into allegations against the Managing Director of Tin Plate Company

4924. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to Unstarred Question No. 9685 on the 9th May, 1978 regarding 'Salary and Perquisites of Managing Director of Tinplate Company' and state:

- (a) whether the allegation has been investigated into since then; and
- (b) if so, the finding thereof and action taken thereon ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Taking into consideration the findings of the Inspection under Section 209A of the Companies Act, 1956, the proposal of the company for the re-appointment of Shri Arun Chakravorty as Managing Director has not been approved and the decision has been communicated to the company.

# Private Employment without Government permission

4925. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3597 on the 13th December, 1977, regarding malpractices indulged in by Shri L. S. Darbari, Director, Vigilance, Ministry of Commerce and State:

(a) the action taken or proposed to be taken against Shri L. S. Darbari for taking up consultancy work without Government permission in violation of the provisions of the Civil Services Regulations;

(b) the Ministry which sanctioned his pension; the amount thereof and the substantive post held by him at the time of retirement:

Written Answers

- (c) whether he is aware that Shri Darbari has also taken up consultancy work with a larger industrial house and is running a concern named L.S. Darbari and Associates, to Pant Marg, New Delhi; if so, whether he obtained Government permission in this case or not; and
- (d) whether he would place on the Table of the House a copy of the application submitted by him in this behalf and Government's letter granting him permission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) (a) As already stated in reply to Lok Sabha Unstarrd Question No. 3597 answered on 13th December, 1977, Shri L. S. Darbari had not sought prior permission of the Government to take up part time consultancy work with M/s. Vaishali International Private Limited. Shri Darbari has in his reply stated that taking up consultancy work does not attract Government's instructions on commercial employment, adding further that permission may be granted if the Government decides otherwise, This is under examination in consultation with the Department of Personnel & Administrative Reforms.

- (b) Shri Darbari, prior to his retirement held the post of DIG/Police on substantive basis in the C.B.I., who have sanctioned a pension of Rs. 948/- p.m.
- (c) Shri Darbari has intimated that he has set up his own legal consultancy service titled "L.S. Darbari Associates, A-157, New Friends Colony, New Delhit10014." No formal request for Government's permission has been made by him in this behalf.
- (d) Does not arise in view of answer to (c) above.

## U.S. Lawyer engaged by the former Prime Minister

4926. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether one Mr. William Sheffield; a U.S. Lawyer has been engaged by the former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi to look after her legal affairs;
- (b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether the Government has enquired into the source wherefirm this U.S. Legal expert is being paid by Shrimati Gandhi in dollars?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRII SHANTI BHUSHAN): (a) It is understood that Mr. William Shtffield, a U.S. lawyer, had voluntered to render legal assistance to Mrs. Gandhi, the feamer Prime Minister, in the cases pending against her in the court of Chief Metropolitan Magistrate, Delhi, without any remuneration. He had not formally appeared for her in any of the Ceurt cases.

(b) and (c). Do not arise.

## Acquisition of Assests of Heilgers sub-Group

4927. SHRI JYOTIRMOY I CSU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Shri Pran Prashad's lamily acquired the Heilgers sub-group with assets of over Rs. To crose as family property following on the 1972 bifurcation of Birds Heilgers group of which he was the Chairman;
- (b) if so, whether the inquiry cenducted by Shri Salil Gupta (of Gupta Ghosh and Chowdhery Chartered Accountants) as an inspector on behalf of the Company Law Board had found the 1972 transactions as "irregular"; and
- (c) if so, what are the details thereof and action taken thereon?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPNAY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUHAN): (a) to (c). Shri Salil Kumar Gupta one of the Inspectors appointed under section 237(b) of Companies Act, 1956 to investigate into the affairs of the companies belonging to Bird & Heilgers group, has in his interim report on M/s. Bird & Cc. Ltd. mentioned an irregularity about management of the saying trust by Shri Pran Prashad and Shri K. L. Dua, erstwhile directors of M/s. Bird and Co. Ltd. and trustees of the fund to the deriment of interest of saving trust and with a view to give benefit to Shri Pran Prashad and his family members, through purchase and sale of shares from/to the family members of Shri Pran Prashad and from trusts in which he was interested, at arbitrary prices during bifurcation in 1972. The final report of the Inspector is awaited.

This and other points brought out in the report are under examination. After completion of the same, the matter will be Considered by the Company Law Board for such action as may be considered necessary.

# सरकारी खेत में कारकाने तथा धन्य प्रतिष्ठान

- 4928 भी सुनाव आहूना: क्या विधि, न्याय और कल्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सरकारी क्षेत्र के ग्रन्तर्गत कुल कितने कारखाने, निगम शीर ग्रन्थ प्रतिष्ठान हैं; ग्रीर
- (ख) उनमें गत एक वर्ष के दौरान किन-किन व्यक्तियों को चेयरेमैन, निदेशक द्यादि के रूप में नियुक्त किया गया !

विधि, स्वाय और कस्पनी कार्य संती(श्री शांति भूकरण): (क) कस्पनी प्रधिनियम की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कस्पनियां, मार्कजिक केला का एक प्रमुख अंग हैं। देश में 31—3—1978 तक 745 सरकारी कस्पनियां कार्यरत थी। इनमें में 159 ऐसी कस्पनियां थीं जिनके सम्पूर्ण प्रथवा बहुसंख्यक शेयर केल्य्रीय सरकार के थे। 548 ऐसी कस्पनियां थीं जिनके सम्पूर्ण प्रथवा बहुसंख्यक हिस्से राज्य सरकारों के थे, तथा ऐसी 38 कम्पनियां थीं जिनके केल्य्रीय सरकार के थे। 548 ऐसी कर्मानियां थीं जिनके सेल्य्रीय सरकार केले हिस्से राज्य सरकारों द्वारा भिनाकर, बहुसंख्यक हिस्से भारत्वा विभागिय उपक्षम हैं, जो सार्वजिक केला नियम नथा विभागीय उपक्षम हैं, जो सर्वजिनक केला होने से स्वाप्ती में विभाग प्रथितियम की सीमाल्तर्गत नहीं होते। अन दनके बारि में सुबता उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय मरकार की कम्पानियों तथा सांविध्यक निरामों के सध्यक्ष तथा प्रबन्ध निरोमकों की नियुक्तिया, सम्बन्धित प्रणासनिक संवालय तथा विक्त समानय थ्यूरों प्राफ पब्लिक इस्ट्राधा नेज के पब्लिक स्ट्राधा नेज के पब्लिक स्ट्राधा नेज के पब्लिक स्ट्राधा नेज के पब्लिक स्ट्राधा नेज कर वार्थ से प्राप्त निफारिजों पर लेखीय सरकार द्वारा की जाती है। 28 मई, 1977 ने 23 जून, 1978 तक की प्रविध के स्ट्रा केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशकों के रूप में नियुक्त किए गए तथा ब्यूरों प्राफ पब्लिक इंटरप्राइजें ब्वारा भेते गए, 52 ज्यक्तियों के नाम, विवरण पत्न में रूप से सांविध संख्या एक से विप्रमालय में रक्षा गया है। विम्यालय में रक्षा गया है। विम्यालय में रक्षा गया है। विम्यालय में रक्षा गया है।

# स्टीम, डीजल ग्रीर इलेब्ट्रिक रेलगाड़ियों की संक्या

4929. श्री सुभाष ग्राहुका: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि:

(क) स्टीम, डीजल भीर इलैक्ट्रिक ट्रेनों की पुर्यक पृथक संख्या कितनी है ;

- (बा) इन रेलगा इयों में से प्रत्येक रेलगाड़ी पर प्रति किलोमीटर कितना व्यय किया जाता है ;
- (ग) क्या सरकार कम से कम लागत-व्यय वाली प्रणाली से सभी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए प्रयास कर रही है; भीर

(स) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस दिशा में क्या प्रगति होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रास्य में राज्य मंत्री (भी शिव नारायण):

(क) भाग, डीजल भीर विजनी कर्षण द्वारा नालित गाड़ियों की प्यक-पृथक संख्या वतलाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत-सी गाड़ियों, खण्डों में उपलब्ध कर्षण-प्रकृति और गाड़ी विशेष के लिए उसकी उपयुक्तता के भाधार पर, दो अथवा अधिक प्रकार के कर्षणों से चलती हैं। लेकिन, 1976-77 के दौरान विभिन्न कर्षण-प्रकृतिकों के भ्रधीन भारतीय रेलों पर सवारी (धनुपनगरीय) एवं माल गाड़ी किलोमीटर नीचे लिखे अनुसार थे:—

	(गाड़ी किलामीटर दस लाख में)					
	सवारी	माल	जोड़			
भाष	166	58	224			
डीजल	48	118	166			
विजली	29	49	78			

- (ख) इन गाड़ियों पर किये गये शिशिष्ट व्यय के कर्पण-वार स्रांकड़े नहीं रखे जाते हैं।
- (ग) भीर (घ). किसी खंड विशेष पर कर्षण का सस्तापन अथवा धन्यथा होता, खण्ड पर यातायात के घतत्व, उस घतत्व के धनुसार कौन-सा कर्षण उपयुक्त होगा, धितरिक्त सुविधाओं के तिए अपेक्षित निवेश भादि बातों पर निभेर करता है। इन कारकों को दृष्टिगत रखते हुए रेल प्रशासन सम्बन्धित खण्डों पर समर्थ कर्षण को व्यवस्था करने के तिए प्रयत्न-शील हैं।

#### Total haulage of Passengers and Goods

4930. SHRI DHARAMA VIR VASISHT: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state:

- (a) the total haulage of passengers and goods year-wise in 1975, 1976 and 1977;
- (b) the availability of total number of locomotives and coaches in the same period year-wise, separately for passengers and goods;
- (c) any conspicuous trends in (a) and (b): if so, with reasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) :(a) Statistics are maintained for financial year and not for calendar year. Total number of passengers and tonnes of goods originating during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 are given below:

	1974-75	1975-76	1976-77
sNmber of pausengers oiriginating )n millions)	2,429.4	2,945*2	3,300.3

Tonnes of goods originating (in millions) 196.7 223.3 239.1

(b) Number of Locomotives, Passenger carriages and Wagons as on 31st March is as under:

#### As on 31st March

	1975	1976	1977
Locomotives	11,113	11,095	11,010
Passenger carriages	28,254	28,526	28,516
Wagons	377,448	381,497	384,190

(c) There is no conspicuous trend.

## Registrar of the Court of Judicial Commissioner

- 4931. SHR1 BAPUSAHEB PARU-LEKAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPNAY AFFAIRS be pleased to state:
- (a) whether a person is qualified to be appointed as a registrar of the court of Judicial Commissioner if he has not attended any law college;
- (b) whether it is a fact that the Registrar of the court of the Judicial Commissioner of Goa, Daman and Diu has not attended any law college but still holds a law degree; and
- (c) whether the Government propose to hold an enquiry in the matter; and if not, the reasons for same?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). The Government of Goa, Daman and Diu have intimated that the present Registrar of the Court of Judicial Commissioner passed the IInd LL.B. (Old) Examination held by the Karnataka University in October, 1969 as an ex-candidate. They had asked for details of his attendance in the Law College but these had not been furnished by the University. The Judicial Commissioner, Goa, Daman and Diu has intimated that law degree is not prescribed as an essential qualification for the post of Registrar in that Court, and that the question of Government taking action against the Registrar does not arise.

# Confirmation of Temporary Officers

4932. PROF. R. K. AMIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether he will ensure that his directives to the Railway Board to confirm all the remaining temporary efficers this year is implemented as there is already abnormal delay in confirming these officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): Yes. Action in this respect has already been initiated.

# Railways' participation in Exhibition arranged by AICC

4933. SHRI BHAGAT RAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) is it a fact that Indian Railways took part in the exhibitions arranged by All India Congress Party or any other agency or an individual on the eve of Session of All Indian Congress Committee or to propagate 20 point programme of former Prime Minister of India during Congress regime;
- (b) if so, the total number of exhibitions in which railways and its production units took part; information may be submitted separately for each railway or production unit with names of occasions or sessions at which these exhibitions were held;
- (c) cost of stores utilized for the construction of pavilions or stalls installed at the aforesaid exhibitions; and
- (d) cost of materials should be submitted in the following break-up-
- (1) cost of material issued from stores depots;

- (2) cost of material drawn from the floor or workshops or from its petty stores depots;
- (3) cost of material utilised from the stocks held by Inspectors of works, electric foreman, head train examiners and other subordinates of the railways?

# THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in library. See No. LT-2736/78].

Out of nine Zonal Railways, three Production Units and other Railways viz. Northern, Northeast Frontier, Eastern and South Eastern, actively participated in 10 exhibitions. Other Zonal Railways, Production Units and the Research Designs and Standards Organisation assisted these our Railways by way of sending models and other exhibits from their existing stock which did not involve any additional expenditure.

#### Upgradation of posts of X-Ray Technicians

4934. SHRI PHOOL CHAND VERMA:

SHRI SUBHASH AHUJA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether there are rules framed by competent authority to upgrade and downgrade the posts of X-Ray Technicians in various Railway Hospitals, specially, the sub-divisional hospital, Amritsar and Divisional Hospital, Lalgarh, Bikaner;
- (b) if there are such rules, what are these;
- (c) if there are no such rules, the reasons therefor and how the upgradation and downgradation is done; and
- (d) whether the exposure of X-Ray films at Bikaner is four times more than at Amritsar; what ar 'the causes of downgrading the post of X-Ray Technician at Bikaner and upgrading the post of X-Ray Technician at Amritsar?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). The nature of work being done by the incumbents of the two grades (Rs. 260—400 and Rs. 330—560) of X-Ray Technicians is identical. The higher

grade posts are provided to improve promotional prospects and the incumbents of the posts are transferred from one post to the other on administrative grounds.

## Central Railway Buildings in Kalyan

4935. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Ministry of Finance by its letter No. 4(7)-P/65 dated 29th March, 1967—fixed quantum and laid procedure and intimated to all local bodies in respect of payment of service charges of Central Government properties;
- (b) whether it is also a fact that the Central Railway have 54 buildings built after 1-4-73 in the city limits of Kalyan Municipality of Thana District (Maharashtra) but their service charges for the period of last fourteen years amounting to the tune of Rs. 3,80.216 have not been paid to the said Municipal Council even after repeated reminders; and
- (c) if so, the reasons thereof and when the said amount shall be paid to the Municipal Council?

# THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) and (c). The 54 buildings in question include some constructed before 1-4-37. It was for the first time in July, 1977 that the Kalyan Municipal Council preferred a claim of Rs. 3,80,216 relating to service charges due from 1-4-54. Since the claim pertains to such a long period, it is being scrutinised, and payments will be made as soon as the relevant points are settled.

# Mercy appeal of X-Ray Technicians

4936. SHRI PHOOL CHAND VERMA: Will the Minister of RAIL-WAYS be pleased to state:

- (a) whether the Minister of State in the Ministry of Railways had accepted the mercy appeal of the X-Ray Technicians working in the low pay scale on the Northern Railway on the 3rd October, 1977 and directed the Director of Establishment of the Railway Board to implement the order and the DE Railway Board wrote a D.O. letter to the Additional C.P.O. Northern Railway on 15/16 October, 1978 but the C.P.O. (Additional) and C.M.O. (Medical) Northern Railway did not comply with the orders issued in this regard;
- (b) whether orders were again given before the G.M. Northern Railway and

Medical Officer (BKN) in the X-Ray Cell of Medical Department, Bikaner on the 1st May, 1978 (Back to ASR) but they ignored the orders; and

### (c) the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAHLWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) The matter relates to one X-Ray technician who was transferred from Amritsar to Bikaner as a result of a Vigilance case. His transfer was stayed under D.O. letter of 16th October, 1977 (not 1978) but the stay order was subsequently cancelled on 30th December, 1977.

- (b) No such orders had been given.
- (c) Does not arise.

# मध्य प्रदेश में एक पोली प्रोपीलीन फिल्म फैस्टरी की स्थापना के लिए प्राशय-पत्र का जारी किया जाता

4937. श्री राधवजी : क्या पेट्रोलियम, रसायन श्रीर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या मध्य प्रदेण में पोली प्रोपीलीन फिल्म फैक्टरी की स्थापना करने के लिए धात्रय-पत्र जारी करने हेनू मरकार को कोई प्रावेदन पत्र प्राप्त हुमा है म्रीर यदि हो, तो यह कय प्राप्त हुमा है म्रीर किस माध्यम में प्राप्त हमा है;
- (ख) ग्राणय-पत्र जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि इस बारे में राज्य सरकार सहयोग करने वाली संस्था के साथ करार करने के लिए सहमत हो गई है; ग्रीर
- (ग) यह भ्राणय पत्र कब जारी किये जाने की संभावना है;

पेट्रोलियम तथा रसायन धौर उर्धरक मंत्री (भी हैमबती नत्वन बहुगुणा): (क) से (ग). जी हां । बिह्युनीय थेड के बायोक्यायानी ध्रीरिएण्टिड पोली प्रोपोलीन फिल्म तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम नि० से एक माजय पत्र जारी करने से सम्बन्धित एक पत्र प्राप्त हुआ था धौर सं० 938/77/बाई एल दिनांक 9—12—1977 के मन्तर्गत पंजीकृत किया गया। बावेदन पत्र पर विचार किया गया धौर इस साधार एर मस्बीकार कर दिया गया कि इस मद के निए पर्याप्त क्षमता के उत्पादन के निए लाइसेंस पहले ही दे दिया गया था।

मध्य प्रदेण सरकार ने घणी हाल में इस मामले पर पुन: विचार करने के लिए धावेदन किया है। मामला सभीक्षाडीन है।

# सफाई कर्मचारियों का चयन

4938. भी फूल चन्द वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सब है कि गत माह उत्तर रेलवे घरतपाल में सफाई कर्मचारियों के चयन में और 1977 में एक्स-रे तकनीशियन के पद को बीकानेर से बमृतसर रेलवे घरपताल में घरतरित करने के मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों से कथित पूम ली गई थी;
- (ख) क्या जोधपुर रेलवं ग्रस्पनाल से एक एक्स-रे नकनीणियन का ग्रमुनसर तबादला किया जा रहा है क्योंकि भर्ती करने वाले क्लक को घस थी गई है;
- (ग) यदि हां, तो इस पर रोक लगाने के लिए रेलवे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की आ रही है;
   श्वीर
- (घ) यदि नहीं, तो रेलवं ग्रस्पताल, अमृतगर में एक्स-रे तकनीशियन के पद का दर्जी बहुति के क्या का रण हैं और उसे बीकानेर घरपताल में तबादला करने के क्या कारण हैं जबकि भ्रमृतगर में कार्यभार बीकानेर के कार्यभार की भ्रोशः कम है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण):
(क) श्रीर (ख). विभागीय कांट के सम्बन्ध में
निर्धारित स्वास्थ्य निरीधकों के 25% पढ़ी को
गरने के लिए उत्तर रेलवे ने मार्च 1978 में एक
प्रवरण किया था । स्वास्थ्य निरीधकों के प्रवरण
में ग्रथमा एक्स-रे तकनीलियन के पद को बीकानेर से ग्रमुतमर रेलवे ग्रम्पताल में ग्रन्तिक करने के
बारे में घूम का कोई मामला रेलवे के लाटिस में
नहीं ग्रामी है। इस बारे में नियुक्त जनके द्वारा
रिण्यत मांगने की कोई णिकायत नहीं हुई है।

## (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) ग्रम्तसर में 260— 430 क (सं व व ) के ग्रंड में काम करने वाले एक एक्स-रे तकनीशियन को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित करना था। उत्तर रेलवे के किसी भी अस्पताल में 260— 430 क (सं व व ) ग्रंड में एक्स-रे तकनीशियन का पद रिक्त न होने के कारण और एक्स-रे तकनीशियन का समृतसर से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए उसे उसके पद के साथ बीकानेर स्थानान्तरित कर दिया गया और बदले में बीकानेर के एक्स-रे तकनीशियन का पद जिसके पदधारी ने संयोगवण अपनी तैनाती अमृतसर में कराने की इच्छा व्यक्ति की भी, अमृतसर सन्तरित कर दिया गया।

12.00 hrs.

RE. SHORT NOTICE QUESTION ON REPORTED MURDER OF TWO CHILDREN IN DELHI

भी कंबर लाल गुप्त (दिस्ली सबर): उपाध्यक्ष महोदय, दोबध्वों का करल हुया है, उनकी हैड बाडी मिली हैं, मैंने इस बारे में णार्ट नोटिश ब्वेष्टवन दिली है, मैं जानना चाहुंगा कि उमका क्या हुया ? यह हमारे लिए भीर मारे मदन के लिए बहुत बड़ी बात है, उसकी इस्वायरी होनी चाहिए।

SHRI VASANT SATHE (Akola): I am sure the whole House and yourself will feel shocked and grieved to hear the shocking and sad news regarding the two young children, one a girl, Gita age 17, and the other, a boy, Master Sanjay, age 15, children of Shri M. M. Chopra, Captain in the Navy, who were kidnapped day before vesterday while they were trying to go from their home in Naval officers' Colony Enclave to the Yuva Vani Programme at 6 p.m. in the A.I.R. They were kidnapped, and today's morning news is, I got it confirmed from the Home Ministry's office, that these young children, unfortunate children, were found murdered with multiple stab wounds and their bodies were left at Ring Road. I do not have words. What is the fault of these young children ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would like to tell you one thing. A short notice question has been given notice of by Mr. Kanwarlal Gupta and I am admitting it. Tomotrow we will have a full discussion on it.

SHRI VASANT SATHE: Let the Government, let the whole House, convey our deep sense of shock and sorrow to the bereaved family. This is the least that we can do. The whole nation is shocked. I am sure every hon. Member in this House is shocked. When this Short Notice Question comes, Government will give a detailed reply, that is a different matter, and it will be considered as a law and order problem, but at present I feel we have to express, and the whole House has to associate itself in expressing, this total shock that we feel at this ghastly tragedy.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, it is very shocking. I think the whole House will associate itself.

THE MINISTER OF PARLIA-MENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I wish, on behalf of the Government, to associate ourselves with the feeling of shock and grief that the hon. Member has given expression to. This is a very serious matter which involves innocent children, and certainly Government will leave no stone unturned to look into the whole case and see that the culprits are brought to book. Meanwhile, we share the grief and sorrow and shock that he has expressed, and the feelings of the House may kindly be conveyed to the bereaved family.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the whole House associates itself.

भी राम अवधेश सिंह (विकमगंज): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है,

उपाध्यक्ष महोदयः श्री राम श्रवधेण सिंह जी स्नाप जरा बैठ जाइये।

भी राम भववंश सिंह: मैंने नियम 144 के तहत नीटिस दिया है कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर बहस कराई जाए और उनको लागू कराया जाय । उस सम्बन्ध में 26 भादमियों ने लिखकर दिया है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ram Awadesh Singh, you came to the chamber and I have told you to give a notice under rule 377. But you have come here and persisted in raising it in the House, Please take your seat. Do not get up like this impromptu. I will not allow it. Please take your seat.

श्री राम प्रविधेश सिह: इम बारे में हाउम को बताया जाये ग्रीर इस पर बहम कराई जाये।

SHRI JYOTTRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Sir, I want to say....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me make some announcements.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I will not take half a minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seats.

SHRI JYOTIRMOY ROSU: It is about the communal riots in Hyderabad.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have given notice about it. I will look into it.

12.06 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST (i) EDITOR. THE NA-TIONAL HERALD AND (ii) SHRI SOMJIBHAI DAMOR, M.P.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K.P. Unnikirishnan had given a notice of question of privilege on the 14th August, 1978 against the Editor, The National Herald, New Delhi, for alleged "gross distortion and wilful misrepresentation" of certain proceedings of Lok Sabha of the 12th August, 1978, and casting "aspersions" on their "conduct as Members in the House" in a news report published in its issue dated the 13th August, 1978, under the caption "Major Tactical Reverse".

The Editor, The National Herald, who was asked to state what he might have to say in the matter, in his reply dated the 19th August, 1978, has stated inter alia, as follows:

"Our reporter has explained that in his attempt to give the gist of the tumultuous proceedings of the day in an abbreviated form, unintentional errors had crept into the report. He has further stated that it was farthest from his mind while reporting the proceedings to misquote any member or misrepresent any party's view point. We express regret and offer our unqualified apology for the erroneous reporting and request that the notice of breach of privilege against The National Herald is not pressed."

In view of the regret and unqualified apology tendered by the Editor. The National Herald, if the House agrees, the matter need not be pursued. The Editor of The National Herald, may, however, be asked to publish the necessary correction and his apology prominently in the next issue of the newspaper.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Pandit D. N. Tiwari, M.P., Chairman, House Committee, had given a notice of question of privilege on 3rd August, 1978, against Shri Somjibhai Damor, M.P. for making certain unfounded allegations against him in the House on the 31st July, 1978 and also in a letter addressed by him (Shri Somjibhai Damor) to the Speaker on that date, regarding allotment of houses to the Members belonging to the Scheduled Tribes.

Shri Somjibhai Dannor was requested to furnish his comments on the matter and either to substantiate the allegations made by him or to express regret. Shri Somjibhai Damor in his reply dated the 2grd August, 1978, has stated:

"In this regard, I express my unqualified regrets to you and also to Chairman of the House Committee."

In view of the unqualified regrets expressed by Shri Somjibhai Damor, if the House agrees, the matter may be treated as closed.

SEVERAL HON, MEMBERS: Yes.

12.10 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 26th August, 1978, agreed without any amendment to the Delhi Police Bill, 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 24th August, 1978."

12.11 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED "TOLENT CLASHES INVOLVING NAVAL PERSONNEL, WORKERS OF HINDUSTAN SHIPYARD AND BUS WORKERS

श्री विजय कुमार मलहोता (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखन विषय की प्रोर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं प्रीर प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तक्षय दें :---

"विशाखापत्तनम में नीसेना कमैचारियों तथा हिन्दुस्तान शिपयाई के कमैचारियों और बस कमैचारियों के बीच हुई हिंगक मुठभेड़, जिस में पांच व्यक्तित मारे गये, से उत्पन्न स्थिति का समाचार"।

गृह संजालय में राज्य संजी (ओ धनिक लाल मंडल): महोदय, गरकार को विशाखापलनम में 26 ग्रीर 27 प्रगस्त, 1978 को हुई घराजकता की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाम्रों जिनके परिणामस्वरुप तीन व्यक्तियों की जानें गई, पर बहुत दुख हुमा है। सरकार इस विषय में राज्य प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

26 प्रस्मत को काफी बाम को नौसेना के कर्मेचारियों तथा हिंदुस्तान विषयाडं के सिविलिन कामगारों, जो एक बम में याला कर रहे थे, के बीच कहा सुनी हो गई। हिन्दुस्तान विषयाडं के बम्ब कामगारों को इसकी जानकारी हुई । बाद में जब बस वापस मा रही थी तो नौसेना के कर्मचारी बस के कंडक्टर को नौसेना के कार्यालय पर ले गए, उसे रोके रखा, भौर शिषयार्थ के उस कामगार को पहचानने के लिए कहा जिससे कहा-मुनी हुई थी। इस बीच सिटी बस के कामगारों को कंडक्टर की इस नजरबन्दी का पता खल गया मीर वे महा-लक्ष्मी थियेटर के निकट एकत हो गए भौर उन्होंने मपने साथी को बचाने के लिए नौसेना के कार्यलय में प्रवेश करने की हिया। बाद में नौसेना के कर्मचारियों ने कंडक्टर को पुलिस को सौप दिया।

26 घगस्त को काफी शाम के समय नौसेना के कुछ कर्मवारियों नया बस कामगारों धौर बाद में हिन्दुस्तान शिपयादं के कुछ कर्मवारियों में एक पुरुषाह हुई । इसके परिणामस्वरूप धराजकता, हिसा घौर बागजनी की कई घटनाएं हुई । शिपयाई के कामगारों, बस कंडक्टरों, जनता के कुछ व्यक्तियों तथा नौसेना के कर्मवारियों के बीच पथराव हुआ जिसमें कुछ धर्मतिक नागरिक, नौसेना कर्मवारी, तथा राज्य पुलिस के कर्मवारियों को भी चोटें धाई । घटना में एक सिटो बस धौर नौसेना के इक को धाग लगा दी गई । स्थित पर काब पा लिया गया ।

27 अगस्त की सुबह को नौसेना के हाथ पैटी आफिसर श्री एन० बो॰ भट्ट, का शव पिछली रात की
वारदातों के मौके के निकट मिला। जब उसकी
गृत्यु का समाचार नौसेना कर्मचारियों को मिला तो
उनमें से कुछ बहुत कोशित हो गए तथा अराजकता
हिंसा तथा धागजनी फिर से नौसेना के कर्मचारियों,
हिन्दुस्तान शिपपांड के कर्मचारियों तथा अन्य के
बेस भड़क उटी। एक मिनेमाहाल, एक पूजा का
स्थान, कुछ आवासीय मकानों तथा कुछ वाहनों को
जला दिया गया! हिन्दुस्तान शिपपांड के एक
कर्मचारी श्री कालीदाम को गम्भी र वोटें झाई जिसके
परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। एक धौर 19
वर्षीय लड़के (सिवलयन) की मृत्यु का भी समाचार मिला है।

स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में 27 अगस्त को शाम 5 बजे से कफ्यू लगा दिया है तथा तब से 28 अगस्त की शाम नक कोई घटनायें नहीं हुई हैं । मामान्य स्थिति पुनः स्थानिय प्रशासन के लिए पुलिम, नौसेना नथा स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों की गतिविधियों में समन्वय करने के लिए एक संयुक्त नियंत्रणकक्ष की स्थापना की गई है । राज्य सरकार ने नगर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रावय्यक उपाय किए हैं । नौसेना के प्राधिकारी थी शांति बहाल करने के लिए उपाय कर रहे हैं ।

मैं सदन से तथा सदन के माध्यम से विकाखा-पत्तनम के लोगों के सभी वर्गों से मांति भौर सद्भावना बनाये रखने तथा सामान्य स्थिति का वातावरण पुन: स्थापति करने के लिए हार्षिक भ्रपील करूंगा।

भी विजय कुमार मलहोता : उपाध्यक्ष, महोदय विशाखापत्तनम के मलकापूरम शिपयाई के क्षेत्र में जो हिसक घटनाएं हुई हैं वे काफी दुखदायी हैं। उन घटनां भों में विशेष रूप से जिन लोगों की मत्य हुई हैं उन में एक विद्यार्थी है जो वहां पर शिप-यार्ड भें गैस्ट के रूप में घाया हुया था जिसका इस लडाई से भीर इन घटनाओं से कोई ताल्लक नहीं था । एक नैवल आफिसर की लाश अगले दिन रात को झाडियों में प्राप्त हुई भीर तीसरे मरने वाले व्यक्ति का भी ऐमा लगता है कि घटनाओं से कोई नाल्लक नहीं था। इस कारण से जो घटनाएं वहां पर घटी हैं उन में कुछ शरारती तत्व बाद में शामिल हुए, इस के बारे में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता। इस के साथ जुड़े हुए जो दूसरे सवाल हैं उन की स्रोर मैं मंत्री महोदय का ध्यान स्नाकर्षित करना चाहता हं कि यह कोई पैटर्न सिर्फ यवशाखा-पतनम का हो ऐसी बात नहीं है , हैदराबाद में जो घटना हुई है, उस से पहले मराठवाडा में जो घटनाएं हुई भीर उस से पहले भ्रन्य स्थानों पर भी जो हिंसक घटनाएं उमह रही हैं भीर तनाव पैदा हो रहा है इस के पीछे कोई पैटर्न है या नहीं, इस को देखने की जरूरत है। मैं यह तो नहीं कहता कि ये घटनाएं कोई प्री-मेडिटेटेड थीं या पहले से प्लान की हुई थीं। परन्तू एक छोटी सी घटना होती है, उस के बाद प्रचानक वह घटना बहुत उग्र रूप धारण करलेती है। इस के बारे में यह जो एक साइकोलाजी बन गई है देश के भन्दर, इसकी केन्द्रीय सरकार भीर प्रादेशिक सरकार इन सब को मिल कर के देखने और इस को रोकने की सख्त जरूरत है। अगर ऐसा न हवाती इस के कारण देश में यह जो बाताबरण बनाया जा रहा है कि ला एण्ड झार्डर तहसनहस हो रहा है, कानन भीर व्यवस्था नहीं रह गई है इस के कारण बहुत ही बीभत्स रूप में पैदा हो रहा है। मैं चाहुंगा कि प्रधान मंत्री जी सभी मुख्य मंत्रियों के साथ बैठ कर इस पर विचार करें भीर इस को देंखें कि इस में किसी तरह की राज-नीति नहीं ब्रानी चाहिए ब्रौर इन सारे मामलों को किस तरह से हल किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो यह चाहते हैं इस बात की साबित किया जाए भीर इस बात का बड़े जोर से प्रचार करने को कोशिश उन की तरफ से है कि एमरजेंसी के भ्रन्दर लाएण्ड भ्रार्डर की स्थिति बहुत ठीक थी, घच्छी थी भौर एमरजेंसी क्यों कि हट गई इस के कारण देश में हर रोज समाचारपत्नों में ऐसी खबरें था रही हैं, परन्तु बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहां कांग्रेस का या कांग्रेस (ग्राई) का शासन किसी जगह दूसरी प्रदेश सरकारों के शासन हैं तो उन सभी को मिलाकर लाएन्ड आर्डर की प्राब्लम के लिए कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जैसा कि भ्रभी यहां पर जिक्र किया गया कि दिल्ली के दो बच्चों का कत्ल कर दिया गया । इसमें एक बात निकलती है कि जो कानन तौडने वाले गुडे धीर शरारती तत्व हैं उनकें मन में कहीं इस प्रकार की भावना न भी जाये कि देश में ला एण्ड ब्रार्डर की स्थिति कमजोर होती जा रही है

इसीलिए मैं इस बात पर बहुत बल देना चाहता

[श्री विजय कुमार मलहोता]

215

हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस सारे सवाल को देखना चाहिए। ग्राज सभी प्रदेशों में इस तरह की घटनायें बढ़ रही हैं।

दूसरी बात यह है कि यह जो घटना हुई है इसक़े सम्बन्ध में नैवी के वाइस एडिमरल, सुपरि-न्टेंडेंड पुलिस ग्रौर शिपयार्ड के प्रबन्धक-तीनों ने अलग अलग घटनायें बताई हैं। आज देश में बहत जगहों पर बी एस एफ, सी आर पी, मिलिट्री, पब्लिक ग्रंडरटेकिंग्ज स्थित है वहां पर इनमें तालमेंल कें लिए कोई ऐसी एथारिटी होनी चाहिए जोकि सबके साथ मिलकर काम कर सके ग्रौर कहीं पर श्रगर किसी प्रकार की कठिनाई होती है, ,कोई तनातनी का वातावरण पैदा होदा है तो उसका निराकरण किया जा सके। ऐसी जगह जहां पर नैवी के सेंटर हैं सेंट्रल गवर्नमैंट ग्रौर मिलिट्टी के ग्राफिस हैं उसके, सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय होना चाहिए कि जिसके ग्रन्डर में वे पूरी तरह से काम करेंगे। अगर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए कौन सी कामन एथारिटी होगी जो मिलकर सारे मामले को निपटा सके । अन्यथा तालमेल बनाने में समय लगता है। नेवी के कमाण्डर को ग्रौर शिपयार्ड के प्रबन्धकों को ग्रपने ग्रादिमयों को सम्हालने में 24 घंटे लगे । जो लोकल बस कर्म-चारी थे उनको भी सम्हालने में समय लगा। इसलिए कोई ऐसी एथारिटी होनी चाहिए जो सभी को कन्ट्रोल कर सके, सभी का आपस में कांट्रैक्ट हो सके और एक दूसरे के विपरीत कोई काम न कर सके-इसको देखने की जरूरत है। इस मामले को देखने के लिए भीर ग्रागे फ्युचर के लिए कोई ऐसी इंक्वायरी वहां पर हो ताकि ग्रागे कभी भी ऐसी घटनायें न घट सकें।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, जिन भावनाश्रों को व्यक्त किया गया है, मैं उनके साथ हूं। विधि ग्रौर व्यवस्था को ग्रपने हाथ में लेने का या हिंसा करने का जो भाव है उस पर काब पाना चाहिए श्रौर उसके लिए माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं मुख्य मंत्रियों तथा विरोध पक्ष के नेता श्रों से मिकलर बात करने के लिए तो चाहते हैं ऐसा वातावरण होना चाहिए कि कहीं पर अगर कोई छोटी घटना हो तो उससे इस तरह की हिसक वारदातें न बढ़ें। इस तरह का वातावरण हमें बनाना चाहिए।

यहां पर जो घटना हुई है उसमें कोई पैटर्न है ऐसा तो नहीं दीख रहा है। ग्रापस में कुछ कहा सुनी हो गई ग्रौर उसके बाद बात बढ़ गई। स्थिति को काबू में लाने के लिए उपाय किए गए यद्यपि माननीय सदस्यों ने जैसा कहा कि ग्रौर भी ग्रच्छे उपाय किए जा सकतें थे।

इंक्यावरी की जो बात माननीय सदस्य ने कही है तो एक मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी का एलान राज्य सरकार ने किया है ग्रौर ग्रभी सबसे जरूरी बात तो यह है कि शांति ग्रीर व्यवस्था स्थापित हो ग्रीर ग्रापस में सद्भाव पैदा हो । यह सबसे पहली भ्रावश्यकता है। यह पहला काम हो जाता है तो बाद में राज्य सरकार से इस बारे में भी बातचीत की जा सकती है।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): Growing violence in the public life of the country is a serious matter of concern. An atmosphere of violence and lawlessness has gripped the entire country.

You know our defence personnel and particularly, the Naval personnel are to safeguard the coast and also to safeguard public lives and property of the country. I have got high regard for our defence forces. But to-day what had happened in Vizag is this.

In fact, to-day, our naval personnel have taken the law into their own hands which is deplorable and no peace-loving citizens of this country can tolerate it. You know there are atrocities on harijans, weaker sections, poor workers, minorities and it has become the order of the day. What has happened in Vizag on the night of the 26th and how the incident has started. The Minister concerned has not given us a correct picture as to how the incident has started. The incident had srated in this way. Two naval personnel got into the bus in a drunken state, that is, under the influence of al-cohol. Then, after entering the bus, some workers of the Hindustan Shipyard got into it. The poor chaps, the poor workers, simply crawled under the feet of the navy men. These navy personnel got angry and there was an altercation. Immediately these naval personnel started beating these workers. These workers got down from the bus; they went to the Shipyard and narrated the incident to their colleagues. The colleagues came back. When the bus was returning at the Naval Sena Dock these people waylaid the bus and removed the bus crew and took them to the workers' quarter of the shipyard and they confined them wrongfully.

At the time when the bus crew were in the quarters the bus crew got collected in strength and they demanded the release of their crew members. At that time there was a clash as a result of which a Petty Naval Officer was killed. In the meantime some naval officers were injured and 8 workers were also injured. Next day once agin the fighting erupted. The dead body of the petty naval officer was found by them near the bush in the naval colony. At that time these people went on a rampage and they took law into their own hands and even went to the extent of setting fire to the Cinema Hall and also to the shipyard staff quarters. At that time what happened was this. In the clash one worker, by name, Kalidas was murdered and another nineteen year old boy was also murdered. When the naval people opened fire on the Gurdwara, at that time these people died. Not only that. Public property was also set on fire. This is the position. Can the Members of this honourable House join me in deprecating and deploring the acts of the naval personnel? What is happening to-day? The atmosphere of violence and lawlessness had gripped the entire nation to-day. You heard what Mr. Sathe has just now stated. Now I will come to the main point. What is the reason?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should have come to the main point long before.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Please excuse me, I will come to that,

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are making here a speech. Actually you should ask for a clarification. Please ask for the clarification.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Please excuse me. Now why it is happening? There is no fulfledged Home Minister in the country. For the last so many months we did not have two Cabient Ministers and six State Ministers. What is the Prime Minister doing? He is concentrating the powers to himself. He is not prepared to give the powers. That is why there is a bottleneck in the administration. That is why what I submit is this. Is the Prime Minister going to appoint a Home Minister in this country? There is no discipline in their party because there is crisis and there is no time for these people to find time for running the administration effectively, Under these circumstances, may I know from the Prime Minister when is he going to appoint the Home Minister for this country? (Interruptions)

Secondly, whether he is going to appoint a High Court judge to go into these allegations?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI JANARDHANA POOJARY:

I am concluding. Sir, people in this country have started feeling that there is no safety for their lives today and as such, I request the Prime Minister to take immediate action, otherwise tomorrow your government will be thrown out by the people. (Interruptions)

भी धनिक लाल मंडल : जो रिपोर्ट हमने दी है वह मान्य सरकार द्वारा भेजी गयी हैं।

भी उप्रसेन (देवरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना चटी है, वह बहुत ही सर्मेनाक है। इस में भी कोई शक नहीं है कि जिस राज्य में यह घटना घटी, वहां की राज्य सरकार इस घटना को मुक दर्गक की तरह देखती रही। इस से उसकी कमजोरी प्रकट होती है।

मुझे तो इस सम्बन्ध में एक तःर मिला है।
यह तार राकोटी इश्वरम्मा का है जिसके पति
राकोटी कालिदास पकड़ कर के ले जाये गये ।
वहां नेवल स्टाफ के द्वारा मारे गये घोर चीफ
साफ नेवल कमाण्ड की हाजिरों में उनको पूरी
तरह कुचल दिया गया । झाज भी वहां पर इस
तरह की अध्यवस्था की भावना है धौर लोग वहां
कम्पूं लगा होने पर भी डर रहे हैं झाया कि
उनका जीवन मुरक्षित रह सकेगा या नहीं।यह जो
तार हमारे पाम झाया है, मंत्री जो के पास भी
पहेंचा होगा।

मैं भव दो-तीन सवाल करना चाहता हं, क्योंकि जनार्दन पूजारी जी की तरह में फालतू लैक्चर देने के लिए तो खड़ानहीं हुआ। हूं। माननीय मंत्री जी ने सपने बयान मंकहा है कि जब वे बस यात्रा कर रहेथे नवल आफिसर के कर्मचारी पकड़ कर के अपने यहां ले गए । क्या मंत्री जी मेरी राय से सहमत होंगे कि ग्रगर वे बस कर्मचारियों को पकड़ कर के नहीं ले जाते कि बताओं कि किस से तुम्हारी कहा-सुनी हुई है तो उसकी पूरी प्रतिक्रिया नहीं हुई होती? मेन्नी जी पहली बात तो यह बतायें कि सही मायनों में क्या वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वे पिये हुए थे ग्रीर बिना मुकाम तक पहुँचे रास्ते में ही मस्त हो गए थे धौर उन्होंने अपने अधिकारों का दूरुपयोग किया ? क्या इसे मंत्री जी खद घपने घाप मानते हैं ? दूसरे मैं मंत्री जी से पूछना चाहता है कि 26.27,28,29 चार दिन हो गए इतनी बडी घटना को घटे, क्या आपने तुरन्त राज्य सरकार को ग्रादेश दिया याराय दी कि हाई कोर्टके जज के स्तर पर इन की न्या-यिक जांच विठायी जाए ? अब भी इस में क्यों देर की जारही है ?

रोड वेज के, शिपयार्ड के भीर नौ सेना के कर्म-चारी ग्रापस में लडते हैं ग्रीर इसकें लिए मल्होता जी ने भी कहा भीर मंत्री ने उसका जवाब भी दिया, इस सम्बन्ध में मुझे याद हैं कि जब हम लोग जेल में थे तो ग्रगरा में भी मारा-मारी हुई थी ग्रौर फौजी किसी को पकड़ के ले गए थे और उन्होंने पूरा भागरा शहर घेर लिया था । उस समय मोहतरमा का राज या या उनके पिताजी का राज या। हम लोग उस समय जेल में थे और हमने धखबारों में पढ़ा था । ऐसी घटनाएं जो अस्वर शहरों में हो जाया करती हैं। क्या मंत्री जी ऐसे शहरों ह जहां पर कि पब्लिक धण्डरटेंकिंगग्स के कर्मचारी धीः फौजी प्रधिकारी काम करते हैं, कोई *सामजा* म्राफिसस या कोभारिडनेशन कमेटी बनाने की व्यवस्था करेगी ताकि जब ऐसे मौके मा आएं तो दुरन्त कार्यवाही की जाए क्योंकि विभाग के मादेशों से तो यह ठीक होने वाला नहीं है।

[श्री उप्रसैन]

मब मैं मंत्री जी से दो-तीन सवाल करना चाहता हूं।

हाई कोट के जज की प्रध्यक्षता में जांच कमेटी बिठाने में राज्य मरकार को क्या कठिनाई है यह मैं प्राप से जानना चाहता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बौधांडिनेंशन कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है ? पश्चिक ग्रंडर-टेकिंग के, नैंबी के कमेंचारी या दूमरे जो लोग वहां रहने हैं उनकी इस तरह कोग्रीडिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनाई गई है, यह भी मैं ग्राप से जानना चाहता हूं।

नैवल प्राफिसर ईस्टर्न कमांड के मामने काली-दाम को मारा गया, इन प्राणय का जो तार प्राथा है, इमके बारे में प्रापके पास कोई जानकारी है प्रीर यदि है तो क्या प्राप वह सदन को देंगे ?

भी धनिक साल मंडस : जांच का प्रादेश हो चुका है। जांच के बाद जो भी माननीय मदस्य कह रहे हैं उसकी जानकारी दे दी जाएगी (क्ष्मवधान) माननीय मदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी माननीय मदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी में ममझता हूं। उनका कहना है कि ज्यूडिशल इन्क्वायरी होनी चाहिए। लेकिन हर बात में ज्यूडिशल इनक्वारी हो यह जकरी नहीं हैं। पहने मैजिस्टॉरियल इनक्वायरी हो रही है। जैमा भागने कहा है पहली भावश्यकता—यह है कि वहां शांति व्यवस्था स्थापित हो, प्राप्त में मद्याव हो। इनक्वायरी हो जाने के बाद ही कुछ कहा जा नकता हैं।

रका मंत्री (श्री जगबीबन राम): ग्रभी प्रातःकाल डिफेस सेट्रेटरो का, नौसेना प्रध्यक्ष को, मैंने
यह प्रादेण दिवा है कि प्रांध्र सरकार से बात करको
विशाखापतनम में बहुत शीध्र सदभावना कमेटी की
स्थापना की जाए जो नीसेना के लोगों की, हिन्दुस्तान शिपयाई के लोगों की, बस, कर्मचारियों की
और नागरिकों के नेताथों की हो जो सबसे
पहले इन सब समुदायों में सद्भाव स्थापित करने
का प्रयत्न करे धीर यह देखती गहे कि कोई
तनाब हो तो उस बवत उसके लिए कारगर कदम
उठाएं जाएं।

SHRI VASANT SATHE (Akola): I want to thank the Defence Minister for the very salutary measures which have been taken because this is a matter which cannot be treated either in an emotional manner or even lightly. It is a very sensitive issue. I can understand things when there are clashes between communities, civilians, in various fields; these incidents themselves are of serious nature. But it is altogether a different matter if there is clash between armed personnel and civilian personnel. That is the seriousness and that is why the delicacy also. I would not like to go into the details, it is no use doing that. The right thing for us to see now is only to see that the whole situation is brought under control and necessary atmosphere created.

I would like to say one thing. You have issued orders, as have appeared in the Press, asking the personnel to remain bound to barracks. One disturbing thing which came out in the newspapers was that the naval personnel could draw arms from the armoury on 27th morning. Sir, on the 26th this incident took place; curfew was imposed; everything was all right; everything was brought under control. Then it is reported that on 27th morning at 11 A.M. they could draw arms from the armoury. You know the seriosness of this because, if armed personnel could get arms from the armoury, then, it becomes a very dangerous thing: anything can happen. Therefore kindly go into this. There may be provocation or whatever it is. The whole committee will now go into it. We should see that in future no such incidents are repeated. There is need for some directions. I believe you will of course do it. But it is my humble suggestion that some strict direction must also be given that the officer concerned or Officer-commanding of the Area must see that these personnel have no access to the arms in the armoury. That must be done.

I hope, you will kindly consider it.

श्री जगजीवन राम: महोदय, मैं जानवृह्म कर साम की स्थिति से यह कहना उचिन नहीं समझना कि किन कारणों से यह पटना बढ़ गई, क्योंकि वह काम तो यह नियान महोहै कि जब हम तरे सुभौकि वह काम तो यह बात महोहै कि जब हम तरह की कमीना (उन्जना) किसी स्थान पर हो जाती है तो नेवी के आसंनन भादि की सुरक्षा के लिये कुछ लोगों की आसमं (हथियार) दिये जाते हैं और यहां पर भी आसमं (हथियार) दिये जाते हैं और यहां पर भी आसमं (हथियार) किये हैं। जो हमें जानकारी मिनी वहां के मिनिज अधिकारियों में कहा था कि नेवी के लोगों को सतक रहना चाहिये सम्भवत. उनकी सहायता हमको आवश्यक हो। लेकिन उस के बाद से यहां से यह आदेश दे दिया गया है कि जिन लोगों को हथियार तितांत आवश्यक नहीं हो उनके पास से हथियार ले लिये जाये, और ले लिये गये हैं।

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Sir, what about the question of relief to the families of those who have been killed? This is very important. I have already handed over the telegram which I have received from the wife of the killed person; she has asked for relief. These families must be given immediate relief.

SHRI JAGJIVAN RAM: I will see that some immediate relief is given to the families of all those who have fallen victim in this.

12 37 hrs.

221

## ESTIMATES COMMITTEE

TWENTY-SECOND REPORT AND MINUTES

श्री सहीकाल (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रापकी यनुमति से प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांग प्रस्तुन करता हूं:

- (1) वित्त मंद्रालय—अनुदानों की मांगें (सामान्य )--कायं—सारणियों का पुनरीक्षण—पर 22वां प्रतिवेदन ।
- (2) उपर्युक्त प्रतिबेदन से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांग ।

### 12.37 hrs.

### PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

EIGHTY-THIRD, EIGHTY-SUTH AND NINETIETH REPORTS

SHRTP, V. NARASIMHA RAO: (Hunamonda): I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:

- (1) Eighty-third Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Tenth Report on Export of Engineering Goods relating to the Ministry of Commerce.
- (2) Eighty-sixth Report on paragraph 37 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1975-76, Union Government (Railways) on Unauthorised Occupation of Railway Land,
- (3) Ninetieth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Sixteenth Report on Fifth International Film Festival relating to the Ministry of Information and Broadvasting.

# 12.38 hrs.

### MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED RESEARCH INTO THERMO-NUCLEAR PUSION.

SHRI D. D. DESAI (Kaira): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to bring to the notice of this august House an event that happened at the Oak Ridge National Laboratory, Princeton, U.S.A. which has the potential to remove poverty from the entire face of the earth where all sources of energy like firewood, coal, oil, hydro and uranium are getting exhausted while

growing the demand for them is at a fast rate. On August 1, a team of physicists led by Dr. Melvin Gottlieb, Director of the Plasma Physics Division of the Laboratory, heated up a mixture of heavy hydrogen atoms to the incredible temperature of 60 million degrees Centigrade-that is 10,000 times the temperature on the surface of the Sun-which, helped set off the fusion of these hydrogen nuclei to form helium and in the process release 180 times the energy used in achieving this temperature. Such controlled reaction once started can go on for everand without external stimuli. The raw material- heavy hydrogen-is available in plenty in sea water. One litre of sea water could provide energy equivalent of 300 litres of high grade gasoline. It said that the break-through came much earlier than anticipated and that 'thermo-nuclear fusion under controlled conditions will become a reality in another decade'.

Because of the promise this break-through holds, of plenty of energy cheap and from inexhaustible source (sea water) and also because the process does not produce problems of pollution from residual radiation, it would be the Alladin's lamp we have all been hoping for to provide cheap and plentiful energy to mankind in any part of the world. But a top U.S. scientist says: "This is the most difficult technological development ever undertaken by man for non-military purposes. It is too big for any country to do alone." For instance, the U.S. scientists in this experiment used an equipment devised by the Russians.

The need for international cooperation in research to make this dream of cheap and plentiful energy a reality carly, opens for us an opportunity to focus international attention on this one problem. India has scientists of calibre, so too many other nations in the world. The research on this is open to all. Therefore, I am sure this House will join me in requesting the Government that it takes the lead and proposes through an appeal international cooperative research on quickly transforming what is now a laboratory success into a great commercial venture to help the poor and the wretched of this world to see a brave new world of plenty within our life time.

(ii) NEED FOR EOUR-LANING OF ROAD BETWEEN PANVEL AND DEHU ROAD

SHRI S. R. DAMANI a (Sholapur): Sir, the Bombay-Pune Road, National High Way No. 4, is a very important road and carries very heavy traffic, about 4300 vehicles per day, from Bombay towards Bangalore, Madras and Hyderabad. The Maharashtra Government

224

[Shri S, R, Damani]

suggested four-laning of this road even in the Fourth Plan period at a cost of Rs. 17.5 crores. The portion between Kho-poli and Lonawala is particularly hazardous, zig-zag and steep-graded and a large number of accidents and breakdowns are daily occurrences; and hundreds of passengers are killed monthly. The Government of India approved the realignment of this portion as far back as March 1973. But implementation was not forthcoming. As a first step, the State Government proposed, to the Government of India to construct a two-lane carriage way that an estimated cost of just Rs. 3 crores. Considering the very heavy traffic on this National Highway, I suggest that (a) the work is of four-laning the road between Panyel and Dahu Road; (b) realignment with a two-lane carriage way between Khopoli and Lonawala and (c) the construction of westerly diversion outside Pune City, can brook no further delay and the Government of India should take immediate action to implement these works.

श्री फिरंगी प्रसाद (बांसगाव): उपाध्यक्ष महो-दय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहना हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था क्या है ?

श्री फिरंगी प्रसाद: धाप मृन लीजियं। धभी कूछ क्द मिनट पहले थी राम भवधेश सिंह ने काका कालेलकर की रिपोर्ट पर बहम के लिए कहा था। मैंने भी उस पर लिख कर दिया है। जनता पार्टी ने भपने थोषणा-पत्न में कहा था कि काका कानेलकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रक्त नहीं है, किसी समय किसी ने कुछ कह दिया स्रीर साप इस तरह से उस के लिये खड़े हो जायेंगे, यह ठीक नहीं है।

Now Mr Raj Narain.

(iii) REPORTED SELECTION OF AIRCRAFT FOR INDIAN AIR FORCE.

श्री राज नारावण (गय बरेली): श्रीमन्, मदन को तो जात ही है कि हमारी वायु सेना को प्राप्त कुछ पुराने विमानों के बदले नये जहाज खरीदने की सक्त जरूरत है। इसके नियं मरकार ने कई कमेटियां भी बनाई थीं। पिछले सेमन में हमारे बरिष्ठ सदन्य श्री श्याम नन्दन मिश्र ने मवाल उठ।या चाकि विदेशी पतिकाझों में हस्ला है कि विमान को हम चुन चुके है, तथा उसके लिए कुछ कमीगन भी बांटे यये हैं। हम यह समझते थे कि सौदा तथ करने के पहले इस विचय पर सबत में प्रकाश डोला जायेगा।

यह पुरानी ख़बर शायव ठीक नहीं थी, पर दस दिन पहले बम्बई के एक साप्ताहिक समाचार पत्न ने बताया कि फ़ांस के एक झच्छे प्रस्ताव को ठुकराया गया है । फांस के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को पेरिस जाने का निभंतण भी दिया था। विकास सूत्रों से हमें यह भी कात हुआ है कि फांस की विसान बनाने वाली कम्पणी, मो० की० मा०, के प्रध्यक्ष ने घपने नये प्रस्ताव में कहा है कि उन के मिराक एक-। को यदि हम खरीदें, तो साथ ही साथ उन के सबसे नये विमान मिराज 2000 को भी से सकेंगे और यहां बना सकेंगे। इस प्रस्ताव को भएनी मान्यता देते हुए उनकी सरकार ने भी लिखा था, पर इसका जबाब हम ने देर से भीर विना आयक्यकता दिखाते हुए लिखा—इसका जबाब देर से दिया।

साथ ही साथ विदेशी पित्रकाओं से पता चला कि समरीका चाह रहा है कि हमें विग्येन हवाई जहाब स्वीडेन सेन मिले । सुनने में झाता है कि सरकारी कमेटी किटेन के जाग्झार विमान खरीदबाना चाहती है, जो कि चार पांच माल के झन्दर यूरोग की बाय सेनाओं की सर्विम से हट जायेगा, यानी वह पुराने टाइप का है ।

यह भी एक चिन्ताजनक बात है कि फांस के मिराज तथा स्वीडेन के विगोन के श्रेप्ट होते हुए भी अगिश्रार विमान को ही लेने का निश्चय किया जा रहाँ है। खबर यह भी है कि इस में भारी कमी गर बंटने की संभावना है। ऐसा क्यो हो रहा है, सपन को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यह बात मारे देण के लिये बहुत ही गंभीर भीर जिला-जनक है । पहली बात तो यह है कि देश के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वायु मेना के बीम साल पुरान विमानों के बदले नये तरह के विमान हम खरीदें, जो कि हमारी जरूरतों को करीब करीब बीस साल तक पुरा करते रहें पर इस के लिए हम ऐसे विमान के लिए नहीं रुक सकते, जो कि इसभी डिजाइन ही किया जा रहा है, क्योंकि हमारे ग्राम-पाम के देश बहुत ही शक्तिशाली भौर नये तरह के विमान तथा मिसाइन खरीद २ हे हैं, जिस से हम पर धार्गवार हो सकता है । इसलिये हमें भी घटी नये तरह के विमान की भी भावत्रयकता है । ये ऐसे होने चाहिएं कि उनके नये माडेल को भी हम बाद में घासानी से खरीद सके तथा भारत में भी बनामकें।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ से तो सुपर पावर का दबाव पड़ रहा है कि नये तरह के विसान हमें न सिलें और दूसरी ओर सरकार के भीतर का एक "प्रैतर प्रुप"या "काकस" चाह रहा है कि एक पुराने विसान को हम खरीदें। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण जानना धावस्थक है। सरकार से घावह है कि उन कारणों से सदन को धावनत करायें।

श्रीमन, मुझे कहने का मौका दिया आये कि
यह देश तथा यह सवन इस खेन को चुप-चाप न
देखेंगे, जिस में हमारे देश तथा इस की वायुनेता को
एक पुराने डंग का विमान दिया जारहा है, जिम
पर पब्लिक का 1500 करोड़ कपयों का खर्च हैं,
जब कि मौर भी अच्छे विमान हमें निल सकते हैं।
सरकार इस बात पर भपनी सफ़ाई वे। हम ऐसा समझौता भी न मानेंगे, जिसमें हमें किसी भी प्रकार

बाष्य किया जाने कि हम अच्छे परीक्षित्र , सुबे जिनातों की जगह पुराने विमान करीते, तथा वैचने वाणी का वादा मान में कि जाने चल कर उन के नये विमान को हम क्रीदेंगे, की कि सभी साबित भी न किया वया हो। हवारा नवा विश्वल ऐसा होना चाहिए जो कि वन चुका हो और जिस की चूकिया सामित हो चुकी हों। इस बात पर हम चिक्य में देश की हानि देखने को तैयार नहीं है।

भी क्यामनम्बन निधा (वेनेसराय) : मैं एक बात की सफाई देवूं। माननीय सदस्य ने श्रपने बक्तका में कहा कि मैं ने पिछले मार्च में यह कहा था कि कमीकन बाटी गई। मैं ने ऐसा नहीं कहा बा । मैंने कहा या कि कमीजन बांटने की परिपार्टी है और घयर कमीक्षन बांटी जाती है तो कमीक्षन राज्ये को बाए, किसी व्यक्ति के हाथ न लगे।

(iv) PUBLIC SCHOOL SYSTEM)

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan): Sir, under rule 377, I mention the following matter of urgent public importance,

The coaching system in private schools is creating a gap within the society and day by day the gap is widening between the common men and the affluent. As has been seen, every person of privileged class is anxious to get his kid admitted in a private school by paying huge sums which are demanded in the guise of donations. While our leaders make loud promises for Indianisation, they are abolutely keeping their eyes and ears closed as to how the brains of innocent childern are being washed. Instead of making them proud of their heritage, they are made to leel that their culture and way of living in Europe. The typical system adopted by these private schools imparts a perverted culture and makes middle-class sahibs intellectu-ally subservient to half-digested ideas of the middle-class west. Therefore, it is very necessary to go into the details of the functioning of such schools and to necessary to a such schools and to determine precisely what kind of a person is created by such institutions. This is a subject which has aroused many suspicions in the minds of the public in general about the way these schools are in operation within the country. They demand higher fees and expect the boys to be better dressed and the medium in all subjects in English. Thereby they create communities of the affluent elites. By destroying their own roots of origin, the boys are alienated from their own people. and remain so far the rest of their live.

It is precisely to avoid the turning out of alienated and rootless young men 2587 LS -8

that 'parents in developed countries have shunned the ideas of public schools' system. Yet in India where we need consciously to promote integration, the State continues to tolerate and assist special schools, which turn out potential brown sakels. It has gone so far as to maintain such schools by direct funding and patronising such a system. It is the time that we should seriously think of discarding such a system which is cutting at the very root of integration and making our children subverters of their own culture and heritage. Although the Centre has not been able to feel the pulse and has realised the extent of damage which such private schools are doing to the nation. Ferhaps primarily this is the reason that they have already adopted a unanimous resolution in Delhi Metropolitan Council
where they have suggested doing away
with the Public School Education System to bring uniformity in the standard of education and have recommended that such schools should be brought at par with those of the Government of Government-aided

It is strongly felt that the Centre should move fast in scrapping out the system of public school education so as to bring an end to corrupt practices by the management of these public institutions throughout India.

> (v) REPORTED DEATHS AND HEAVY LOSSES DUE TO RAIN IN HIMACHAL

SHRI DURGA CHAND (Kangra): I am thankful to the Chair for having permitted me to raise this matter of urgent public importance under rule 377....

This year, Himachal Pradesh has faced heavy and incessant rains causing death of 141 persons. Hundreds of cattle have perished, thousands of houses have collapsed, standing crops have been des-troyed and there is heavy erosion of fertile lands, damage to roads, culverts and bridges by landslides, particularly in Kangra, Chamba, Mandi, Bilaspur, Hamirpur and Solan District. The total loss as per reports amounts to several crores of rupees. This is too much for a backward State to bear such a heavy loss on account of natural calamities.

There is an urgent need to provide adequate funds from the Central Exchequer for relief measures in the worst affected regions in the State and to send a Central Study Team to make an on the spot assessment of the havoc wrought by the heavy rains in this State and the damage caused by the earthquake shocks in the Dharma-sala area (District Kangra). 19 56 hrs.

PRESS COUNCIL BILL contd.

4R. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the following motion moved by Shri L.K. Advant on the 24th August, 1978. namely:

"That the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the freedom of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers and news agencies in India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.

Shri Venkataraman to continue.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : About the telephone system in Calcutta, I have given notice.

MR. DEPUTY-SPEAKER: A hundred notices are there, including yours.

भी राज नारावज (राव बरेली): महो एक निवेदन भापसे करना है कि एभर फोर्स के हैड 31 तारीच को रिटावर हो रहे हैं। सरकार इस पर एक क्यान यहां पर दें। इस में देश की सुरक्षा का सवाल है।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): (Begusarai): It is an urgent matter which is going to be decided by the 31st. This matter has to be brought up before the House before that date and the expert committee report has also to be placed on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have called Shri Venkataraman to continue his speech on the Press Council Bill.

VENKATARAMAN South): I was saying last (Madras evening that the public have a right to independent and objective news and fair comment. One of the factors which militates against an objective presentation of news is the self-interest of the newspaper proprietors, and the self-interest is brought about by other extraneous interests like business which the propreitors of the newspapers have. Therefore, all over the world, wherever there is a free press, there has been an agitation for diversification of the ownership of the newspapers and for controlling the monopolistic tendencies in the press.

The Press Council Act of 1965 stated in section 12A that the object was :

> "to study the developments which may tend towards monopoly or concentration of ownership of newspapers and news agencies, including a study of the ownership or financial structure of newspapers or news agencies, and if necessary to suggest remedies therefor."

28'50 Are.

[Surimati Parvadur Kriednam in the Chair]

The hea. Minister, while introducing the Bill here, said that he had more or less faithfully carried out the provisions of the old Act, and he mentioned only one or two deviations, but he omitted to mention this very serious deviation which he has made in the Bill now before the House.

If you refer to Clause 13(i) relating to monopolics, the power of the Press Council under the Bill before the House is:

'to concern itself with developments such as concentration of or other aspects of ownership of newspapers and news agencies which may affect the independence of the press;".

#### 13.00 hrs.

I want you to kindly look at the difference in the language. In the old Act, the Press Council was authorised to study and make recommendations for the avoidance of monopoly and concentration. In the new Bill before the House, the Press Council is asked only to concern itself with developments such as concen-tration. I have looked into some of the judicial dictionaries of Words and Phrases and I have found that there is no judicial definition of the word "concern" as a transitive verb. There is a definition in the dictionaries where it is a noun that "concern" means anxiety. In certain cases where there are contracts and a person is said to be a "concerned" with the contract, it shows the interest of the person is the con-tract. But "to concern itself" would only mean, according to the Oxford Dictionary, to interest oneself in or about the matter.

So, don't you see the great difference between the power of the old Press Council to study the monopolistic tendencies and the concentration of power and to make recommendations and of the Press Council recommendations and of the Press Council under the present Bill, which shall concern itself, that is, interest itself? Sir, I am making this point because if the Press Council tomorrow takes up any issue of concentration of, or monopolistic tendencies in, the press, the press concerned will go and more the Supreme Court and uencies in, the press, the press concerned will go and move the Supreme Court and say that it is beyond the jurisdiction of the Press Council, because it has no power to study, as it was in the original Act, it has no power to make recommendations, as was the position in the original Act, but it can only concernized from the original concernities it will be itself, that is to say, interest itself; it will be interested in knowing who is the owner and what is the extent of his holding; nothing more. I do not know why the hom. Minister thought it necessary to deviate from the old section, when he has adden advanted them in menet of all the other idem adopted them in repect of all the other

clauses. It amounts to weakening of the powers of the Press Countil. Unless the Government wanted to be soft towards some press barons, there is no other justification whatsoever for changing the clause, as it stood in the Act of 1965, into this almost anaemic clause, saying that it shall concern itself.

I shall briefly refer to the position in England. There the Press Council shall have the power to report publicly on developments that may tend towards greater concentration or monopoly in the press, including changes in ownership, control, and growth of press undertakings and too publish statistical information relating thereto. The British people believe that public opinion is a far greater check against abuse than any legislation. Therefore, the British people have provided that if statistical information regarding the ownership of newspapers is published widely, then it will give rise to an opinion in the country, both against the tendency towards growth of monopoly as well as against the concentration in a few hands. Therefore, they have relied upon public opinion, rather than legislaton, as a check.

But, what do we do here? We follow, neither the British pattern, in which we will create public opinion by publishing all the information regarding the ownership and control of the press, nor do we follow a pattern which was adopted in the last Press Council Act, in which the Press Council was specifically given the powers to study the growth of monopolistic tendencies and to make recommendations therefor. Today, in my opinion, the Press Council cannot make any recommendations with regard to the concentration of power and monopolistic tendencies in the press with the clause as it rtands.

As you know, in the interpretation of statutes, if there was a previous statute and that statute had been amended or changed, then the interpretation of the new statute is that the Parliament did not want an old law to continue and they enacted a new law, different from what the original law was. Therefore, the point really is, if you want that the Press Council should have the power to study, then you must adopt either the clause which was in the original Act or you must adopt the clause which the Press Council in England has. If you do not adopt these two things, the fact that there is a clause saying that the Press Council "shall con-cern itself" is mere verbiage and will have no affect and no value.

भी निर्मल चन्न चैन (सिमनी): समापति महोवय, मैं इस विश्रेय क को लाने के लिए संत्री जी को बन्चवाद देता हूं। जहां तक प्रैस का सवाल है, प्रेस की महतां [किसी प्रकार से नकारी नहीं जा सकती । वह प्रपंत्र कार में कहना है । वह प्रपंत्र कार में बहुत विकार में है । कभी कभी में में यहां वेचा है कि प्रध्यक्ष की जब वह कह वेदे हैं कि प्रकार को कोई जी गांवण रिकार नहीं किया जाएवा तो तोय व्य हो कर की कोई जी गांवण रिकार नहीं किया जाएवा तो तोय व्य हो कर बैठ आते है व्योक्ति उन का वह भावण प्रस में नहीं बाता । यह भी अपने आप में प्रस की सिक्त के साथ साथ संवय की भी बहुत की सिक्त होती है वहां किया का परिवार में में सिक्त ने साथ से स्वय की भी बहुत का बक्त की सिक्त होती है । जब वो प्रतिकृत की सिक्त के पास पैसा हो और इसरी सरकार की जिल्ला तो इन वोनों अपनरमां की बीच में संसुक्त की भी बहुत धावस्थकता होती है । इस संसुक्त की भी साध्यकता होती है । इस संसुक्त की भी साध्यकता होती है कि जनान सहस्त के तरण पीड़ित न हो ।

समाचारों के बारे में बहुत प्रभावशाली इंग से कहा जाता है कि समाचार क्या है ? यदि कुता प्रावशी को काटता है तो समाचार नहीं बनता, लेकिन यदि प्रावशी को काट लेता है । कई बार समाचार वर्ते तो समाचार व जाता है । कई बार समाचार पत्रों में इतनी सनसनीखेज बीजें पाती हैं कि जनमानस को उचम पुषस करने में वे बहुत सहायक होती हैं । इसिलए जो पत्र सेंस में नहीं बहिक सेंसिम्यलज्भ में ज्यादा विकास रखते हैं, उनकी भी रोक बाम के ज्यादा विकास रखते हैं, उनकी भी रोक बाम का जाता है । लेकिन यह रोकयाम किसी कानून से न होकर वे धूमपने माप को स्वतः प्रमुकासित करें ।

धाजकल पीत पत्नकारिता बहुत बढ़ती चली जाती है। बहुत से पीत पक्ष तो धनुप्रास धौर धार्ल-कारिक भाषा में इस कदर लिप्त रहते हैं कि उनकी इस प्रवृत्ति पर अंकुश की भावश्यकर्ता है । लेकिन प्रैस की स्वतंत्रता का गलान घोंटा जाए, उनके भक्षिकारों का शंरक्षण हो। प्रैस भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अपनी शक्तिका दुरुपयोग न करे । इसलिए इस सम्बन्ध में इस प्रैस कार्जेसिल बिल को ठीक ढंग से लाने की चेव्टा की गयी है। बहुत विवाद जला था पहले कि इसका गठन किस प्रकार से हो । कुछ लोगों कामत थाकि प्रान्तको स्तरपर भी एक काँउंसिल होनी चाहिए। लेकिन अन्ततोगत्वा विचार विमर्श के बाद जो तथ्य सामने झाए उन में पहले के संसद सदस्यों की समिति की जो सिफारिश यी उस के ऊपर भी एक सुझाव यहां पर शाया कि तीन व्यक्तियों का पैनल बने भीर बह एक चैयरमैन को मनोनीत करे। मैं समझता हं कि इस से एक योग्य सभापति, निष्पक्ष सभापति भौर कर्मठ सभापति प्रैस काउंसिल को प्राप्त हो हो सकेगा ।

घषी तक वही प्रेस जानी मानी होती वी जिसक सम्पर्क बनी मानी वर्ग से होता वा जो घपने छाप में प्रभावशासी होती थी। क्षेत्रीय भाषामों की उस में सबहेतना होती थी। घब क्षेत्रीय भाषामों, को, उन के सम्पावकों को बीर न केवल सम्मावकों को बस्कि अम जीवी पक कारों को भी उस में प्रतिनि-क्षित्व देकर इस को वास्तव में एकप्रतिनिश्चि संस्था

बनावे की चेच्टा की नई है । इस में अवबीदी पक्षकार साम होंगे, सम्वायक छ: होंने, संवासक की जो विभिन्न प्रेसें हैं उन की तीन वर्गों में बोटा नया है, बड़े मध्यम और छोटे, उन में से दो दो रखे गए हैं, तमाचार एजेंसी का एक विकिच्ट व्यक्ति जिन को मान रहता है वैसे तीन और सादे पांच, इस प्रकार से जो इसका गठन है उस गठन में इस बात की चेव्टा की गई है कि सभी प्रकार के लोग और सभी रिजंज के लोग इस में प्रति-निधित्व प्राप्त कर सकें ताकि उसका प्रतिनिधि रूप पूर्ण रूप से विकसित हो सके धौर वह एक स्टैंडर्ड, एक कोड धाफ कंडक्ट भी बना सके पत्रकारों के बिए । इस बारे में बहुत व हस चली थी कि कोड भाफ कंडक्ट होना चाहिये भयवा नहीं। कुछ लोग बाहते थे कि निरंक्ष स्वतंत्रता उन को प्रदान की जाए। लेकिन मैं ऐसामानता हं कि जो का पिछले कुछ दिनों स्तर पीत पत्रकारिता से देखने में आया है और जैसा मैंने कहा सैसंगन-लिण्म की जो एक प्रवृत्ति रहती है उस के कारण एक कोड प्राफ कंडक्ट का होना बहुत प्रावश्यक 8 1

इन सभी दृष्टियों से इम वें जितने प्रावधान किए गए हैं, बहुत संतुलित ढंग से किए गए हैं बौर उस के लिए में मंत्री महोवय को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रेम गरिवद की पुनस्योपना का प्रवास किया है जिल्ल को खापातकाल में जबदंस्ती प्रैम का गला बींट कर समाप्त कर दिया गया था।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Gunanore): I support this Bill. But, while supporting the Bill, I would like to make a few observations.

First of all we are not discussing the Press Council Bill in a vacuum. There is a background. We had a Press Council according to a parliam intary statute and that was working in this country for more than 10 years and then it was scrapped. But it is useful for us to know or for us to look back what happened during the operation of that Press Council in the country. We had succeeded in fulfilling the objectives for which the Press Council was made. Why I am saying so is because I have gone through this Bill and all that which is said is laudable. It is like a good ornament but whether it is going to serve the purpose for which it is being enacted, I have my own doubts.

First of all, the Bill says that this is to help newspapers and news agencies to maintain their independence. For making the Press independent this enactment is being brought forward. But is it possible really in the situation as we have it in our country to-day? Because the important newspapers in the country are owned by industrial houses. That is why the question of diffusion of ownership and delinking the press from the industrial

houses becomes a major issue. When we speak of the press freedom. So long as it is not a reality. You have expressed yourself for the delinking of the press from the industrial houses. So long that is not done. I cannot visualise that we will have a free press.

Sometimes some accident may occur and due to political reaons, the industrialist may take a stand; that is laudable. But that is an accident. Here Shri Venkatraman pointed out that thing. When you speak of the concern that the Press Council should have about the pattern of ownership, you do not seem to have gone further in that. There I would like to disagree with Mr. Venkataraman also.

According to him, he wanted to study the pattern of ownership. Earlier the Press Council was making recommendations to Government from time to time. But, what happened to the recommendations that they have made? You know that nothing was implemented. In a society like this, where press is part of an industrial house—if the the press, by and large, is run by the industrial house—it will not serve the purpose of creating a free and independent press in our country. Take the industrial houses. They run not only the press but also the hospitals. There are temples run by them; there are social welfare organisations and there are schools, colleges and everything as also newspaper. It is one of the status symbols for an industrial house to have a temple—Lakshmi Narain Temple by Birla. (Interruptions). You may not know that ever God is being sold in retail and wholesale. the problem.

So, my point is this. In a Bill like this, you are not going to make much headway unless you have a political will to diffuse the ownership of the newspapers and delink it from the business house; I am sure, you—not the minister but the Janata Party Government—will not be able to do that.

Coming to another aspect of the matter, recently, I was very much amazed to know about the P.T.I. I think it is now a part of the Non-aligned News Pool. We now have got rid of the Samachar. We wanted to make the news agency more independent. Look at it as to how they reported the Non-aligned Conference of the Foreign Ministers which took place in Belgrade. That was one of the most distorted version. Eeven the press in U.S.and in U.K. reported that much more fairly. What was said about the role of Cuba in Africa? Here the monopoly press of the industrial house and their masters, the imperialists, wanted to depict Cuba as an aggressor in Africa. That was done in a most unashamed manner. And you want to call it an independent news agency. It is not possible. These limitations you will have when you enact

this legislation. Even then it is good that at least we speak about press freedom and about the necessity of the independence of a press.

As I said at the beginning, I extend my support. I have of course moved my amendments specifically to improve the legislation further. If the Minister accepts my amendment to the legislation regarding the monopoly houses, the ownership of the press and having more representations of the journalists, I will be very happy about it.

When I move my amendments at that time I shall refer to them.

भी स्रोम प्रकाश त्यांनी (बहराइच) : सभापति महोदय, में इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हं और मंत्री महोदय को धन्याबाद देता हं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विश्वेयक को इसी सैशन में पारित करने के लिये हम को धदसर दिया । मैं इस दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण मानता है कि हमारे देश ने प्रजातंत्र में विश्वास प्रकट किया है। प्रजातंत्र के लिये यह नितान्त ग्राव-म्यक है कि उस में मन्ष्यों की वाणी स्वतंत्र रहे. प्रेस, मन वजन पर पूरी स्वतंत्रता के साथ मौखिक और लीखिक रूप में विचार करने और प्रकट करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिये। जहां डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, चाहे किसी भी रूप में है, उनको प्रैस की स्वतंत्रता की भावस्थकता नहीं है. चन्द्रप्पन जी । चाहे यह एक द्राइमी की डिक्टेट**र**शिय हो या स्टेट की डिक्टेट-क्रिप हो, जैसे चाइना भीर रशिया में प्रैम की स्वलंबता की कोई कीमत नहीं मोनोपली और बिग हाउसेज की बात चाप कर रहे हैं, परन्त वहां मनध्यों के विचारों भीर स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं है। प्रगर स्वतंत्रता पूर्वक कोई विचार व्यवस कर दे तो बढ़े बढ़े साइन्टिस्ट भीर हिस्टोरियन जेलों में डाल दिये गये. धाप यहां स्वतंत्रता के शीत गारहे हैं।

SHRI?C. K. CHANDRAPPAN: Do you seriously believe it or because you just want to score a point that is why you are saying all that?

MR. CHAIRMAN: Let there be no interruptions otherwise, Mr. Tyagi, you will lose your time.

भी स्रोम प्रकाश त्यागी: मैं इसीलिये कहता हूं कि सगर प्रेस की स्वतंत्रता रहती है तो प्रजातंत्र मुरक्षित रहता है। 19 महीने की सापातकालीन स्थित के दौरान प्रेस पर सैंसरिशप लगाया गया और प्रेस देश की वास्तविक स्थिति को सरकार के सामने नहिं खसका, इसीलिये सरकार संधेरे में रही और उस को विनाश का मूंह वेखना पड़ा। प्रेस का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि बहु जनता और सरकार का मार्थवर्शन करे। इसके लिये भी उसकी स्वतंत्रता की सावश्यकता है।

मैं इसलिये भी इस विधेयक का समर्थन करता हुं कि ग्रापने किसी तरह से प्रैस की स्वतंत्रता के

मिये प्रेस काउंसिन की स्थापना की है। यही है। मैं बताना चाहता है कि प्रैस की स्वतंत्रता के उसूत्र हैं लोग, लालक भीर भय । प्राप भारतवर्षं के कितने समाचार-पत इससे मुक्त है ? वही समाचार-पत्न इन तीनों बातों से मुक्त हैं जिनका व्यक्ति गत रूप में एक बादमी मालिक है, मन्यभा जो बिग हाउसेच भीर मस्टीनेशनस्य की सपोर्ट के पैपर हैं या विदेशी धन के बाधार पर वहां चल रहे हैं, वह स्वतंत्र नहीं हैं और आपकी प्रैस कांच-न्सिस इन के द्वारा स्वतंत्र समाचार जनता तक दे सकेती, इस में मुझे संदेह है । प्रैस कांत्रसिल की जो प्रधिकार प्रापने दिये हैं, क्या उन की समझ में यह बात भा सकेगी कि उन समाचार-पक्षों के द्वारा भी जनता को स्वतंत्र विचार मिल सकें ? चास तौर पर जो स्वतंत्र रूप से चलने वाले कुछ समाचार-पत्र हैं, नोकि व्यक्तिगत हैं, उन के सामने भी बाढ़ा सा प्रसोभन है और वह है विज्ञापन का । हमने 19 महीने की ग्रापातकालीन स्थिति में देखा है कि सरकार ने उनका गला घोटने के लिये धपनी विज्ञापन नीति को ऐसा कड़ा बना विधा जिस से उनको सरकारी विज्ञापन न मिल सकें। उसका परिणाम वह हमा कि दिल्ली में ही ऐसे समाचार-पत्न, "वीर प्रज्न" प्रादि जो स्वतंत्र विचार व्यक्त करते थे, वह समाप्त हो गये।

इस प्रेस काउसिल बिल में यह घररा कहीं भी नहीं है कि सरकार की विकापन नीति में यह होगा कि कोई भी सरकार घाये यह निष्पक्ष नीति के द्वारा सभी को घपने विकापन देशी, पक्षपात नहीं कर सकेती, ऐसा घगर इस बिल में हो तो टीक रहेगा।

वर्तमान विज्ञापन नीति के अन्तर्गत समाचार-पत्नों को विज्ञापन उनकी सक्त्रेयन के भाषार पर विये जाते हैं। जिन समाचार पत्नों के पास ज्यादा धन है, विज्ञा हो कि क्याते हैं, मल्टी नीकनलल्ड जिनके पीछे हैं, विदेशी ताकतें जिनके पीछे हैं, यह स्वामाविक है कि उनकी सक्त्रेयन ज्यादा होगी। लेकिन जिन समाचार पत्नों की पूंजी कम है, जो व्यक्तिगत समाचार पत्न हैं, उनकी सक्त्रेयन कम होती ह भीर इस लिए उन्हें विज्ञापन नहीं मिलते हैं, भाज विज्ञापन उन्हों को मिलते हैं, जो प्रैस की स्वतंत्र का गला भोटते हैं, जिन के डारा निज्यक्ष और स्वतंत्र कम से समाचार नहीं विये जाते हैं। मिस सरकार की इच्छा है कि प्रेम स्वतंत्र रहे, तो उसे इस सरकार की इच्छा है कि प्रेम स्वतंत्र रहे, तो उसे इस

प्रैस काँसिल को यह भी अधिकार दिया जाना बाहिये कि कोई समाबारपत बाहे किसी व्यक्तिगत मालिक का हो, किसी दिया हाउस का हो या मल्टी-नेशनल का हो, उस के सम्पादक की कलम पर की प्रीवन्ध म लगाया जा सके। श्री वर्गीय ने कुछ लिखा, तो वित्र हाउस ने उन्हें निकाल दिया । प्रैस काउँसिल को यह व्यवस्था करने का अधिकार होना वाहिए कि अगर कोई सम्पादक किसी दिग बिजिनेस की नीति के खिलाफ सम्पादकीय लिखता है, या विवार व्यक्त करता है, तो उस के खिलाफ कोई कार्यवाही न की जा सके, उसकी रोजी-रोटी पर

235

कोई कृतरा न माये। भाज स्विति यह है कि भौर पत्र-प्रतिनिधि भपने मालिकों निवाह को देख कर ही समाचार बनाते हैं।

प्रैस कौंसिज के प्रधिकारों में एक महत्वपूर्ण बात शानिस होने से रह गई है। राष्ट्रीय एकता की रका भी उस के प्रधिकारों में होनी चाहिए। कुछ समाचार-पन विश्व भारत भीर उत्तर भारत , हिन्दी भीर महिन्दी, हिन्दी भीर शंग्रेजी के नाम पर शाव-नार्ये उचाइने की कोशिश करते हैं, ताकि इस देश की एकता न रहने पाये। प्रैस कॉसिल को इस बारे में समुचित व्यवस्था करन का अधिकार भी होना होना चाहिए।

मैस कौंसिल के प्रधिकार में यह भी हो कि समाचारपत्र में समाचार या तो छपेन भीर अभर छपे, तो वह पूर्ण होना चाहिए, एकांसी नहीं होना चाहिए । हम देखते हैं कि कई समाचार पत्नों में सभूरे या तोड़-मरोड़ कर छापे जाते हैं। वे समाचार पत्र का उतना ही संश प्रकाशित करते हैं. कित से उन के विचार का समर्थन होता है। जो क्रिक्स से उन के परंपच को सर्व करता है, केवल उतना ही हिस्सा — अपने मतलब का हिस्सा ही-कई समाचार पत्नों में छपता है, जिस से जनता प्रांति में रहती है। जो समाचार पत पूरा समाचार नहीं देते हैं, जैस नीसिल को उन के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए . ताकि पूरा समाचार जनता के सामने आये ।

यह विधेयक लाने के लिए मैं मंत्री महोदय को बन्यवार देता हूं भीर भापको भी धन्यवाद देता हं कि आप ने मुझे बोलने के लिए समब दिया।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Madam, Chairman, while welcoming major portion of the Press Council Bill, as proposed in this House, I would like to make some observations and suggestions.

Madam, 'Freedom of the Press'is a must. Here, from this Press Council Bill, we see that this will be mainly controlled by the Gentral Government and there are too many restrictions for controlling the Press Council. The Press Council should really be an independent body under whose purview even, radios, televisions, all newspapers, journals and the whole mass media should come in. In England there has been legislation even in 1977, that is, last year in this regard. This is a so the case in the U.S.A. Radios and televisions are under the control of their Press Council. Here it is said regarding the objects that it shall preserve the freedom of the press and maintain and improve the standards of newspapers and news agencies in India. I wish to submit that all journals, radios and televisions should come within the purview of this Press Council. the past, there were certain restrictions.

But if there are certain restrictions even now, if there are controlling factors, under which they are to be brought up, the Press Council cannot act freely. The Press Council should be given wide powers to see that the freedom of the press is achieved in real terms.

Press Council Bill

Then, the freedom of the press will not be there if there is individual ownership of newspapers. By individual ownership, I mean, certain newspapers are owned by Goenkas, Bangurs etc. and other privated limited companies. This is also to be considered as individual ownership. The Press Council should be empowered to see that the individual ownership of the newspaper is done away with. The Press Commission of U.K. has been given wide powers and we should see that the Press Council in India is empowered fully to achieve these objectives.

Sir, as we know, the Press Council in India was suspended some time back; that was very unfortunate for all of us and the nation. When this Bill is again before the House, it should have been brought in a comprehensive way and the Press Council should have full autonomy in all its administrative and other matters and should have ample powers to work freely. The Government of India should not in terfere in their affairs and should not impose limits on them that they will go upto this limit and not beyond that. They should be given suitable powers so that they are able to achieve the objectives enumerated in the Bill that is being enacted.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, as it is, the objectives of this Bill are very limited and the scope of this Bill is very small; the hon. Minister will bear me out. The objectives are only to improve the standards of newspapers and news agencies in India. The objectives should be to improve, to enlarge the newspaper industry as a whole, and bring about the required improvements in the working of the mass media, so that they can reach the people in an objective manner. The mass media would include the television and broadcasting and as I said, these should also come under the purview of the Press Council. If this is not done, we would be able to achieve only partial freedom of the press and not full freedom.

As I said earlier, the Press Council should be fully empowered to do away with the private ownership of the newspaper. Where there is private ownership of any particular newspaper, the editors and reporters cannot give vent to their views freely and fearlessly. It is, therefore very essential that every effort should be made to do away with the private ownership and that should be one of the objectives of the Press Council.

I have got many other things to say, but I shall speak at the time of discussion on my amendments. With these words, I conclude.

कां राजबी बिंह (जानलपुर) : समापति
महोदय, प्रेस कौसिल का जा बिल यहां पर उपस्कित
किया गया है, यह हमारे मंत्री जी का सीमान्य है कि
संसद में स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जितने विश्वेयक
है उनको उपस्थित करने का उन्हें ही प्रवसर प्राप्त
हुमा है। प्रवार्तन के प्रिप तामह, रूसो ने कहा
है :

"Low of liberty to mind is worse than death. Death is not the greatest calamity. There are still more terrible calamities for the brave ones who, if need be, are prepared to lay down their lives for the noble cause of freedom and liberty".

यह हमारा सीमाग्य है कि घाओं फिर माननींय मंती जो के प्रयत्न से प्रेस परिवद् का पुनर्जन्म हो रहा हैं। जिस प्रकार से 1977 में भारतवर्ष में स्वतन्त्र ता का पुनर्जन्म हुया उसी प्रकार 11 वर्षों के बाद प्रीर 19 महीने की इमर्रजेंसी के बाद प्रेस परिवद् का पुनर्जन्म हुया है । प्रेस की घाओंची के लिए यद्यपि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेहरू जी ने बहुत हुए कहा था, वैकिन फिर भी उनको प्रेस धान्येश्वनेवल मैटर ऐक्ट बनीना पंडा था। यह हुनारा सीमाग्य है कि माननीय मंत्री जी से प्रसानवेवल नैडर ऐस्ट को जी निरस्त कर दिया है। यंबंपि नेहरू जी ने कहा था:

"I would rather have a completely free Press with all the dangers involved in the worng use of freedom than a suppressed or regulated Press."

नेकिन उनको भी प्रेस पर कुछ वाजावें उपस्थित करनी पड़ी भी जीर हमारे माननीय सकस्य को जान मेस भी स्वतंत्रकता के लिए बोल खे हैं उनको सुननर यूने हात्य होता हैं कि कस तक ये मेस की मुनानी ना समर्थन कर रहे वे बीर काल प्रेस भी स्वतंत्रकता का समर्थन कर रहे हैं। पर देर से ही सही जेकिन हुदस्त बावे—मैं इतना ही क्षूनेया।

वास्तव में भाज को मेस का स्कूल्यस्य इन-वास्त है उसको भी देवने भी जकरत है तथी मेस की स्वतन्त्रता रह सकती है। श्री के स्थित तथे के देवसे 23.5 परतेंट हैं। मेहोसीसेटमं सिटीय, कलकस्ता, बन्बई, महालं भीर विस्ती में 31.2 परतेंट हैं और एकं माध्य से मंग की घांवादी के जो टाउन हैं जमाँ 11.3 परतेंट हैं। तो इस बात को हमें ज्यान में रखना होगा कि संमानीरायें जो हैं बहु बेबन इताईट्स के लिए हैं, प्रवेष वेस्ट हैं इसलिए खनर संगोधार-मंत्रों मी स्वतंत्रता के साथ मारत की जनता की स्वतन्त्रता को बोदा मारता याद स्टूक्संट्रक इन्वेनेंस को खर्म करना होगा परम्या गांवाँ में जो करीड़ीं गरीब लीग हैं जिनके लिए संगोधार-मंत्रों की स्वतन्त्रता श्री स्वतंत्र हैं। इसलिए में समझता हु साम जन इस श्रेस परिवद के गठन के सम्बन्ध में कातवीत कर रहे हैं को वह ब्यान देने की मानवयकता है कि यह ठीला है कि एक स्वतन्त्र प्रेस के लिए उसकी सतानिरदेश भी होना चाहिए भीर स्वामित्वनरपेक्ष भी होना चाहिए। सत्तानिरपेक करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इसकी सरकार के बन्द्रवैत नहीं रका हैं भीर यह एक बहुत बड़ी बात है। धाप देखेंगे कि प्रगर सरकार भी निरंकुत हो अधि तो प्रेस परिषद सरकार के खिलाफ भी धनशंसा कर सकती है लेकिन अंच्छा होता अंगर प्रेस परिवद के बाध्यक्ष को सरकारी कीव से पैसा नहीं लेना पहेता क्योंकि जिसका पैसा मिलेगा उसकी बायेगा---यह नैसर्गिक सिद्धांत हैं। इसलिए प्रेश्न परिवर् को सत्तानिरपेक्ष करों की जो बात कड़ी गई है यह तो पहला प्रेस कमीवन जी था उसके लिए भी रिपोर्ट के पेज 53 पर कहा गया था:

"Press could be free only when the Government keeps away from it, nor is the Press above the law of the land..".

यह ठीकं बंति हैं कि प्रेंस की यंशे के कानून का दुरुयोग करने का मिंडिहोर नहीं है लेकिन सला से प्रेम की स्वतन्त्र होना ही काहिए। मैं समझता हूं प्रगर सबनुब में श्रेम को स्वतन्त्र देश बाहते हैं तो सता से उसको हटाना होया लेकिन प्रेस की स्वतन्त्रता की दूंगरी वर्त की है कि उसके स्वामित्वनिरंपेकां भी होना चाहिए।

> "Press Council would never be able to discipline the Press, unless it was de-linked from Big Business."

धनर टार्टा, बिंधुना धीर जैंन जैंस संरंधीयेवाँसे के त्रेस चलते रहेंगे तो फिर हिन्दुस्तान में प्रेस की स्वतन्त्रता का घर्ष बेकार हैं। इस लिए सबन्ब में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए उकका सती निकेंब के साव-साव स्वामित्व निकेंब की क्षीना काहिए।

> "A definite danger exists of news being twisted to serve the personal interests of the owners."

इसी लिए यह भावश्यक यां---प्रेंस कमीशन ने कहा वा---

"If you cannot do anything with the ownership you must do with the management of newspapers."

बिंद इस पर बिग-विजनेस वालों का एकाधिकार रहेगा, को वह प्रेस की स्वतन्त्रता केवल पृंजीपतियों के स्वामित्व धौर उनके निहित स्वाचों को पूरा करने के लिए होगी। इसी लिए नेरा निवेदल है कि बहां भारत के लिए प्रेस परिषद् बनाई कई है, वहां केवीय स्तर पर—चूंकि भारत केवल एक वेश नहीं हैं, बस्कि एक महा वेश हैं— रीजनक वैस कालिस वार्ड जाये, एक नेशनक रिजस्ट रखा जाय।

इसी सम्बन्ध में मैंने एक और बीध देखी है---जिसे संबक्त प्रवर समिति ने दिया है। हमारे नाननीय नायसंकर साहब भीर दो धन्य सदस्यों ने मोट-बाफ़डिसेच्ट दिया है ---कोड बाफ़ कण्डक्ट के बारे में। यह कोड बाक़ कम्बक्ट क्या चीज ह ? हम समझते हैं कि जो सरस्वति की बाणी के उपासक हैं-जन को स्वयं अपने अधिकार के साथ-साथ करीव्य के लिए प्राचार-संहिता बनानी चाहिए, हमें उन पर कोई बीच लादनी नहीं चाहिए . . . .

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

**डा॰ राजजी लिह: मैं** एक मिनट मौर सेना बाहुंगा---स्लाख 14 (1) में---

Decision of Press Council beyond courts.

MR. CHAIRMAN: You have given notice for an amendment. You can speak Please conclude on your amendment. your general remarks.

डा॰ रामजी लिंह: इस लिए मैं एक जीज कहना चाहता हूं ---

Decision of Press Council Bryond courts.

मैं समझता हूं---यह गलत है। प्रेस कॉसिल भी तानाबाही के रास्ते पर जा सकती है, इसुलिए उस का न्यायालय को द्वार बन्द नहीं हीना चाहिए। द्मश्री हाल में भगरीका के एक प्रोफेसर भाये ये 🖚 एक सेमिनार हुआ या -- 'Judiciary can save the Press'. इसक्यें कहा गया है — "The judiciary can provide "salvation" for the Indian Press from Governmental Pressure.

ः इसलिए नैं समझता हूं---माननीय मंत्री जी का यह कहना कि प्रेस कॉमिस के लिए कोर्ट का दरवाजा बन्द कर दिया जाय, मैं समझता ---यह **ठीक नहीं हो**गा।

इन गन्दों के साथ मैं इस विधेयक का हरय से स्वागत करता है।

बी राभ कुष्म (भरतपुर) : समापति जी, जो विशेषक प्रेस की स्वतन्त्रता, प्रेस के स्तर को ऊंचा करते के लिए लाया गया है, मैं उसका स्थागत करता है।

लेकिन, सभापति जी, सवाल यह है कि हम प्रेस के स्तर को ऊंचा रखना चाहते हैं धीर हमारी यह स्वतन्त्रता भी सुरक्षित रहे---इस का प्रयंश भी करता चाहते हैं। लेकिन जो समाज की · वर्तमान विका है और जो समाज की वर्तमान दशा है--- उत्तका रिफलेक्सन प्रेस पर हो--- यह बोई रोक महीं सकता है। म्राज स्वतन्त्रताका**मर्थ** क्या है? अगर स्वतन्त्रता का अर्थ केवल सरकार का इस्तक्षेप करना नहीं है, तो मैं समझता हं-- यह बारणा नितान्त गर्जत है। बाबिर सरकार जनता की निर्वाचित सरकार है पीर सरकार का जी भपना कुछ दृष्टिकोण होता है। स्वतन्त्रता का अर्थ केवल इतना होना चाहिए कि जो हमारे नीति निवेजक तिद्यान्त हैं, उन के विवास प्रेम सन्र कोई काम करे तो उस की स्वतन्त्रता का हनन मानेंगे। जिस राज्य की कल्पना हम ने की है, जैसे समाजवादी राज्य-में समझता हूं सजा समाजवादी राज्य की कल्पना के जिलाफ़ अगर प्रेस आचरण करता है. उसके खिलाफ़ प्रचार करता है--उस का समर्थन करे यान करे, यह दूसरी बात है ---लेकिन जो हमारे मौलिक सिद्धान्त हैं, मौलिक मान्यतायें हैं, यदि उन के खिलाफ़ प्रेस काम करता है, तो इस के लिए हमें निश्चित रूप से कोड बाफ कम्बन्ट बनाना चाहिए और हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं। स्वतन्त्रता का धर्ष यह कभी नहीं हो सकता है - असीम स्वतन्त्रता या वगैर बन्धन की स्वतन्त्रता । स्वतन्त्रता का एक सीमित धर्य होता है। उस के सीमित वर्ष में जिस तरह हिन्दुस्तान का नागरिक या संसार का नागरिक प्रपने माप को उपलब्ध करता है, उसी तरह की स्वतन्त्रता प्रेस की भी रहनी चाहिए धीर उसी द्विष्ट से बहु भपने स्तर को बना सकता है।

प्राज सब से बड़ा सवाल यह है कि हमारे प्रेस की स्थिति क्या है ? स्थिति यह है कि हिन्दु-स्तान का बड़ा प्रेस हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों के हाय में है भीर जो प्रेसपूँजीपतियाँ के हित में रहेवा, वह पूँजीवाद के विलाफ संबर्ध कर सकेगा — यह कभी मी सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिए ग्राज सब के बड़ा सवान हमारे देश के सामने यह है कि हम पूंजीपतियों ग्रीर बढ़े भरानों के इस प्रेस के स्वामित्य को कैसे दूर करें? धौर में समझता हु कि इस प्रेस परिषद् के बारे में या प्रेस के सम्पूर्ण मामले पर घर्मी में सरकार इस दृष्टि से विचार नहीं कर रही है। असभी विकारणीय प्रश्न तो यह है कि अब हम ने समाजवादी समाज की कल्पना की है, समाजवाद राष्ट्र की काल्पना की है तो हमारा हर संदम, हमारा हर परण, हमारा हर कार्नेन उस विका की सम्पृष्ट करने बाला होना बाहिए, उस दिशा की मजबूत करने वाला होना चाहिए। प्रेस परिवद विधेयक में इस की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हं कि इसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस मान्वता के प्रधिकांत्र सदस्य कार्यल है।

सभापति महोदया, एक बात कहीं गई कि प्रेस लोभ भीर लालक के मुक्त रहना बाहिए। क्या यह बीच कभी इस समाज में संभव है जहां व्यक्तिगत पूंजी है? जब तक पूंजी का बाकर्षण बना रहेगा बुनिया में उस से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अवर हम इस सारे प्रेस को स्वतन्त्र करना चाहते हैं, तो इसके स्वामित्व पर भी हमें विकार करना होगा।

हुमारे देश में एक बड़ा संकट पीली पत्रकारिता का है। यह पीकी पत्रकारिता क्यों प्रतपी? इस के दो-तीन कारण हैं। एक तो यह है कि जो छोडे पक्ष हैं जनकी भाषिक स्थिति शत्यक्षिक खराब है। इसलिए ने पीनी पक्षकारिता के रास्ते पर जाते हैं। मंत्री जी बुद पत्रकार भी रहे हैं, राजनीतिक कार्य-कर्ता जी रहे हैं, इसलिए मैं उन से बाहुना कि वे बड़े समाचार पत्नों की बजावे छोटे छोटे पत्नों को, क्षेत्रीय पक्षों को मजबूत करने की कोशिश करें। क्यों कि पीली पत्रकारितों की तरफ छोटे पत्र ही जाते

एक सवाल जिसकी इस सदन में चर्चा की जा चुकी है विज्ञापन के मामले में है। क्या प्रेस सरकार पर माधित नहीं है? सरकार पर तो वह माधित रहेगा ? नेकिन सवाल यह है कि कीन-सी सरकार के भाश्रित रहेंगे? सभापति महोवया, मैं मानता हुं कि तीन-वार तरह की तानाकाही होती है। बाहे बेह सैनिक तानाशाही हो, चाहे वह सामन्ती तानाव नाही हो, चाहे वह एक दलीय तानानाही हो। तरह की तानाकाहियों में प्रेस कभी स्वतन्त्र नहीं रह सकता है। जिन नोकतांत्रिक म्ल्कों में प्रेम की स्वतन्त्रता की बात की जाती है, बँहां भी प्रेस की स्वतन्त्रताका अर्थ है शोवकों के पक्ष में प्रचार जो कि नहीं होना चाहिए। यहां भी जोचकों के पक्ष में बाताबरण बनाया जाता है। इसलिए ऐसी स्वतन्त्रता पर बन्धन लगाना बहुत अरूरी है। प्रेस परिवद में जो कंडक्ट की बात कही गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उस में विमित की सम्मति दी गई थी. उसको भी देखा गय। है। प्रेस परिषद् को कुछ कंडक्ट बनाना चाहिए जिस से दीली पन्नकोरिता की निवत्साहित किया जाए। त्रेस को शोवितों के विद्ध प्रचार करना चाहिए, कमजोर और दलित बगों के हित में प्रचार करना चाहिए और स्टेट पालिसी का प्रचार करना चाहिए । हमारे प्रेस का यही दुष्टिकोण होना चाहिए।

सरकार जैसी होगी, दैसा ही ससर प्रेस पर होगा । लेकिन हुम वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में जो हुमारी सरकार है, उसका जो दृष्टिकीण है, उसका समर्थन हिन्दुस्तान के पत्र करें। यह धाज का धर्म है, यह आज की जकरत है, इस से हमें इंकार नहीं करना चाहिए। स्वतन्त्रता की प्रसीमित बात कर के एक प्रकार का संकट प्रेस खड़ा कर दे, इसकी चूट प्रेस को नहीं दी जा सकती है।

मन्त में समापति जी मैं चाहूंगा कि हमारी कोनिन एक दूसरी होनी चाहिए। हालांकि हिन्दी और अंग्रेजी के नाम पर विवाद खड़ा किया जाता है। अप्री माननीय सदस्य थी बसु साहब दोल रहे वे। उन्हें मंत्रेजी में बोलने में कब्द हो रहा था। क्या पानका भाता प्रगर ने पंग्रेजी में बोलने के बजाये बंगला में बोलते। इसलिए हमारी यह कोशीश होनी बाहिए, हवारा यह वृष्टिकीण होना बाहिए कि हम तमिल को मजबूत करें, तेलगुको, बंगला को, प्रसमिया को मजबूत करें लेकिन ग्रंग्रेची को समाप्त करें। युद्द हमारी प्रेस परिषद्की नीति होनी चाहिए क्योंकि विदेशी भाषा से सामतबाद और केपिटेलिजन पनपता है। जहां मोक माबा होगी, वहां शीकमत जागृत होगा। जहां लोकमत जागृत होगा वहां जनवाद मजबूत होगा। विदेशी भाषा की बात करना, में

समझता हूं कि यह एक दंश है, एक बहुत बढ़ा झूठ है। इसमिए हमारे बेसे की कोतिस करनी चाहिए कि वह विवेशी भाषा की दासता से मुक्त हो। प्रेस की प्रपत्ती भाषा लोक भाषा हो सकती है। इस नोक समा को प्रोत्साहन देने के लिए धीर सामन्ती भाषा को समाप्त करने के लिए वदि प्रेस परिचद को कोई डिस्किमिनेशन भी करना पढ़े तो करना चाहिए भीर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनका प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिए, उसे पूरी मदद करनी चाहिए।

इन बन्दों के साथ , जो प्रेस परिचव् विश्वेयक लाया गया है भीर जिस सीमित उद्देश्य से लाया गया है, उसका में समर्थन करता है।

MR. CHAIRMAN: I should like to put this point to the hon. Members. According to the time allotted for this Bill, I have to call the Minister now. But there are as many as 12 speakers, still remaining to be called (Interruptions).... Normally such extension of time at this stage of the session is referred to the Business Advisory Committee. In view of the importance of the Bill.

AN HON. MEMBER: The time should be extended.

MR. CHAIRMAN: If you hear me me patiently, it will be helpful. We have got one hour remaining for the Bill. would request the members to co-operate when we come to the clause by clause. Meanwhile I would like to know whether the House wishes to extend the time.

**बौधरी बलबीर सिंह** (होशियारपुर): चैटा बढ़ा दिया जाए

SEVERAL HON. MEMBERS: One hour more may be given.

MR. CHAIRMAN: I want to make one thing quite clear. Mmebers will have to co-operate in this matter and that is that there will be only five minutes for each speaker. And, therefore, when I ring the bell, I would request the speaker would request the speaker not to say-one minute or two minutes more. When I ring the bell, kindly start concluding and do not force me to ring the bell a second time.

So, Minister will reply after one hour.

भीनती चन्द्रावती (भिवानी): जो प्रेस काउंसिल बिल पेश किया गया है इसका में समझने करती हूं। इस काउंसिल में जिन लोगों को रखा गया है तन में गांवों के रहने वाले जो लोग हैं जैसे डा॰ रामजी सिंह ने कहा है उनके लिए कोई गैजाइश नहीं रकी गई है। इनका बहुत बड़ा सैक्शन हैं। उस में [बीमती चन्द्रावती]

243

समनो समाबंदे आ सकते थे। वे गांव के लोगों की बात कहें सकते थे। पंचायतों की तरफ से पढ़े लिखे शीम या सकते थे, उनके नुमाइवे या सकते बे, फार्बर एसोसिएशन से नुनाइवे पा सकते थे। इस तरफ शापको ध्यान देना चाहिए।

जैसा कहा गया है बाज देश में दस्ट टाइप जाफ पूर्वीबाद है। पालिटिशियन भी पूर्वीपतियों के असर में रहते हैं। हमारे यहां गांवों में एक कहाबत है मुँह चाए तो भांख शरमाए। हम खुद तो चन्दे लें भीर उनके प्रभाव में रहें भीर यह कहें कि एडीटर उनते प्रभावित होते हैं तो यह ठीक नहीं है। जिस देश में इकोनोमिक सिक्योरिटी न हो वहां वे प्रभावित तो होंगे ही। हम लोग भी होते हैं। इसलिए हम उनको क्या दोष दे सकते हैं। उन में बहुत बहादुर क्रोग भी हैं। मुझे याद है हिन्दुस्तान टाइम्ज के प्रस कारेसपोडेंट चंडीगढ में जर्मा जी थे। उनका सब से पहला चैक मेरे पास चुनाव में प्राया मैं उनकी परसनली कभी धन्यबाद तक भी नहीं दे सकी हूं और नहीं उन्होंने मुझे से किसी चीज की इच्छा ही रखी है। मैं समझती हूं कि जो रिप्रिजेटेटिय भाषने मैनेजमैट के रखे हैं उनके स्थान पर प्रेस कारेसपीबेंदस के भन्दर से चुनाव करा कर रखे जाएं, सीनियर प्रेस कारेसपीडेंट्स में से द्भुनाव करा कर रखे जाएं धीर उनके नुमाइदे एडीटजें के धमाबा भी धार्वे तो प्रेस कार्डसिन स्थाया मजबूत हो सकती है।

टी॰ बी॰ और रेडियो को भी मैं समाचारपक्षों के शलन नहीं कर सकती हूं। वहां पर भी कुछ सैकांश्रंत्र की मीनीपोली ही नई है। पंटा थाध पंटा चने जाते हैं और सौ सवासी मारलाते हैं। जिस वैशे में इकोनोमिक सिक्योरिटी न हो वहां कुछ कोगों की मोनोपोली रहे यह बड़ी धापलियनक बात है। मुझे इस पर बड़ा जारी एतराज है। किस तरह से कुछ लोगों को बहा बुलाया जाता है, क्रिकेष वर्षाओं में भाग तेने के किए मुनाया जाता है, र्याटकसर सैक्सन के लोगोंकी बसाया जाता है, पैट्नाइज किया जाता है, इसकी तरह में आपको जाना चाहिए। हमारे गरीय देश में इस तरह की वात नहीं होनी चाहिये। सभी तरह के सीगों को वहां बुलाया बाना बाहिए । ऊपर नीचे के लोगीं को बुलावा काना चाहिए। बहिक मैं तो कहुंनी कि जो नरीय सीम हैं या जो अनएम्प्लायड संस्के हैं उन से और उनको बुला कर बगर वर्जाएं चलाई जाय तो कम से कम उनकी इतना ती मिलेगा। जी पहले क्षे एम्प्लामड है उनको रेडियो और टीं० **बी**० पर बुलाने से कोई लाभ नहीं है। प्रपएम्प्लायड को बुलाएंगे तो कम से कम उनको महीने में 250 इपये तो मिलेंगे। कुछ इनपसूर्णज्ञल जोगों की परिनयां हैं, उनका जी बहुजावा हो सके सिर्फ इसजिए अनको बहा ब्लाया जाता है। भीर उनके परिवार 🕏 जोगों को इसीलिए लाया जाता है ताकि उनका भी बहुल आयमा भीर उनका जैन बर्च भी निकल मानेगा । जो इस तरह के लोगों की पैट्रोनाइन किया जाता है इसके मैं सब्त व्यक्ताफ हूं ।

रेडियो और टी० बी॰ पर बंध विश्वास सीर भत परेतों से भरे नाटक विकासे जाने हैं, जब कि इस देश में अंधविश्यास पहले से ही हो वहां इस तरह के नाटक नहीं दिखार्य जाने वाहियें। कई बार तो इतने बरावने नाटक होते 🕻 कि बज्बे उनको देखते देखते हर जाते हैं। प्रैस वाले भाई यहां मुनते होंगे, ऐस्टोलाजी की बात हर संडे को बाती है. तो यह इमरजेंसी से बानी शरू हुई क्योंकि इनका कसूर नहीं था, यह कोई बात छाप नहीं सकते थे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी प्रैस काउन्सिल में जो लोग होंगे उनते भीर प्रैस वानों से भी कि भी विकापन वेते हैं तो विकापन से भी प्रभाव होता हैं। इसलिये विकापन के लिये एक कमेटी होनी चाहिये, जो निष्पक्ष रीजनल संखबार हों चाहे बहु कहीं से भी देश के किसी हिस्से से निकलते हों, उन सब को एक सा विज्ञापन निलना चाहिये। बल्कि होना तो यह चाहिबे कि जिसका सक्लेशन कम हो उसको ज्यादा मदद करनी चाहिये। कुछ लोगती कोटाले कर ही बाजाते हैं. इस तरफ ध्यान देना चाहिये। धाला है मंत्री महोदय मेरी बातों पर झ्वान बेंने।

बीधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर): संजायति महोदया, में श्रांपको धन्यबाद देता हूं और संती महोदय को मुदारक्याय देता हूं कि यह कैस काउन्सिल बिस नाये हैं। प्रैस अवाद हो बाद धीर उसकी कितनी साकत है यह सारी दुनिका को पता है। धमधीका में को सबसे ज्याचा कोट ने कर प्रेसीजेंड बना या उसको प्रैस ने खरन कर दिया एक काटर गेट स्कैंडल पर । एक मामूकी सी बात है। मामुली मैंने इसलिये कही है कि यहां हिन्दुस्तान में उससे 10 गुना ज्याका स्कैंबन हुए लेकिन किसी ने भाषाज तक नहीं उठायी।

MR. CHAIRMAN: I would request hon, members not to interrupt speakers. They have only five minutes. He fair to them,

चीवारी वसवीर जिल्ला: ४१० वसदेव प्रकरित कष्ट रहे हैं कि मैं शैर मुतार्क । काविस बाले बहुत मोर मकते हैं, उस तो सारी क्टी इस्के बुंती में मोमिन, आधिरी वक्त क्या धाक मुसलेमी होने । इंदिरा गांधी के राज्य में प्रेस कमिटेड / जुडिकियरी कमिटेड घीर क्योजीशन भी कमिडेड हुवा । वह कहत ये कि अपोजीशन हमारे से बात कर के बात कर सकते हैं, बैसे नहीं । मैं मार्जनीय चन्द्रप्पन साहब को बताना चाहता हूं कि जिस जमाने में बुकिया शबदार कम्बुनिस्ट पार्टी के छपते वे 1940 तक मेरे प्रैस में छपते रहे । जब इनकी ककाई पीपूरत कार बन नई तो हमारा और इनका नाता दूटा । तो मैं बहुना चाहता हूं त्रैस साजाव हो सके वह अच्छा है। लेकिन प्राचीय कैसे होगा नव करोड़पति इस पैस को चसाने वाले हैं। घंकी को, चार महीने भी बात है इसी देश में चन अनता पार्टी सरकार ने फैसला किया कि देहाती सनलों के मिन्ने, छोडे बंबों के सिन्ने और ऐत्रीकरून्र के लिये कुल बजट विया जांक्या, 40 परसेंड हि: जिल्ला के बार कि मही पता नहीं। लेकिन सारै मुश्क के सरमायेदार प्रेस वाले लाठी से कर पीछे पढ़ गये कि जनता पार्टी टूटनी चाहिये सीर रोज यहां उस ढंग से प्रवाद किया गया ।

### 14.00 पंटे

हम जो यह कहते हैं कि प्रैम घाबाद है, तो यह घाजाद कहां हैं। करोइपति लोग इसके जलाने वाल हैं, किसी के पीछे बिड़ला है, किसी के पीछे टाटा हैं भीर गोयनका है। प्रैम काउन्सिन इस तरह, के अधिकार दें कि ये सरमायेदारों के चंगुल से छूट सकें, एडिटर लोग उनके इज्ञारों पर न चल मकें। प्रेम के कौरल्पौंडेंट्स भीर रिमेजेन्टेटिकन के निये कुछ करिये। मात्र ये लोग घाजाद नहीं हैं, इनको पैसे के लिये किसी का मुंद देखना पड़ता है। इनके लिये कोई ऐसा कानून-बनाइये कि प्रैम वाले इनका गला न घोट सकें।

माज हम लोग जो इस हाउस में बोलते हैं उसके बारे में भी यह है कि जगर मखबार वालों को मनाम करने के लिये चले जायें तो खबर मुर्वी में बायेगी, धनर प्रैस वालों को सलाम करने नहीं जाइये तो खबर एक लाइन में भायेगी भीर वह भी इस ढंग से भावेगी कि बलबीर सिंह भालसो स्पोक । मैंने क्या प्वाइन्ट कहा है या न्या नहीं कहा है, वह अध्यक्षार में नहीं आयेगा । मैं चाहूंगा कि को प्रैस हैं; वह आजाद हीं और इन पर सरमायेदारों को गलबा बंश्म होना चाहिये। को एडीटर, कौरस्पीडेंट्स भीर रित्रैकेंटेटिक्स हैं, उनके लिये भी कोई इंतजाम करिये, कानून बनाइयें <sup>4</sup> तार्कि उनको पूरा पैसा निस सके, उसे कोई रोक न मके । बाली प्रैय काउंसिल बनाने से कुछ नहीं होगा । इस में कोई खारा ऐसी नहीं है जिससे उन नोगों को प्रोटैन्सन मित्र मके । इस तरह से प्रैस प्राजाद महीं हो सकेना ।

प्रेस पाउंसित एक्ट को घाप बना रहे हैं, उसमें मुलाजियों के लिये, क्लास III और क्लास-4 धीर जो घरों में जाकर पेपर सप्लाई करते हैं, छोटे-छोटे सब्बे अपनी जीविका के लिये यह धंक्या करते हैं, उसके लिये भी कोई इन्तवास करिये तमी यह प्रेस धाजाब हो सकेगा !

लोगों को लिखने की पूरी कावादी हो बौर उन पर किसी का प्रवाद म हो, वह अपनी मर्जी से अपनी बात लिख सकें, यह बद तक नहीं होगा, तो जो प्रेस काउंसिल विस धापने बनाया है, इनका कोई फायदा नहीं होगा । आप वह बातें पूरी की पूरी इसमें रखें, ताकि प्रेस झाजाद हो सके और इस देव की झाजादी की भावना पूरी हो सके ।

SHRI AMRUT KASAR (Panaji): I support this Bill and congratulate the Minister for bringing forward this Bill. But at the same time, I am surprised that this Government has taken 17 months to come with this Bill.

When I read the Press Council Act, 1965 and the present Bill, I find my surprise that there is no difference between the two except the composition of the Council and the sequence of the sections or clauses of the Bill. Anyhow, I am happy that the Janata Government have fulfilled another promise by bringing forward this Bill. The freedom of speech which was curbed during the emergency has been restored now. Some of the Members who had been supporting or the Memoers who had been supporting the emergency at that time asked 'where is the freedom of the press'. I do not support their views. Today, there is freedom of speech. In spite of their views, they have been saying that they preserved the freedom of the press. But the freedom of the press is not protected by the big monopoly houses. I feel that the big monopoly houses and big business houses are the outcome of our economic system, and unless this economic system is changed, their hold over the press also will not go.

The hon. Minister said in his speech that the Bill is brought for protecting the press from various onslaughts and encroachments being made either by the Government or by big business houses or by any other sector. The preamble also speaks about the same thing and in the objects of the Council the same thing is repeated. There are two parts of this. One is maintaining and improving the standards of newspapers and news agencies in India. For that there are a number of sub-clauses in Clause 13, but for the other namely preserving the freedom of the press, I do not see any sub-clause here in Clause 13. It is only said that the object of the Council shall be to preserve the freedom of the press. Freedom from whom? That is not se From Government authorities, from private individuals whether that is going to be done or not, that is not clear. And today actually the threat to the freedom of the press is also from Government. Government has also become a big monopolist and capitalist in the present society. The Minister may re-member that I gave him concrete examples. Many times Government has used its authority for unilaterally cancelling the advertisements to newspapers. Advertisements are stopped in order exercise coersion on newspapers. There must be a uniform policy as regards the distribution of advertisements. Unless these things are done how will you assure the freedom of the press from Government authorities also ? That is why that should have been cleared in Clause 13 of the Bill.

## Clause 13 (i) says:

"to concern itself with developments such as concentration of or other (Shri Amrut Kasar)

aspects of ownership of newspapers and news agencies which may affect the independence of the Press:"

The same clause was there in the pre-vious Act also. There is no change, So, the question is whether the in corporation of the same clause, even after the emergency, without some restrictions on the monopoly houses is going to help. If it is going to help, the Minister may explain in what way this will help us.

Again, Clause 14 speaks about the conduct of the newspapers only, but what about the conduct of the Government towards the newspapers? What is the provision made for tha in this Bill? That is also not there.

I am happy about the composition of the Council. It has become more representative than the previous provision in the Act of 1965. I have moved some amendments, and I shall speak on them at the appropriate time.

I again support this Bill and congratulate the hon. Minister on the restoration of the freedom of the press.

भी लक्ष्मी नारायण नायक (खुजराहो) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रेस परिवद विधेयक पेश कर के स्वतंत्रता का वातावरण प्रस्तुत किया है। धाप देखें कि समाचार पत्नों का काम केवल समाचारों का बादान प्रदान करना ही नहीं है बल्कि मैं मानता हूं कि राष्ट्र को सणक्त बनाना, समद बनाना और जो शोषित है उन को शोपण मुक्त बना कर के समानता के आधार पर एक समाज की रचना करना भी उन का काम है धीर इस में वह ज्यादा से ज्यादा अपना पार्ट घदा कर सकते हैं।

मनी कई माननीय सदस्यों ने कई बातें सामने रखीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सभी हमारे समाचार पत्न को गहरों का वातावरण होता है या उन के कार्यकलाएं होते हैं उन की ही सामने रखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गरीब, शोषित और पीड़ित भाई रहते हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं, उन को वह सामने नहीं रखते और वह किस तरह से समाज के मंग बन सकते हैं तथा उन् की कठिनाइयां किस तरह से दूर हो सकती हैं, इस में वह अपना पार्ट भेदा नहीं करते । मैं चाहता हूं, जैसे कि केन्द्रीय सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब महरों में धन्धे नहीं खुलेंगे, बड़े बड़े कारखाने नहीं खुलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ही हमारा सारा कारीबार होंगा, इसी तरह से यह प्रेस परिषद्की इस तरह से निर्देश दे, प्रेस के सामने ऐसे सुभाव दे जिस से देहाती श्रंचल के जो भी कार्यकलाप हैं उन को वह सामने लाएं धौर वहां जो मानव पीड़ित हैं उन्हें उठाने के लिए

बह काम करे । जैसा मैंनै निवेदन किया समाचार पत्ने का काम केवल समाचार का धादान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि उस की दूरगानी वृष्टि होनी चाहिए । मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कुशल सवार मनचाहे चोड़े को चाबुक भीर लगाम से भपने काबू में रखता है इसी तरह से प्रेस भी चाहे वह मनचाही सरकार हो, चाहे धराजक तत्व हों या समाज-विरोधी तत्व हों उन को अपने अंकुक्त में रख सकता है। तभी एक अच्छे समाज का बातावरण बन सकता है। मंभी कुछ मचवार ऐसी मतिरंजित बातें करते हैं, बढ़ाँ चढ़ा कर बातें लिखते हैं जो समाज के लिए हितकर न हो कर दुखदायी हो जाती हैं। इसलिए में चाहुंगा कि प्रेस इस प्रकार काम करें जिस से लोगों मैं एक अच्छा वातावरण बने । वह स्वतंत्रतापूर्वक भीर साहस के साथ भपना काम करें। एमजेंसी में भी मैं ने देखा कुछ प्रवादारे को, जैसे "नयी दुनिया" इन्दौर धौर "बीर प्रज़न' इन्होंने जिस समय एममर्जेंसी में न्यायपालिका मे म्याय के लिए जाने पर रोक लगी थी उस समय उस का विरोध किया था। मैं ने जेल से धान के बाद उन के साहस के लिए उन की पत्र लिखा था। मैं चाहता हुं अखबार प्रपने को बेच न दें, अपनी सबसकता कायम रखें क्यों कि नागरिक धाजादी के लिए वह ज्यादा से ज्यादा समाज के सष्टायक बन सकते हैं।

इसी तरह से जिस तरह ब्रिटेन में प्राकाशवाणी स्वतंत्र है, उसी तरह यहां भी स्वतंत्र होना चाहिए ताकि देश में एक मण्डा और स्वतंत्र वानावरण बन सके, लोग धपना एक नया जीवन बना सकें भीर हमारा देश समृद्ध हो, देश में एकता का बाताबरण बने । हमारे समाचारपत इस दिशा में काम करेंगे, ऐसी मैं भाषा करता हं।

MAVALANKAR PROF. P. G. (Gandhinagar): Madam Chairman, I warmly commend this Bill, because it revives the Press Council, and I hope it also now revitalises this Council, in view of the new improved Bill that we have got before the House today. I congratulate the Minister also because of the fact that the missing loophole in the Emergency Parliament's trio-the Prevention of Publication of Objectionable Matters Act. Feroze Gandhi Act (abolished) and the Press Council Act (abolished), ail these three were there, but two of them were repealed and so one of them was missinghe has now completed that trio and for that he deserves congratulations.

Madam Chairman, I was a Member of the Joint Select Committee and I have given a note of dissent. I do not want to elaborate on that again. Precisely because I was a member of the Committee, I do not think I should move amendments and that is why I have not moved any amendments. It would be wrong perhaps for me to say that now after the Select Committee Report, it has

come with betterment or improvement because that would be, in a way, self-praise. But I do say in all hamflity that the Select Commistee gave considerable thought in some quiet moments to the whole Bill in order to make the press not only more free, not only more strong, but, if I may say so, more responsible and more sensible and more sersible and the Government's responsibility vis-a-vis the press in general. I hope, therefore, the new Press Council, when it comes into being, will set that the code of conduct about which I am legitimately somewhat nervous, will try and see that the whole thing is built up brick by brick, gradually, and that there is not a priorial value of disciplinarian points, commandments, "Ten Commandments" as it were, "do this" or "don't do this"; "hat should not happen, because the pressmen themselves will do it.

Why is a press freedom vital? It is vital for democracy, vital for people, vital for Parliament. Unfortunately, the situation in India today is that, generally spraking, you might say that the freedom of the press situation is rather at a low level. In other words, this deterioration, if at all there is some, is in line with or is a part of the general overall deterioration in the whole country in terms of excellence in various fields. That is why we are suffering in that respect also. In 1954 when the Press Commission was set up for the first time, it recommended the constitution of a Press Council. I am sorry it came as late as 1966 and, again, because of the emergency aberration, it was removed. Therefore, it was an abortive experience, or abortive experiment of the Press Council. I hope and pray that the new Press Council, bearing in mind that experience and encounter, will improve and strengthen the media through the pressmen themselves so that the freedom of the press in general can be preserved.

In India, of course, we must remember that the Press Council is a statutory body unlike what happens in Britain. In the United States there is no Press Council, although I have learnt last week from a Seminar where some of the US pressmen were present, some of them eminent, that they want a Press Council in America as well. That only shows that the pressmen themselves are aware of their own responsibility in the matter of building up and strengthening the freedom of the press.

I would say only one more point and I have done. I am sure the Minister will agree with me when I say that if the Press Council has to function efficiently, then it has to act as an agency for generating what is called accountability of the

press to the community; by accountability of the press to the community I mean not only social accountability but accountability to the community, to the country and to the ideals of a free press; not accountability to the Government and certainly not accountability to the management. Because, if it is accountable to the management or the Government, it will go astray from the normal path of the freedom of the press. It has to be accountable itself, to its own conscience, laid down by the tenets of the free press. Therefore, I would say that this social accountability would imply self-control, self-randysis and self-criticism by the press, I am sure the Press Council can generate this accountability as well.

One final word and I have done. I am sure the Minister has seen and perhaps the House has seen a recent article in Sunday of 27th August by Shri Kewal Varma, given as a cover story, entitled "How Editors are Managed". Not only editors are managed, even columnists are managed and they are not properly treated, indeed, they are ill-treated by the proprietors on the one hand, and let the Minister not forget it, that on the other hand there are occasions when Government have badly treated the editors and columnists. I have my own experience when I was a columnist of several newspapers in Gujarat. At one point of time they did not like what I wrote, just because the Government at hat point of time did not like what I wrote. Therefore, I was asked very quietly to leave.

Take the very recent example of Editor Shri Chalapathi Rao of National Herald, who had to go precisely for the same reasons. We all know how a new Editor, who was complaining of being sacked from a Bombay paper has been brought to Delhi. But he forgets that he was brought to Delhi to fill up a post because a Delhi editor was sacked in the same way in which he was sacked in Bombay. These things have happened, but they should not happen.

I will conclude by saying that the responsibility of the press is far greater because it is very powerful. I only hope that the Press Council will act as a sacred temple and as an edifice of freedom which will go into these problems in their entirety with a sense of seriousness and responsibility, because it has to guard its own freedom, namely, the freedom of the press.

बी दुर्गावन्य (कांगड़ा): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रेस कौंसल बिल यहां पर पेड़ किया। इम्पर्येखी के दिनों में जो एक्सेक्ब हुई बीर जिस तरह है जास-जीडिया पर पाबच्यी लगाई गई सवा हमारे [भी दर्शायम्य ]

नोकरांत और हमारी बाबावी को बिस तरह से भागविक आरे हुनारी आस्वार्य कर गाउँ तरहे स जब पहुंची वी उसको हुर करने के लिए जनता सरकार ने कबम उठाए हैं। मैं लमझता हूं— माकनीय मंत्री जी को यह अय जाता है—कि उन्होंने ब्रेस की घाजादी को बहास करने के लिये धीर मास-मीडिया को स्वतंत्र करने के लिये जो कदम उठावे हैं, वे सराहतीय हैं।

मैं शीझता से कुछ बातें कहना बाहता हूं-क्लाब 5 (बाइटन 2) से बाहिर होता है--नामिनेशन आक वैद्यर्जन-वेद्यर्जन का नामिनेशन कितने प्राजा-वाना तरीके से होगा। इसी तरह से क्लाज 4 घाइटम । में 'भाषर हु सेन्सर एनी न्यूजपेपर धार न्यूज एजेन्सी"---इस में प्रेस कोन्सिल को अधिकार दिया गया है कि उन वैपर्जया न्यूज एजेन्सीज के खिलाफ, को गाइड लाइन्ज या कोड धाफ कम्डक्ट के खिलाफ जायेगी, उनको सेन्सर किया जा सकता है।

कल श्री बनातवासाजी ने कहा था-नलाज 16 में जो यह कहा नया है कि कॉन्ट ख की को लेवी कर सकती है-यह नहीं होना चाहिये। वानी कॉन्सिल को यह प्रधिकार नहीं होना चाहिये कि वह की को लेबी करे। मैं यह सर्ज करना चाहगा-बाबिर कौन्सिल को बलाने के लिए फण्डसें की जरूरत पड़ेनी, वह स्पया कहा से आयेगा? जनर कौन्सिल खूद अपने पैरों पर खड़ी हो-तो इन से श्रम्की और क्या बात हो सकती है। इस लिये मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो प्रावीजन किया गया है, वह डीक है। उन्होंने कहा कि सरकार को सारी जिम्मेदारी लेगी चाहिये, लेकिन प्रगुर वह क्लाज 17 को पढ़ते तो उने की मालूम हो जाता उस में साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार अपने खजाने से इस कौन्सिल को चलाने के लिये पैसे का प्रबन्ध करेगी भीर वह कीन्सिल की भी (लग सकेगी।

जहां तक प्रेस कौन्सिल विद्येयक की दूसरी प्राचीन्जज का ताल्लुक हैं- उन को देख कर वह मालूम होता है कि वाकई यह प्रेस की रेगुलेट करने के लिये एक बहुत प्रच्छा प्रयास किया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के विकार के लिये एक बात कहना चाहता हूं-छोटे पेपर्स को प्रेस कौन्सल में जो रिप्रेजन्टेकन मिलेगा, उस को दृष्टि में रखते हुए बहुत छोटे-छोटे रीजनल और लैंग्बेज [पैपर्समणेरूम की तरहसे खड़ेहो गये हैं⊸उन को यह प्रेस कीन्सल कैसे रेगुलेट कर सकेगी-यह धाप को देखना पढेगा।

वहां तक ऐडवर्टिजमेन्ट की बात हैं-इस के सिस्टम को भी रेगुलेट भीर कन्ट्रोल कियाजाना वाहिये। यैली-जर्मलिंग्म के करिये छीटे और वहे प्रखवारों में बढ़ा ब्लैक-मेलिंग चलता है। वे अपने व्हिन्ज पर खबरें शाया कर देते हैं, जिस से सोसायटी पर बस्टा धसर पड़ता है। इस तरफ भी भापको गौर करना चाहिये।

केरे कुछ निक्षों ने कहा कि बढ़े-बढ़े सक्तवारों की भाज जी भोकरतिय हैं-उस को विषयुक्त करने की जरूरत है, उसकी तरफ भहन करम उठाने की बारूरत है। मैं भी इस विचारधारा से सहनह बीर उम्मीद करता हूं प्रेस कौन्सिस इस वरक र्वकोगी भीर माननीय मंत्री भी जो भी मुनासिय कदन उठाना जरूरी होगा, उठावेंगे।

नैने बाजी लैंग्वेज और रीजनल पेपचंका विक किया। भेस कौन्सिल की एक भारी जिम्मेदारी यह भी होती कि इन वेपसे की कठिनाइयों की तरफ गीर करे। ये पेपसं जिस तरह से चलने चाहियें, उस तरह से भाव वल नहीं रहेहैं। जिस तरह से इस मास-मीडिया की गांवों में वेनिट्रेट करना चाहिने, उस तरह से हो नहीं पा रहा है। इस के लिये जो हमारी एजवटिजमेंट पालिसी है- प्रेस की न्सिल को उस के बारे में सोचना पडेवा।

मैं इतना ही कहता हुया-मंत्री जी को धन्यवाद वेता हं भीर कान्मेथुलेट करना चाहता हैं-उन्होंने एक बहत प्रच्छा बिल इस सदन में पेन किया है।

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Madam Chairman, I rise to support the Bill. But I have certain observations to

The press, particularly in our country, has got a very important and crucial role to play. The freedom of the press has all along been one of our cherished values of life. These cherished values of life have struck deep roots into our national life right from the days of national freedom movement in our country.

In order to understand what is the specific role of the press in our country today, I only want to mention that the press has got the role (1) as an inspirer of the masses, (2) as a teacher of the masses and (3) as the Inspector-General of the governmental activities and policies. To fulfil this very important and the crucial role of the press, the press requires freedom. In actual terms, the freedom of the press means, freedom from proprietorial interference, freedom from the governmental interference and freedom from interference from other conceivable sources. The freedom of the press has also been defined as "the freedom to hold opinions, to receive and to impart information through the printed word without any interference from any public authority".

The Press Commission itself feit that the freedom of the press must include editorial independence, objectivity of the news presentation and the fairness of comment. I concede that the freedom of the press which was completely ex-tinguished has been restored, by and large, and the proposed legislative measure, think, can go a long way to fulfil the promise for the restoration of democracy in our country. But the fight for the freedom of the press is a continuous process. It cannot be, I would say, a gift from the Government, a gift from any authority.

Further, the freedom of the press has wider connotations also. It is an integral and an indivisible part of the democratic rights and civil liberties of our people. Therefore, the fight for the freedom of the press is not only the fight for the press alone but it is also the fight for the pressryation of democratic rights and civil liberties of our people. It is true that the press fights for itself alone but equally, I now, it also fights for others. This is the lesson which we have learnt from the traumar of the Emergency. The experience that we have gained is that a monopoly press which gives rise to vested interest is a complete negation of the true values of the freedom of the press.

The money bags which control the press and have a strenglehold over the media are a constant threat to the freedom of the press in our country. Here is the most glaring example of the infirmity of the Bill and that is that the Bill is conspicuous in its lack of understanding or lack of concern for this growing threat to the freedom of the press, Since I have not much time at my disposal, I do not want to dilate on the subject. But I would only like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the common ownership and interlocking of the newspapers have grown in recent days.

According to the information available with me, the common ownership of newspapers account for 81 percent of the circulation of all metropolitan dailies published in our country.....

# भी एस० एच० नायक (नानदरवरि) । मेरा व्यवस्थाका प्रकृति । कोरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN: When the question of quorum is raised, the bell has to be rung. The bell is ringing...... Now, there is quorum. You can continue. Please finish in half a minute.

SHRI CHITTA BASU: This particular problem of growing concentration of ownership of the Press has been dealt with by the Press Commission itself and certain recommendations were made. I have come to learn that the Government has set up a committee to take certain steps. May I request the hon. Minister that in the course of his reply he should take the House into confidence as to what steps have so far been taken in the matter of transfer of management of the Press to public trusts, the diffusion of ownership, delinking of the Press from

business-houses, etc. He should tell the House.

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tespur): I congratulate our Minister for bringing forward this Bill which has been passed by the other House.

The Bill emphasises what we want our Press to be. Freedom is not required to be qualified by any amount of definition in the body of the Act. Freedom is freedom. There is no guarantee of freedom against the government or anybody and changes have been made in this Bill in order to guarantee freedom.

A Press Council will be constituted with 28 Members. There are 13 Pressumen, 6 from owners or managers of the newspapers, one news agency man, the Chairman and 3 wisemen and five politicians, i.e. the M.Ps. I think this constitutes a good team.....

MR. CHAIRMAN: MPs are also wiscmen.

SHRI PURNANARAYAN SINHA I They are. The other point is: This morning I read in one of the local newspape to that the session is being extended. I get Times of India, Hindustan Times and the Statesman. One reported that the session is being extended. I immediately inquired of our Minister if this is correct. He said, 'No, no.' Now If the reporter had only taken little pains to......

SHRI DINEN BHATTACHARYA: (Scrampore): This is the freedom of the Press.

SHRI PURNANARAYAN SINHA: Sir, I have been reporting from 1934. Even to-day I report for some of the papers including my own paper in my district. There are pitfalls but there is no such lack of responsibility. Mr. Mavalankar wants them to be accountable to the society. But I say not only to the society but to the nation and the world, to the human society at large they should be accountable. The Indian Press should be at least an ideal Press. Here the Reporter could have ascertained the fact from the Minister or his Secretariat whether the House is being extended.....

SHRI DINEN BHATTACHARYA: What is the harm? It is simply over-zealousness.

SHRI PURNANARAYAN SINHA: Publication of it even before the House decides is something wrong.

I have an allegation against the Press. After this Party has come to power, freedom of Press has been guaranteed

### [Shri Purnanarayan Sinha]

but the press here, particularly, in Delhi is behaving with some amount of irres-ponsibility which has resulted in some of the squabbles. Perhaps they want to divide us. That is the idea. Perhaps they have been instigated by some agents from somewhere to drive a wedge between us. I have cited one sample of wrong report that has appeared to-day. They do not try to verify, they publish guess work, their imagination, their own story. I do not expect the Indian Press story. I do not expect the Indian Frees to be like it is done now in some papers. In section 13, there are so many clauses. I do not find the main thing in any of the clauses 'virtue of the press is truth'. Truth is found nowhere.

MR CHAIRMAN : You should conclude now.

SHRI PURNANARAYAN SINHA 1 I have taken three minutes

MR. CHAIRMAN: I have got the clock here. You have taken four minutes.

SHRI PURMANARAYAN SINHA: The word truth is not found in any of the clauses that the press should be truthful.

The word 'truth' itself is nowhere there. The question of jute, textile, sugar industrialist monopolising the press is not foreign to my own way of thinking. I understand the sense of responsibility that is to encourage the growth of sense of responsibility. Sub-Clauses (d) (e) and (f) of Clause 13 should have been more elaborately defined. At the same time it is said the Council should not take cognisance of the complaint in the opinion of the Chiarman if it is felt there is not sufficient ground for holding an enquiry.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI PURNANARAYAN SINHA: Any responsible reader could find if the press is dabbling in untruth or that is trying to create some political confusion among the people or the party. In that case, the Press Council should take cognisance of it and an enquiry should be

With these recommendations I support the Bill. I hope the House will accept them. At the same time, I also want that due representation should be given to small newspapers in the Press Council so that their voice is heard and they could speak for the people for whom the the Government speaks a lot, that is, rural people.

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): Madam, so far as the provisious which pertain to the public

service and public interest are concerned, I welcome those provisions. But they are only casual provisions. However, I would like to plead with the hon Minister to kindly define broadly what he means by public service or what he means by public interest, so far as the freedom of the press is concerned,

So far as freedom is concerned can So har as recoom is concerned can there be freedom for the press or for any category of people in India when the material resources of this nation are concentrated in the hands of 20% people? There can hardly be any freedom. In case the hon. Minister is sincere for the feathers of the resources havely that their herefore. freedom of the press, break that chainby which the press is enslaved. There are two chains-one chain is by the capitalists and the other chain is by the Govern-ment. Therefore, break that chain. So long he has not broken that chain ; it is not possible also. Take the principle of nomination. Press Council is being constituted under the principle of nomination. Do you mean to say that the press Council, by such a nomination, will be able to preserve the freedom? It is impossible. Therefore, the principle of nomination was discarded long ago in the Constituent Assembly. Do not revive that principle. Accept the principle of direct election. I have suggested certain amendments but I shall not go into them in detail at this stage. But whatever be the conception of the Press Council, if it is by nomination, Parliament has an insignificant place in the Press Council, Therefore, instead, the principle should be like this. I would say that even among the Working Jour-nalists there should be representation on the Press Council. Their representation will never be on the Press Council. That seems to be the provision here.

Looking to the provision about the foreign aid or foreign money or assistorcign and or foreign money or assistance, all must come up before Parliament, even the economy of the press must come up before it. That can at least be done at this stage. The budgets or foreign assistance for which there is a provision, all the details of them must be a provision. placed before Parliament. Annually, there should be a report submitted through this Press Council so that there will be a full discussion.

Now, Madam, there is a provision with regard to rates. There is a provision for uniform rates for medium, small and big newspapers. Why do you want same rates. Therefore, I have proposed graded rates. For the small newspapers there should be low rates; for the medium newspapers there should be middle rates and for the life measurement there should and for the big newspapers there should be higher rates.

Lastly, I would like to ask what is the purpose for which this freedom is to be given. You define the purposes for which it is necessary. In that regard, I have given certain amendments. I will conclude by making certain suggestions. Let there be some choice for the public with regard to newspapers. Let there be diffusion of ownership. Let the economies of the Press be brought before the House and let there be relationship between the labour and the management. In case our nation has to go ahead, the Press has to play a big role which it has not so far played and, as such, vast masses of the people are steeped in illiteracy and are below the poverty line. As such, certain portion of blame goes to the Press as it has not played its proper part.

SHRI AJITSINH DABHI (Anand):
Madam Chairman, the Bill seeks to
establish the Press Council and thereby
to make the law regarding the preservation of freedom of the Press and to improve its standards. The law by itself is not sufficient. It has been shown by experience that many a law are 'flouted with human intelligence and ingenuity despite legialtive checks and strict legal provisions. What is more, the attitude of the government goes a long way in the growth of a free Press. I am sorry to say that I have no faith in the sincerety of the present Janata Party government regarding the proposed enactment. The attitude and conduct of the Janata Party government hears testimony to the fact that this government wants not a free press but a coloured press. This government wants to lend it a 'Bhagwa' colour of RSS and Jan Sangh to whom the hon'ble Minister for Information and Broadcasting belongs. Because, Madam Chairman, he has become a minister in the Janata party government by virtue of a quota of ministers given to Jan Sangh in the Janata Government. Immediately after the breaking up of the single news agency, namely the Samachar into four news agencies the Minister and his colleague in RSS, Shri Baleshwar Agarwl, tried to invest colour to 'Bhagwal Samachar Bharati—an independent progressive news agency—by merging it with the Hindustan Samachar controlled by the RSS. It is well known that the hon'ble Minister had brought pressure on Shri P. C. Gupta, Chairman of the PTI Board and got accommodation in the PTI building for the RSS controlled Hindustan Samachar. Not only that. Last year he had allotted Rs. 8 lakhs for each of the four news agencies but for the Hindustan Samachar controlled by the RSS, he gave Rs. 4 lakhs more. Therefore, Madam, I say that the establishment of the Press Council, by itself, does not ensure the independence of a free press. How can

you expect unadulterated news and information by a news agency which is controlled by religiously fanatic people who in fact distributed sweets when the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, was assassinated? Madam Chairman, it has been recommended by the first Press Commission that the Press should be de-linked from the big industrial houses. Not only that. The hon. Minister, Mr. Advani, while speaking before the conference on the Indian Press and Freedom, last year, stated that the Press should not be in the hands of unregulated forces of market. What he is doing today is exactly to the contrary. His Ministry recommended Rs. 60 lakhs to be paid to the Express Newspaper Group which is controlled by a big multimillionaire jute baron.....

MR. CHAIRMAN: You have taken more time than what is your share. Please conclude.

SHRI AJITSINH DABHI: While the newspapers like the Patriot and Mainstream were allowed to famish. I say that......

MR. CHAIRMAN: You are taking a long time. Kindly conclude.

SHRI AJITSINH DABHI : I am just concluding. I say that with the present Minister in charge of Informattion and Broadcasting, the freedom of the Press is far away. I am just concluding.....

MR. CHAIRMAN: No, no. I am calling the next speaker, Mr. A. K. Roy. Kindly resume your seat.

SHRI AJITSINH DABHI: I am concluding.

MR. CHAIRMAN: No, please. You can speak on the amendments which are standing in your name, Mr. A.K. Roy.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : Madam Chairman, this deserted House\*\*

MR. CHAIRMAN: Don't record. Kindly don't make such aircmark. It is against the rules. It will not go on record.

SHRI A. K. ROY: and complete boycott by the AIR of the proceedings of this Press Council Bill indicate the real worth of the Bill. It shows either that the people's representatives and all concerned are not interested in the real freedom of the press or there is no genuine element of freedom of the press in this Press Council Bill. There can be only two alternatives to this general apathy all round towards the so-called impressive Press Council Bill with which the Minister has come.

<sup>\*\*</sup>Not recorded.

[Shri A. K. Roy]

Madam Chairman, you will agree with me that our position has become very difficult, because, we are to choose between genuine slavery and a counter-feit freedom. We don't know what to do. We have seen 19 months of genuine slavery, unadulterated agmark slavery, and now we are having 17 months of counterfeit freedom; that is also regulated, processed, finished and presented. So, Madam Chairman, our position has become very difficult Previously in that controlled Press, so-called committed Press, we used to read from our jails, storics of Sanjay Gandhi. Today in the so-called uncontrolled and free press we are reading stories of Kanti Desai and nowadays of Suresh or some such chaps; we don't know tomorrow what we will read about and about whom. The voice of the teeming millions, the voice of the working people was choked before and it is being choked even today.

Now, we may see how the Press Council can preserve the freedom of the press. I wonder, how an odd 29 nominated Members can give us freedom. Out of the 29 nominated Members, even if that is a good body, I am afraid, it will be only good for nothing.

Only seven will be from the working journalists and live will be from the two hon. Houses. So, the entire concept of freedom of press is being mortgaged to the good wishes and wishful actions of some press barons or press owners.

Madam, while you are busy with pressing the bell, the Minister has come with an unimpressive Bill in this House. Freedom means freedom from what and freedom for what. Freedom has to be from intimidtion, freedom from compulsion, freedom from all sorts of terror and fear. I would like to ask the hon. Minister, can the Press Council Bill provide that freedom to the working journalists, freedom from their owners, freedom from the management? Now, freedom for what? Freedom for venting one's views and facts about the huge agony of the society. Can there be any guarantee for that?

Press in this poor country is not only a means of entertainment, it is an instrument for change, it is an instrument for giving direction to the society. But what is the press today? It is full of scandles; it has become unreadable now-a-days. I was just reading a few lines by Oscar Wilde with regard to the difference between literature and the press. He said that while the press is unreadable, literature is never read and that is the position now.

Sir, the fight for democracy is a long one. It requires not only democratic tongue, but it also requires democratic teeth and this Press Council Bill is devoid of any democratic teeth. It is simply like the previous one and as I told you, it is only the counterfeit freedom which the Janata Party is offering us instead of the unadulterated salvery from which we have emerged.

MR. CHAIRMAN: I wonder, who will give the Chairman freedom from speakers who exceed their time limit?

The Minister.

सुचना भीर प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण **प्राह्माणी)** : सभापति महोदया, मैं बहुत भाभारी हुं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इम बहुस में भाग लिया हैं। कैवल एक ग्रपवाद को छोडकर जोकि प्रभी प्रभी बोले हुए बक्ता से पहले बोले थे, बाकी सभी ने, जहाँ तक इस विधेयक का मम्बन्ध है, इसका स्वागत किया है । इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में टीका-टिप्पणी की गई है लेकिन वह भी मामान्य रूप से ही । अधिकांगतः जो भी आलाचनायें और टीका हुई है वह प्रेम के कार्यकलापों के बारे में हुई हैँ। प्रेंश की जीसामान्य समस्यायें हैं, जिनसे मैं भी परिचित है, उनके बारे में कई विचार व्यक्त किए गए हैं। मैं पहले पहल प्रेम परिषद् के बार में जो टीकाटिप्पणी हुई है उसके बारे में कुछ संक्षेप में कहंगा और उसके बाद जो सामान्य चर्ची की गई है प्रेस के बारे में उसपर जितना मझे लगेगा कि ब्राज की सारी चर्चा के सन्दर्भ मे उपयक्त है उसका उत्तर देने की कोशिश कर्रगा।

सबसे पहले हो जो चीज मावलंकर जी ने कही है, यह तीमरा विधेयक है जिसका लाने के बाद हम समझते हैं कि विधायी स्तर पर लेजिस्लेटिव लेवल पर, प्रेस की ब्राजादी के मम्बन्ध में इस सरकार ने जो वायदे किए थे वह पूरे हो जायेंगे। प्रेस की ब्राजादी ऐसी नहीं है जो केवन कानन द्वारा पूरी हो जाये।

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the

14.55 hrs.

इस प्रस्ताव से मैं महमत हूं ग्रीर जिन-जिन लोगों ने इस बात को कहा है—मैं समझता हूं कि उन्होंने उपयुक्त कहा है। मान लीजिये-हम पीनल कोड में कोई ग्रन्छी व्यवस्था कर रहे हैं--पीनल कोड में भ्रच्छी व्यवस्था करने कै बाद कोई यह कहे कि जब तक बेकारी खत्म नहीं होती, जब तक लोगों का चरित्र टीक नहीं होता, तब तक इस कानून का क्या मतलब है ? कहने के नाते तो यह बात ठीक है, लेकिन कानून की भ्रपनी एक सीमा रहती है भीर उस सीमा तक वह अपनी स्थित को सुधार सकता है। यह जो तीसरा विधेयक "प्रेस परिषद् विधेयक" लागा गया है, यह एक सीमित माला में प्रेस की म्राजादी को सुरक्षित करेगा, जिस सीमा तक कि कोई कानून सुरक्षित कर सकता है। दो कानून हम वे पहले पास किये वे--- शायद मंसद के पहले ही सत्र में "प्रीवेश्यान आफ पहिलक्षान आफ आक्जैक्सनेवल नैटसं एक्ट" को रिपील किया या, भीरोज गांधी एक्ट जो पिछली सरकार ने बत्स कर दिया या, उस को इस सरकार ने किर से रिवाइज किया।

मैरे मिक्र श्री घमृत कासर ने यह सवाल उठाया कि 17 महीने पहले या 18 महीने पहले ही इसे क्यों नहीं लाया गया ? सवाल वाजिब है— क्योंकि ये तीन विधेयक एक साथ थे, सरकार चाहती तो पहले ही सल में तीनों को ला सकती थीं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहंगा-जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है-पहले ही दिन से हमारी यह इच्छा रही है कि हमने इस सम्बन्ध में जितने वायदे किये हैं, उन को जितनी श्रीधता से पूर्ण कर सकते हैं-पूर्ण करें। लेकिन प्रेस काउन्सिल विधेयक के बारे में जब उस को फिर से रिवाइज करने की बात धाई, तो एक दम चर्चा गुरू हो गई-खास कर पत्रकारों में पाब जब प्रेम परिषद फिर से कायम की जा रही है तो उस को ज्यों-को-स्यों लाने की जरूरत नहीं है। उस पर विचार किया जाय, बहस की जाय, चर्ची की जाय । मैं यह भी बताना चाहता हं--प्रेस कौन्सिल का जहां तक सम्बन्ध है-इंग्लैंड में इस प्रकार की प्रेस कौन्सिल नहीं है । यहां स्टेच्टरी प्रेस कौन्मिल है, जब कि इंग्लैंड की प्रेस कौन्सिल एक बालंदी प्रेस कौन्सिल है । वहां पर कोई कानून नहीं है, जिस के भ्रन्तर्गत वहां की प्रेस कीन्सिल बनी है, वहां की प्रेस कौन्सिल स्वयं की बनी प्रेस कौन्सिल है।

इस सम्बन्ध में यहां पर चर्चा हुई---एक प्रमुख संस्था है---धाइ०एन०एस०---इन का नाम ब्राप ने सुना होगा---इन का मत रहा है कि हिन्दुस्तान में भी प्रेस कौन्सिल उसी प्रकार की बननी चाहिये, जैसी इंग्लैंड में है, स्टेचूटरी प्रेस कौन्सिल की जरूरत नहीं है। इस बर्चा पर विचार शुरू हुआ । मैं यह नहीं चाहता था कि मैं अपनी तरफ से प्रेस कौन्सिल ज्यों-कि-स्थों ले ग्राऊं। सरकार से इस पर विचार किया और निर्णय किया कि हम इस बात की घोषणा कर दें कि हम प्रेस कौन्सिल फिर से बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रेस कौन्सिल विधेयक लाने से पहले घण्छा होगा पत्रकारों से सलाह कर सी जाय, जितने मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा कर ली जाय। "Whether it should be a voluntary hody, or a statutory body."

# 15.00 hrs.

एक पहलू झौर भी है--जिस की शुरू में बहुत चर्चा होती बाई है। शायद प्रेस कमीशन ने जब पहली बार प्रेस परिषद् की लिफारिश की थी, तब से होती बाई है।

> "Should the Press Council have teeth, or should it have only the power to censure and admonish and express its opinions?"

एन॰ यू॰ जे॰ ने, बाँकन वार्नोलस्ट्स की फैडरेबन ने भी भपने विचार रखे थे। मुझे निस्चित कव से तो याद नहीं है, बेकिन एन॰यू॰ जे॰ के बारे में मुझे याद है—उन्होंने बड़े धावह से यह बात कही थी कि हम जो प्रेस परिवद् बनार्ये—

"We should provide it with teeth. We should not make it a body similar to what was there earlier."

मब में सारे मुद्दे ऐसे थे--जिन पर जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं करना चाहता था, परन्तु साख-साथ विलम्ब भी नहीं करना चाहता या । इस-लिये थोड़े दिनों के बाद मैंसे जितने पलकारों के प्रतिनिधि थे, उन को बुलाया, उनकी की, उन से चर्चा की भीर एक बाड-कांसेंसस-इमर्ज हुआ और वह यह हुआ कि हम को हिन्दूस्तान में एक स्टेचटरी बाडी चाहिये. बालंटी बाडी नहीं चाहिये, क्योंकि इस बात की पूरी सम्भावना है-धगर हिन्दस्तान में कोई वालंदी बाडी बनेगी तो उस पर बड़े-बड़े पत्न छाये रहेंगे, छोटे **धौर** मीडियम पत्नों का उसमें कोई स्थान नहीं रहेगा। स्टेचटरी बाडी होगी तो उस के जितने प्रधिकाद होंगे, उस की बात का जितना बज्जन होगा-वह वालंदी बाडी में नहीं हो सकता है। इसलिये प्रेस कौन्सिल के द्वारा हम जिस उद्देश्य की प्रति करना चाहते हैं, वह स्टेचूटरी बाडी के द्वारा ही हो सकता है। इसलिये भाप स्टेब्टरी संस्थाद्यों बनाइये । दो कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। ए० बाई ० एन ० ई० सी० ने मत व्यक्त कियाँ कि हम स्टैचटरी बाडी नहीं चाहते हैं, एक वालैंटरी बाडी के पक्ष में हैं। इस सब चर्चा के चलते चलते सरकार ने एक मत बना कर एक विधेयक यहां पर रखा । विधेयक लाने के बाद उस सदन ने तय किया कि इसकी एक प्रवर समिति एक ज्वायंट सिचैक्ट कमेटी के सुपूर्व कर दिया जाए । बजट सैशन में वह समिति बन गई थी । यह तय हुआ। था कि मानसून सैशन के पहले दिन रिपोर्ट दे दी जाए । मुझे याद है जब उस प्रवर समिति की पहली बैठक हुई तब मैंने समिति से निवेदन किया या कि यह मामसा कई दिनों से लटकता था रहा है, फिर से यह प्रवर समिति के पास चीज भाई है, बार बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ताही जा रहा है, इस बास्ते मैं निवेदन करूंगा कि जो संसद ने हुमें भादेश दिया है उस भादेश का पालन करते हुए इस सत के, बर्चा ऋतु के सत के पहले दिन ही जैसे हमें कहा गया है हमें रिपोर्ट दे देनी चाहिये फिर चाहे हमें इसके लिए कितनी भी बैठकें क्यों न करनी पड़ें। जितनी भी बैठकें हमें करनी हैं, एक महीने में कर लें। मुझे सन्तोष और खुशी है भीर मैं धन्यवाद भी देता हूं प्रवर समिति के सभी सदस्यों को जिन्होंने पूरा सहयोग दिया ग्रीर देखा कि किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन मांगना न पड़े भीर जिस दिन हम से कहा गया था उस दिन धा कर हमने प्रवर समिति का प्रतिवेदन **धापके** सामने रख दिया। इस बात की मुझे विशेष खुशी है। हमारा जो पहला विधेयक या जो संसद में इंट्रोड्यस किया था उस में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन

बी लाल इच्च बाहदानी हुए हैं चाहे बोड़े ही हुए हैं। लेकिन जितने भी हुए हैं सब सर्व सम्मति से हुए हैं। एक मत से हुए हैं। एक मुद्दे पर, एक प्रावधान पर मतभेद रहा है जिस के बारे में डाइसेंटिंग नोट भी है। उसका मैं उल्लेख करूंगा यह कोड धाफ कंडेक्ट का है। बाकी जितने संशोधन थे सब सर्वसम्मनि से हुए थे। सब की उनके साथ सहमति थी। परी सहमति यही थी कि यह जो बाडी है उसमें टीय नहीं देने चाहिये । बनातवाला साहब ने कहा या राय साहब ने कहा कि इससे क्या फायदा होगा. प्रेस परिषद कोई निर्णय देती है और उसको कोई मानेगा या नहीं मानेगा तो उसकी क्या व्यवस्था होगी इत्यादि । बाढी हम की ऐसी बनानी चाहिये जिस की बात में उसके कम्पोजिशन के कारण वजन हो । प्रगर प्रेस कार्जिमल कहती है कि सरकार ने गलत बात की है तो मैं समझता हं कि सरकार के वास्ते इन्कार करना आसान बात नहीं होगी, कम से कम कोई भी हैमोकेटिक सरकार उसमे इन्कार नहीं कर मकती है, उसकी बात उसको माननी पडेगी । घाप देखें कि हाउस के प्रिविलेज का बीच होता है तो केवल बीच करने वाले को भगर डमानिण भी कर देने हैं नो उसका कितना वजन होता है, इसको हम जानते हैं। इस प्रकार की संस्था के द्वारा एडमानिशन होना या किसी प्रकारसे सैंकर होना बहुत बड़ी चीज होती है, मामली बात नहीं होती है।

ग्रलबला पिफले विधेयक में एक बात धी कि उस में इस बात का उल्लेख नहीं था कि प्रेस परिवद सरकार के काम पर भी टीका कर सकती है। कभी भी सरकार के खिलाफ कोई मामला जाता था तो एतराज उठाया जाता था । मुझे दिब्यून के सम्पादक का मामला याद है । सम्पादक ने प्रेस कांउमिल में हरियाणा सरकार के खिलाफ एक महा दायर किया था । पटना के सर्चलाइट ग्रह्मबार ने बिष्ठार सरकार के खिलाफ एक मुद्दा दायर किया था। दोनों मामलों में सरकारी बकीलों की तरफ से प्रिलिमनरी भावजैन्छन हुमा था कि यह प्रेस काउंसिल बिल जो है उस में कहीं नहीं लिखा है कि सरकार की बात पर भी टीका वह कर सकता है। एडवोकेट जनरल ने यह धार्गमेंट दिया था कि सरकार की बात पर प्रेस काउसिल को टीका करने का कोई प्रधिकार नहीं है। प्रेस परिषद ने उनकी इस बात को नहीं माना, पिछली प्रेस परिवद ने । उसने कहा कि जो रेजीडमरी पावर्ज इत्यादि हैं उनके प्रधीन यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम को यह भी भधिकार है कि प्रेस की भाजादी पर अगर सरकार कोई आक्रमण करती है, कोई हस्तक्षेप उसके द्वारा होता है तो उस पर भी हम टीका कर सकते हैं। उसके भाधार पर उन्होंने की भी। सरकार को लगा कि इस बारे में कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये धीर इसके बारे में प्रावधान कर देना चाहिये कि प्रेस परिषद की अधिकार होगा कि सरकार अगर प्रेस की आजादी में हस्तक्षेप करे तो उसकी बात पर भी टीका करे भीर उसका प्रावधान कर दिया गया है। भौर यह प्रावधान करने से स्थिति भ्रष्टी बनी ।

ऐसा में नहीं मानता हूं कि प्रेस परिवद् वन नई तो प्रेस की बाजादी की गाएल्टी हो गई । मैं तो कई बार कह सकता हं कि एक खतरा है सरकार का, इसरा चतरा है मालिकों का या स्वामित्व के रूप का भीर तीमरा खतरा है लैक धाफ इंटेगरिटी भीन दि पार्ट भाफ जर्नेलिस्टम । तीसरा खतरा सबसे बड़ा है और इसका कोई भी इंस्टीटयशनल सब्स्टीटयुट नहीं हो सकता है । और उसके प्राप्तार पर तो प्रेस की भाजादी का सारा भवन खड़ा रहेगा मुख्य रूप से । यह तो हम केवल सहारा वे रहे हैं, जितना दे सकें अक्छा होना।

सब सदस्यों ने कहा कि जब तक भीनरिक्रप पैटर्न नहीं बदलता. जब तक स्वामित्व का ग्राज का रूप नहीं परिवर्तित होता प्रेस की धाजादी धार्राक्षत नहीं हो सकती । मैं इस बान से सहमत हूं । भलेबलो यह बात जरूर कहुंगा कि पिछले मालों में प्रेस के घौनरिशप की बात एक स्लोगन के रूप में की गई है हमेशा । डिप्यंजन धीर डीलिकिंग इन शब्दों का भी गलीशे के रूप में प्रयोग किया गया है इस नाते कि सरकार की तरफ से खतरा है सबसे बड़ा, मैं उसको सबसे बड़ा मानता है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी मोनीपली हो सकती है, धौर सरकार से जिनना खनरा है उसकी वुलना में मालिकों का खतरा इतना बढ़ा नहीं है । उस खतरे से लोगों का ध्यान झोझल करने के लिये पिछली सरकार ने बार-बार डीलिकिंग और डिपयजन की बाद कही । जब कि किया कुछ नहीं, एक कदम भी भागे नहीं बढी । मैं मानता हं कि डिप्यजन बहुत बड़ा मामला है । हीलिकिंग ण्यादा प्रैक्टिंकल हैं । लेकिन उस दिशा में कुछ को करना चाहिये या । मेकिन बह नहीं किया। यह ठीक है, लेकिन उसकी चर्चा रोज करते थे। जो भी बोसला या सरकार की छोर से वह उसकी चर्चा करता या और हमेशा यह दिखाने की कीशिश करता था कि सगर देश के सन्दर प्रेस की प्राचादी सीमित है तो उसका कारण मालिक हैं। धपनी बात कथी नहीं करते थे । यह सरकार जब से ब्रायी है, जितने कहम उठाये हैं वह कहम प्रपती कम करने € **1** One by one we have been shedding the powers of the government. मुक से ले कर झाज तक, मैं धपने मंत्रालय का उल्लेख कर सकता हुं कि जितने कानून हम लाये हैं उन कानुनों के पास होने के बाद<sup>ें</sup> मेरी ताकत कुछ कम हुई है। जिस समय में मंत्रालय की कुर्सी पर बैठा था तो सगता था कितनी ताकत है माहे जिसको जो कुछ कर दो । ग्रीर ग्राज स्थिति यह है कि मैं अपने बचनों से बंधा हूं जिसके कारण गाज रेडियो पर कई बीजें भाती हैं जी मुझे पसन्य नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता है। मैं नहीं क ता है। चुंकि हमारी बहन ने रेडियो की चर्चा का हमारे झाने के बाद हमने शुरू किया gleaning from the Press.

ऐडिटोरियल प्रति दिन देना चाही दो । प्राज ऐडीटारियल फोम दी प्रेस सगर आप देखेंगे तो कहेंगे वह फॉलग पार्टी के खिलाफ हैं, भीर वह वेपर क्लिंग पार्टी के खिलाफ हैं। धंच्छी चीच है,
मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं बता रहा हूं कि
सारी चीचें ऐसी हैं जिनके कारण सरकार ने प्रपत्ती
स्वित स्वेच्छा से कम को है क्योंकि हम मानते हैं
कि जब तक वह सकित जो सरकार के हाथ में
केन्द्रित है वह जनता तक नहीं जाती, बैस की
साजाबी बहां नहीं रहती, तब तक लोकतंत्र नहीं
हो सकता है। ईमानदारी से हम उसमें विश्वास
करते हैं।

हमारे कई सदस्यों ने चाहे जितनी बार चिसी पिटी बात कही थी कि हमने बालेश्वर प्रश्नवाल भौर "हिन्दुस्तान समाचार" को पी०टी०माई० में कोई स्थान दिलाया । मुझे ताज्युव होता है, क्योंकि में कई बार स्वयं इस बात का खंडन कर चुका हूं भौर पी०टी०भाई० वाले भी खंडन कर चुके हैं, भौर सब से बड़ी बात यह है कि पी०टी० माई० ने कभी उनको कमरा दिया ही नहीं। फैक्ट ही नहीं कि कोई कमरा दिया। मुझे जब पता चला ऐसी कोई बात चल रही है कि पी० टी० माई० वाले शायद "हिन्द्स्तान समाचार" को कोई कमरा देने जा रहे हैं, तो पी० टी० प्राई० के सम्यादक मुझे मिले ये मैंने उनको कहा कि भाई क्या कर रहे हो ? अगर ब्राप दे रहे हो, ब्रापके पास कोई जगह है देने की तो "समाचार भारती" भीर "हिन्दस्तान समाचार" दोनों को मकान की जरूरत है, देना है ता दोनों को दे दो । मैं तो प्रपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि वक्स भीर हाउसिंग मिनिस्ट्री उनको दे दे । लेकिन अगर उनको वक्स हाउसिंग मिनिस्ट्री नहीं दे सकती है भीर धापके पास एबेलेबल स्पेस है, देना है तो दोनों को दें, ऐसा न ही कि एक की दें ब्रीर उसके कारण हमारे ऊपर ग्रासोचना हो । स्थित दूसरी है, उसके बाद भी क्योंकि दूसरा कुछ नहीं मिलता तो वह पुरामी बात घोहराते जार्येंगे । (अवस्थान) उसी प्रकार से मुझे बाद है एक माननीय सदस्य ने सायद अप्रवन्त सिंह का भी उल्लेख किया।

SHRI AJITSINH DABHI (ANAND): The Employees of the P.T.I. had passed a resolution unanimously that accommodation to Hindustan Samachar would endanger the independence of the P.T.I.

SHRI L. K. ADVANI: That I have said officially and I sm giving the full facts of it. It did not actually happen, but the moment I came to know that this is the possibility which the PTI people are thinking about, I told them that if you have space and accommodation to provide, give it to both. So far as I am concerned I requested Works and Housing Ministry to give accommodation to both, which the Minister of Works and Housing did give to them. So, that question did not come up at all. But that old bogey of it keeps on being repeated.

क्योंकि मैं यह मानता हूं, कभी-कभी मजबूरी भी समझ सकता हूं विपक्ष की, बास तौर बद इस कोमे में बैठे हुए लोगों की कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ में ताकत झाये तो वह ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे। यह झसंभव बात है।

They perhaps find it impossible to contemplate that a Government or a person who wields such power would be willing voluntarily to shed it. But this is exactly what is being done.

स्वेच्छा से सारी बातें की जा रही हैं। बार-बार लोग हमकी कहते हैं कि घाटोनामी करेंगे धाप, घाटोनामी होगी नहीं। कौन गवर्नमैंट छोड़तीं है ? मैं मानता हूं कि घादान नहीं है, मन में लगता है कि कोहे के लिये छोड़ देंगे, इतने घिषकार है, हम ठीक कर सकते हैं। घगर छोड़ देंगे तो बायद खराब हो जायेगा, विगड़ जायेगा। लेकिन डैमोकेसी का जो स्ट है वह है विश्वास, जनता और प्रेस पर विश्वास 1

मेरे एक मिल्र ने कहा कि उनकी झाजादी इतनी मिली है कि इरिस्पौसिब्लिटो से लोग लिखने लगे हैं अखबार वाले । मैं बड़ी विनम्प्रता से अपने साथी से कहंगा कि

Irresponsibility is not a monopoly of the politician.

बाखिर इरिस्पौंसिब्लिटी सब के लिये दिखाई वेती है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां दिखाई न वेती हो । प्रेस में भी विखाई वेती है । लेकिन चूंकि कोई प्रेस का सैक्बन या कोई घखबार इरिस्पौं-सिब्लिटी से व्यवहार करता है तो सहज रूप से हमारे कोई साथी पोलिटिकल पार्टी में इस तरफ मा उस तरफ कर वें

Press has become irresponsible.

स्रौर इसीलिये उस पर बन्धन होना चाहिये, स्रामात होना चाहिये, मैं इस बात को मानने के लिये तेयार नहीं हूं। (व्यवसान) देखिये, कुछ होना चाहिये, इसके लिये ही व्यवस्था को जा रही है। यह जो प्रेस झायोग है, यह झाटोनोमाइजेशन के लिये एक संस्थागत व्यवस्था है।

It is an institutionalised arrangement for self-discipline.

इसमें वहां के लोग बैठेंगे और वह कहेंगे कि यह जो है, यह पीत पत्नकारिता है, लेकिन हम बैठ कर यह कहें, जो बीज हमको पसन्द नहीं बाये कि यह यैसो जनंतिज्य है, यह बात ठीक नहीं। यह स्राधकार हम प्रपने पास रखना नहीं बाहते । इसिलये कई लोगों ने विद्येयक पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन 2, 3 सदस्यों से मैंने मुना कि नामिनेटेड बाडी है,

This is going to be nominated body!
This is not going to be a nominated body.
That Government has nothing to do with
it absolutely. So far as the persennel
of the Press Council are concerned, right

# [Shri L. K, Advani]

from the Chairman who is to be nominated by a minating panel comprising of the Lok Sibia boraker, the Rajya Sabha Chair-min and one person elected from among then selves by the members of the Press Council. So, this is the nominating nominating panel who is going to nominate the Chairmin. So fir at the members of the Council are concerned उसके लिये व्यवस्था की गई है चौर वह प्रावधान ऐसा है कि जिनमें संस्थाएं नाम देंगी, हम नाम नहीं देंगे। ए० प्राई० एन० ई० सी० नाम देगी, **बाई•**एन०एमे० नाम देगा, विका जनेलिस्ट फैड-रेशव नाम देगी, एन०पू०सी० नाम देगी। जो भी संस्थाएं रूप्त में भारती हैं, क्योंकि रूप्त फोम होंगे, बह नाम देंगी भीर उसमें भी हम यह न्यबस्था कर रहे हैं कि इल्स में सिस्टम सलैश्यन का हो बह भाटोमैटिक हो, किसी को डिस्कियन न हो । Not even the Chairman is going to have discretion in picking and choosing.

बहु भी नहीं कह सकता है कि इसमें यह व्यक्ति होना चाहिए, या वर व्यक्ति होना चाहिये। हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि मुने नहीं मगता है कि कियी को इसे एक नामिनेटिड पैनल कहने का चिकार है। कम से कम सरकार बीच में नहीं स्नाती है।

बायर श्री बननवाला ने की या लेवी लयाने का बिरोध किया है। मैं समझता हूं कि यह शावबान बहुत सीच-निवार कर किया गया है। कई मानीय सदस्यों ने यह शी मन कथन किया है कि मनर तारा पैसा सरकार से शायेगा, तो सरकार किसी न किसी दिन—घाज नहीं तो कल—उतको नियंत्रित करेगी, इस लिए पूरा पैसा मरकार से नहीं भाना वाहिए। हम चाहने हैं कि प्रेस कौंसिल को वितीय क्यवस्था, उसके फिनांबल एरें अर्थेट्स इस प्रकार के हीं कि सरकार को उसे कम से कम पैना पड़े। हम ने सरकार की नरफ से ब्राट-इन-एड देने की व्यवस्था की है, क्योंकि है से स्वीत को साम के लिए इस की जकरत है।

लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहना है कि सरकार का इरादा है कि जिस पत्र की सर्कृतेवन पांच हुजार से कम है, उसका की सर्कृतेवन पांच हुजार से कम है, उसका की बिल्कुल न वेनी पढ़े—छोटे पत्र पर इस का बोझ बिल्कुल न पड़े, और जो बड़े पत्र हैं, उस पर भी बेडिड बोझ पड़े। सर्कृतेवन नैसे जैसे पांच हुजार है कपर जायेगी, उस समावार-पत्नों को प्रधिक वेता पढ़ेगा। हैसे, कुल मिला कर प्रेस कौंसिल का बबट, या इस की पांवयकतायें, इसनी प्रधिक हैं नहीं। हिन्दुस्तान में बहुत पत्र हैं। इस लिए खबर सभी से बोड़ा-बोड़ा हिस्सा प्रायोग, तो प्रेस परिवर्ष के प्रायोगता का भाव पैदा होगा, पांटिसिस्तन का संस पैदा होगा, जो प्रेस परिवर्ष की महसा बीर असके प्रधाव को बहुत बड़ायेगी।

घषिकांश माननीय सबस्यों ने घोनरशिव पैटनं की बात कही है। यह सरकार उसके बारे में जानक है, घौर यही कारण है कि इस सरकार ने घमी निर्णय किया कि सैकंड प्रैस कमीकन बनाया जाये—उहना प्रैस कमीकन बाज से पान से पान के पान की पहले बना या—और उसकी टम्में घाफ रेकरेंस में सब से प्रमुख प्रावधान यह है—

"It will examine the ownership pattern and the financial structure of organs of the press with a view to ensuring editorial independence and professional integrity and readers' right to objective news and views and comments freely expressed."

This is one of the primary objectives why we have set up the second Press Commission.

इस कमीशन के घटपक्ष धीर उन के साबी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं घपेशा करता हूं कि वे साल घर में हमको घगनी रिपोर्ट दे देंगे, ग्रीर जो दूसरा खतरा हम देखते हैं, उस खतरे के बारे में भी एक निष्वत करम उठा कर यह सरकार टीक प्रकार की व्यवस्था कर सकेगी

बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जिन का उल्लेख मैं धाराघों घीर संशोधनों पर चर्चा के समय करूंगा।

एक माननीय सदस्य ने किसी ग्रखबार--संडे-में से क्वोट करते हुए विशेष रूप से प्रधान मंत्री का नाम ले कर कहा कि प्रधान मंत्री जी के कहने पर **इलस्ट्रेटिड बीकली** के सम्पादक को वहां से हटाया गया । मैं इसका जोरदार खंडन करना चाहुना । मैंने प्रधान मंत्री जी से भी बात की है, भीर एक बार मुझे स्वयं इलस्ट्रेडिड बीकली के सम्पादक से भी बात करने का मौका मिला। उसके बाद में इसका साफ-साफ खंडन कर रहा हं कि जहां तक सरकार का सवाल है, उसने गुरू से ले कर ग्राज तक, कहीं पर भी, इस प्रकार की बात नहीं की है, न डायरेक्ट और न इनडायरेक्ट प्रभाव डाला है। सरकार के हाथ में प्रभाव डालने का जो सब से बड़ा साधन रहा है, वह रहा है विज्ञापन नीति, एडवरटाइजमेंट पालिसी । भीर वह एडवर टाइजमेंट पालिसी पिछले नवम्बर महीने से जिस प्रकार से बनी है, जिन गाइडलाइन्ज के ग्राधार पर बनी है, उससे भाज मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे पास लोग रोज पाते है—बास तौर से इधर से माते हैं—और कहते हैं कि इस अखबार को पिछली सरकार से कोई एडवरटाइजर्नेट नहीं मिलता था, क्योंकि हम उस समय सरकार के खिलाफ थे, ग्रीर ग्राज भी हमारे ग्रखवार को कुछ नहीं मिलता है, या बहुत कम मिलता है। मैं उन को कहता हूं कि बाप को जितना एडवरटाइजमेंट मिल रहा है, क्या बापसे कम सर्वेश्वन वाले कियी प्रवार को उससे ज्यादा

मिलता है । वै नहीं बता सकते । ग्रगर वे बता वें, तो मैं उसको तुरन्त रैक्टिफाई करूंगा।

कुछ लोगों ने कहा है कि घगर सर्कलेशन के घाघार पर विकापन विये जायेंगे, तो कैसे काम चलेगा । मैं नहीं मानता हूं कि इसके घलावा कोई दूसरी कसौटी हो सकती है । यह सब से प्रमुख फ्रीर प्रच्छी कसौटी है।

भी क्रोम प्रकाश स्थागी: तो छोटे पेपर्ज की मदद कैसे होगी ?

श्री लाल कुरून झाडवाणी : श्रगर इसी प्रकार मदद देनी हो, तो खिस पत्र का सर्कुलेशन कुछ भी न हो, उसको सब से ज्यादा एडवरटाइजर्मेट मिलेगा । मेरी बात समक्रिए ।

PROF. P. G. MAVALANKAR: Is it the contention of the Minister that circulation is the only and the most effective criterian? If that is so, I want to remind him of what I read years ago when a British journalist said at that time that "Newspapers with large circulation are like fashionable ladies who are more concerned with their figures than their morals"?

श्रो लाल कृष्ण धाडवाणी: मावलंकर जी ने मुझे ठीक किया है एक प्रकार से क्योंकि मैं मानता हूं कि यह एक प्रमुख कसीटी है।

It is one of the ceiteria and it cannot be the only one. But at the same time, all the other things being equal, the difference only being whether this paper supports my Government or not, I want to make this clear because all other things equal mean that both are political papers, the fact that this paper who supports me and the other paper who does not support me will have nothing to do with the advertisement. Political views and political opposition is totally irrelevant so far as this Governments' advertisement policy is concerned.

SHRI KANWAR LAL GUPTA Delhi Sadar): What about yellow journalism? Will you allow such sensational news in this country?

श्री लाल कुष्ण बावणाणी: में इस कं बारे में यह कह सकता हूं कि मेल परिषद् के गठन के बाद मेंस परिषद् के जो निजय होंगे एबाउट येलो जनालियम, वह मेरे लिए बहत सहायक होंगे क्योंकि वह ऐक्वटिइजमेंट पालिसी को भी प्रधावित कर सकते हैं क्योंकि इस में यह जरूर है कि घगर कोई बल्पर या बाबसीन पेपर है तो उस को ऐक्वटिइजमेंट नहीं दिया जायेगा। इस में क्वांटिटी का सबाल नहीं है। हमारी ऐक्वटिइजमेंट पालिसी में यह बात तो है कि खगर कोई इस प्रकार के पत हैं तो उन को ऐक्वटिइजमेंट नहीं दिए जाएंगे। बहुत से ऐसे पत्न होते हैं जो झान दि फेस झाफ इट पोलिटिकल लगते हैं But they are indulging in all kinds of obscenity and vulgarity. तो उन पत्नों के बारे में भी में अपेक्षा करूंगा कि प्रेस परिषद् के निर्णय, उन के दृष्टिकोण मेरे लिए सहायक हांगे इस माम ने में भी।

कोड भाफ कांडक्ट के बारे में श्री मावलकर जी ने कहा । उन्होंने स्वयं भी इस बात को एप्रिशिएट किया कि कोड ग्राफ कांडक्ट ग्रगर बैठ कर के बनाया जाये एक दो तीन चार पांच छः कर के तो उस से संभावना है कि उस को कोड प्राफ डिसिप्लिन कर के यज किया जाये. खास कर के क्योंकि एमर्जेसी के दौरान कोड आप कांडक्ट की बात इस सन्दर्भ में की गई कि सरकार की झोर से एक कोड भाफ कांडक्ट बनाया जाये या ए ध्राइ एन ई एस से बनवा कर उस को लेजिस्लेट किया जाए । इसलिए मैं ऐसा मानता हैं कि पत्नकारों में उस कोड ग्राफ कांडक्ट से ही भेरुचि पैदा हो गई। मैं जानता हूं, मैं इस बात से परिचित हूं और इसीलिए मैं इस बात को नाफ करना चोहंगा कि जब इस में बिल्ड अप कोड ग्राफ कांडक्ट की बात कही गई तो वह बिल्ड अप जानवृक्ष कर कहा गया है। ले डाउन नहीं है, फारमुलेट नहीं है ग्रीर पिछली प्रेस परिषद् ने भी इसँबात को स्पष्ट किया है कि हम जो एंडजडिकेशन करेंगे, हम जो केसे निर्णय करेंगे, उनँका जो केस ला बनेगा वह स्वयं में एक कोड प्राफ कांडक्ट बनेगा । उसी की कोड बाफ कांडक्ट माना जायेगा । इस के आगे कछ नहीं।

श्री वेंकटरमन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहीं । उन्होंने मेरा ध्यान इस बात की घोर दिलाया कि पिण्ले प्रेस परिषद् ऐक्ट घौर इस प्रेस परिषद् थिंध्यक के प्रावधान से परिवर्नन है। जो क्लाज 13 का सब क्लाज (ब्राइ) है उस में यह है:

> "To concern itself with developments such as concentration of or other aspects of ownership of newspapers and news agencies which may affect the independence of the press."

में यह कहना चाहूंगा कि यह जानवृक्ष कर हम ने लिखा है। पिछली बार की प्रेस परिषद् म, चाहे उस में मोनोपली या धौर जितनी मच्छी मच्छी बातें कही गई हों, लेकिन मैंने पृछा कि उन्होंने किया क्या उस बारे में भौर कर सकने की कुछ गुँजाइण भी है क्या ? प्रेस परिषद् का कास क्या है ? प्रेस परिषद् का काम है इंडिपेंडेंस

# [श्री लाल कृष्ण ग्राहवाणी]

भाफ दि प्रेस से अपने को कंसर्न करना । प्रेस श्वायोग का काम घलन है जिस का हम ने उस्लेख किया कि प्रेस कमीशन को तो इन बेप्च जा कर के स्रोनरशिप पैटर्न के बारे में, मोनोपसीज के बारे में, कसेंटेशन प्राफ फोनरशिप के बारे में अपनी रिपोर्ट वेनी पड़ेगी और हम को उस के बाधार पर बायबल घास्टरनेटिव घाप के सामने रखना पढ़ेगा। लेकिन So far as Press Council is concerned, that Press Council is mainly concerned with the freedom of the press. और फीडम प्राफ दि प्रेस जिस माला में कंसेंट्रेशन भाफ भोनरिमप द्वारा कुठित होता है, जहां लगता 🕏 कि ये चार पेपर इकट्ठे हो गए, इसीलिए वह कम हो गया तो it has to concern itself with that Concern itself does mean, as you say, interest itself in. And when it has to take interest in this particular matter, it has to express itself. हमने यह बात जानवृक्ष कर इसलिए की है कि हम चाहते हैं कि यह प्रेस परिषद बास्तव में एक इफेक्टिव बाडी बने भीर जो काम उसके सुपूर्व किया गया है उसको वह करे। उसमें मोनोपली की भी बात थी। मैं समझता हूं मोनोपली की जहां तक बात है It falls more within the purview of the MRTP. यह उनके प्रावधान में आये, उनके क्षेत्र में आये। जिस मात्रा में फीडम ग्राफ प्रेस कुंठित होती है उस मात्रा में उनके प्रावधान में माये।

SHRI KANWAR LAI. GUPTA: MRTP is absolutely different. Monopoly is in the sense that a chain of papers is So, the owned by certain businessmen. freedom of the editor comes. He becomes the boss. Then again, there is the question of the monopoly of the editor, and then the question of the freedom of the correspondent comes in. You have been watching that a particular editor during the emergency was behaving in a particular way. The same editor now is behaving in a different way. Prior to the emergency he behaving in another way. freedom of the press means the freedom of the correspondent, the editorial staff and everybody. so, what are you doing to do about it?

भी लाल कुष्ण झाडवाजी: इस मात्रा में में सहमत हूं कि फीडम भाफ दि प्रेस की जब हम चर्चा करते हैं। It means editorial freedom as well as the climate to maintain the professional integrity of those who work in the press. As I have said, I mean the freedom of the press as opposed to the freedom of the purse. I am not talking in terms of the owners of the press.

तो इस से मैं सहमत हूं लेकिन मैं चाहता का कि जितने सारे प्रावधान होते हैं, श्राम्जेक्ट्स में बास कर जो होना They should be practicable. They should not seem just airy words.

केवल मध्य प्राडंबर हो जिसमें करना कुछ न पड़े, ऐसी स्थित नहीं होनी चाहिए । प्रेस परिचर् के सामने जो काम रखा जाये वह उनको लगे कि प्रैक्टिकेवल है।

श्री स्रोम प्रकाश स्थागी: प्रगर इन बातों के प्रनुसार प्रेम प्राचरण न करे तो उसके लिए कहीं भी विधान में नहीं है कि प्रेम के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जायेगा धौर क्या सजा दी जायेगी।

भी लाल कृष्ण भाववाणी : इसमें सजा देने का कोई कारण नहीं है । दूनिया भर में प्रेस परिषद की कल्पना इस प्रकार की है कि सजा नहीं दी जायेगी। प्रगर सजा होगी तो कानन के अन्तर्गत होगी । अगर कान्न का उल्लंघन किया जायेगा तो सजा होगी। सगर किसी प्रखबार ने एक बान लिख दी, इर्रेस्पांसिबल बान लिख दी I would say it is carelessness, not being particular about being accurate about one's report. में जानता हूं खासकर विदेशों में जो प्रमुख ग्रखबार है वे बहुत सतर्क रहते हैं चेक के बाद काउटरचेक हैं ग्रीर जब तक पूरा विश्वास नहीं हो जाता तब तक खबर नहीं छापेगे । प्रगर हम में से किसी ने बाटरगेट के सारे काण्ड को फालो किया होगा भीर जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है उसकी पढ़ा होगा तो देखा होगा, यथपि जो बात कह रहे थे वह गही थी लेकिन कहीं बारीकी मैं दोष बा गया तो फिर उनको कितना पश्चानाप होगा, एडिटर को कितनी परेशानी होती थी और कितना एम्बेरसमेंट होता था । मोटे तीर पर जो बात कह रहे हैं वह सही है लेकिन व्यवहार में, डिटेल्न में हमारी यह बात गलत क्यों निकली--इस बात की उन्हें चिन्ता होती थी । मैं समझता हं हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पक्षकार हैं जो बहुत सावधानी रखते हैं भीर इसीलिए उनका नाम है। प्रगर एक पत्रकार ने लिखा है, उसका साइन्ड प्रार्टिकल है तो लोग कहेंगे कि फलाने ने लिखा है इसमें जरूर कुछ होगा । बिना तैयारी के यह ब्रार्टिकल नहीं लिखा गया होगा। यह केडिबिलिटी तब डेक्लप होती है जबकि पत्रकार स्वयं सतर्कहो, जागरूक हो भीर टथ के बारे में, सञ्चाई भीर इमानदारी के बारे में वह सावधान रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेस परिषद् विश्वेषक पारित होने के बाद ऐसी व्यवस्था हो जायेगी कि एक तरफ तो घात्मानुसासन का प्रतिबंध मिल जायेगा धौर दूसरी तरफ प्रेस की बाजादी पर, जहां से भी भाकमण होगा, जहां से भी हस्तक्षेप होगा, वह बाहे सरकार की और से हो या मालिकों की भोर से हो या किसी भी तरफ से हो, एडवर्टाइजर्स की तरफ से हो उस पर रोक लगेगी। इस उम्मीद के साथ में इस विधेयक को सबन के समक्ष प्रस्तुत करता है।

SHRIB. K. NAIR: Clause 14 of the Bill provides for punishment—warning, adminishing, censuring and all that. All these actions are aimed at journalists, editors and other parties. Do you conceive of any action on the part of the owner of the newspaper which may call for censure or any other punishment for the offence committed by him, who is a very prominent constituent of the Press Council? Does the owner come under this Act for punishment for any of his actions?

SHRI L. K. ADVANI: Why not? He is not free from...

SHRI B. K. NAIR: He is not free? He is above all these? There is no censuring, no admonition or no other punishment for him? Does he not commit any offence?

SHRI L. K. ADVANI: If you see clause 14, it is stated:

"Where on receipt of a complaint made to it or otherwise, the Council has reason to believe that a newspaper or a news agency..."

It does not mean the editor, it may mean the manager. it may mean the owner. It depends upon the Council's assessment or the appraisal of the case as to who is at fault and then he will be censured.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will you take the representatives of the readers on the Press Council? This is very important because you have to educate the people.

SHRIL, K. ADVANI: Mr. Chairman, this point was made by Mr. Kanwar Lai Gupta at the outset. I may point out that in India we do not have associations of readers as such. But the lay members of this Council which include all the five Members of Parliament, the representatives of the various councils, academies, the Sahitya Akademy or the U.G.C. all these are supposed to be there as representatives of the readership. Their capacity to be there is as reader. Incidentally I may mention that five of us, Members of Parliament, are there on the Council and I would be very happy if by convention one of the Members of Parliament nominated to the Council is a trade unionist. I would be very happy about it. This is something that was suggested in the Joint Select Committee and there I said that I would certainly like to express a wish in the House when I reply to the debate because it will be for the Speaker to nominate or the Chairman to nominate. If this happens by convention, it would ensure that a large section of the workers in the country are represented. SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Deogarh): Mr. Chairman, the hon. Minister just now said that papers having a circulation of less than 5000 will be free from the payment of subscription. But this is not provided in the Bill.

SHRI L. K. ADVANI: I will explain this when we deal with clauses. We now come to the clauses because there are amendments on them.

MR. CHAIRMAN: Now, I put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill to establish a Press
Council for the purpose of
preserving the freedom of the
press and of maintaining and
improving the standards of
newspapers and news agencies in
India, as passed by Rajya Sabha,
be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up clause by clause and amendments thereto. First of all we shall take up clause 2. There is one amendment, amendment No. 130 by Shri C. K. Chandrappan and Shri K.A. Rajan.

Clause 2 (Definitions)

SHRIK .A. RAJAN: Sir, I move:

Page, 2 line 3,-

after "working journalist" insert—
"and other newspaper employees"
(130)

MR. CHAIRMAN: I now put amendment No. 130 to the vote of the House.

The question is:

Page 2, line 3,-

after "working journalist" insert—
"and other newspaper employees"
(130)

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill"

The metion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill
Clauses 3 and 4 were added to the Bill.
Clause 5 (Composition of the council)
SHRI BHAUSAHEB THORAT: I
beg to move:

276

```
Shri Bhausaheb Thoratl
```

Page 2, line 19,-

for "twenty-eight" substitute "thirty" (1)

Page 3,-

after line 10, insert-

"(f) two shall be members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, each nominated by the President of India:" (2)

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : I beg to move :

Page 3,-

after line 10, insert-

"(f) one shall be nominated in accordance with such pro-cedure as may be prescribed from among persons who send news to newspapers (correspondents):" (45)

SIRIA. K. ROY: I beg to move:

Page 2, line 21,-

after "nominated" insert -

"from the panel of three persons suggested by other members of the Counc'l" (60)

Page 2, line 28,-

for "thirteen" substitute "eighteen" (61)

Page 2, line 28,-

for "no minate I" substitute "elected" (62)

Page 2, line 30,-

(i) for "six" substitute "three".

(ii) for "seven" substitute "fifteen" (63)

Page 2, line 34,-

for "three and four" siubstitute "two and eight" (64)

Page 2, line 34,-

for "six" substitute "three" (64)

Page 2, line 35,-

for "nominated" substitute "elected" (66)

Page 2, line 40,-

for "nominated" substitute "elected" (67)

Page 9, line 4,-

AUGUST 29, 1978

for "Bar Council of India" substitute "Indian Science Congress" (68)

Page 3, line 6,-

(i) for "five" substitute "three"

(ii) for "three" substitute "two" (60)

Page 9, line 8,-

for "two" substitute "one" (70)

Page 9, line 10,-

adi' at the end-

"who are not members of any other Committee of the Parliament' (71)

Page 3, line 14,-

for "nominations" ubstitute "elections" (72)

Page 3, line 15,-

for "nominated" substitute "elected" (73)

Page 3, line 23,-

for "fifteen thousand" cu hetitute "ten thousand" (74)

Page 3, line 26,-

for "fifteen thlusand" substitute "ten thousand" (75)

Page 3,-

for lines 27 to 38 substitute-

"(4) Before making any nomination of Chairman under sub-section (2), the members of the Council shall be elected by secret as per the provisions laid down in sub-section (3) under the super-vision of the Election Commission in accordance with existing law". (7b)

Page 3, lines 39 and 40,-

for "nominated" substitute "elected"

SHRI AIITSINH DABHI: I beg to move:

Page 3, line 21,-

for "fifty" substitute "seventy-five" (8g)

Page 3, line 23,-

for "fifty" substitute "seventy-five". (90)

SIRI ANANT DAVE : I beg to

Page 2, line 20,-

277

add at the end-

"and one member of every State Legislative Assembly nominated by the Speaker of the Assembly who shall not come within the meaning of section 24 of this Act and who shall simply assist the Council and protect the interest of small newspapers of his State" (98)

SHRI G.M. BANATWALLA:

Page 3, line 31,-

for "panels of names comprising twice the number"

substitute "the required number of names" (103)

Page 3,-

after line 17, insert-

"Provided also that in case nominations under clause (a) and clause (b) do not include any member from any one or more of the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, such additional number shall be nominated so as to secure members from all such languages," (149)

Page 3,-

after line 38, insert-

"(4A) Before making any nominations under the third proviso to sub-section (3), the Central Government shall, in the prescribed manner, invite names of the required number of members to be nominated from such associations of persons as may be notified in this behalf by the Central Government." (150)

SHRI B.C. KAMBLE : I beg to

Pages 2 and 3,-

for lines 27 to 42 and 1 to 47, respectively, substituts—

"(3) of the other members-

(a) fifteen shall be elected from amongst the working journalists including editors; the persons who own or carry on the business of management of newspapers, big medium or small newspapers, those managing news agencies, by electoral college of members of the above mentioned bodies;

- (b) ten shall be elected from amongst the members of the House of the People;
- am' ngst the members of the Council of States.
- (4) The Election Commission shall be entrusted with the preparation and conduct of and superintendence of these elections as may be prescribed by the Government.
- (5) Central Government shall notify the names of persons elected under sub-sections (3) and (4) in the Official Gazette and the same shall take effect from the date of notification." (100)

SHRI R. VENKATARAMAN: I beg to move:—

Page 2, line 19,-

after "Chairman" insert-

"who is or has been a Judge of a High Court or Supreme Court" (120)

SHRI K. A. RAJAN: I beg to move:-

Page 2, line 10,-

for "twenty-eight" substitute "thirtytwo" (131)

Page 2, line 28,-

for "thirteen" substitute "fifteen" (132)

Page 2, line 30,-

for "seven" substitute "nine" (199)

Page 2,-

afer line 39, insert-

"(bb) two shall be nominated in accordance with such procedure, as may be preceribed, from among the other newspaper employees;"(134)

Page 2, line 41,-

for "who manage" substitute—

"who are working in" (135)

SHRI YASHWANT BOROLE : : beg to move :--

Page 2, line 26,-

add at the end-

"and the Committee, as far as possible shall, nominate a person as Chairman having judicial background." (137)

SHRI BHAUSAHEB THORAT (Pandharpur): Mr. Chairman, Sir, I have suggested two amendment to Clause 5 and in those amendments, I have suggested that the Press Council should consist of a Chairman and thirty other Members in order to accommodate two Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is my suggestion.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I have given notice of amendments No. 8 and 9, which are identical with amendment Nos, 1 and 2. I have also given notice of an amendment to clause 13 i.e., my amendment No. 10 and here I would like to refer to the same. I will read out that amendment.

"Page 6-

after line 35, insert-

"(1) to encourage the newspapers, news agencies and journalists to undertake the greater responsibility for the upliftment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and economically backward classes by highlighting the true and correct socioeconomic and cultural conditions in national and regional papers."

If the hon. Minister is not agreeable to amendment Nos. 1 and 2, I would request him to make at least a provision in clause 13, so that the Press Council can deal with the matter.

श्री सक्सी नारायण नायण: मेरा संगोधन यह है कि जो तीस सदस्य रखे जाएं उन में संवादवाताओं के प्रतिनिधियों को भी रखा जाए। संवादवाता समा-चारपतों के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और वे संवाद एकल करके भेजते हैं और इस काम में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसलिए प्रेस काउंसिल में इनके भी प्रतिनिधि होने चाहियें, यही मेरा सुमाव है।

SHRI A.K. ROY: Mr. Chairman, Sir, as I already said sometime back, the freedom of the press means, freedom of the pen, freedom from the purse and freedom for the people. No freedom is

possible otherwise if the body wnich will give freedom is not democratically constituted. So, this Clause 5 is very important as it is concerned with the making up of that body.

Any democratic body is formed from the bottom, from below. Any autocratic body is formed from the top. Any type of oli-garchy is formed from the top. The whole body has been formed from the top. Somebody is nominating the Chairman; some-body is nominating the members and somebody is nominating others. I have proposed that first the members of the council will be elected from different categories, as I have explained. Then, that Council will propose a panel of three names from amongst whom the Chairman will be elected. There will be one representative on behalf of the Speaker of the House of the People which is an elected body; one representative on behalf of the Chairman of the Council of States which is also an elected body and third one will be on behalf of the members of the Council, So, the panel of three will be an elected body. The Chairman will be elected from the panel of three names which would be suggested by the members of the Council and which would be an elected body. In this way, I think, we can have a truly de-mocratic body to bring or to enforce democracy in the press,

As regards the membership also, you will find that the members nominated from amongst working journalists are in a minority. Under the present Press Council Bill, only seven members will be taken working journalists and five Members of Parliament, three from the Lok Sabha and two from the Rajya Sabha. These people will have direct concern with the people outside. I have proposed that out of 29 members of the Council, the majority of members should be from working journalists, that is, 15 members should be elected from amongst working journalists; two members from the Lok Sabha and one member from the Rajya Sabha, three from the editors; three from the management, etc. But the majority in the Press Council should remain in the hands of working journalists if we want to give freedom to the press, freedom of the pen, freedom from the purse and freedom for the people.

I have suggested that we must give a scientific orientation to the society. And that is what is needed most. We do not want much of htigants. We have go enough lawyers both within the Parliament and also in the politics outside, in our Cabinet and in every sphere of our life. We have got enough lawyers everywhere. It is becoming a lawyer's paradise. And I believe they are interested in increasing the

arena, in increasing the power of the courts and to curtail the power of the Parliament. That is why I have suggested that at least let the Press Council be free from these lawyers. Yes, you can have one member from the University Grants Commission. He will be an academician. The one from the Sahitya Academy will be a good ditterateur. Then with respect to one member from the Bar Council of India, instead of the Bar Council directly or indirectly dominating everywhere, I suggested let one member be from the Indian Science Congress so that in the Press, in the Television and in the Radio a scientific o itlook is correctly projected as the hon. lady M mber was telling that now-adays radio and television is preaching sup-

What I am pressing on our Minister is: let him beware of the Bar Council. We should take procaution. Otherwise, they will enter and you will be out. So, I have suggested that instead of the Bar Council, have one member from the Indian Science Congress so that you can project a sciencific outlook both in the Press as also in other spheres.

Another thing is : I have put certain limitations on the members who would be from the Rajya Sabha and the Lok Sabha and who will be selected from the Bar Council. As in the society outside, there should be one man, one job, at least within the Parliament. Here you will find that many of our m mbers are busy with so many jobs and many of our membes are sitting idle like me in the back benches, doing nothing and not even getting a chance to speak. At least let the principle of one man, one job be applicable within this House so that members who are members of other hodies would not be taken into this Press Council. The membership of the Press Council will have nothing to do with other spheres-there I have said, 'No'. Only those members who are not members of any other bodies will be eligible to become a member of the Press Gouncil. We are talking of diffusion of ownership and distribution of facilities. In this way, at least within the Parliament, let us distribute the facilities. That is why I have said that members who are already members of other committees like Estimates Committee, Public Accounts Committee or Public Undertakings Committee, this committee or that committee would be debarred from becoming a member of the Press Council.

Regarding nomination I have said that the members of the Press Council will be elected from different organisations through a secret ballot and with the help of the general election laws and under the guidance of the Election Commission, That also I have said because the very idea

of nomination is incompatible with the spirit of democracy we want.

SHRI AJITSINH DABHI (Anand):
Mr. Chairman, Sir, I feel that in view
of the report of the Newspaper Economy
Enquiry Committee of 1975 and observations made therein, the definition of newspaper given in the Bill should be amended.

I will actually quote the words of this Committee wherein it has been stated that:

"Small newspapers may exist simply for the purpose of acquiring of newsprint allocations depending on the revenue on the blackmarket sales of the quota or a part of the quota."

So, in order to ensure that this mischief regarding the newspaper quota may not continue, the definition clause should be amended. Instead of 50,000, 75,000 should be there.

MR. CHAIRMAN: Mr. Anant Dave. He does not want to say anything. He was there at that time. Shri Banatwalla.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani) Sir, I have moved three amendments. My first amendment is with respect to the manner in which the Council will be composed. It is strange that the Bill has a partial or a hesitant approach to the principle of election. When nominations will be required to be made under Clause 5, sub-clause 3(a) and (b), names will be invited from the relevant associations. But these associations will be called upon to suggest twice the number that is sought to be nominated and then, out of this panel, nomination of persons is required to be made.

If we read sub-clause (4) to Clause 5, in the first instance, we find that the wording is very vague. It is clear that in the case of first nomination, the Central Government will call for the names from the relevant associations. It is also clear that in case of subsequent chairman of the Council will call for the names from the relevant association.

It is, however, not clear from the wording of this sub-clause (4) as to whether it is the retiring Chairman in the subsequent cases who alone is going to sit in judgment and select the final persons from the panel suggested by the relevant association. I submit that this method will not be proper. It is necessary that the principle of election should have a fair and full place. There is no reason why associations should be called upon to elect twice the number required to be nominated. Then, somebody else has to sit and to name them out of that panel that has been elected by this Association. This, I say, is a partial

[Shri G. M. Banatwalla]

approach, a hesitant approach, towards the principle of election. It should go.

Therefore, my amendment seeks to provide that the relevant association should elect the number required to be nominated and those elected by the relevant association should be nominated on the Press Council.

MR. CHAIRMAN: Mr Banatwalla, do you want more time or you will finish with a sentence or two?

SHRI G. M. BANATWALLA: I am still to speak on two more amendments.

MR. CHAIRMAN: Then you may continue your speech on a later date when it is taken up.

16.00 hrs.

MOTION RE. INCREASING PLAY OF MONEY POWER IN ELECTIONS

MR. CFAIRMAN: Now, the House will take up Mr. Unnikrishnan's motion.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Sir, I beg to move:

"That this House is of the opinion that increasing play of money power in elections pose grave threat to the future of Parliamentary Democracy as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making."

Sir, I rise to move this motion with great sorrow and anger and also with deep concern because in recent months and weeks this country has gone through many traumatic experiences which come across the history of nations on very few occasions. But this country went through a crisis of confidence in ability to run its democratic institutions which the people of India had earned for themselves through their national struggle under the leadership of Mahatma Gandhi and Jawahar Lal Nehru.

Now, Sir, I am deeply worried not only about the troubled present but also about the future. Sir, you are probably familiar with a term, in Greek terminology they call it 'Catharsis'. Has this country and its democratic institutions come to this moment of catharsis. We have lived through these experience—as I have noted—and we thought in March 1977 at a moment of decisive intervention by dumb millions that things would be set right. A new order was born, it was announced from house tops by Jayaprakash Narayan, by Moraiji Desai, by Chandra Shekhar

and even though it was a conglomerate which had come into power they went to Rajghat to seek inspiration.

As I recall, one other vow which was taken was to cleanse the public life and to fight corruption. A man, who, we thought was an apostle of the new regime, an apostle of fearlessness, took over as Prime Minister of this country. He had a long and distinguished record as a fighter in the freedom movement, long record of administrative experience in various capacities. But what we thought he had more than all these was certain moral fibre. He claims to be the disciple of Mahatma Gandhi and he has been associated with him. We had a Home Minister who is absent today-the then Home Minister-who repeatedly told this House that we shall not rest till corruption is totally knocked out and destroyed. We thought, here was a new crusader. Commissions were set up. Cases were filed against what was known and what was publicised as criminal activities of the previous Prime Minister, the caucus around her. And the list did not end there. It was extended in an act of megalomania to many others. I recall that one of those cases was the way the congress party collected its election funds or funds in general. We had expressed the hope on our side that at last a new nation would emerge out of this with its moral fibre strengthened.

But, Sir, today where are we? The Indian National Congress did not accept the political base of the Janata party or its thrust and attitudes to various national and international questions and many other policies that were proclaimed. But we said this. I recall the Resolution of the AICC in May 1977 that we shall not shield corruption, we want to cleanse public life. If we are guilty, through legal means. Pronounce us as guilty and punish us. This was the attitude that we took. We hoped that the long awaited reform of elections would come. We hoped that places will be taken to its logical end. We hoped that the wheel would have turned a full circle. Today the wheel has again turned.

This conglomerate which took over is in shambles. Its Titans are locked up in a grim battle, not over policies and principles, but over positions of power, over chairs as Raj Narain was fond of saying. He ence called Charan Singh, Chair Singh. The Chair Singh is again active. The entire moral worth and credibility of this conglomerate, as Babu Jagjiwan Ram has called it, is in rhambles. It is exceed. The hopes and the dreams and the aspiration of the people of this country who fough for you and who thought that distortions will be corrected, are shattered today. Why should this country traverse this path,

this trejectory? That is my concern today, Sometime ago there was what is known as a correspondence between the Prime Minister and the then Home Minister Mr. Charan Singh. It was reported in the press that the allegations treated in these letters may not be specific but the thurst of the correspondence was that things have to be enquired into that a belief, strong belief or conviction is there in high places that corruption has entered the sanctum sanctorum. It is very unfortunate that we should be discussing this issue and this Parliament should be concerned day in and day out with these issues, which I will say, are peripheral issues. We are discussing this issue, which is important for our functioning, but this House has no time to discuss basic questions of our economic life, economic policy. would say that this Government and the Prime Minister are responsible for the situation, for having brought this House to this situation, because the opposition in a parliamentary democracy has a function to perform. The attitude of high and mighty that the Prime Minister took and his Party took has forced the opposition into this position, which is not very natural position, not very important from the long-term perspective of the country, but you have compelled us to take this position.

After this correspondence, Shri Virendera Kapur of Indian Express brought out a story-I will come to other stories laterthat Shri Madhu Limaye, General Secretary of the Janata Party—I do not know whether he has resigned or is still there has said that Rs. eighty lakhs or more were collected by Shri Kanti Desai .towards the election funds of the Party. Shri C. B. Gupta, the treasurer of Janata Party, said that it was not Rs. eighty lakhs, but Rs. ninety lakhs and I had said that it was neither Rs. eighty lakhs nor Rs. ninety lakhs, but it could be anywhere around Rs. one and a half crores. Shri Madhu Limaye later took a position that he would neither deny nor confirm it. He has not denied it, all that he would say that he would neither deny nor confirm it. This revelation is of crucial significance.

In March 1977 and later in June 1977, when elections were held to the State Assemblies, Shri K. Santhanam, who was the Chairman of the first Committee for Electoral Reforms, who had been exercised over these things as a patriot for a long time....

AN. HON. MEMBER: That Committee was concerned with elimination of corruption.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN:.. charged the Janata Party with extorting money by using unfair means. The reply came from the Party Chairman, Shri Chandra Shekhar, that they had never asked

any of their Ministers to collect money and Shri C. B. Gupta, treasurer of Janata Party said that they had not asked any one, only authorised persons were collecting the funds. Mark the word 'authorised'. This was on May 24, 1977. He said: "Only authorized persons." When he was asked to disclose as to who were these authorized persons, he said that 'it was an internal affair of his party.'

I do not want to take the position today that parliamentary democracy, our institutions and the electoral system or the party structures that we have inherited due to historical circumstances, can be run without money. I am not taking that position at all. And these were some of the debates that we had in the past in the Congress organization itself. But the basic question is not only one which concerns the immediate present, but also one which concerns the future. Immediately we are confronted with a party which, having come to power, having taken a pledge at the Samadhi of Mahatma Gandhi and entered the portals of power, is now in shambles. Not only that; its moral worth and credibility have been eroded. It is not merely a question of collecting election funds. It is the means which have been used in collecting these funds, as well as nexus betweeen administrative actions and collection of these funds, as also collections by unauthorised persons, which breeds corruption in the whole system. There lies the crux of the matter.

As I said earlier, Commissions of enquiry have been set up and many, including Mr. P. C. Sethi who was treasurer of our party, are still facing similar charges. I do not want to go into details, because some of them are sub judice. This is the time when this House should assert itself, to guide us, because the party which came to power on the same platform, after a prolonged agitation in Bihar and Gujaratwhich, according to Jayaprakash Narain centred around the theme of corruption in high places—is in such a state that its moral worth has further deteriorated. So, in an environment like this, it is time that this House intervenes effectively and decisively, no matter who is involved, and says: "We shall not go back to the situation where we came from." It is in this spirit that I look to this Motion to-day.

When allegations are made, the obvious reaction should be that one cannot judge oneself. That is the basis of our functioning or the basis of any kind of functioning. I do not want to call it juristic; it is basic, simple, commonsense.

What are these allegations? I shall take one allegation, viz. that Mr. Kanti Deser-collected Rs. 80 lakhs or Rs. 90 lakhs: figures are not that relevant, but the fact

remains that - it is admitted that large sections of people in this country believe that - he collected not only funds, but also that it has not been fully accounted for. The question is also whether he had the permission, because he is in close proximity to the highest centre of decision-making in this country. Mr. Morarji Desaihas gone on record as saying that he (Mr Kanti Desai) terminated his business connections as early as in 1964. On 30th July 1968, in reply to Mr Umanath and Mr Madhu Limaye he told this House— and I quote—"Let him know that my son has given up business from the year 1964, and not now." But subsequently it was known that he continued in this business. So, possibly it could be that because he was involved in that business in the past and had been in the business contact, the Janata Party decided to make use of his good offices. But the trouble here is that he is not a nobody. I do not dispute his right as a citizen or a political worker; if he wants to enter into politics and remain in politics, I do not dispute it at all nor do I say that the Party should not collect

But, as I said, his activities have bred corruption; his activities have led to what Justice Shah called "Deviation from established administrative procedure" for which the people are being arraigned. It means subverting the established administrative procedure and misuse of authority. This is the crux of the problem.

Now I am happy that the Finance Minister is here. I do not want to go into lot of things because there are lot of things to be talked about what is going on in his Ministry from March 1977 to this day. But I only want to mention a few things. You are aware of the situation of the Central Board of Direct Taxes. Mr. Kanti Desai, one fine morning, last year, landed in Calcutta. A group of businessmen methim and lobbled the case of Mr. I. P. Gupta and said that he should be appointed as the Chairman of the CBDT. I am told, a substantial amount of Rs. 50 lakhs was donated to Janata Party's fund as a quidpro quo for making Mr. I. P. Gupta as the Chairman of the CBDT.

Now, Mr.Kanti Desai, as an experienced businessman who keeps his words, had to promote his candidature when the post of Chairman fell vacant. The appointment is of the rank of the A I litional Secretary to the Government of India and governs the rules male by this House, according to the Central Board Act of 1963. The orlar of seniority for this post was: (1) Mr. Kailash Narain, (2) Mr. I. P. Gupta and (3) M. Karuvilla for reasons I have explained. The choice of Mr. Kanti Desai fell on Mr. I. P. Gupta. But the Central Vigilance Commissioer was investigating certain serious allegations against Mr.

Gupta. The Finance Secretary approach, ed the Central Commissioner Mr. Pimputkar who refused to submit to the plandishments of the messengers and couriers o Mr. Kanti Desai. Mr. Kailash Narain was overruled for Janata Party's political views: and the Finance Secretary then suggested and the Finance Minister and the Minister of State endorsed it on the file that Mr. Kuruvilla be considered. The Prime Minister was away in Kashmir. But Mr. Kanti Desai did not stop, conscious as he was of his commitment to his friends who were pressing him. After this again the Finance Secretary was sent to C.V.C .--All this can be checked up-to revise its opinion about Mr. Gupta but he refused to do so. The dates of his meeting also are important.

MR. CHAIRMAN: Two hours time had been allotted; you can take half an hour; you have already taken 25 minutes. You have to look at the watch also.

AN HON. MEMBER: Time will be extended.

SHRIK, P. UNNIKRISHNAN: There were other members. I shall cut short my observations because there are many other kissas also - members like Mr. Srinivasan, Avtar Singh etc. on the Board. Mr. Badami for whom I have personally high regard and I hold him in great esteem, who was in charge of forfeited property was brought in. When it went to the Appointments Committee of the Cabinet he was not a member of the Board. According to the Gazette of India January I, 1964 notification of the ministry of finance rule No. 3, it says: The Central Government may by notification in the Official Gazette appoint one of the members to be chairman. I do not think the Appointments Committee was told about this. He was appointed straightaway, asked simultaneously to become a member and then take over as chairman. CBDT and settlement commissions have been important arenas of Kantilal Desai's operations. I want an enquiry: I challenge this government to conduct an enquiry; how many settlements have been effected since April 1977 till October 1977 and then from November 1977 to June 1978? How many violations were there? Clause 245 (d) of the Income-tax Act of 1961 says; sub-section 1, proviso (3) of 245: Provided further that an application shall not be proceeded with under this sub section if the commissoner objects to the application, being proceeded with on the ground that concealment of particulars of income on the part of the applicant or perpetration of a fraud by him evading any tax or other sums chargeable or assessable under income-tax has been established or is likely to be established before any income-tax author ity.

290

section 30 the Official Secrets Act. Please How many fraud cases have been settled? There are clear implications. I do not want to mention names because of shortness of time. How many cases have been decided against the clear cut advice of the Commissioners, paticularly in Bombay circle and in Ahmedabad circle. I do not want on this occasion to refer to some firms-because that is outside the scope-with which the Finance Minister was earlier connected or firms with wnich the Secretary to the Prime Minister, Mr. Shankar was connected. That is outside the scope, I presume. What I want to know is: tell us the donors to the Janata Party election funds; give us the accounts; then 'tell us-the House and the country are entitled to know-how they have been favoured by the income-tax and CBDT and settlement commissions.

MR. CHAIRMAN: Your half an hour is over. You know the total time is two hours.

SHRI K.P.UNNIKRISHNAN: I have to tell you more.

MR. CHAIRMAN: You must finish in five minutes.

SHRI VINODBHALB, SHETH (Jamnagar): Ultimately he is going to prove that Janata Members are not interfering in the day to day affairs of the government.

How much of it was in black money?

MR. CHAIRMAN: How much of time do you expect me to give you?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I will take at least 15 minutes more.

MR. CHAIRMAN: How is it possible? Out of two hous if you take 45 minutes, then what about others?

UNNIKRISHNAN: SHRI K. P. Time may kindly be extended.

In regard to settlement of income tax and wealth tax, what about penalty and prosecution and in how many cases was the interest waived? This is one question. How much was it in black?

On this question of appointment Mr. Morarji Desai, who happens to be the Prime Minister now, once recalled the advice that he gave to the then Governor of Rombay in 1939- Sir Roger Lumley who had approached the then Revenue Minister with the request that somebody be appointed for some minor post. Mr. Desai asked him how dare you ask me to do this. I am not going to do it. But, unfortunately, when Kanti proposes, things are different. Now, I do not want to go into various questions like Polyster Filament Yarn, C.P.M.O., and how they are connec-

ted. But I must tell you something of which I have the privilege to bring about, regarding Hindujas Bros. A very important question has arisen out of this. That is not the question of 11 million dollars, which I have brought before the House and the Prime Minister's Secretariat. I allege, was requesting the President of India to get invited for the banquett, latest on this last trip of Mr. Kanti Desai or the Prime Minister's trip. Hinduias were consorting with him in Hotel Beaurivage in Geneva. It has been the scene for money collections-unauthorised collections in foreign exchange. Not merely Hinduias, there are chibas in Westbury in London. How much was colected in the last trip i.e. in 1977? Janata Party and the Government of India, do they know how much has been collected not merely through their independent contacts, not in Indian currency but in foreign exchange?

Now, what is relevant is. I refer to the Central Vigilance Commissioner's latest Report, wherein there is a very interesting case regarding Hindujas Bros. An Indo-Iranian firm produces a film called 'Subah aur Sham' and without the knowledge of the Information and Brondeasting Ministry and Castons Cl arange Permit was bronght to India. It was changed and was made a film. This happened during Sanjay Gandhi's days. But the point is the officials were proceeded against as a result of C.B.I. enquiry, not the Hindujas. To this day no prosecution has been launched.

Now I refer to the Hindu Report of July 24, 1978, Heading—P.M. Tops Slush Payment. What was this payment of \$450 million? What was this contract of \$ 450 million? Was it the same that Kanti discussed with Hindujas in Hotel Beaurivage, we want to know? That is an access. The source is these corrupt links . Now, investigations were held in another case - Boeing purchees regarding Maneckji. The two serious things to which I want to draw your attention are these. On 30th September, 1977, in spite of his friend Shri Kanti Desai being in a position of power and influence, he had to be charge-sheeted because it was linked with other VIPs of the former regime. In the FIR submitted to Mr. Kotwal, the Additional Chief Metropolitan Magistrate of Bombay, under section 56 of FERA of 1973, two lines of enquiry were to be pursued. One was that Commandant-General Maneckj and his younger brother, Kekoo used part of the money to promote the sale of Boeing aircraft by bribing Cabiment officials. The second was that Mr. Kekoo Maneckji received unauthorised information of a secret nature relating to and aquisition of the development defence aircraft and stores in our country, which is punishable under Section 3

### [Shri K.P. Unnikrishanan]

of the Official Secrets Act. Please refer to page 84 of the CBI report for 1977 placed on the Table of the House, where what I have read out has been substantiated. I would like to know what has happened. The moment the investigation reached the point of Kanti-Shankar axis, the investigation was stopped and has found itself in a blind ally! How much money has come through, Mr. Haridas Mundhra shoud be able to tell us. He is another new friend. I do not want to go into all to ese details. It does not end there. The kissa of Janata misrule and corruption that they are breeding in this country, all in the name of election funds, does not end here. There was the ques-tion of impouding of passports in April, 1977. I woud like to know how the passports of Mr. Raunaq Singh of Raunaq International were returned. Who was lawyer Juneja who approached the close relatives of the then Home Minister and get it out for a consideration? Mr. Charan Singh has always been very vehement on the issue of corruption. Speaking in this House on 13th July, 1977 he said:

"Corruption is prevailing from top to bottom. Political leaders and Ministers are not also free from it. The moral fibre in this country has completely collapsed." But he allowed his son-in-law that is the tragedy of this country what do you do with them?—to interace in the cases of impounding of passports of criminals and racketeers who abund in this country? Armed racketeers are now around because we are considering the purchase of DPSA and Mr. Kanti Desai cannot deny that he met the racketeers Chibber Brothers in Westbury Hotel in London. I am making that charge.

I do not see the former Health Minister here unfortunately. He should have been here. We are entitled to know from him how much money was collected by his Special Assistant, Mr. Chitragad Singh. It is a very amusing story, the collections made by his Special Assistant.

Mr. CHAIRMAN: You should conclude now.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Before I conclde I would like to say some thing about this Mr. Chitra Anged Singh.

चौधरी बनबीर सिंह (होसियारपुर) : यह धर्म तेवा वही नहीं था, को जिससे इन्दिरा गांधी सिंक कोट मिला था ?

SHRI K. P. UNNIKRISHANAN:

श्री के0 पी0 उन्नीकृष्णन : इस जुलाई में हीटल बुरबाज, जेनेवा में शंकर साहब ग्रीरकांति देसाई जिससे मिले थे, वही धर्म तेजा ।

Mr. Raj Narain had a very colourful Private Secretary or Special Assistant Known as Mr. Chitra Angad Singh. It is rumoured that an enquiry is going on. Ms . Chitra Angad Singh was not merely colourful but he also understood the requirements of political finance of his mentor and his group. He used many ordinary and extraordinary means. One of them is very amusing. There were three Persian carpets belonging to a VIP which on a fine March morning of 1977 found its way to Vishwayatan Yogashram. Swami Dhirendra Brahmachari tried to take them out but by that time, he had come under surveaillnce. So, they got stuck there at Vishwayatan Yogashram. Mr. Raj Narain appointed an Administrator of this Ashram a man called Chhatrasal Singh from UP who has nothing to do with voga but every thing to do with Chitra Angad Singh. One fine morning, all the carpets including these carpetworth lakhs of rupees, kambals, matresses lock, stock and barrel were removed from the Ashram. Many have been returned but not these expensive carpets.

The whole question is one of standards. We had set up certain standards in this country because Mr. K. D. Malaviya's Personal Assistant was found having collected Rs. 10000/-. An inquiry commission was set up. It was scrutinised. An inquiry was held by a Supreme Court Judge. He resigned. These were the standards we had set for ourselves in this country. Now, Sir, I want the Prime Minister to be remembered in this country, remembered by posterity not a a father who showed infirmity at a crucial moment of his own life and the life of this country, but I want him to be remembered, as I said, as an apostle of fearlessness who came from Raj Ghat, went to define certain standards of public conduct to strengthen the moral fibre of this country. This is what is lacking today. I recall what he told this House on 9-12-74. This is what power corrupts. I quote:

"I hopethe Prime Minister will realise it if not today some day, it will have to be realised,"

I hope, Morarji Bhai will not abdicate his commitment. I hope, he will not abdicate his position of responsibility or what he owes to this country which has put him where he is. I have not said this out of a perverse love. I have not said this out of personal prejudiced. But if you want to cleanse the system, you will have to. And about this I shall come back in my reply.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House is of the opinion that increasing play of money power in elections pose grave threat to the future of Parliamentary Democracy as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making."

Now, amendments will have to be moved.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Sconi): I beg to move:

'That in the motion,-

after "evidenced" insert-

"since the elections of 1971 and" (1)

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): I beg to move:

'That in the motion .--

add at the end -

"and recommends to the Government to bring forward expeditionsly legislation by which all political parties in the country should be registered under the Registration of Societies Act, 1860 (as amended up-to-date) and should maintain accounts of all their receipts revealing their sources and expenditure supported by stamped vouchers and publish annually a statement of receipts and expenditures duly audited and certified by a chartered accountant which should be published in the Gazette of the Government of India." (2)

SHR1 SHANKAR DEV (Bidar): I beg to move:

'That in the motion,-

after "Parliamentary Democracy"

"and to the highest Indian traditions and culture." (3)

MR. CHAIRMAN: Mr. Kamath.

SHRI HARI VISHNU KAMATH
(Hoskangabad): I had given notice of a
substitute motion. Id onot know why
it is shown as an amendment. Is it
permissible or not as a substitute motion?

MR. CHAIRMAN: You can only move an amendment.

SHRI HARI VISHNU KAMATH:
I gave notice of a substitute motion.

MR. CHAIRMAN: Office informs me that it will be in the form of an amendment itself to substitute that.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I have no objection. I beg to move:

'That in the motion,-

add at the end-

"and expresser its grave concern over the fact that the electoral process as well as public life in India which was badly polluted and vitiated by an unholy alliance of political power and money power during the decadent decade, 1967—77, with the steep erosion of ethical standards and moral values, threatened to disport democracy into a plutocracy deform 'Janatantra' into 'Dhanatantra' and recognizes the imperative need to reverse those morbid trends and is convinced that for the purpose the formulation of a voluntary code of conduct by all political parties is essential and urges the Government to initiate, without delay, comprehensive measures with a view to cleansing public life in general and purifying the electoral process in particular." '' (4)

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : I beg to move :

'That in the motion,-

for "as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making."

substitute-

"and directs the Government to refer the matter to the Chief Justice of India to ascertain whether there is a prima facie case for a thorough probe under the Commissions of Inquiry Act, and further directs the Government to bring suitable legislation before the House to ban collection of election funds from business houses by any body." 1(5)

भी गौरी शंकर राथ (गाजीपुर): मान्यवर, आज सदन के सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत है वह एक बड़े गम्भीर प्रमन से संबन्धित है। जो मेरे निल इसको मून करने वाले हैं वे शुरू में तो ठीक रहे लेकिन मन्त में उन्होंने इस विषय को छोड़ कर बड़ी लम्बी दौड़ लगाई जिस पर में जाला नहीं बाहता। यह प्रमन बहुत पूराने समय से बला

## भी भीरी संकर राय?

Motion re. Play of

धा रहा है कि मंत्री भीर सरकार में जो लोग हैं उनके पर का प्रयोग बन्दा बसुन करने में कैसे नहीं होगा और यह जो मनी है वह किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित न करे-प्रसका प्रयास बहुत पहले से हुमा है। सन् 1960 में इस प्रकार की बात ग्राई थी लेकिन पंछ नेहरू ने इसका विरोध किया था और चन्दा लेने की बात उन्होंने रखी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1969 में चन्दा लेने के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई तब हमारे मिल्रों का पाबंदी लगाने का मतलब यह या कि मान बुक चन्दान लिया जाये। इसके दो नतीजे निकले । एक नतीबा तो यह निकला कि स्लैक मनी भाने लगा भीर दूसरा नतीजा यह निकला कि पार्टियों का हिसाब देना बन्द हो बया क्योंकि ब्लैकमनी जो पाती थी उसका हिमाब देने के लिए वे मजबूर नहीं थे। मैं कांग्रेम की परम्पराधों को भी जानता है क्योंकि हम कोई दूर के नहीं हैं, हमारा भी रिश्ना रहा है । जबसे चन्दा बैन हुआ तब से रसीद से रुपया न आ करके बीफकेंस पालिटिक्स प्रारम्भ हा गई हमारे उन्नीकृष्णन स्रीर चव्हाण माहब जैसे विवेकानन्दी की बात मैं नहीं करता, मैं ऋषियों की बात नहीं करना चाहमा, में साधारण कांग्रेसमैन की बात करता हूं कि तबसे बीफकेस पालिटिक्स शरू हो गई । उसमें ब्लैकमनी का प्रभाव माने लगा भीर वह चल पड़ा । पिछले 8-10 माल, 1969 के बाद की जो कांग्रेस रही है, उसके धांकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन प्रभी मेरे मामने जो मांकडे हैं इनमें ग्रगर किसी ने बन्दा लिया तो मेरा खायाल है कि दम प्रतिशत से कम में सारे दल हैं भीर 90 प्रतिशत से ज्यादा में उस समय कांग्रेस के लोगों ने चन्दालिया। फर्कयह थाकि कांग्रेस में कई प्रकार के लोग थे---कुछ प्रगतिशील ये भीर कुछ प्रतिक्रियावादी थे । मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन प्रगतिशील की गरिभाषा जो की जाती है---

A progressive is a man who can digest money from Russia. A rectionary is a man who can digest money from the dolar area. A dyamic person is one who can digest money from both places most effectively. And there were dynamic people, they conducted the whole country's fianances and elections.

इस प्रस्ताव में एक शब्द जो लिखा है, हम चाहते हैं उस पर बहुस हो लेकिन हमारे मित्र ने प्रस्ताव को पर्वर्ट कर दिया । उन्होंने कहा रैविलेशन्स हुए हैं। श्री उल्लीकृष्णन को ग्रन मालुम हुन्ना है कि प्रभावशाली लोग चन्दा इकट्ठा किया करते थे । इससे पहले इनको यह बात मालूम नहीं थी। चन्हाण साहब ने स्वप्त में भी नहीं देखा कि चन्दाभी लिया जाता है। यह हरिजन प्रेमी ये इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी धौर चन्हाण साहब सारा चन्दा हरिजन बस्ती से ले धाते थे धौर सारे देश में बाट देते थे । इस प्रकार से सन्त समाणम चलताथा । मैं इसके लिए कोई शब्द कहना नहीं चाहता, एक तो इंसल्ट प्रुफ बादमी होता है हिन्दी का सन्य सण्छा नहीं होना, "हपादार" अनपार्लमेन्टरी हो आयेगा । आप देखें कि किस साहब के साथ बन्दा लेने की परम्परा का विरोध करते हैं।

कस्टम वाली जो बात है, उन्होंने कहा कि कृति भाई उसमें भापरेट करते हैं। मेरा खमाल है मेरे मिल को उस क्षेत्र में बड़ी जानकारी है क्योंकि उसका हम जवाब नहीं दे मकते हैं। उन का कस्टम से ज्यादा ताल्लक है, इसलिये वह जानते होंगे....

श्री सौगत राव: (बैरकपूर): इन्कम टैक्स की बात है।

श्री गौरी शंकर राम : इन्कम टैक्स के बारे में भी मझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं गांव का ब्रादमी हैं। इत्कम टैक्स ब्राफिसर कौन हैं, मैं नहीं जानेता । लेकिन एक का तो सम्मान करता हू, बड़े भादरणीय हैं। लेकिन कितने भादरणीय हैं या किनने घृणित है——मैं नही जानता स्वीर जान भी नहीं सकता हु-- क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव भी नहीं है, रिएक्शनरी भी नहीं है और डाइनेमिक भी नहीं हं-इस लिये नहीं जान सकता है।

मै निश्रेदन कर रहा था---धाज सदन के सामने जो गम्भीर प्रका विचारार्थ है--लेजिस्लेशन से यह प्रवन्ति नहीं बदलेगी, एक्यजेणन्त्र से यह प्रवन्ति नहीं बदलेगी । कान्तिभाई ने चन्दा मांगा, जनता पार्टी ने बन्दा मांगा, सरकार में जो लोग हैं उन्होंने चन्दा मांगा, राजनारायण त्री ने चन्दा मांगा लेकिन ये जो चन्द्रे में घणा करने वाले लोग है---मैं भपने विरोधी दलों के मिलों से भौर साथ नीर से माठे माहब से कहना चाहना हुं---ग्राप की माताजी को भी चन्दे से नफरन है, तो मैं इस चन्दे से नफरत करने वालों ने कहना चाहता है---एक साथ बैठ कर इस पर विचार करें, प्रपने सीते पर हाथ रख कर विचार करें--क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? इस समस्या का समाधान एक्युजेशन्ज से नही होगा। यह कहना गलत है कि नई रेबेलेकरण हुए हैं। मैं चन्दे ने नफरत करने वाले मिल्रों से कहना चाहता ह--यह परम्परा प्रारम्भिक काल से है, जब से कांग्रेस पावर में प्राई, चन्दा मांगती रही । फर्क सिर्फ इसना है—सी0 बी0 गुप्ता जैसे जो पुराने रिएक्शनरी लीडसे रहे हैं, वे रमीद दे कर चन्दा लिया करते थे, लेकिन जब से प्रगतिशील हो गये, तब से रसीद बीर पूर्जें की जरूरत ही नहीं रही ।

मैं आप के अरिये अपने मिल्लों से कहना चाहता हं-इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिये बैठिये-- प्रस्तवार में छप जायगा, इतना काफी नहीं है। हिन्दूजा बोदसे के बारे में चव्हाण साहब से पूछिये। वह विदेश मंत्री और वित मंत्री रह चुके हैं---आज उन को साहस के साय कहना चाहिये कि उस का व्यवहार क्या था। मिसिज गांधी उस को प्रकेले टैकल नहीं किया करती थी, उन को भी इस की थोड़ी-बहुत जानकारी सबस्य होगी ....

## भी सौगत राय : प्रुफ लाइयें।

श्री गोरी शंकर राख: प्रफ की क्या जरूरत है, यह कोई बदालत नहीं है । मैं तो भले बादमी के लिये यह बात कह रहा हु---जो उस को महसूस करने के लिये तैयार हैं। यह कह देने से कि इन्होंने चन्दा बमूल किया, उन्होंन चन्दा बमूल किया, इस से काम नहीं चलगा । धाप ने धपने मायज में एक भी ऐसा मुझाव नही दिया कि इन को कैसे ठीक किया जाय । चन्दा वमूल करना कोई नई बान नहीं है, यह प्रवृत्ति प्रारम्भ से ही थी । जब हमारा राष्ट्रीय झान्दीलन चल रहा था, तक भी देश के पंजीपतियों ने राप्टीय भ्रान्दोलन में साक्षा दे कर हमारी महायता की थी. लेकिन उस समय पावर उन के पाम नहीं थीं. इसीलिये करण्यान का ग्रसर नहीं पड़ा । उस के बाद पं0 जबाहर लाल नेहरू के जमाने में भी पंजीपति चन्दा वेते थे. इन्दिंग गांधी के जमाने में, चुकि वह प्रगतिज्ञील और डाइनेसिक थी, इस लिये बड माकाश तक चला गया। मैं ग्रंपने उधर बैठे हुए मिलों से कहना चाहता है--- उन्होंने घपने समय में इस परम्परा की बड़ा बीभतम रूप दिया । सभापति महोदय, 1977 में जब पालियामेन्ट के 'चुनाय हुए मै विश्वास के माथ कहता हं—हमार्ग पार्टी पास एक स्पया भी देने के लिये नहीं था। लोगो ने चन्दा देकर हम को चुनाव लक्षाया था। मैं यह नहीं कहना कि इधर सब सन्यासी बैठे हुए हैं या बह चन्दा नहीं लेगे । लेकिन में अपने भाई उन्नीकरणन और चटहाण साहब से कहना चाहना ह--एक कांसेन्सम इवाल्व कीजिये कि किस तरह में इस समस्या का समाधान होगा । लेजिस्लेजन में इस समस्या का समाधान नहीं ही सकता ।

1969 में ब्रापने लेजिस्सेशन बनाया, लेकिन उस लेजिस्सेशन से ब्रापने त्मैक-मनी को व्यापार मुक्त कर दिया, चोर-बाजारी का पैसा राजनीतिक फण्ड में ब्राने लगा। मैं एक पुरानी डिबेट पढ़ रहा था—उसमें लिखा था—

The Government of the people by the industrialists and for the industrialists.

ऐसा झापने उस समय किया। मेरे पास समय नहीं हैं,
मैं प्रापकी तरह से मुख्य बनता नहीं हूं—वर्ना में आपको
बतलाता कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने एस
एमं टी सी के द्वारा कास्ट-झायरन का दास बढ़ा कर
किन-किन कस्ट्रीज से टच्ज भाफ-मनी लेकर
किनीकिन कस्ट्रीज से टच्ज भाफ-मनी लेकर
नहीं है, लेकिन मैं जानता हुं—जो लोग प्राथारिटी में
बे—उनका कितना द्या विदेशी बैंकों में जमा है।
रिकार्ड बिस्सा-बिस्ला कर इन बातों की बतलाता है।
मैं एक्सयजेशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात
कहना चाहता हुं—पार सबमुब में इस समस्या की
समस्या के ल्या कर इन बातों का समस्यान निकत्त
समस्या के ल्या कर वार्च कराना ममाधान निकत्त
सकता है, लेकिन यदि उमका उट्टेग्य कान्ति भाई का नाम

सेना है, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, सेकिन साठे माहब आपको मालम होगा, आपके यहां उमाशंकर दीक्षित पहले चन्दा इकट्ठा किया करते वै। वहले झानन्द भवन के ट्रेजरर थे, उसके बाद कांग्रेस के टेजरर हुए और फिर देश के । हमारे यहा एक नेशनल हेरल्ड प्रखबार है। इसमें मंबली ब्लैक मनी इनजेक्ट होती रहती है । अखबार में बाटा है लेकिन उसकी बिल्डिंग बनती रही । व्यक्तिगत रूप से चन्दे से नहीं, पोलिटिक्स के नाम पर स्लैक मनी मांग करके नेशनल हेरल्ड को सींचा गया जोकि एक परिवार की सम्पत्ति है। उसको सीचा गया । मैं जानता हूं कि माज मी, जो लोग अब शक्ति में या पावर में नहीं हैं, दिस-दम हजार रुपये महीना खर्च करते हैं । उनमें बहुत से पालियामेंट के मेम्बर भी हैं। कहां से यह सब भागा है ? ये सब बातें किस चीज को साबित करती है ?

धाप प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई पर हमला करिये लेकिन जीगे के घर में रहने वाले लोग ऐसा हमला न करें। धाप धाप करना वाहते हैं तो इस दृष्टि से करो कि कोई सुझाव रखों जिससे सब लोग सिल कर, बैठ कर वात करें। धार्ष प्रधान मंत्री जी से, मंत्रियों से बात करिये । जैं कहूंगा कि चन्हाण माहब बात करें। गामद धाप लोग नहीं जानते कि हिन्दुजा बदसं च्या है। यह पुरान मंत्रिसंडल में रहने वालों की जानकारी में है, यह उस बक्न चंदे की बात है ।

में कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को लाकर इस सबत का इस नगह से बुक्पयांग नहीं होगा चाहिए कि कोई धादमी कोई खास शिकायत करने के निए, जीविटिकल मोटिव से इसका दुक्पयांग करें। मैं धापसे कहना चाहना हूं कि धाएकों कोई धात्मा वाले के लीच मिल कर बैठें और विचार करें कि चैसे इस देश में चित्र के तो इस प्रकार है। देश में के चित्र को अच्छा ग्याना है, की इस देश में चंद की राजनीति चलगी और कहां नक चलेगी, कहां नक उसकी सीमायझ करना है। यह चीज एकर दूसरे को गाली-गनौज देकर नहीं सोची जा सकती है।

मान्यवर, हमारे दो टीचमं थे । एक बढ़े विद्वान थे धीर हसरे कुछ कम पढ़े लिखे थे । हसरे टीचर जब इन्तिहान होता तो नकल करने बात कहा के तो पकड़ निया करते । उनसे हमारे विद्वान टीचर कहा करते थे कि तुम बचपन में जकर नकल करते होंगे तभी नकलियों को पहुचाने जाते जहां । इस्तिए हमारे थे भाई भी जानते हैं कि कहां कहां से चन्दा झाता है, कहां कहां इसके होता है में इनकी 16 झाने बेबूनियाद बात की भी ढंकने से हिचकता हूं स्पीति इनको सब मालूम है कि कौन कहां कहां नाजुक मौका है । ये बहुते से नाजुक मौकों को जनते हैं । इसलिए में आपसे कहता हूं कि झाप इस पर बैठकर विचार की लिए भीर मुझाव टीजिए। यह काम कानून बनाने से

# [भी गीरी शंकर राय]

होता है तो वह बताइये। यह देश 62 करोड़ का है। देश में कांति भाई अतिरिक्त क्या हर किसी को बंदा मांगने से नफरत है ? शाबिर शाप क्या कहना चाहते ह। बाट इ यू बांट टू इम्प्रेस झपीन भी ? मैं कहता हुं कि इस सारे मामले पर बैठ कर विचार कीजिए कि कैसे इस समस्या को हल किया जाए । इस प्रस्ताव का एक हिस्सा अपनी पराकाच्छा पर चला गया है। जब चव्हाण साहब मंत्रिमंडल में ये तब भी रिविलेशंस हुए हैं। इसलिए यह कहना कि पंजीपतियों से पैसा लिया गया, इस बात की ज्ञायद श्री उन्नीकृष्णन जी उतना नहीं जानते जितना कि श्री चव्हाश साहब जानते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी दलों के लोग बैठें, एक कांसेन्सस, एक भण्डरस्टडिंग पर मार्थे कि किस तरह से सार्वजनिक जीवन में एक परम्परा कायम की जाय, मैयार निश्चित रूप में कायम किये जायें । जासी गाली देने से तो यह नहीं होगा । बाप इसके लिए मैयार तय कीजिए । यह मै किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो बैठ करके इसका हुल इंद्रें, वह जरूर निकलेगा ।

भी बसन्त साठे (बकोला) : सभापति महोदय, मैं गौरीलकर राय जी से सहमत है को मनी उन्होंने बात कही । यह को प्रस्ताव मेरे मिल भी उन्नीकृष्णन जी ने यहां पर रखा है, इस प्रस्ताव से जो सबाल उन्होंन उठाया है, उसका हल इस तरह से निकल सकता है यह बात मेरी समझ में नहीं भायी । (ज्यवज्ञान) भापकी भागी हो तो बताइये । मैं गौरीशकर जी से सहमत हु। इसलिए कि चन्दा इकट्ठा हो रहा है और मनी पावर की बहुत बड़ी संमस्या है और उससे खतरा पैदा हुआ है, वह प्रभावित करती है धीर बड़े लोग जो सत्ता में हैं मिनिस्टर हैं उन्हें ज्यादा सहिमयत होती है तो यह बात तो प्राज से महीं है । जो मिनिस्टर रहेगा और जो सत्ता में रहेगा स्वाभाविक है चन्दा उसी के पास जाएगा और सता में न रहे तो उसके पास चन्दा नहीं भ्राएगा. यह भी स्वामाविक बात है । प्राज सत्ता में नहीं रहे इसलिए शिकायत हो तो बात अलग है। लेकिन सवाल जैसे राय जी ने कहा, यह है कि इसकी बुनियाद में हमें जाना होगा। बुनियादी बात के लिए भाप क्या करना बाहते हैं। कोई नया सिस्टम निकालने वाले हैं जर्मनी में जैसे है कि गवर्नमेंट सारा खर्चा इलेक्शन का करती है बैसे होगा ? क्या ऐसा सिस्टम धाप सुझा रहे है ? मैं समझता हूं कि यहां वह हो नहीं सकता है। जब तक इस देश में जो प्राधिक लाज है, जो प्रार्थिक व्यवस्था है, जो पूंजीबाद पर प्राधारित है उसके रहते काला धन बेहिसाब बढ़ता जा रहा है....(व्यवधान) लाल पगड़ी वाले की समझ भाएगी यह बात । वह समाजवादी हैं । हमारे तायी रहे हैं और वह इस बात को जानते हैं। जितनी पूंजी जमा होती जाती है चन्च कोगों के डाय में, देश की मेहनत से निर्मित हुई पूंजी जब

बन्द लोगों के हाथ में एकलित हो तो वहां काला धन भी पैदा होता हैं। ऐसी अर्थ स्ववस्था में धाप बाहें हुछ कर लें तो हुछ नहीं हो सकेया। के किया प्रथ सचा होगी तो उसका उपयोग या दुरुपयोग राजनीति को दबाने के लिए कंट्रोल में लाने के लिए किया हो जाएगा। यह हुकीकत है, यह वस्तुस्थित है। धाप धीर हम इसकी बबलने के लिए काज भी तैयार नहीं हैं। जो विस्टा इटरेस्ट हैं उनको बहम करने के लिए तैयार नहीं हैं। अप्यान्य सवालों पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। होता क्या है? हम धापकी बौर धाप हमारी टोपी उछानने की कोशिश करते हैं। इस कान्ति भाई को गालियां दे देते हैं। यह क्या है। इसीर धाप संजय को गालियां दे देते हैं। यह क्या है। इरा धाप संजय को गालियां दे देते हैं। यह क्या है। इरा धाप संजय को गालियां दे देते हैं। यह क्या है। इरा धाप संजय को गालियां दे देते हैं। यह क्या है। इरा धाप संजय को गालियां दे देते हैं। यह क्या है।

भी सौगत राम (बैरकपुर) 1 दोनों में मेलजोल हो गया है।

भी बलक्त साठे : यही बात बलेगी और इसमें आपकों सन्तीय है मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने नाह कमीका बैठाया । साठ केसिस सजय गांधी पर बलाए । तेरह केसिस इदिरा जी पर बलाए, मिसपुज बाफ पावर, कुरफान इन हाई धाफिम । पर जब दूनरे का बेटा हो तो खराब, धपना बेटा हो तो खराब, धपना बेटा हो तो ललवा । उसके नाम से बोलो मत, वह दूब का धुना हुआ है, साफ है, वह कोई बदबलन नहीं है, उसकी बात न करो, वह कुरफान नहीं करता है बेकिन दूसरे में सभी बुराइयां हैं । इससे मामला निपटेगा नहीं । मैं आपसे पूछना बाहता है कि क्या आपने इस पर गम्भीरता से विचार किया है है

17 03 hrs.

[DR. Sushila NAYAR in the Chair] प्रर्थ व्यवस्था के बारे में कोई बोलता है क्या ? भाप भौर हम किसी को भी शायद उसकी फुरसत नहीं है। जब से बाप सत्ता में बाए हैं मुझे बनाइयें कभी ऐसी चर्चा, कभी ऐसी बेठक हुई है कि बुदियादी परिवर्तन भाषिक होने में हम कैसे लाए भीर भाग हमें चुनौती दें कि चलिये बुनियादी परिवर्तन लाना है, ये जो वैस्टिड इटरेंट्स हैं, कपिटलिज्य के जो गढ़ हैं, जो जम कर बैठ गए हैं सीने पर इस देश के इनको खत्म करना है, बलो यह हमारा प्रोग्राम है जिसको बेलेंज सम-शना चाहिये और प्राप्तो इस प्रोग्राम को चलाएं। कोई बात हुई ? इस बात पर चर्चा नहीं होगी। इस बात पर प्रापको भी फुर्सत नहीं है क्योंकि थाप उन्हें धनका नहीं लगा सकते । वेस्टेड इटरेट्स हैं, 20 हजार करोड़ ब्लेंक मनी जिनके कब्जे में है और वह भी दो, तीन हजार लोगों के हाय में हो तो वह किसे इस देश में नहीं खरीद सकते हैं ? सारी टीप ब्यूरोजेली उनसे मिली हुई है। साप बताइये सीने पर हाथ रख कर कोई मेम्बर पालियामेंट कह दे क्या एक एम० पी० का भूगाब 35,000 रु में होता है ? नहीं । फिर् कहां से भाता है पैसा जो लाख, सबा लाख वर्ष होता है, यह पैसा कहां से भाता है वही भाता है जो कांति भाई ने जमा किया । उनकी जी 80

लाख ६० मिला, प्रापने तो सूबेनियर कलेक्सन जो कांग्रेस का हुमा, उस सम्बन्ध में 180 लोगों के नाम भापने गिनाये भौर उस पर कार्यवाही भी की, नौटिस दिये गये कम्पनियों को । 80 लाख जिन लोगों से बाया उनकी भी लिस्ट दे दी। जए धीर उनके अपर भी नोटिस दीजिये। लेकिन नहीं देंगे भ्राप, क्योंकि सी० बी० गुप्ता साहब कहते हैं कि उसने मझे पूरा हिमाब दे दिया है। बौर जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने बन्दा कलेक्ट भी किया लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया । यह गुप्ता जी कह रहे थे । श्रव इनसे पूछिये कि उन्होंने 80 लाख हु० बिना मन्नी रहे, कैवल प्रधान मत्नी के पुत्र होने के नाते, इक्ट्ठा किया तो जो मंत्री हैं माननीय पटनायक या माननीय एव० एम० पटेल इनको कितना मिला होगा ? उसका हिसाब कोई बतायेगा पर वह बात भी नहीं होगी। मैं ग्रापसे कहना हूं फिर से गम्भीरता से विचार कीजिये।

हमारे कामत साहब को बाह कमीशन पर बोलते समय उनको एक ही बात मालूम है कि किम तरह से चरिल हनन इन्दिरा गांधी धौर उनके खानदान का किया जाय जिससे उनकी धाम्या संतृष्ट हो । हमारे बाकी के भी लोग हैं । भाषको याद होगा कि उन्होंने हमप्टी डम्प्टी लियरिक मृनाई थी....

भी हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : बह रेकार्ड पर है, टेप पर है ।

श्री बसल्स साठे: एक रिमरिक मैं भी इनको सुनाना चाहता हू भ्रापके बारे में, गौरीशंकर राय के बारे में:

मम जूठमलानी गौरी लाल, गौरीक्षंकर झौर कंवर लाल, झौर झाई० सी० एस० हरि, झाई० मी० एस० हरि विष्णु कामत,

Some jooth malani. Gauri, Lal, ICS Hari with much sound and fury; Signifying nothing.

Indira Gandhi they wanted to bury: Now they fret and fume in impotent rage at her renewed success and glory.

# श्रीहरि विद्युष काश्रतः जमानहीं ठीक ।

SHRI VASANT SATHE: Now, to report to the subjet under discussion, it is said that Kantibhai has nothing to do with politics, he is only a Private Secretary looking after his aged father. What does Kantibhai have to say about this? A German correspondent interviewed him and this is how the interview goes on.

The correspondent asks: "Well, how do you serve your father?".

Kantibhai: "Well, you see my father is very old and he needs to depend upon some one for decision-making."

Correspondent: "surely he can cunsult his Cabinet colleagues."

Kantibhai: "Yes, he consults them and they give their opinion. But I usually advice him on which opinion to take."

So, Madam Chairman, Kantibhai has no role at all!

द्रस्पात और खान मन्त्री (भी बीज पटनायक) । यह कहीं से पद रहे हो ?

था बसन्स साठे: German Magazine कांति भाई कांई रोल भवा नहीं करते वह तो केवल अवण कुमार की तरह पिता की सेवा में लगे हैं। में भापसे कहता हूं कि कोई दूध का धला नहीं है, कोई यह नहीं कहे कि holier than thou माप तो खाली करण्यत के दूतले हैं, मृटे की जो बूनियादी बात है, मैं भापकी माफेत कहूं तो सवाल का हल निकाला जा मकता है। नहीं तो वह तो हम रहे हैं कि भ्रष्टा मौका है, तून, मैं-मैं हो रही है। जूतम पैजार में लगे हैं और जब वकना भायों तो बन्वे के लिये हमारे पास सोंगे। वह जानते हैं, हंस रहे हैं, भापका मखील उड़ा रहे हैं।

ग्राप एक दूसरे पर कीवड़ उछाल रहे हैं। ग्राप इस भावना से सत देखिए, राजनीति वह रही है, पटरी पर से फिर से उतर रहीं है।

Our whole national debate is getting derailed on non-issues. Believe me, the biggest non-issue was Indira-baiting. Now it is coming home. It has started against each other in he Janata Party itself. This cancer will grow. I beg of you, I beg of who friends through you, Madam Chairman, to consider this issue in this larger perspective and gravity and approach it with that basic approach of removing the system which corrupts and which corrupts all individuals. And as long as that system prevails you cannot undo corruption by just passing this resolution or some law. Thank you very much for giving me this opportunity.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Madam Chairman, though the resolution expresses concern in the future of parliamentary democracy by the increasing role of money in elections but mainly the discussion is centering round charges of corruption against Kanti Desai. These two aspects I want to deal with separately.

I do not blame them because they are out to utilise every occasion to discredit the Janata Covernment and the Janata Party and to take maximum political advantage of it. My accusation is against the Janata Party and the government and Mr. Morarji Desai himself because the Prime Minister should not have given any scope. Wherever any charge of corruption

[Shri Samar Mukherjee]

comes and when it comes in a concrete form, he should have faced it with some form of inquiry. If, without that, the Prime Minister comes to defend the son, it links up the old tradition. Here a tradition has developed that sons and daughters of Prime Ministers and Chief Ministers have become the real reasons of the exist of the Prime Ministers and Chief Ministers from the scene of political life.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum) : That is why Bengal has always chosen the bachelors.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Now is the time for the Janata Party Govern-ment, the Janata Party as well as the Prime Minister to defend their image before the public life. They should come forward to have a probe on every case wherever any concrete charge of curruption comes and, if that charge is proved, the Prime Minister and the Government should take proper steps and fully dissociate with those actions and defend the integrity, honesty, purity of the party and the position the Prime Minister is holding. When again and again this type of complaints and charges come, they should be met with proper enquiries otherwise the entire attention of the House and the whole country will be engaged and diverted into those issues and only this will be a common talk before the public, while the government gave no time, no attention, to the basic problems of the people. Only these issues are getting primacy. That is why we told in the primary. Intal is why we told in the past also that whenever the question of the letters came up, we had told the Prime Minister to lay the letters on the table. Let the public see what is there in the letters. If there are charges, that should be subjected to be probed. Now, it has been declared by the Prime Minister that if there is a concrete charge and if any Member is prepared to give it in writing, 'I am prepared to forward it to the Judge of the Supreme Court.' I would urge upon the freinds here to give them in writing and offer to the Prime Minister the scope to test this declaration. Let him forward that to a Supreme Court judge and let it be probed. (Interruptions)

SHRI SAUGATA ROY: Whether it applies to the foreign transactions also?

SHRI SAMAR MUKHERIEE: That the judge will decide.

Madam, Chairman, whenever the friends bring these charges, they pose themselves as if they are the real fighters against corruptions. Look at their own background. They must be self-critical; they must be honest.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: The less said the better.

SAMAR MUKHERJEE: Before starting accusing others, their attendtion should be drawn to the issue of Blitz, last year, April 16, The whole headline is: 'Congress Looted Crores from State Bank'. It is alleged—I am reading.

"It is alleged, for example, that Varadachary personally carried Rs. 9 crores in tin boxes to Malda, from where former Banking Minister was contesting the Lok Sabha elections....

Shri Dinesh Joarder is here. He defated Shri Pranab Mukerjee.

".....as well as Rae Bareili and Amethi, Indira and Sanjay Gandhi's constituencies, and supervised the cash handouts to voters."

SHRLC, M. STEPHEN (IDUKKI): Shah Commission was there.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: No. please be self-critical. Don't absolve yourself of the responsibility. You never raised your voice against this type of curruption. (Interruptions)

My accusation is that you never raised your voice against corruption. Now you become the critics of corruption, thier-ruption). Lakhs are spent on posters.

### I quote:

"Two of the premier financing units, the State Bank of India and the LIC, were horribly muleted in a Mafia-like operation. Dissenting officials were sacked or transferred and the compliant or c's given undue promotions and ex-

After State Bank Chairman Talwar was brusquely edged out of the job, his seccessor T R Varadachary was forced to pull crores out of the Bank's funds to finance the Ruling party's election campaigns.

Insiders claim the money was collected from the banks' customers who were given generous overdrafts and forced to part with a substantial percentage of it on pain of withdrawal of all facilities in future. In the process the bank's till was severely drained.

To get an extension of service, Chairman Varadachary was further compelled to please the Banking Minister by giving huge advances to certain par-ties. In some cases the advances were handed over even before processing the documents, and in other cases before the signing of the agreements."

After the election were over they tried to regularise these in bad debts. There are other details also but I am not going into them. I simply want to draw the attention of the hon'ble Members who have now brought these accusations—I am not opposed to bringing accusations—if they are sincerely interested in fighting corruption then they must start from their own self. (Interraptions)

SHRI C. M. STEPHEN: Let us begin with the four GPI (M) Ministers against whom corruption charges were established by Commission of Enquiry instituted against them. (Interruptions)

SAMAR MUKHERIEE: Madam Chairman, I support Mr. Sathe in one respect that this very systemunder which we are living-is based on exploitation and for thirty years of Congress rule the rich have become richer and the poor have become poorer and there has been concentration of money and growth of monopoly houses. For this you cannot accuse Janata party government. But we accuse the Janata party government that they are pursuing the same policy. There has been no basic change in the policy of the Janata party government. Money is being concentrated in the hands of the few. What does the Directive Principle in the Constitution say ? It says that disparity should be reduced. But what is there is in actual practice. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. The disparity is growing day by day. Only last month the Reserve Hank reports revealed that the monopoly houses have carned nearly 50 per cent more profit in the years 1972 to 1975. The monopoly houses know that this government is providing through their policies the scope for earnings huge profit and, as such, they are interested to keep this govern-ment in power. They know so long as this government is in power their profit carning scope will remain intact. As the people at large are being exploited and so their dis-content is growing day by day. These monopoly houses know that it is becoming more and more difficult for the ruling party to get support and face the elections. That is why power, by using casteism, communalism and various other fradaulent methods.

Day by day, capitalism is faced with crisis. Day by day, money is concentrated in the hands of a few. Day by day these peonle's movements are growing. More and more, these big capitalist houses and the exploiting classes are bound to purchase the ministers and use them, and use their money power for influencing the voters. This is invitable in this system. That is why, when you

talk of removing corruption, we must keep this in mind. The Government has changed. But the State machinery has not changed. The entire bureacracy is there. You can change one officer from one department to another department. But he is bred in this atmosphere, where everybody has been forced to be corrupt. If any honest officer is there, he has to face punishment. By becoming honest, face punishment. By becoming honest, by refusing to become corrupt, he is pressurised, he is transferred or he is demoted. They are forced to become corrupt and they become part and parcel of the ruling machinery. That is why in this atmosphere you cannot expect that the entire administration will be free the entire administration will be free from corruption. That is why I say that higher political consciousness is necessary higher pointest constronsies is necessary and the entire people must be aroused to fight corruption. The consciouness of the people must be roused against corruption to curb the possibility of corruption spreading in other spheres. The level of the political consciousness of the people must be aroused higher. must get the feeling that mency cannot corrupt the people. The people of West Bengal have exhibited their political west beight nave exhibited their pointeau consciousness. They have correctly se-lected as to which party they should support; they have found out which are the parties which are the agents of are the parties which are the agents of the big business houses and who are the agents of the exploiters. They have proved that money cannot influence them, money cannot purchase wites. Although the bourgeois parties spent lakhs and lakhs of tupies, they found that their candidates had been defeated and the Left forces had wen, glaring example of West Bengal is there. Lakhs and lakhs of rupees were spent, but the people in the villages knew to whom they should vote. In the villeges landlords spent huge amounts of mency. But the peasantry has been intelligent enough. They decided "we will get the enough. They decided "we will get the money, but we will vote for our own selected candidates. These who wanted to influence the voters with miney see that even after spending so much money their candidates had been defeated. Then they will refuse to spend money in those areas in future.

So, what I say is that the consciousness must be roused, cooperation must be enlisted to system and to change this system. People's organisations must be organised and developed. Without this, there is no way out.

The Janata Party Government, inorder to keep thier image, must come ferward and order probe whenever there is any concrete charge of corruption, particularly if those corruption charges are in crunection with any relation of any Ministre-

### [Shri Samar Mukherice]

or in case of any relation of any Prime Minister. Otherwise, with the experience of 31 years, people automatically take it for granted that, even after the Prime Minister denying it, that man is linked with corruption. That impression you cannot remove from their mind. If there is a probe, that probe can prove that certain charges are baseless. If it is proved that the charges are valid, then the strictest punishment must be awarded to them. Then the image of the Prime Minister will become more heightened in the eyes of the peole. Then only he will be a capable of leading this Governm nt and the people of the country to fight corruption. Then only his words will carry weight with the people. Otherwise, his words will never carry weight with the people. That is why we are inisting that corruption must be fought ruthlessly. The Janata Party has given pledges to the people before elec-tions that they will fight corruption upto So, I demand that they must come forward with this proposal: Whenever there is any corruption charge against any Minister or any relative of a Minister, they must immediately order a probe, ter, they in ist immediately order a probe. They must place before the country the results of such a probe. That alone will heighten the image of the Janata Government. Otherwise, looking at the way you are fighting among yourselves, you will also have to face the same future which the Congress had to face. That is why I give you a most serious warning that you must re-think and remodel and reorient your entire method of functioning.

With these words, Madam Chairman, I would tell the Houe that the question of fighting corruption should be taken up seriously and due weightage must be given to the various points made by me.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Chairman, after hearing the mutual recrimination from both sides and after so many stinking skeletons have come out of the cupboard. I think, no persuasion would be required on my part for the House to accept a very constructive suggestion which I have put forward in the shape of my amendment. In my amendment, I have said:

#### "add at the end-

'and recommends to the Government to bring forward expeditionally legislation by which all political parties in the country should be registered under the Registration of Societies Act, 1860 (as awended up-to-date) and should maintain accounts of all their receipts revealing their sources and expenditure supported by stamped vouchers and publish annually a statement of receipts and expenditures duly audited and

certified by a a chartered accountant which should be published in the Gazette of the Government of Inda."

There would be no two opinions that it is a matter of great concern that these are undemocratic intrusions which have been susceptible to pernicious influences. It is said that in some countries power flows through the barrel of the gun, but in this country, we know that power flows through money bags during elections. The poverty and ignorance of the voters are fully exploited. After the elections, they start engineering defections, indulging in political horse trading and in forming minority Governments. In my thirty years of active political life in every case, I know that while submitting my election expenses return, I have submitted a false return. I admit this myself and it must be true in the case of every Member in this House.

Money and politics are two sides of the same coin in this country. In last September, the Government released of 180 companies, who had paid Rs. one lakh and above for advertisments in the souvenirs of the political party then in power. We would also like to know the quantum of money collected from the warious sources, along with the sources, by the present ruling party in this country. Money and politics have always have a adulterous relationship; it is illegal and exciting. Despite various picus statements moraility, politicians do take full of money from rich people and from the various companies, and in return they promise them favours. Most of the money flows from the unaccounted black money and this money is syphoned to the coffers of the political parties in a very clandestine way and under the table. In this House, there has been a debate in the past how the CIA and KGB mency has played its role in patronising the various political parties having clandestine relationship either with CIA or KGB.

In this regard, I take this opportunity to quote a few lines from the latest book "Rescue Democracy from Moncy-Power" by Shri Rajagopalachari. It is a compilation of the vaious articles written by late Rajaji in "Swarajya". And the Foreword to this book has been written by no less a person than Shri Jayaprakash Narain; and JP says:

"One who weighed every word he uttered or wrote, Rajaji was a relentless campainger for rescuing our democracy from the corrosive influence of money-power and its evil brood. As I went through his collected writings on the subject, I could not help admiring his

310

far-sightedness, absolute sincerity. depth and courage of conviction and total devotion to national welfare.

No truth gains currency when it is first propounded and no prophet has been spared of initial calumny and disparagement. Similar was the fate of Rajaji when he set face sternly against the conventional politics of election-winning and pursuit of pelf and power. At the time when Rajaji wrote these articles, they did not evoke the response they deserved. This was perhaps due to the then prevalent all-pervasive charisma of Pandit Nehru and the blinding force of unshared power and the all-round subservience and sycophancy it generates.

But to-day, both Jawaharlalji and Rajaji have left the scene. The nation itself has just regained its freedom from despotic rule, about the advent of which Rajaji had clear forebodings and of which he had given ample, timely and unambiguous warnings. Against this setting, today his writings acquire a new dimension and significance and call for fresh in-depth study.

His words are words of wisdom. the plant of parliamentary democracy is not merely to survive but thrive on our soil, it is imperative to create a corruption-free and congenial climate for it till the top roots go deep into the soil." And then he mentions how it is essential that politics in this country should be freed from the influence of money. I had, in this regard, tabled a non-official Bill identical to the amendments which I have given here; and in this regard, I sent a copy of it to some persons who had taken interest in this matter. And Mr. K. Santhanam who presided over the Anti-Corruption Committee has written to me thus:

Mylapore, Madras

"Dear Shri P. K. Deo,

Thank you for the copies of the two Bills sought to be introduced by you in the Lok Sabha. Both of them are important. I would however like that in the Bill for Registration of Political Parties and Publication of their accounts, you had provided for the maintenance members' list and the constitution of the party, including the executive authorties and procedure for changing the Constitution. You may table amendments for the purpose.

I wish you success in your brave attempt. With kind regards,

> Yours sincerely. K. Santhnaam".

Similarly, many messages have come from all over the country. I do not want to take the time of the House; but if the Government and the Opposition are anxious to have a permanent solution to this problem of corruption and to root it out from the body politic of the country, I think they should gladly accept the amendments I have suggested to the Motion so ably moved by my friend Mr. Unnikrishnan.

भी राज नारायस: (राय बरेली): मैं एक परसनल स्टेटमेंट देना चाहता हू ।

MR. CHAIRMAN: देखिये, राज नारायण जी, Direction 115C says:

"No member shall be permitted to make a statement by way of personal explanation under rule 357 unless a copy thereof has been submitted in wirting by the member to the Speaker sufficiently in advance and the Speaker has approved it. Words, phrases and expressions which are not in the statement approved by Speaker, if spoken, shall not form part of the proceedings of the House. मैं तो यहां भी नहीं। उन्नीकृष्णन साहब ने कुछ कहा, ऐसा धापको बताया गया । उनके कहने के बाद द्यापको घगर परसनस एक्सप्लेनेशन देना है तो बोड़ा सा लिख कर भेज दें कि क्या एक्सप्लेनेशन वेना है। उसके बाद द्यापको धवसर मिल जाएगा।

चौधरी बलबीर सिंह : प्रेसीडेंट है कि जब कोई बोला है उसके बाद जिस के बारे में कहा गया है उसने परसनस एक्सप्लेनेशन दिया है।

**भी राज नारायशः :** मैं जानता हं नया नियम है। भव तक के कनवेंशन के बिल्कुल विरुद्ध भापकी बोत है। मैं खुद इस सदन में कई बार परसनल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। कल ही जब उपाध्यक्ष बैठे हुए ये तो एक विषय भाषा या जिस में उन्होंने मझे स्थक्तिगत स्पष्टीकरण करने को कहा था और मुझे उसका मौका दिया था। मैंने स्पष्टीकरण दिया था। स्पीकर ने भी कई बार दिया है। सभी को दिया है। जो चीज हैपंच इन दी ग्राइज ग्राफ दी हाउस इमिडिएटली उसका एक्सप्लेनेशन उसी समय दिया जाता है। भगर कोई चीज ऐसी हो जो बाहर की हो किसी लेख पर ग्राश्वित हो उसके बारे में लिख कर दिया जा सकता है। श्रीकेन यहां भामने सामने की बात है। उन्नीकृष्णन साहब मिले हैं उन्होंने बताया है, दूसरों ने भी बताया है कि उन्होंने यह कहा है। मैंने फौरन जा कर श्री चित्रागंद सिंह को फोन किया है। मैंने उन से भीर श्री छन्नसाल से बात की है---

SHRIK. GOPAL (Karur): I am on a point of order. Mr. Unnikrishnan, [ Shri K. Gopal ]

311

in his speech, nowhere has he mentioned about Mr. Raj Narain; he only mentioned about his Private Secretary. Members cannot come before this House on behalf of their Private Secretaries.

भी राज नारायण: मैं इतना ही कह देना चाहता हं कि श्री चित्रागंद मिह ग्रीर विक्वायत्तन योगाश्रम के जो डायरेक्टर हैं श्री छत्रसाल सिंह जी उन्होंने कहा है कि जिस सदस्य ने यह कहा कि यहां से कारपेट्स ले जाये गए हैं वह बिल्कुल धसस्य है, निराधारे है, बेबुनियाद है, सूठ है भौर अनुरोध है कि आ कर लाग बक की देख लें कि क्या सामान गया है स्रौर क्या नहीं गया **8** 1

मैं समझता था कि हमारे मित्र सज्जन हैं भीर बिना इनक्वायरी किए हुए, जांच किए हुए भक्छी तरह से किसी बात को बोर्लेंगे नहीं। मैं इंके की चोट पर कहना चाहता है कि इस तरह से असत्य आरोप लगाना बहुत असचित है। जो भादमी सदन में नहीं है उसके बिरुट इस नरह से आरोप लगाना संसदीय परम्परा के विपरीन 8 1

मन मर्लान तन मुन्दर ऐसे। विष रम भरा करके घट जैसे ।।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Do not pretend . He pretends to be an angel.

MR. CHAIRMAN: I must say that it is not right.

श्री राज नारायण : मैं कल लिख कर भी दै दंगा। प्रव तो हो ही गया है।

समाक्ति महोदय : अगर आप यहां बैठे होते श्रीर कोई माननीय सदस्य बोलना, ग्रीर ग्राप सुरन्त उठ कर एक्सप्लेनेशन देते तो बात समझ में धा सकती थी। ब्रव तो कंट्रीवर्सी हो गई है। वह कहते हैं कि भाषका नाम ही नहीं लिया गया है, भाषके लिए कछ कहा ही नहीं गया। ऐसी परिस्थित में उचित यही होगा कि को भी कहा गया है उसके बारे में प्राप स्पीकर को लिख कर दे देवें। जो उन्होंने कहा है वह रिकार्ड में या गया है। साप जब लिख कर देंगे तो उसको देख कर श्रापकी क्पीकर माहब इजाजन दे सकते हैं।

भी राज नारायण प्रभी नो जो कहना या मैंने कह दिया है। प्रापकी ग्राका निरोधार्य करता है। कल जो बाप ने कहा है मैं लिख कर दे दुंगा। याज जिनना कहना था मैंने कह दिवा 8 1

वन मलीन तन मृत्दर ऐसे विष रम भरा कनक घट जैसे।।

SHRI KRISHAN KANT (CHANDI-GARH) : Mr. Chairm n, I am than ful

to you that after all you thought of calling me. There is a general practice that one Member from the Opposition and one from the Ruling Party should speak. But, this time, probably the rule was changed to accommodate the Opposition.

I am grateful to the mover of the Resolution that he tried to raise the level of the debate by changing the motion from individual corruption to the general individual corruption to the general approach to the problems of power politics and money politics.

The Resolution says :

"This House is of the opinion that increasing play of money power in elections pose grave threat to the future of Parliamentary Democracy as evidenced by the recent revelations of collection.."

The first part really points to the malady. What is to be sorted out has been mentioned by Mr. Unnikeishnan. But, he confined himself to citing a few cases, and did not attack the problem as a whole. He refers to the recent weeks and months. What about the present and what about the future? This is not a new thing. When Dr. Rajendra Prasad retired as President, he gave a valedictory address in the Central Hall. In that he referred to the money power and he said that money power was taking over, was taking hold of politics in India and unless something was done about that, the elections would become a farce and altimately power will go into the hands of those who have money power as well as physical power. Babu Purushottam Das Tandon addressed the Lok Sabha and he referred to the danger of money power taking over the politics in India. So, it is not a new thing. We have not learnt the lessons. While Mr. Unnikrishnan was speaking, I was expecting that he would refer to the perspective, to the whole problem and say how things could be solved. refreshing to hear Shri Unnikrishnan. and I hope, he will not mind if I refer to the AICC meeting. I wrote a letter against black money power and I pointed out how black money was taking over, how black economy was leading to black politics. I am referring to what was happening in the Congress and then some friends challenged me. ... (Interruptions). I do not want to name any friends, It was done first in the Delhi AICC and secondly, the same question was referred to in the Gandhinagar session. When I said that some delegates had told me that the price of sugar was increased because we took money from the sugar barons, thirtytwo Members of the Congress Party spoke against me as if I was talking blasphemy. It is refreshing to note now, I will be glad if he joins in the crusade for the total

eradication of black money and black money power. There is nexus between black money and black politicians, black bureaucrats and the black businessmen. Unless that nexus is broken nothing can be broken. And that starts, as he said, from the election processes. We have to examine whether by merely attacking balck money and black politicians we can eradicate the whole nexus and really remove the black money from the country Kindly analyse the situation. At that time in the Congress Party I was referring to certain figures and I wrote three articles in the Hindustan Times on black money electoral reforms. I had power and calculated this on the basis of my Haryana experience, a Lok Sabha constituency and 9 assembly constituencies. If you give two jeeps in every constituency, it means 18 jeeps; one jeep for the candidate and one jeep for the election agent-that comes to 20 jeeps. The rate of hiring a jeep is Rs. 150 per day; it means Rs. 3000 per day for 20 jeeps. If you calculate petrol at the rate of Rs. 100 per jeep, it means the expenditure is 2000; the total is 5000. For thirty days the expenditure is Rs. 1.5 lakhs. That is the minimum. There is no black money involved; there is no corruption, nothing. Secondly, if we leave out the slips that you give, if you send them by post to each candidate, by 25 paise covers, it means 1.25 lakh for 5 lakh candidates. The total is Rs. 2.75 lakhs. I remember that when I read these two figures in the Congress, Shri V. B. Raju who was the General Secretary said that it cost a rupee per voter, it cost Rs. 5 lakhs. Are we not playing false to ourselves by putting it at 10,000 and 25,000. Even the Tarkunde Committee which J. P. had appointed referred to 35,000 and 50,000. Why deceive ourselves? Because we are deceiving ourselves, we are not true to the economy or true to the polity. If you want to remove it, some fundamental cure has to be done. Mr. Sathe spoke and criticised that the Janata Party has done this or that. He did not refer how the political system was utilised by Mrs. Gandhi in 1977. Rs. 9 crores worth advertisements were taken for the souvenir; most of them were not published. How was the administrative machinery utilised

TBE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAEE): They saved paper.

SHRI KRISHAN KANT: They made the Company Law Board issue a certificate that advertisements will not be considered as political donations. Secondly, they made the Central Board of Revenue to issue a certificate that all the advertisement expenses whould be allowed as deductions in the income tax. The list of donors to the Congress funds was seized on the Baroda Rayon and was

handed over by the investigating authority to Shri Mehta which was given to Shri Pranab Mukherjee and which went to Smt. Gandhi. I would like to knew from Shri Patel whether the list has come or not? Is it stil there?

Mr. Sathe was talking of those things, I am not talking of those things which are irrelevant.

Vimat Lal Commission is sitting there, looking to the excesses. It was given out on the basis of evidence that each candidate of Legislative Assembly was given a lakh or a lakh and a half. If that is the situation for an Assembly candidate—lakh or lakh and a half, which was given out by Vimat Lal Commission, then what about the Lok Sabha candidate? Unless we have a big thrust on the whole system of election, nothing is possible. I may like to reiterate those suggestions which I had given in 1974 and 1975 and had talked to Shri Jaya Prakash Narayan also. I said that the Tarkunde Commission recommendations will not do. What is happening to-day? The four curses of elections are—

- 1. Caste and community.
- 2. Communalism and religion.
- 3. Money.
- 4. Gunda power, muscle power which they contribute and those gundas survive according to Mahatma Gandhi enly on the protection of politicians.

If politician has to be purified, if politician has to be ennobled, then the basic attack has to be on the methods of election.

How can we make people based politics and not money politics? I had given two or three suggestions. May I urge the Government to consider that the elections should be held only after giving a notice of a week, not three weeks or four weeks. There is not office of the political parties in the villages, towns, talukas or anywhere. Any political party which has worked for a period of five years will be able to face election within a period of seven days and before one month no vehicle should be allowed. The workers of the political party which have worked for whole five years will go immediately and voting will be held. This has to be done if you want people based politics rather than money based politics. Secondly, if we want people based politics and the political parties to work then let us not have any inhibition on donations to political parties, whether by individuals or by companies and all of that, like Germany should be given income tax deduction, because we want to have the political system on the basis

#### [Shri Krishan Kant]

political parties. Let us not dupe orselves by closing the Company relations and we start the same donations in a much bigger amount under the table.

All the accounts of the political parties must be audited annually, not only the election account. If that is done, it will become easier to cleanse the politics. Black money starts from bad politics. If black economy has to be given a goby...

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Time is coming. I have to move for extension of time. I have to do it. This is time to do it.

I move for extension of time.

MR. CHAIRMAN: What is the wish of the House? Two hours are nearly over.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Four hours.

SEVERAL HON, MEMBERS: Four hours.

MR. CHAIRMAN: The House may sit till 7 O'clock and this will continue till 7 O'clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: No, viill 8 O'clock.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VERMA): Not later than 7 O'clock.

MR. CHAIRMAN: Not later than 7 O' lock. Is it the wish of the House that this debate be continued till 7 O'clock?

HON. MEMBERS: Yes. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: I have understood that the House wants to discuss this till 7 O'clock.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We can discuss it till 7 and continue it tomorrow.

MR. CHAIRMAN: It is for the House to decide. Probably it is for the Minister of Parliamentary Affairs to say whether he wants this to be concluded today?

SHRI RAVINDRA VARMA: Yes; this will be concluded today. The Business Advisory Committee had recommended 2 hours. But in view of the demand, one hour more may be given. More than that we are not willing today.

MR. CHAIRMAN: May I request hon. members not to waste time on this? Let everyone be brief and to the point. Let us try and see how much we can get through by 7 O'clock. Mr. Krishan Kant, please wind up.

SHRI KRISHAN KANT: Madam Indira Gandhi had institutionalised black money politics. I do not want to refer to instances, as Mr. Unnikrishnan has done, how files in the Commerce Ministry were sold for getting licences or how certain moneys that certain companies wanted to give were refused because she suspected that they were giving money to other parties also. She wanted to completely institutionalise the whole political system for herself.

What I am referring now is to the political malaise and how it is to be checked. I would like that this present debate should not end up having one against this man or that man or against this company or that company, but lift up the whole thing so that a situation is created where all political parties in this House will sit together and evolve a system where you can have clean politics, on the basis of which this democratic system was evolved, according to the dream of Gandhiji. Only then, we shall be able to buildup a system which will be a system of cleaner economy for the people and cleaner economy for the society.

MR. CHAIRMAN: Shri Chandrappan:

SHR1 A, BALA PAJANOR (Pondicherry): What is the procedure you are following?

MR. CHAIRMAN: I am calling the different groups one by one.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You have to call two members from this side and one from the opposition.

SHRI A. BALA PAJANOR: Even among the opposition parties, she is not following the order.

MR. CHAIRMAN: You sent your name much later.

SHRI A. BALA PAJANOR: That does not matter. You have to go according to the order.

MR. CHAIRMAN: All right. If you want to speak first, you may speak. Shri Pajanor.

### z800 hrs.

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry): Madam Chairman, as

usually mentioned by Members of Parliament when they rise to speak that they are happy to participate in the discussion, I am not happy to participate in this discussion for the simple reason that it is about a sad affairs. Secondly, I am happy to speak after Mr. Krishan Kant because he has pointed out a very important matter. It is more like a privilege issue that we always take in this House. Without any party barrier, it is to be discussed.

337

I was happy to see in the beginning when Mr. Unnikrishnan moved his motion. If you read the motion there are four particular points, to which he has referred. This House is in agreement with him about the money power in elections posing grave threat to the future of parliamentary democracy as evidenced by the recent revelations of collection of huge election funds by some important persons including Ministers and those who are in proximity to high offices of power and decision making.

Madam, I am not going to restrict myself to the people who have collected money in the recent past because when I go through the Indian history as far as collection of money is concerned, it is very much embedded. If you see the history of 30 years, I think, even 50 hours are not enough for this Parliament to mention the names of those people who were concerned with this. If my revered Sirend. Mr. Unnikrishnan has the occasion to go to the Library, he can collect the cuttings of the papers and find out this starting from the days of Mr. Nilalingappa.

श्री हुभल चन्द कछवाद (उज्जैन) : काला धन इनके पास नहीं होता तो तीस साल तक ये कांग्रेस के नोग नहीं टिकते।

SHR1 A. BALA PAJANOR: I can undertand Mr. Kachawai. It is a matter of deep concern for every one of us. Mr. Sathe and many other Members also mentioned this and they were concerned about it. (Internations)

MR. CHAIRMAN: Please continue. You have only ten minutes like everybody else.

SHRI A. BALA PAJANOR: It is a matter where we have to take serious note of. Since the Chairman is restricting my time, I take you to the Asian Drama by great Gunnar Myrdal. If you want to ask about my party, even before Lok Nayak J.P. Narayan, my Party leader and the present Chief Minister of Tamil Nadu rose against corruption within the Party. He is much against this. I do not think any person can come forward and say publicly that we are for corrup-

tion and for money power. But I want to put it very clearly that our Party has established to this country that without money also we can came to power. When our great leader, late Anna, started the Party, we were penniless and we were the party representing the poor and common people of this country. We fought against the great Congress which had big money bags, in those days. In one of the brilliant speeches in Tamil which I cannot correctly translate here. Anna said that we would make you one of the biggest money bags and the greatest industrialists of this country who sit on the top towers of this country and who come down to the common man's feet. That is our greatest achievement. We are not bothered about the number of seats that we are going to get in the Legislative Assembly. And that happened also. In 1967, the present Janata Party tried to dislodge the Congress Party but they could dislodge it in 1977. But they could not come to Tamil Nadu or Pondicherry because of the simple reason that we do not believe in money; we believe in the common people of this country. This is what I want to ask on this occasion. This money is collected for what reason? -to conduct elections as has been explained by many hon. Members. This money is utilised as expalained by Santhanam Committee as speed money, to speed up the matters for which they are lobbying. I am sorry to say that it is said about Members of Parliament also that some of them are being purchased by these money bags. That was mentioned in a very clever manner, in a covered manner by Shri Krishan Kant. There are certain lobbies—sugar lobby, jute lobby. They are able to purchase Members of Parlia-ment, Legislators to influence and direct the process to be followed up. Not only here but they are able to do it with burea-ucrats also. That is the weakness of the democratic system in this country. So, if we are going to find out a solutionit is interesting to have an academic exercise in this House by means of a motion by saying that we all condemn and this House takes serious note of it. And this resolution states that. The next moment we go in for it and only collect funds. But I see that there is a difference between the present and the past. From the ruling benches, whenever they speak, they refer to the past 27 years, but there is only one difference, because you are decentralised. Like four or five parties, in a decentralised manner, you are collecting, while it was centralised in the past. But the same offence is being committed in the same manner. So, don't distinguish between the present and the past.

As far as we are concerned, we are much against corruption. It is we who

319

### [Shri A Bala Pajaner]

started saying that corruption must go out of palities because otherwise it is impossible for the common man to come to the top. We make the commonest man the Mayor of Madeas for the first time, Prior to that it was the prerogative of the righes class only to seeupy the first chair of the city of Madras. Many other cities have subsequently followed it. We made a third rate fellow, according to the presentday polities the first citizen of the city of Madras, but instead of taking a lesson from that, you try conveniently to say that you will abolish denations by companies, you will amend the law etc. So many legislations have come, but nothing has happened.

As time is short, I will just read out certain passages so that they may go on record. It you take the report given by Gunnar Myrdal when the analyses the poverty of nations, especially in Southeast Asia, he says:

"When considering the prospects of reform in countries where corruption is so embedded in institutional and attitudinal remnants of traditional society and where almost everything that happens increases incentives and opportunities for personal gain, the public outcry against corruption must be regarded as a constructive force. This holds true even when this reaction is basically only the envy of people who themselves would not hesitate to engage in corrupt practices had they a chance, and even though the common awareness of corruption is apt to spread cynicism. As those people who can benefit personally from corrupt practices are a tiny minority, the public outcry against corruption should support a government intent on serious reforms. What the people-and the outside observergenerally demand is punishment of the offenders. Resentment stems especially from the belief that ministers and high officials go unpunished."

I think that is the main outcry now.

I am well aware of the fact that then is a lot of character assassination. I am in agreement with the Prime Minister when he says that whenever he is in power, they talk bout these things, and the moment he is not in power they stop talking about them. If they were sincere, they would have taken it up even earlier. This is character assassination and so I am not prepared to associate myself with it.

But if you take ocrruption in general, see what the Santhanam Committee has said. You read the report. It has been there for such a long time. I do not know why the previous Government did not take note of it, and I cannot under-

stand why the present Government is also not taking note of it. Please permit me to read this passage at least:

"It is believed that the procedures and practices in the working of Government offices are cumbersome and dilatory. The anxiety to aviod delay has encouraged the growth of dishenest practices like the system of speed money. 'Speed money' is reported to have become a fairly common type of currupt practice particularly in matters relating to grant of licences, permits, etc., Generally, the bribe giver does not wish, in these cases, to get anything done unlawfully, but wants to speed up the process of the movement of files and communications relating to decisions. Certain sections of the staff concerned are reported to have got into the habit of not doing anything in the matter till they are suitably persuaded. It was stated by a Secretary that even after an order had been passed, the fact of the passing of such order is not communicated to the person concerned and the order itself is kept back till the unfortunate applicant has paid appropriate gratification to the subordinate concerned. Besides being a most objectionable corrupt practice, custom of speed money has become one of the most serious causes of delay and inefficiency."

This is the crux of the problem. You require money to speed up the files, to get decisions you require money. The quantum of money is the only consideration whether it is Rs. 10 or Rs. 10 lakhs or Rs. 10 crores. I am not referring to any particular person or Minister of the past or the present. For a poor man, to part with Rs. 10 may be something; for a rich man, to part with Rs. 10 may be something. The Finance Minister deals with crores of rupees. So, this is a very serious matter. This House should take it up as a matter of privilege, but sometimes we do not take up even matters of privilege in the proper spirit. But if you take up the matter, I am sure we can get out of it. I am happy that Mr. Unnikrishnan and Mr. Vayalar Ravi have brought this motion in this House so that the country will know that we are also serious about it and the country will be grateful to us and will keep us in this House without sending us out if we are sincere about it and execute it.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Chairman Madam, I move an amendment, rather s a substitute motion to the motion mentioned in the Order Paper, listed as amendment No. 4. My amendment to the motion is as follows:

"The House expresses its grave concern over the fact that the electoral

process as well as public life in India which was badly pulluted and vitated by an unholy alliance of political power and money power during the decadent decade, 1967—76, with its steep erosion of ethical standards and moral values, threatened to distort democracy into a plutocracy, deform 'Janatantra' into 'Dhanatantra', recognises the imperative need to reverse those morbid trends, is convinced that for the purpose the formulation of a voluntary code of conduct by all political parties is essential and urges the Government to initiate, without delay, comprehensive measures with a veiw to cleansing public life in general and purifying the electoral process in particular."

This, Chairman Madam, I submit is a major amendment in substance and I would crave the indulgence of the House and yours too, to speak at some length, but not at great length.

MR. CHAIRMAN: I am afraid I can't give you more than to minutes and you have taken three minutes already in reading your amendment.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I have to read it. If I don't read it, how can I convince the House? You make it 15 minutes.

SHRI SHANKAR DEV: Madam Chairman, our Party Members are also there to speak.

MR. CHAIRMAN: Please continue Mr. Kamath.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Now, Chairman Madam, I am sorry to say that though my friend, Mr. Unnikishnan, has brough a motion of some importance before the House, yet the main thrust of his argument was with regard to collection of election funds recently, and particularly he mentioned the name of Shri Kanti Desai. I am afraid that Shri Kanti Desai has occupied more of parliamentary time during this Session than perhaps any other single person in the country. Both the Houses together, the Rajya Sabha and the Lok Sabha, have taken more time in discussing Shri Kanti Desai's activities at various places than they have in discussing any other person in this House. It should not have been so because the hon. Speaker, when the issue was raised in the House last Tuesday, a week ago, gave a clear ruling. I am sorry that has been overlooked in this discussion. The Speaker said :

"The collection of funds for political purposes by those in power as well as those near the seat of power is likely to give rise to suspicion that there might have been misuse of official power or position. This is a political question.

Solution to such issues must be found either by enacting necessary laws or by developing appropriate conventious. This is not a matter for me."

Nor was it a matter for an adjournment motion.

Madam Chairman, I have followed the line laid down by the Speaker and, as suggested, the Government must come forward without delay to enact measures for cleansing public life in general and purifying the electoral processes in particular.

My hon friend, Shri Sathe, he has again fled. On the 12th of this month, earlier, he had fled. He makes, I suppose, a good job of it. Because, he himself said onceit was his own words—once a coward, always a coward. He said it last time, and he follows to the letter and also to the spirit, his own words. Now he is, if I may say so, a beknighted knight, in shoddy armour, of Her Extinguished Majesty, and he is not present here. Both he and his leader are absent. Though his leader has been given the status of the Leader of the Opposition, de jure Leader of the Opposition, more often than not de facte he is a misleader of the opposition. And the second in command, as I have already said, has made it a profession or vocation of fleeting the battle-field at the nick of time. He did it once and he has done it again. It is for him to consider, to decide, to mend his ways.

Now I do not wish to go into all the lurid details not merely of the elections, but of every form of corruption, because corruption is a hydra-headed monster, which has been indulged in by the Congress Governments for over 30 years. There is a saying in Hindi or Urdu, I hope I am right in saying it,

## सौ सौ पृहे बाय बिल्ली हज को चली।

That applies in totality, entirety to our friends of the Opposition.

In 1971 and in 1977, and in the previous four years 1967 to 1971 during the famous or notorious era of Ayarams and Gayarams, money had to be found to inance the buying and selling on the exchange of the Legislatures at the Centre and the States; I do not know I do not wish to go into it, but money was found for that also. Be that as it may, in 1971, I remember, because some of the Congress candidates in Maharashtra and Madhya Pradesh had told me personally, that each of them, many of them, had received at least Rs. 2 lakhs to 3 lakhs. Out of that, some of the more enterprising once kept something for the rainy day, and did not utilise it, use if for election purposes.

## [Shri Hari Vishnu Kamath]

They did not mind losing and some of them lost. They used it perhaps for their own other purpose. In 1977 also the same thing happend. And the money found for these elections perhaps rained from heaven. According to some of the members of the opposition only money collected by the Janata Party and Janata Party agent came from some fishy sources, but all the money that came for the Congress Party candidates for the elections in 1971 and 1977 must have come from God himself, rained like manna from heaven. He need not go into how the money was collected.

My hon. collegue, now a Minister here, a former party collegue, Mr. Dandavate,—I was not in Parliament then in the fifth Lok Sabha, I believe, he made a charge against one of the Congress Leaders saying that money was collected by that leader, who was then a Minister of the Governmnt, but was not accounted for and only a very small portion was paid to the Congress Party and the rest was retained byhim and Shri Dandavate challenged the Government on the floor of the House to institute in inquiry No, inquiry was instituted, only that Minister was 10 tincluded in the Cabinet and he was made a Governor and sent to one of the States.

You are very well aware and the House is very well aware as to how and in what manner money from the nationalised banks, some of the nationalised banks was siphoned off for Maruti Ltd. I believe some of it has come in the Shah Commission's Report, more could be said, much more could be written about this. But since you are ringing the bell, I do not think I can continue for long. But I wish to refer to one or two salient points before I conclude, I have to conclude. Otherwise, I had a number of points, and I could have gone into all this at some length to prove that democracy was dis-torted into a plutocracy during those years and now if there is anything at all, it is a hangover from the past, from those years, from thirty years. Hangovers cannot be cured, cannot be got rid of so soon. (Interruptions).

SHRI A. C. GEORGE: Hangover cannot be passed on to somebody else.

SHRI HARI VISHNU KAMATH:
There is a saying that

## कराब का नक्षा उतर जाता है लेकिन सत्ता का नक्षा अकृता जाता है और ने कर बूबता है।

That is what happened to them. Now they are coming in the House with stories about the collection of funds by an individual or two or three individuals. As a matter of fact, the statemens attributed to certain

persons—Shri C.B. Gupta's name was mentioned here—they have been contradicted, denied and not authenticated, how they could be relied upon in this House as matters materially valid enough or good enough for a motion of this kind, I do not know, But, or course, I may make it clear that I do not hold any brief for anybody who is accused of corruption.

The Prime Minister has told the House plainly, he has told the country, the nation that if any specific charge is made against anyone, it will be referred to a against anyone, it will be referred to a Supreme Court Judge. My friend, Mr. Unnikrishnan referred to that. In the olden days, in the Third Lok Sabha when you, Madam Chairman, were also a Member of that Lok Sabha, the them Prime Miniser, Shri Jawaharlal Nehru referred to a Supreme Court Judge a specific charge made by the party to which I had then the honour to belong, the Praja Socialist Party, my colleague Shri Surendra Nath Dwivedi and myself, we brought home a charge and we have a specific instance about an entry in the documents, in the account books of Mr Serajuddin of Calcutta, we gave that and that was then referred to Mr. S.K. Das of Supreme Court informally; the report was not placed before the House, but Shri Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister asked the Minister the then Frime minister assection to quit the Cabinet. Who took him back into the Cabinet? His daughter, Shrimati Indira Gandhi. The daughter, whose father had expelled him from the Cabinet, that daughter took him back into her Cabinet. That is the sort of example they have set.

One word more and 1 have done. My hon, friend, Mr. Sathe, referring to my criticism of "Her Extinguished Majesty" on earlier occasions.

AN HON. MEMBER: Extinguished.

SHRI A.K. ROY: Who was the Minister, involved in that affair

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Pandit Keshv Dev Malaviya wasinvolved in that Serajuddin affair. He was expelled; he was asked to quit the Cabinet after the inquiry.

So, I would also ask my hon. friend, Mr. Unnikrishnan and his colleagues, the paries in he Opposition, to bring forward such specific instances. Then, I am sure the Government will not fight shy. The Government will be really prepared to refer those specific charges for an inquiry.

As regards the Motion as it stands, nobody will have any quarrel with that. What does it say? It say, "increasing play of money power" is detrimental to parliamentary democracy. Is there any question about that? The play of money power is derimental to the growth of a healthy parliamentary democracy.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I am concluding. Please don't be im-parient. I appeal to you to have a little more patience. We have patiently borne the Congress Government's misrule for 30 years. Now, at least for a few minutes more you can bear with me.

What is the operative part of the Motion? Please read it. I do hope, you have read it. Are you reading it just now? What does it say? It says :

> 'increasing play of money power in elections pose grave threat to the future of Parliamenary Democracy..."

MR. CHAIRMAN: You have read it once. Why do you want to read it again ?

SHRI HARI VISHNU KAMATH: It says "increasing glay of money power." It has been increasing, not now, and it went to a climax in 1971 and 1977. From the year 1977, the year of peaceful revolution, it has been showing a downward As fas as possible, we must eradicate this evil. I am sure, the House will agree with me that, human nature being what it is, all over the world, not India alone, there are many hues and colours of and corruption of many kinds, of all kinds, cannot be totally eradicated not only in India but anywhere in the world. All that you can do is to mini nise it, as far as it lies in human power. To that, our Government is committed; to that, our party is committed

Before I sit down, I would once again ask the absent mover-his deputies and colleagues are here-and I would ask them: they have not asked for an inquiry. An inquiry was asked for by Mr. Sathe on that day on which he fled. That does not arise now. I would ask them to make a concrete issue of this and not to leave it in vacuo, in the air. It says, "grave threat to the future or Parliamentary Democracy" and it, later on, says, "as evidence by the recent revela-tions". Have they made any demand or requestfor an inquiry into this matter? No. They are silent on that point.

I am sorry to say, this is an imporant motion, withut any legs to stand upon, without any heart, without any head, without anything at au-ilis a lifeless motion; it is a still-born motion. Therefore, I would like them to make it a live motion, a concrete motion, so that it can

be brought home to the Government. Otherwise, there is no alternative before the House but to accept my motion which I have moved already asking the Government, all political parties, that you I and all of us sit together and accept a code of conduct. That is my fervent appeal to all Parties, Let us evolve a voluntary code of conduct.

Achar Sanhita so that all Parties may honour that code of conduct and the Government should come forward with measures to cleanse the public life in general and purify the electoral process in particular.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandra-

श्री निर्मल सम्य भैन : सभापति महोदय, जिनके संशोधन हैं, उनको बोलने का समय मिलेगा क्या ? कुछ तो बोलिये, हां या ना।

की शक्रंप देव : हमने जो धर्मेंडमेंटस दिये है. तो मुवर को चांस मिलेगा या नहीं ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandrappan.

If you do no interrupt, we will accommodate two more speakers.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (Cannanore): I am very happy that this motion gives us an opportunity to discuss the political corruption in our country. But I am sorry I cannot share the views expressed by some of our distinguished colleagues including Shri Krishan Kant who said that we should discuss it in a very academic fashion and that we should go to a higher plane. I cannot float with them in that higher plane because we are discussing this motion in the House in a definite context.

The Janata Party which came to power a few mounths ago in the year of revolution, as it was put by my esteemed friend, Shri H.V. Kamath, came with the slogan, 'We will remove corruption from public life.' That was one of your main slogans. And, to-day, we are witnessing a strange spectacle. It is not only kantibhai Desai but the father, Morarji Bhai Desai himself and the whole Janata Party have proved to be more currupt than any administration we ever had . (Interruptions)

भी हक्तन चन्द कछनाय: 'जनता पार्टी ने सब को करप्ट किया है," इन शब्दों को निकाला जाये।

समापति महोदयः देखिये, प्राप बैठ जाइये, जब शाप बोलें , शाप शपनी तरफ से उनको जबाब दे दीजिये। यह उनका प्रधिकार है, जो उनके मन में है वह बोलें। यह कोई भन-पालियामेंटरी नहीं है।

### [समापति महोवय]

को मापके मन में है, जब माप जवाब वें, तब कह जें। इस तरह से इन्टरप्ट न करें। इस तरह से कैसे काम हो सकता है ?

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: I do not know why they are shouting. Perhaps the shoe pinches. If the shoe pinches, then those who feel the pain of it, may get up....

MR. CHAIRMAN: Proceed with your speech. Do not waste your time.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: Please call the House to order. How can I speak in this way?

I am telling out of certain facts. There are certain facts to prove that. We in this House heard about it.

श्री हुकम चन्द कछवाय: ग्रापके दांत खाने के ग्रीर हैं, दिखाने के ग्रीर हैं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: I can shout better than you. You are a little bit older than me.

We have heard about Kantibhai Desai and his money collection. Not that I said it. The Treasurer of the Janata Party said that he authorised him to collect Rs. 90 lakhs. Not a matter of joke. He did not deny it.

When the whole world said that the Party is corrupt and the Prime Minister's name is in mud, an after-thought dawned on him and then he denied. We heard it from your leader, Shri Madhu Limaye, Secretary of the Janata Party who wrote that letter saying Rs. 90 lakhs but when he was asked in the Central Hall 'Do you confirm or deny?' he did not have the guts to say that 'I don't deny or confirm it'. (Interuptions) No more shoutings will help.

SHRI VAYALAR RAVI : Please keep quiet.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: What does it mean?

SHRI VAYALAR RAVI: If the Congress is corrupt, you are also corrupt.

SHRI A.K. ROY: They are corrupt, they are corrupt—we are not corrupt.

SHRICK CHANDRAPAN: Madam, Chairman, they are not allowing me. That time should not be counted against me.

What was the period in which these collections were made. What was they amount collected? They came in power after the last general election and the Assembly Elections. In three month's

time, Rs. 90 lakhs of rupees-in nienthy days Rs. 90 lakhs. For them one lakh does not matter. But it is on record. Here is the proceedings of the Rajya Sabha where one of the former ministers, who died—he became the President—the late Shri Fakhuddin Ali Ahmed is answering question No. 3812 on 13th August, 1968, gave certain figures of collection. (Interruptions) Why are you getting so much excited (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: May I request you all to let him proceed? Please continue, Mr. Chandrappan.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Madam, it says that within the period from 1st March 1962 to 20th February 1968 they compiled the figures, the money given by various companies to political parties, accounted money—unaccounted money is not included. It says:

"The Congress Party received Rs. 2,05,22,798."

The Congress stood very good. They were Number 1. Then came Shri H.M. Patel's party, the Swatantra Party at that time—

"Rs. 46 lakhs." (Interruptions)

Why are you reducing it to Rs. 20 lakhs. I am reading:

"46,02,563/-; then came Praja Socialist Party with Rs. 66,000/-."

Like that it goes on. What I am saying is (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please continue.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: How can I continue if so many people are interrupting me?

MR. CHAIRMAN: Do not take any notice of it. You continue your speech

SHRI CK. CHANDRAPPAN: I am continuing. I am trying not to listen to them (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please let him proceed. Don't waste the time of the House.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: The point which I am emphasising is that there is a corrupt system. I agree with those who said that a capitalist system is corrupt. The Leader of the Janata Party or Lok Nayak said that he would wipe out the corruption. The people changed their place. When they were sitting there, these Congreess people, when they were sitting there, these Congreess people, of the control of the contr

when the Janata Party is sitting there wearing the garbs of angels trying to flutter the Heaven, they could also collect and they even broke all the records. This is what I said. It is not the only story of this country (Instruptions) They collected Rs. go lakhs in go days. Madam, then comes the father. As a person, I do not like that our Prime Minister is known as the corrupt Prime Minister. This is not something to be proud of for any nation. But the Prime Minister is sitting silent. On his face we are asking everyday 'Did you write that letter?' Even to-day Shri H.M. Patel said that he wrote that letter to the Andhra Pradesh Chief Minister successively from Shri Vengal Rao to Dr. Chenna Reddy, asking for exempting the former Raja—Raja of Challappalli of 2,000 acres of land. So, the father is not better.

Madam Chairman, corruption is there. It is not a new thing. From 1961 onwards the country was worried about political corruption. In 1952 elections, 1957 elections, 1967 elections and in 1971 elections the capitalists were very cleaver. They knew whom they should butter. They knew whom they should butter. Here, with your permission, Madam Chairman I would like to quote a portion of what Mr. Tata said in his affidavit in a court in Bombay. In this case one of the share-holders of the Tata company had questioned the right of Tata company to change their Article of Association to enable them to donate Rs. 10 lakhs to Congress Party. He challenged it in a Bombay court and then Mr. Tata gave a very interesting affidavit in the court. He said that it was in the interest of the company that I gave donation. The share-holder said that my interest is not looked after by giving Rs. 10 lakhs. Mr. Tata said that you do not live in this world. It was to safeguard your interest and to enhance your profit that we are giving money to this party. And today these people are sitting on this side. I do not say that they are absolutely useless. But for practical purposes for Indian monopoly houses they are second in the list whereas Janata party is at the top and they will get anthing. It is only a question of stretching their hand.

AN HON, MEMBER : Are they not stretching?

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: They are. Otherwise how would you explain a man, who is not even a public man, who is only a businessman, Shri Kantishai Desai, can collect Rs. 90 lakhs in 90 days. It is because he is the son of the Prime Minister and he is living with the Prime Minister and he is the one—according to everybody—who advises the Prime Minister on important matters. So,

he has a price and the Indian capitalists are ready to pay that price and that is what is happening.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: While concluding, I must say that I am sorry I could not make the Janata benches so happy but I must tell the House one thing that those who came sixteen months ago—in the year of revolution—chanting a song about anti-corruption today we are seeing them sinking in the mire of corruption. They are standing in the dock in the other House. Let us not forget that. The other House is equally a part of Indian parlaimentary democracy. It has put the Janata party in the dock. (Interruptions)

It has asked them to appoint a parliamentary committee or a commission to probe into the corruption charges. It is a matter of shame that our Prime Minister went and said: You give in writing, if you have a definite allegation. I will send it to a judge. It is much bigger than what Indira Gandhi did when she flouted the Allahabad High Court judgement.

Then, Madam, it was expedient ..

MR. CHAIRMAN: Please resume your scat. I have called Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: It was then expedient for Mrs. Indira Gandhi to say 'I don't care for the Allbahad Judgment; the people are with me." But today what happens?

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Madam Chairman, by flouting the decision of the other House, Mr. Morarji Desai and his Government today stands in the dock of the people. If you want to remove poverty, to the extent it is possible under the present system, you have to bring about radical electoral reforms and there should be proportional representation.

MR. CHAIRMAN: How can it go on like this, if you take so much time? How will others get time?

SHRI C.K. CHANDRAPPAN: Madam, I have not taken so much time as some others have taken. There should be radical electoral reforms and proportional representation. Part of the essential part of the election expenditure should be borne by the State itself as was susggested by Shri Vajpayee when he was sitting here in the opposition. If that proposal is accepted, to the extent possible in our system today, we may succeeded in

[Shri C.K. Chandrappan]

331

rooting out corruption; but, so long as capitalism remains, corruption is also bound to remain in the body-politic of this country. Thank you.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: How will you manage? It is already 6.50. Mr. Unnikrishnan has to reply.

MR. CHAIRMAN: We will conclude by 7 O'clock today, and continue for one hour at 3.30 p.m. tomorrow. in which one or two speeches can be made and the Minister will reply and then Mr. Unnikirshnan will reply. It is not possible to extend the House after 7.00 p.m. today according to the hon. Minister.

श्री कंबर साल गुप्त : Please extend it up to 7.05 so that I may get sufficient time.

सभापति महोदय, जिस समस्या की तरफ उन्नीकृष्णन जी ने ध्यान दिलाया है वह समस्या बड़ी जटिल है। इस देश में चुनावों में पैसे का कितना प्रभाव होता है, इस चीज की धोर उन्होंने ध्यान दिलाया है। मैं समझता हु इसमें किसी पार्टी का सनाल नहीं है। मैं पूछना बाहता हूं कि यहां पर जितनी भी पार्टियां है, चाहे इस तरफ की या उस तरफ की, क्या इनमें से एक भी ऐसी कोई पार्टी है जो यह कह सके कि हमने चनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं किया? मैं इमान-दारी के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, माक्सिंस्ट पार्टी ही या कोई भी दूसरी पार्टी हो, कोई भी ऐसी पार्टी पार्टी नहीं है जो कह सकती हो कि हमने चुनाव में काले धन का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यह सवाल सारे देश का है और उसी स्तर पर इसको सुलझाना चाहिए। मेरा कहना है कि केवल भारत का ही सवाल नहीं है, जितनी भी डिमोकैटिक कंट्रीज हैं सभी में पैसे का प्रभाव बनावों पर होता है। धमरीका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, सभी जगह पर इसका प्रभाव होता है। लेकन भारत चंकि गरीब देश है इसलिए यहां पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन से यह नहीं मानता हूं कि केवल पैसे से चुनाव जीना जाता है। अगर पैसे से चुनाव जीता जाता, तो इन्दिरा जी की हार कभी नहीं होती। इन्दिरा जी के पास जितना पैसा था, उस के मुकाबले में जनता पार्टी जब पैदा ही नहीं हुई थी, उस समय कितनी जोर से उस की विजय हुई---इम का गर्य है कि केवल पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, उम के लिये जनता की सपोर्ट भी चाहिये, प्रोप्राम भी चाहिये, दूसरी चीजें भी चाहिये। सेकिन मैं इस बात की जरूर मानता हुं-- कि हमारे गरीब देश में पैसे का प्रभाव बहुत रहा है। शुरु से, 1947 से लेकर आज तक हमारे लोग इस के लिये कोशिश करते रहे । उन्होंने कम्पनीज के ऊपर पाबन्दी लगाई ताकि वे डोनेशन्ज म वे सकें, लेकिन जितनी कोशिश प्राजतक की गई. जिस का प्रभाव उल्टा

ही हुआ है। जितना प्रभाव काले धन का चुनाव के उत्तर पहले था, झाज उस से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि झव क्या होता है—में जितने बड़े-बड़े विग-विजनेस-हाउसेज हैं, इन की कम्मनियां यैसा नहीं ये सकती हैं, तब उन से कहा जाता है कि झण्डर-दि-टेबिल दे दीजिये और इस तरह से झण्डर-दि-टेबिल करोड़ों स्पया इक्ट्रा किया जाता है। उन को भी करण्ट किया जाता है, पार्टी को भी झाप को भी करण्ट किया जाता है, पार्टी को भी भी करण्ट किया जाता है, वर्कस को भी करण्ट किया जाता है और चरिल का हनन होता है।

इस लिये मैं कहंगा--मंत्री महोदय, भ्राप ने कंपनी ला में जो प्रावधान किया है कि कोई भी कंपनी पैसा नहीं दे सकती, इस के ऊपर दोबारा विचार करने की जरूरत है। मेरा सुझाव है कि इस पर दोबारा विचार कीजिये. इस को रीकन्सीडर कीजिये, इसको सैकेण्ड-बाट दीजिये और उस में एक मैक्सिमम लिमिट लागु कर दीजिये कि कंपनी 30 हजार या 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं दे सकती। लेकिन जो भ्राण्डर-विटेबिल पैसा दे, उस का प्रासीक्यमन होना चाहिये । लेकिन मैं यह भी कहना चाहता है कि यह चीज संभव नहीं है--जब तक पब्लिक-घोपीनियन ग्रीर पोलि-टीकल पार्टीज का ध्रपना कोड-ध्राफ-कण्डक्ट न हो। जब तक हम लोग मृद ठीक नहीं होंगे, नव तक इण्डस्टीयलिस्टम को दीव देने से कुछ नहीं होगा। उन को तो लाइमेंस लेना है, वे तो धाते ही रहेंगे भीर जैसा चन्द्रप्पन साहब ने भ्रभी कहा---जो पैसा टाटा ने दिया, उस से कई गुना ज्यादा उम ने ले लिया—वे तो पैसा देकर फायदा उठार्येंगे ही। इस लिये मेरा कहना है-अब तक कोड-धाफकण्डक्ट पोलिटीकल पार्टीज धपने लिये नहीं बनायेंगी, जब तक जनता में पोलिटीकल-कान्यसनेस नहीं होगी, तब तक इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। यह बीमारी बढ़ रही है ग्रीर तेजी संबद्ध रही है।

इस लिये मेरा सुझाव है--पोलिटीकल पार्टी बैठ कर तय करें कि मिनिस्टर-चाहे स्टेट के मिनिस्टर हों या सेन्टर के मिनिस्टर हों--कोई भी हों, उन को पार्टी के लिये बन्दा इकट्ठा नहीं करना चाहिये। इस तरह का नियम बनाना चाहिये भौर उस के बावजूद भी यदि कोई मंत्री इपट्ठा करे ग्रीर वह साबित हो जाय, तो उस को डिसमिस कर दिया जाना चाहिये। चाहे कोई भी हीं, मैं यह बात सब के लिये कह रहा हूं। मैं कोई मारोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यदि पश्लिक लाइफ को स्वच्छ करना है. यदि माप चाहते हैं कि पश्चिक-मैन के अपर लोगों का विश्वास बना रहेती यह जरूरी हैं कि कोई भी मंत्री पार्टी के लिये या किसी के लिये भी पैसा इकट्ठा न करे। मैं यह जानता हूं-पार्टी के नाम से पैसा पार्टी के लिये भी इकटठा होता है भीर द्मपने लिये भी इकटठा होता है।

दूसरी बीज, मैं जवाब नहीं देना चाहता---ग्रभी मेरे भाई बोल कर चले गये-हम ने स्लोगन लगाया था। टीक है हम में जरूर स्लोगन लगाया था-पश्चिक लाइफ में प्योरिटी लायेंगे। मैं पृछना चाहता हं--किस ने वह स्लीगम नहीं लगाया था, क्या भाष चाहते हैं कि पब्लिक लाइफ में प्योरिटी नहीं रहनी चाहिये ? अगर सबमब मं हमारे बारे में यह ख्याल है कि हम करण्ट हो बके हैं, तो जनता को हमें हटा देना चाहिये-इस में कोई दो रामे नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने स्थष्ट कह दिया है-मेरे परिवार के ऊपर या चरण सिंह जी के परिवार के ऊपर-धाज तो उबीकृष्णन जी में राजनारायण जी के बारे में भी कहा है, भें उन को भी उस में शामिल करता ह—या कोई ग्रीर हो, किसी के खिलाफ वह लिखित प्रमाण के साथ लिख कर दें तो एक्कवारी होनी चाहिये। कोई हो, इधर से हो, उधर से हो धगर कोई लिख कर के स्थेसिफिक चार्जिज दिये जाते हैं तो उसकी इंक्बायरी चीफ जस्टिस से हो । मैं समझता 🗦 कि इसके ग्रामे कोई गंजाइश महीं है। इस तेरह से ग्राप पोलिटिकल कंसीड्रेशन से कुछ भी कहते जाइये, राज्य सभा में दुहाई देते जाइये, मेरा कहना यह है इस सब की चीफ अस्टिम पर छोड दीजिए। किसी बार में भी यहां बोलने का जो हमारा प्रधिकार है, उसका मिसयुज नहीं होना चाहिये। प्राप बाहर बोलिये, लिख कर बीजिए ताकि दूध का दूध ग्रीर पानी का पानी सामने भा जाए।

सभापति महोदया, भेरा एक कंकीट मुझाव है कि इलेक्शन फाइमेंसिंग का सारा सिस्टम दिब्यू होता चाहिए। एक गरीब भादमी माज चुनाव नहीं लड़ सकता है, पालियामेंट का मेम्बर नहीं वन सकता है। मेरा सुझाव है इस के लिए एक पालियामेंट की कमेटी बनायी जाए।

The entire system of financing the elections should be reviewed; and that should be done by a parliamentary committee.

वह कमेटी इस पर विचार करें और सारी बातों पर विचार कर के वह अपनी रिपोर्ट मदन के सामने रखें। कोई वह कंकीट प्रपोजल सदन के सामने पेक करें।

दूसरी घोर सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो खर्च इलेक्शन में होना है उसका कृष्ठ हिस्सा वह बर्दाध्त करें। जब तक यह नहीं होगा, तब तक मं नहीं समझता कि कोई भी काम ीक हो सकता है या इसका प्रभाव कम हो यकता है।

सभापति महोदया, एक स्टेब्टरी प्रोविजन बनाया गया था कि दिल्ली में पालियामेंट का मेन्बर देस हजार बपये, किसी दूसरी जगह पर 35 हजार रुपये खर्च कर सकेगा । मैं समझता हूं कि इसको रीकंसीडर करना चाहिए । यह नहीं कि हस खर्च को बढ़ा कर दुगना कर दिया जाए या

तिगना कर दिया जाए । लेकिन मैं यह चाहता है 🐿 यह इतना भवश्य कर दिया जिससे कि इसका ठीक ठीक हिसाब दिया जा सके मैं कहता हूं यहां एक भी मादमी ऐसा नहीं ŧ जिसने कि अपना इलेक्शन रिटर्न ठीक से हो । फ़ोम टाप दूबोटम कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा । मैंने प्रपने इलेक्शन के सिलसिले में एक याजिका दी थी भीर मेरी याजिका पर फैसला होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी में कानन को ही बदल डाला । यह कर दिया कि पार्टी खर्चा करे. नेटा खर्चा करे. बाप खर्चा करे, वह उसमें शामिल नहीं माना जाएगा। केण्डीडेट जो खर्च करेगा, वही माना जाएगा । लेकिन दस हजार रुपये में पालियामेंट का **इलेक्शन** नहीं हो सकता हैं। इसके लिसे कोई संतोषजनक हल निकाला जाना चाहिए । प्रगर हम यह नहीं निकालते हैं तो इस प्रावधान को ही बदल देना चाहिए । पालियामेंट में घाने से पहले ही हमारे चरित्र का हनन हो जाता है, हमसे झूठ बुलवाया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए । इसके बारे में सर-कारध्यान दे।

सभापति महोदया, मैं पोलिटिकल पार्टीज के ब्राडिट के बारे में एक बिल लाया था । उस समय प्रापने कहा था कि पार्टियों के प्रकाउंट का भी ब्राडिट होगा । श्रब तक कांस्टीट्युएशन में पोलि-टिकल पोर्टी नाम की चीज नहीं है। अब एण्टी डिफेक्शन बिल के कारण से वह भी कांस्टी-ट्युशन में ब्रा रही है। इसलिए पोलिटिकल पार्टी ब के प्रकाउंट्स पर भी कंट्रोल होना चाहिए । धगर पांच हजार स्पए से ज्यादा किसी को दिया जाता है तो उसका नाम जनता के सामने भाना चाहिए । उस पार्टी का अकाउंट भी भाडिट कर के जनता के सामने रखा जाना चाहिए कि किसने उसे पैसा दिया, उसने किसको पैसा दिया ? कामध साहब ने जैसा कि कहा कि पार्टी वाले खुद पार्टी का पैसा खा जाते हैं। इससे वह चीज भी नहीं होगी भीर सब को पत लग जाएगा । भगर भाडिट होगा तो यह चीज पता लगेगी कि किस धकाउन्ट से पांच हजार रुपया भ्राया, उसका नाम 🛎 पता भी सामने था जाएगा । जो नहीं देता है उस पार्टी को चनाव नहीं लड़ने देना चाहिए । इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाना चाहिये।

19.00 hrs.

मैं इसको सीधा करण्याम का सवाल बनाना नहीं बाहता । केवल चुनाव में करण्यान का सवाल बनाना चाहता । है । जनरल करण्यान का सवाल इसको में नहीं बनाना चाहता । मेरे पास बहुत से इंटरिंसस हैं जिनको यहां रखा जा सकता है। बहुत गड़बड़ी हुई है जिसको झमी तक पकड़ा नहीं गया है। लोगों के पास इंदिरा गांधी का रुपया है जो पकड़ा नहीं गया है। उसमें कमजोरी हमारी सरकार की है। मैंने बित्त मंत्री को एक पत्न भी लिखा है। एक यूनिविस्ति का लड़का है उसके नाम से डेड करोड़ रुपया जमा हुमा पोस्टल सेविंग एकाउंट में। मेरे पास पत्न भी है जिसको में पढ़ देता हं।

# [की कंबर ताल गुप्ता]

335

"There are also a few suspicious deposits like those in the name of a Delhi student amounting to about Rs. 1.35 crores. It is evident that the student concerned did not have the means to make the deposits. Even if he had the resources, it is inconceivable that he could have deposited large funds in the post office for just a day or two."

This is dated 28th February, 1978 written by the Minister of State for Fianance.

यह जो पैसा है इसके बारे में मैंने बोबारा पत लिखा है धीर कहा है कि इसकी इक्लवायरी की जरूरत है। मिनिस्टर प्राफ स्टेट कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। मैंने वित्त मंत्री को लिखा है कि इक्लबायरी की जरूरत है। उनका उत्तर नहीं स्राया। इस तरह का एक प्रकाउंट नहीं है। एक साल में 24 करोड़ घरवा हरियाणा के पोस्ट धाफितिस में जमा हुधा है, एक ही हस्ते में मौर एक ही हस्ते में निकाल लिया गया है।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Who is the student?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I do not know. He is a student from Haryana.

MR. CHAIRMAN: Please conclude,

भी कंचर काल गुन्त : यह बेनामी नामों से हैं । मेरा कहना यह है कि यह सब पोलिटिकल पंता है। किस संती जी ने से रख का प्रभी तक नोई जलर नहीं दिया है। मैं कहना चाइता हूं कि इसकी इनक्यायरी की जरूरत है। मिनिस्टर साफ स्टेट ने कहा है कि नहीं है। इनक्यायरी होगी चाहिये कि साजिर स्पा कहां क्या, किस का है। इस सब के बास्ते मिल जुन कर एक पालियामेंटरी कमेटी हमको बनानी चाहिये जो इस सारे प्रावंभेम की तह में जाए। तभी यह समस्या हल हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाध्य करता हूं।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow. 19:09 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 30, 1978/Bhadra 8, 1900 (Saka).